चौथी दुनिया

हिंदी का पहला साप्ताहिक अखबार

www.chauthiduniya.com

मूल्य 5 रुपये

दिल्ली, 12 अप्रैल–18 अप्रैल 2010

गडकरी जी, अध्यक्ष की तरह दिखिए

पेज 3

ग्लोबल वार्मिंग बनाम मानवाधिकार

पेज 5

अमिताभ को अपमानित मत करो

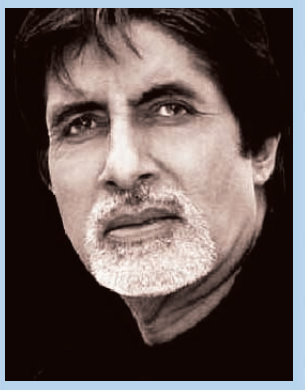

पेज 9

साई बाबा सच्चे दिग्दर्शक हैं

पेज 12

प्रधानमंत्री पद की दौड़ में बाबा रामदेव

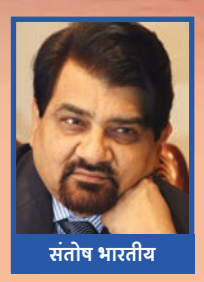

संतोष भारतीय

जिस काम को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नहीं कर सका, जिसे करने की आस लिए विश्व हिंदू परिषद बूढ़ी होने लगी है और भाजपा भावी प्रधानमंत्री का नाम घोषित करने के बाद भी इस सपने की ओर एक क़दम नहीं बढ़ पाई, उस काम को अब एक बाबा पूरा करना चाहता है. इस बाबा ने इंग्लैंड में एक पूरा आइलैंड ख़रीद लिया है, इसने अमेरिका के ह्यूस्टन में लगभग तीन सौ एकड़ ज़मीन ख़रीद ली है. आज इस साधु के पास एक मोटे अंदाज़े के अनुसार, साठ से सत्तर हज़ार करोड़ का साम्राज्य है. पिछले दस सालों में इस साधु बाबा की सफलता की ऐसी अप्रतिम कहानी निर्मित हुई है, जिसका कोई जोड़ भूतकाल में नहीं मिलता. आज यह बाबा देश की सभी 542 संसदीय सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़ा करने की योजना बना कर उस पर अमल कर रहा है. भाजपा और कांग्रेस इसकी रणनीति से परेशानी महसूस कर रही हैं. चुनाव लड़ने के लिए राजनैतिक दलों या ईमानदार राजनेताओं को भले पैसे की कमी हो, लेकिन बाबा के पास पैसे की कोई कमी नहीं है. चुनाव जीतने के लिए अधिकतम जितने धन की ज़रूरत होगी, उसके इंतज़ाम का नक्शा बाबा के दिमाग़ में तैयार है. आइए, आपको विस्तार से बाबा रामदेव के बारे में बताते हैं.

अमेरिका में राष्ट्रपति पद का चुनाव हर चार साल में होता है और वहां की प्रचार एजेंसियां और रणनीति बनाने वाली एजेंसियां एक चुनाव ख़त्म होते ही अगले चार साल बाद होने वाले चुनाव की तैयारियों में जुट जाती हैं. अब तक भारत में ऐसा नहीं हुआ, पर लगता है कि दिमाग़ रखने वाले कई समूहों ने मिलकर बाबा रामदेव की रणनीति बनाई है तथा 2014 में होने वाले आम चुनावों में उन्हें प्रधानमंत्री बनाने की आख़िरी बाज़ी चल दी है. ये समूह हो सकता है देसी हों, लेकिन हो सकता है विदेशी भी हों. लंदन के पास का आइलैंड और ह्यूस्टन की ज़मीन कुछ तो इशारे कर ही रही है.

बाबा ने देश में योग सिखाने की शुरुआत की. बाबा से पहले योग देश में कम, विदेश में योगा के नाम से ज़्यादा जाना जाता था. हमारे यहां से योग जानने वाले विदेशों में बड़े धनवान स्वामी बन गए, वहां संपत्तियां भी ख़रीद लीं. बाबा ने देश में योगा को योग के रूप में पुन:स्थापित किया तथा योग को लेकर एक नई चेतना पैदा की. नरसिंहराव की उदारीकरण की नीति के बाद देश में पैसे का तीव्र आगमन हुआ, जिसने मध्यम वर्ग व उच्च वर्ग की जीवनशैली पर ख़ासा असर डाला. शरीर बेडौल हुआ, बीमारियां बढ़ीं. मधुमेह और हृदय रोग ने तो सर्दी–जुकाम की जगह ले ली. बाबा के योग की मार्केटिंग ने लोगों को आकर्षित किया.

इन्हीं दिनों टेलीविज़न आया, सहारा ग्रुप के मालिक सुब्रत राय ने संभवत: सबसे पहले बाबा को अपने टेलीविज़न पर उतारा. बड़े मैदान में योग के सार्वजनिक प्रदर्शन को टेलीविज़न के ज़रिए दिखाया. इसमें सबसे बड़ा योगदान बाबा के पेट खींचने की यौगिक मुद्रा ने किया. पेट निकलने के कॉम्प्लेक्स के शिकार लोगों ने इसे एक स्वर्णिम अवसर के रूप में लिया. पैसे वालों में यह बीमारी आम है, ख़ासकर उनकी पत्नियों को लगा कि बाबा का योग उन्हें छरहरा और आकर्षक बना देगा. उनका सोचना ग़लत नहीं था. लगातार योग करने से यह संभव हो सकता था. कई लोगों को इसका फ़ायदा भी हुआ. सुब्रत राय के सबसे विश्वस्त साथी ओ पी श्रीवास्तव और उनकी पत्नी को भी इसका लाभ मिला. उनकी पत्नी ने बाबा रामदेव को अपना भाई बना लिया. सुब्रत राय का साम्राज्य ओ पी श्रीवास्तव ही चलाते हैं. बाबा रामदेव के देशव्यापी भ्रमण और उनके व्यक्तित्व को विराट बनाने की योजना कार्यरूप में परिणित होने लगी.

बाबा रामदेव की यौगिक क्रियाओं की सीडी तैयार की गई और उन्हें लगभग हर टेलीविज़न चैनल पर सुबह और शाम चलवाया जाने लगा. देश की जनता हतप्रभ थी तथा उसने बाबा रामदेव के बारे में जानना और पूछना शुरू कर दिया. बाबा के बड़े मैदानों में योग शिविर की सीडी और वीडियो कैसेट बनाकर बेचे जाने लगे. जिन बीमारियों से पैसे वाले पीड़ित हैं, उन्हीं से राजनेता भी पीड़ित हैं. मंत्रियों, सांसदों, मुख्यमंत्रियों ने भी बाबा से संपर्क करना शुरू कर दिया. और, यहीं से बाबा रामदेव सत्ता प्रतिष्ठान के ड्राइंगरूम, किचन रूम और बेडरूम में घुस गए.

बाबा ने योग सिखाने का मूलमंत्र बनाया. आप ख़ैरियत से हैं तो सारा देश ख़ैरियत से है. बाबा ने हिंदुस्तान के हर हिस्से में घूमने का कार्यक्रम बनाया तथा लोगों से संपर्क का प्रमुख ज़रिया योग को बनाया. बाबा विदेशों में भी गए, क्योंकि उनकी योजना बनाने वालों को मालूम था कि बिना विदेश में पैठ बनाए हिंदुस्तान में सर्वशक्तिशाली नहीं बना जा सकता, क्योंकि दुनिया ग्लोबल हो गई है. इसी क्रम में बाबा रामदेव ने योग के लिए पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट बनाया तथा भारत स्वाभिमान के नाम से आंदोलन का सूत्रपात किया.

बाबा रामदेव हरिद्वार में गुरु शंकर देव के शिष्य थे तथा साइकिल पर चलते थे. उन्हें साइकिल पर चलते देखने वालों की बड़ी संख्या है. अब गुरु शंकर देव का कुछ

(शेष पृष्ठ 2 पर)

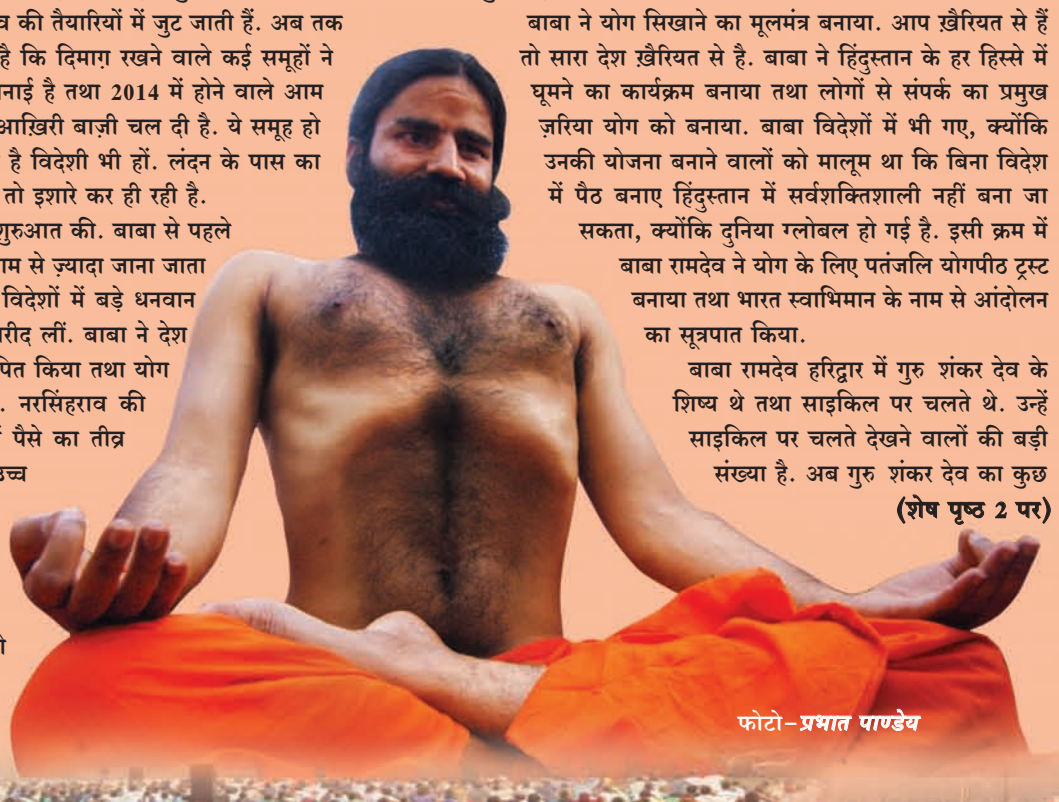

फोटो–*प्रभात पाण्डेय*

भारत का राजनीतिक इतिहास
कमल मोरारका

इंदिरा गांधी सन् सतहत्तर में चुनाव हार गई थीं. चंद्रशेखर जी आपातकाल में उन्नीस महीने की जेल काटकर आए थे. जेल जाने से पहले वह कांग्रेस की सर्वोच्च संस्था, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य थे. देश में मोरारजी देसाई की सरकार बन चुकी थी. चंद्रशेखर जी इंदिरा जी से मिलने गए. उन्होंने इंदिरा जी से कहा कि मुझे बताइए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं. इंदिरा जी परेशान थीं. बोलीं, मैं रहने के लिए महरौली में घर तलाश रही हूं. मेरे पास तो कोई घर भी नहीं है. चंद्रशेखर जी ने उनसे कहा कि आप परेशान मत होइए, आपके लिए घर का इंतज़ाम हो जाएगा.

वहां से उठकर चंद्रशेखर जी मोरारजी देसाई के पास गए. उन्होंने इंदिरा जी के घर के बारे में कहा तो मोरारजी ने तत्काल मना कर दिया. चंद्रशेखर जी ने उन्हें पहले तो समझाया, फिर कहा कि मैं वायदा कर आया हूं. अब आपको घर देना है, चाहे जैसे दें. मोरारजी भाई ने सोच कर कहा कि मार्केट रेट पर दे सकते हैं. चंद्रशेखर जी ने कहा, वैसे ही दे दें. इस तरह इंदिरा गांधी के लिए घर का इंतज़ाम हुआ.

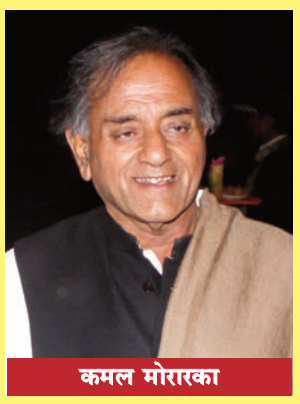

कमल मोरारका

इतिहास का पहिया घूमा. इंदिरा जी की हत्या के बाद चुनाव हुए, जिसमें राजीव गांधी अपार बहुमत से जीते. चंद्रशेखर जी चुनाव हार गए. उनके लिए भी घर का सवाल खड़ा हो गया. अब्दुल गफूर शहरी विकास मंत्री बने. सेंट्रल हाल में चंद्रशेखर जी ने उनसे कहा कि गफूर मियां, मुझे जब नोटिस भेजना, तब बता देना. मैं घर का इंतज़ाम कर रहा हूं. गफूर साहब ने उनसे कहा कि चंद्रशेखर जी, मुझे राजीव गांधी ने कहा है कि चंद्रशेखर जी को औपचारिक नोटिस भी नहीं जाना चाहिए. उन्हें वही घर मिलना चाहिए. शायद राजीव गांधी को इंदिरा जी के घर वाली घटना याद रही होगी या इंदिरा जी ने उन्हें बताया होगा.

अब्दुल गफूर ने चंद्रशेखर जी को वही घर जनता पार्टी अध्यक्ष के नाते एलॉट कर दिया, जो किसी श्रेणी में आता ही नहीं था. पांच साल वह रहे, बाद में वह पुनः चुन कर लोकसभा में आ गए.

चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री थे, तब भारत की आर्थिक हालत ख़राब थी. यह पिछले दस सालों की ग़लत आर्थिक नीति का परिणाम था. उन्हें फ़ैसला लेना पड़ा कि सोना गिरवी रख पैसा लिया जाए. देश में माहौल बना दिया गया कि सारा सोना लंदन में गिरवी रख दिया गया. जबकि हक़ीक़त थी कि वही सोना गया था, जो स्मगलरों से ज़ब्त किया गया था. भारत का अपना सोना रिज़र्व बैंक के पास ही रखा था.

कश्मीर को लेकर चंद्रशेखर जी ने नवाज़ शरीफ से काफी गंभीर बात की, जिससे प्रभावित होकर नवाज़ शरीफ ने हॉटलाइन लगवा कर उनसे लगातार बातचीत की.

आमतौर पर धारणा है कि चंद्रशेखर जी की सरकार इसलिए गिरी, क्योंकि उनके घर के सामने हरियाणा पुलिस के दो सिपाही खड़े थे, जिन पर जासूसी का शक़ था. दरअसल सरकार इसलिए गिरी, क्योंकि चंद्रशेखर जी दो दिनों बाद बाबरी मस्जिद-राम जन्मभूमि विवाद का सर्वसम्मत हल घोषित करने वाले थे. शरद पवार ने इसकी जानकारी राजीव गांधी को दे दी, जिस पर राजीव गांधी के सलाहकारों ने उनसे कहा कि सबसे बड़ी समस्या तो यही है. अगर इसे चंद्रशेखर जी ने हल कर दिया तो आपके लिए कुछ बचेगा ही नहीं. राजीव गांधी ने चंद्रशेखर जी से कहा कि आप दो दिनों तक कुछ न बोलें. और, इन्हीं दोनों दिनों में चंद्रशेखर जी की सरकार से कांग्रेस ने समर्थन वापस ले लिया. सरकार शरद पवार और राजीव गांधी की बातचीत के बाद गिरी.

कमल मोरारका 39 वर्षों तक चंद्रशेखर जी के विश्वस्त रहे. यह पूरा इंटरव्यू आप www.chauthiduniya.tv पर देख सकते हैं. इतिहास की ऐसी ही कई घटनाओं का पहली बार ख़ुलासा हो रहा है और आगे भी होता रहेगा.
संपादक

कुछ सप्ताह पहले कलमाड़ी ने राष्ट्रमंडल खेलों के लिए बनी आयोजन समिति के अध्यक्ष की हैसियत से आर्थिक विशेषज्ञ संजीव मित्तल को उनके पद से हटा दिया था.

दिल्ली का बाबू

पीएमओ का जवाबी हमला

एक बार फिर बच गए सुरेश कलमाड़ी. राष्ट्रमंडल खेलों के लिए अमिताभ बच्चन को ब्रांड एंबेसडर बनाने से इंकार कर उन्होंने ख़ुद को बचा लिया, वरना उनकी गिल्लियां बिखरने ही वाली थीं. फिर भी यह जीवनदान उनके लिए क्षणिक हो सकता है.

कुछ सप्ताह पहले कलमाड़ी ने राष्ट्रमंडल खेलों के लिए बनी आयोजन समिति के अध्यक्ष की हैसियत से समिति के आर्थिक विशेषज्ञ संजीव मित्तल को उनके पद से हटा दिया था. उनके साथ-साथ दो और अधिकारियों की छुट्टी कर दी गई. जबकि सूत्रों के मुताबिक़, मित्तल को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अनुशंसा पर नियुक्त किया गया था. ज़ाहिर है, कलमाड़ी के इस फ़ैसले को प्रधानमंत्री कार्यालय के लिए एक झटके के रूप में देखा गया, लेकिन सरकार की ओर से प्रतिक्रिया आने में भी ज़्यादा देर नहीं लगी.

मामला आगे बढ़े और प्रधानमंत्री कार्यालय को एक बार फिर शर्मिंदगी का सामना करना पड़े, इससे पहले ही कैबिनेट सचिवालय ने मित्तल को फिर से बहाल करने का आदेश जारी कर दिया. साथ में यह भी स्पष्ट कर दिया गया कि मित्तल राष्ट्रमंडल खेलों की समाप्ति तक अपने पद पर बने रहेंगे. लेकिन कलमाड़ी को जानने वाले लोगों का मानना है कि बच्चन एपिसोड के बाद युद्ध विराम भले हो गया हो, यह ज़्यादा टिकाऊ नहीं होगा.

दिलीप चेरियन

पत्नियों की महिमा

हर सफल पुरुष के पीछे एक महिला होती है. यह कांग्रेसी नेता भी भलीभांति जानते हैं. लेकिन हाल के दिनों में आयकर विभाग का कोपभाजन बने मध्य प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों ने इस कहावत को एक बार फिर सत्य साबित कर दिया है. छापों के दौरान आयकर विभाग के अधिकारियों ने पाया कि अधिकांश नौकरशाहों की पत्नियां बीमा एजेंट का काम करती हैं. अपने रसूखदार पतियों की एक्स्ट्रा आमदनी का निवेश करने के लिहाज़ से यह धंधा काफ़ी उपयोगी है.

ये पत्नियां अपने पति और उनके वरिष्ठों की एक्स्ट्रा आमदनी का निवेश तो करती ही हैं, ठेकेदार और ठेका कंपनियों को बीमा योजनाएं बेचकर अपने कारोबार को भी बढ़ाती हैं. अब यदि पति महत्वपूर्ण विभागों में रसूखदार ओहदों पर काम कर रहे हों तो इसके अपने फ़ायदे हैं. आयकर विभाग के छापों के बाद आईएएस अधिकारी अरविंद जोशी और पीडब्ल्यूडी के एक्जीक्यूटिव इंजीनियर दीपक असाई को उनकी पत्नियों के साथ दोषी पाया गया.

सूत्रों पर भरोसा करें तो इस सारे घालमेल के पीछे भी एक महिला का दिमाग ही काम कर रहा था. शुरू में बीमा एजेंट का काम करने वाली सीमा जायसवाल बाद में एक बीमा कंपनी में शाखा प्रबंधक बनी तो पीडब्ल्यूडी, मध्य प्रदेश सड़क निर्माण प्राधिकरण और जल संसाधन जैसे विभागों में अपनी ऊंची पहुंच का फ़ायदा उठाते हुए सीमा ने नौकरशाहों की पत्नियों को भी एजेंट के रूप में काम करने के लिए राजी कर लिया. रोचक तथ्य तो यह है कि अब जब सरकार दोषी अधिकारियों के ख़िलाफ़ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप में कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है, तो ये पत्नियां चैन की बंसी बजा रही हैं. आख़िर सरकार अपने अधिकारियों के ख़िलाफ़ ही तो कार्रवाई कर सकती है.

प्रधानमंत्री पद की दौड़ में बाबा रामदेव

पृष्ठ एक का शेष

पता नहीं है कि वह कहां हैं. न देखे जाने से पहले वह बहुत दुखी थे, ऐसा हरिद्वार में बहुत से लोगों का कहना है. कहां हैं गुरु शंकर देव, इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है और बाबा रामदेव तो इस पर बिल्कुल ख़ामोश हैं. गुरु की पूजा भगवान से पहले की जाती है, गुरु-गोविंद दोउ खड़े, काके लागू पाय, बलिहारी गुरु आपने, जिन्ह गोविंद दियो बताय. पर बाबा रामदेव ने कभी अपने गुरु का नाम कहीं, किसी भी परिस्थिति में नहीं लिया.

बाबा रामदेव के सबसे विश्वस्त साथी बालकिशन महाराज हैं. बाबा जिन्हें भी लाते हैं या जिन्हें खींचते या आकर्षित करते हैं, उन्हें कंसोलिडेट करने का काम बालकिशन महाराज करते हैं. बाबा के पीछे रहने वाले बालकिशन महाराज ने बाबा के आयुर्वेद का साम्राज्य खड़ा किया है. पहले आयुर्वेद को भारत में ग्लैमर मेडिसिन के रूप में नहीं देखा जाता था. जड़ी-बूटियों को इज़्ज़त दिलाने में, ग्लैमरस बनाने में बालकिशन महाराज का बड़ा योगदान है. आज बाबा रामदेव को एक ब्रांड बनाने में सबसे बड़ा योगदान बालकिशन महाराज का है. आज बाबा सब कुछ बेचना चाहते हैं. आटा, आंवला, फलों का रस, दवाएं, यहां तक कि अब वह पानी भी बेचने जा रहे हैं. और, सबके पीछे हैं बाबा के परम विश्वस्त बालकिशन महाराज.

अब तक बाबा रामदेव को भाजपा के लोग हिंदुत्व का अलमबरदार मान रहे थे और कांग्रेस उन्हें आरएसएस का ख़ुफ़िया एजेंट मान रही थी. मुसलमानों के एक हिस्से को उनमें धर्मनिरपेक्षता दिखाई दे रही थी. सबसे पहले बाबा के मुस्लिम नेताओं से रिश्तों के बारे में जानें. बाबा ने एक मर्म समझ लिया कि यदि हिंदुस्तान में सियासी तौर पर कुछ करना है तो बिना मुसलमानों के संभव नहीं है, क्योंकि उनकी आबादी अट्ठारह प्रतिशत के आसपास है. इस तथ्य को जानते हुए भी भाजपा इस ओर क़दम आज तक नहीं उठा पाई. बाबा ने सबसे पहले मुस्लिम उलेमाओं से संपर्क साधा. काफी परखने के बाद उन्होंने धर्मगुरु कल्बे रुशैद रिज़वी से संपर्क किया.

महीनों की बातचीत के बाद बाबा ने उन्हें अपने कार्यक्रमों में आने का न्यौता दिया. मौलाना कल्बे रुशैद रिज़वी के भाषणों से प्रभावित हो, बाबा उन्हें अपने पास बैठाने लगे और उनके द्वारा मुस्लिम समाज से संपर्क साधना शुरू किया. बाबा की इस कोशिश का नतीजा जल्दी ही सामने आ गया, जब जमैतुल उलेमा ए हिंद के मौलाना महमूद मदनी ने एक बड़े जलसे में उन्हें देवबंद आने की दावत दी.

देवबंद मुसलमानों में काफी इज़्ज़त की नज़र से देखा जाता है, बल्कि यहां से जारी की गई सलाहें फतवे का असर रखती हैं. बाबा रामदेव देवबंद गए और उन्होंने लाखों मुसलमानों की भीड़ को संबोधित किया. संबोधन उन्होंने कुरान शरीफ की आयत से शुरू किया. इस बीच देवबंद से कहा जा चुका था कि वंदे मातरम गाना ग़ैर इस्लामी है. बाबा ने वहां जमा लाखों की भीड़ के साथ प्रमुख मौलानाओं से कहा कि जब मैं कुरान की आयत पढ़कर मुसलमान नहीं बन सकता, तब आप वंदे मातरम पढ़कर हिंदू कैसे बन सकते हैं? उन्होंने वहां उपस्थित उलेमाओं से योग करने के लिए कहा, क्योंकि सभी के पेट निकल गए हैं. मुस्लिम समाज को बाबा रामदेव में ऐसा साधु नज़र आया, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या विश्व हिंदू परिषद से बिल्कुल अलग क़िस्म का साधु है. मौलाना मदनी ने बाबा की देश को बनाने की कोशिश में साथ देने का वायदा किया. बाबा का बड़ा मक़सद पूरा हो गया और उन्हें मुस्लिम समाज एक अलग नज़र से देखने लगा.

विश्व हिंदू परिषद या भाजपा से अलग बाबा रामदेव ने धर्म की जगह संस्कृति का सहारा लिया. बाबा को पता है कि गुजरात में नवरात्रि में मुसलमान डांडिया खेलते हैं और सत्ताइसवां रोज़ा शबे कदर का हिंदू औरतें रखती हैं. बाबा इस बात को कहते भी हैं और समझाते भी हैं. इसलिए उनकी स्वीकार्यता हिंदू धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले नेताओं से बहुत ज़्यादा है. एक मुस्लिम धर्मगुरु ने कहा कि पता नहीं चोली के पीछे क्या है, पर दिखने में चोली अच्छी दिखाई देती है.

मौलाबा कल्बे रुशैद रिज़वी का ज़िक्र एक बार फिर करना चाहेंगे. बाबा के साथ सभाओं के अलावा बाबा उन्हें अपने टीवी चैनल पर भी लाते हैं. हरिद्वार में पतंजलि दो के उद्घाटन के अवसर पर उन्होंने मौलाना से कहा, आपसे दिल मिलता है, बाक़ी से आंखें मिलती हैं. उन्होंने इस अवसर पर आयोजित सभा में कहा कि वह अट्ठारह करोड़ मुसलमानों में से हीरा चुनकर लाए हैं. मज़हब वालों का तो मकान रहता है, पर सेक्युलरिज़्म का पूरा मुल्क रहता है. कहना चाहिए कि बाबा ने अपने साथ मुसलमानों, सिखों, जैनियों और ईसाइयों के ऐसे धर्मगुरुओं को लिया है, जिनकी गुणवत्ता और छाप अच्छी है. बाबा ने 2009 से 2010 अप्रैल तक हर राज्य से लोगों को हरिद्वार में बुलाया तथा पतंजलि योगपीठ में बड़े-बड़े शिविर लगाए. अलग-अलग क्षेत्रों में काम करने वालों जैसे डॉक्टर, बुद्धिजीवी, चार्टर्ड एकाउंटेंट, शिक्षक, सीनियर प्रोफेसर तथा उनके अनुसार देश से प्यार करने वाले ईमानदार लोगों के आठ-आठ दिनों के शिविर लगाए गए. इन शिविरों के अंत में सभी को सेहत की हिफ़ाज़त, योग की तालीम तथा देश में शरीफ़ों को जीने का हक़ दिलाने के लिए लड़ने का संकल्प दिलाया जाता है.

बाबा ने अपना आख़िरी विदेशी दौरा अभी-अभी समाप्त किया है. वह नेपाल गए थे और वहां उन्होंने माओवादी नेता प्रचंड से राजनैतिक बात की और उन्हें भी अपने अभियान में शामिल करने के लिए तैयार कर लिया. अब बाबा विदेश नहीं जाएंगे, बल्कि देश के हर हिस्से में घूमेंगे. अप्रैल के बाद यानी इसी महीने के बाद बाबा एक देशव्यापी आंदोलन की योजना बना रहे हैं. उन्होंने भारत स्वाभिमान ट्रस्ट बनाया है और उसकी राजनैतिक शाखा भारत स्वाभिमान जवान बनाई है. यह भारत स्वाभिमान जवान ही इस वर्ष राजनैतिक दल के रूप में बदल जाएगी, जो लोकसभा का चुनाव लड़ेगी. बिना जाति को आधार बनाए राष्ट्र के बारे में सोचने वाले जीतें, ऐसा बाबा का कहना है. बाबा ने एक और बात कही है कि हिंदू मुसलमान को जिताएं और मुसलमान हिंदू को. बाबा की योजना है कि 2014 तक भारत स्वाभिमान ट्रस्ट के सदस्यों की संख्या पचास करोड़ हो जाए.

बाबा रामदेव चुनावी घोषणापत्र का पूर्वाभ्यास अभी से कर रहे हैं, जिसे वह अग्निपत्र कहते हैं. अग्निपत्र कहता है कि सत्ता आने पर स्वदेशी चिकित्सा व्यवस्था 2. स्वदेशी शिक्षा व्यवस्था 3. स्वदेशी अर्थव्यवस्था 4. स्वदेशी क़ानून व कर व्यवस्था 5. भारतीय संस्कृति की रक्षा 6. भ्रष्टाचार, बेरोज़गारी, ग़रीबी, महंगाई व भूख मुक्त वैभवशाली भारत का निर्माण 7. ग्रामीण स्वावलंबन 8. पर्यावरण की रक्षा 9. नियंत्रित जनसंख्या लक्ष्य हासिल किए जाएंगे. बाबा ने अपने लोगों से कहा है कि वे देश की व्यवस्था चलाने वालों से सवाल पूछें. इसके लिए उन्होंने एक प्रश्नावली भी तैयार कर अपने समर्थकों को दी है.

बाबा ने नौ सवाल पूछने के लिए कहा है और स्वयं नौ सूत्री घोषणापत्र बनाने की योजना बना ली है. उन्होंने देशभक्त पत्रकारों, लेखकों एवं बुद्धिजीवियों का भी आह्वान किया है कि वे आएं और उनके साथ जुड़ें. बाबा ने स्विस बैंकों से कालाधन वापस लाने की मुहिम पिछले लोकसभा चुनाव में चलाई थी. यही मांग भाजपा के मनोनीत प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी ने भी उठाई थी. 14 अप्रैल 2009 को बाबा से एक पत्रकार ने पूछा कि आप स्विस बैंक का मुद्दा, बीजेपी का मुद्दा उठा रहे हैं तो क्या आप भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं? बाबा रामदेव ने जवाब दिया था कि मैं भारतीय जनता का एजेंट हूं, पार्टी का नहीं.

बाबा रामदेव भारत की राजनीति बदल देना चाहते हैं. वह सभी संसदीय सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं. पिछले बीस सालों में यह काम भाजपा भी नहीं कर पाई. उसके पास सभी संसदीय सीटों पर लड़ने वाले उम्मीदवार ही नहीं उपलब्ध हो पाए. बाबा रामदेव की पतंजलि योग पीठ में एक भी मंदिर नहीं है और न ही वह आज हिंदू धर्म को अपना ध्वज वाहक बना रहे हैं. उनका कहना है कि वह इंसानियत को मज़हब मानते हैं.

ओशो रजनीश के पास धर्म और धन का बड़ा साम्राज्य था, उन्होंने अपने को भगवान कहलवाना प्रारंभ कर दिया था. महर्षि महेश योगी का हेडक्वार्टर हालैंड में था तथा लगभग साठ देशों में उनके विश्वविद्यालय थे. भारत में उनके शिष्यों में रामनाथ गोयनका से लेकर मंत्रियों की बड़ी फौज़ थी, पर यह सपना तो वे भी नहीं देख पाए. बाबा रामदेव 2014 में लोकसभा का चुनाव पूरी तैयारी के साथ लड़ना चाहते हैं. वह दो हज़ार ग्यारह में छह लाख लोगों से व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहते हैं. देश भर में फैले इन छह लाख लोगों की चयन समिति संसदीय चुनावों के लिए उम्मीदवार चुनेगी, जिनकी घोषणा भी 2011 के अंतिम दिनों में कर दी जाएगी. भारत स्वाभिमान ट्रस्ट के पचास करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य भी बाबा दो हज़ार ग्यारह में ही पूरा कर लेना चाहते हैं.

बाबा के पास नाम है, बाबा के पास धन है, बाबा के पास चेहरा है, बाबा के पास अधूरे ही सही, पर कुछ मुद्दे हैं, लेकिन बाबा को दु:ख है कि उन्हें लोग गंभीरता से नहीं लेते और अभी तक उन्हें योग गुरु ही मानते हैं. इसलिए बाबा ने अब अपना टेलीविज़न चैनल ख़रीद लिया है तथा कई और ख़रीदना चाहते हैं. वह एक न्यूज़ चैनल भी शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि उनकी पूरी बात कोई टीवी चैनल नहीं दिखाएगा. टीवी चैनलों की रुचि उनकी राजनीति में नहीं, उनके पेट सिकोड़ने वाली कपालभाती की मुद्रा को दिखा कर अपने दर्शक बढ़ाने में है. जिस सहारा टेलीविज़न ने उन्हें सबसे पहले दिखाया था, उसी के चीफ को वह अपने न्यूज़ प्रोजेक्ट का चीफ बनाकर ले गए हैं. दूरदर्शन के लिए काम करने वाले वीरेंद्र मिश्र उनके लिए अब पूरे तौर पर कार्यक्रम बना रहे हैं. ये लोग पत्रकारों की बड़ी संख्या को अपनी ओर खींचने की योजना पर काम कर रहे हैं.

भाजपा के बड़े नेता अशोक साहू का कहना है कि बाबा आते हैं, जाते हैं, पब्लिक नोट देती है, वोट नहीं देती. लेकिन भाजपा अध्यक्ष नितिन गडकरी ने बाबा को ख़त लिखा है कि यदि वह चुनाव में खड़े होंगे तो वोट बंटेगा. उधर कांग्रेस भी परेशान है और उसने अपने सभी मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को निर्देश दिया है कि वे बाबा से दूर रहें. सिर्फ़ उसने संपर्क सूत्र के रूप में सुबोधकांत सहाय को बाबा से मिलने और भाजपा से दूर रखने की ज़िम्मेदारी सौंपी है.

भारत के पुराने और नए पूंजीपतियों के घरों में बाबा घुस गए हैं और बाबा को विश्वास है कि सभी उनके साथ खड़े होंगे. सुब्रत राय, रजत शर्मा, गुलाब कोठारी और सुभाष चंद्र गोयल बाबा के साथ खुले रूप में हैं. बाबा ने साधुओं की बड़ी संस्था अखाड़ा परिषद को भी अपने साथ कर लिया है.

पर बाबा ने एक घोषणा और की है कि वह न ख़ुद चुनाव लड़ेंगे और न प्रधानमंत्री बनेंगे. बाबा इस बुनियादी मर्म को जानते हैं कि अगर आप ख़ुद पद से दूर भागेंगे तो लोग आपको उस पद पर बैठा देंगे. आज बाबा रामदेव ने इस लड़ाई का मोर्चा ख़ुद संभाल लिया है. उन्हें लगता था कि रजत शर्मा, सुभाष गोयल और गुलाब कोठारी जैसे मीडिया के महारथी उनके लिए राजनीति में आने का माहौल बना देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं. अब बाबा रामदेव चारों तरफ़ चुनाव लड़ने की, अपने मुद्दों को उजागर करने की घोषणा स्वयं करने लगे हैं. भारतीय उद्योग जगत के बड़े पैसे वालों की बीवियां और उनकी बहनें बाबा के साथ अक्सर कार्यक्रमों में देखी जाती हैं, जिससे अंदाज़ा होता है कि यह वर्ग इस बार एक नया दांव खेलना चाहता है.

बाबा रामदेव को पहले भाजपा अपना सहयोगी मानती थी. उसे लगता था कि वह हिंदू जो उसकी कट्टरता की वज़ह से या विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल से चिढ़कर उसका साथ नहीं देगा, वह बाबा रामदेव के साथ जाएगा और चुनाव के बाद दोनों मिल जाएंगे, लेकिन अब भाजपा बाबा रामदेव से डरने लगी है. दूसरी ओर मुलायम सिंह यादव, लालू यादव और राम विलास पासवान बाबा रामदेव के क़दम को अपने लिए शुभ मानते हैं. यहां एक सवाल सभी को कांटे की तरह चुभ रहा है कि क्या बाबा रामदेव संघ का नया पत्ता तो नहीं हैं? बाबा के क़रीबी संबंध संघ के कई नेताओं से हैं. दूसरा सवाल कि क्या बाबा की राजनैतिक योजनाओं की रणनीति कहीं अमेरिकी कंपनियां तो नहीं बना रही हैं, जिन्हें इस काम में महारत हासिल है?

कुछ भी हो, कैसे भी सवाल हों, पर सत्तर हज़ार करोड़ की प्रत्यक्ष हैसियत से ज़्यादा ताक़त रखने वाला भारत का योग गुरु देश के स्वास्थ्य को सुधारने के लिए एक बड़ा दांव खेलने जा रहा है. ऐसा ही दांव पिछले लोकसभा चुनाव के समय आंध्र में वहां के सुपरस्टार चिरंजीवी ने खेला था. उनकी सभाओं में अप्रतिम भीड़ होती थी. लगता था, आंध्र की राजनीति में चिरंजीवी का एकछत्र राज होगा, पर ऐसा हुआ नहीं. सिनेमा प्रेमी जनता ने उनका उत्साह बढ़ाया, लेकिन वोट देकर सरकार नहीं बनवाई. बाबा रामदेव और चिरंजीवी में बहुत अंतर है. बाबा अपना क़दम फूंक-फूंक कर रख रहे हैं. राजनैतिक दलों के प्रति आम जनता में उपजी निराशा उनके लिए बहुत बड़ी आशा है. अपनी बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए बाबा के योग को आशा की किरण मानने वाले भारत के लोग बाबा का संसद के लिए कितना समर्थन करेंगे, यह देखना दिलचस्प होगा.

editor@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया
देश का पहला साप्ताहिक अखबार

वर्ष 2 अंक 5
दिल्ली, 12 अप्रैल–18 अप्रैल 2010

संपादक
संतोष भारतीय

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210-211 सेक्टर 63, नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के- 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय

के-2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग
कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ-2, सेक्टर -11, नोएडा
गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश-201301

फोन न.

संपादकीय 0120-4783999/11-23418962
विज्ञापन + 91 9873575318
प्रसार + 91 9810017924
फैक्स न. 0120-4783950

पृष्ठ-16 (+4)

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुन: प्रकाशन पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

नितिन गडकरी उस दल के नेता हैं, जिसकी ज़िम्मेदारी सरकार चलाने वाली पार्टी से ज़्यादा है. यही प्रजातंत्र की मर्यादा है.

गडकरी जी, अध्यक्ष की तरह दिखिए

मनीष कुमार

क्या देश की मुख्य विपक्षी पार्टी के नेता का कद किसी उद्योगपति की पत्नी से छोटा हो गया है? भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष नितिन गडकरी आईपीएल के मुंबई और चंडीगढ़ की टीम के मैच के बाद पुरस्कार वितरण समारोह में मौजूद थे. मंच पर और भी लोग थे. जो सबसे प्रमुख अवार्ड था, उसे मिसेज मुकेश अंबानी के हाथों दिया गया और गडकरी के हाथों एक छोटा अवार्ड दिलाया गया. सबसे ज़्यादा छक्के मारने का अवार्ड. सोचने वाली बात यह है कि क्या सोनिया गांधी या फिर आडवाणी के मंच पर होते हुए कोई और सबसे बड़ा अवार्ड दे सकता है? लगता है, नितिन गडकरी को अभी तक अपनी ज़िम्मेदारियों और पद का एहसास नहीं हुआ है. वह यह समझ नहीं पाए हैं कि प्रजातंत्र में मुख्य विपक्षी पार्टी की हैसियत क्या होती है. नहीं तो क्या हम यह मान लें कि देश की मुख्य विपक्षी पार्टी के नेता का कद किसी उद्योगपति की पत्नी से छोटा होता है?

नितिन गडकरी उस दल के नेता हैं, जिसकी ज़िम्मेदारी सरकार चलाने वाली पार्टी से ज़्यादा है. यही प्रजातंत्र की मर्यादा है. गडकरी को आरएसएस ने एक सर्जन बना कर भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनाया था. आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि बीजेपी की बीमारी एक सर्जन ही ठीक कर सकता है. मगर, अफसोस इस बात का है कि गडकरी ने न तो कोई सर्जरी की और न ही कोई ऐसा इलाज किया, जिससे बीजेपी की बीमारी ठीक होती नज़र आए. आने वाला समय बीजेपी के लिए चुनौतियों से भरा है, लेकिन संगठन बीमार है. और, जो नई टीम बनी है, वह अपने साथ और भी कई सारी बीमारियां लेकर आने वाली है.

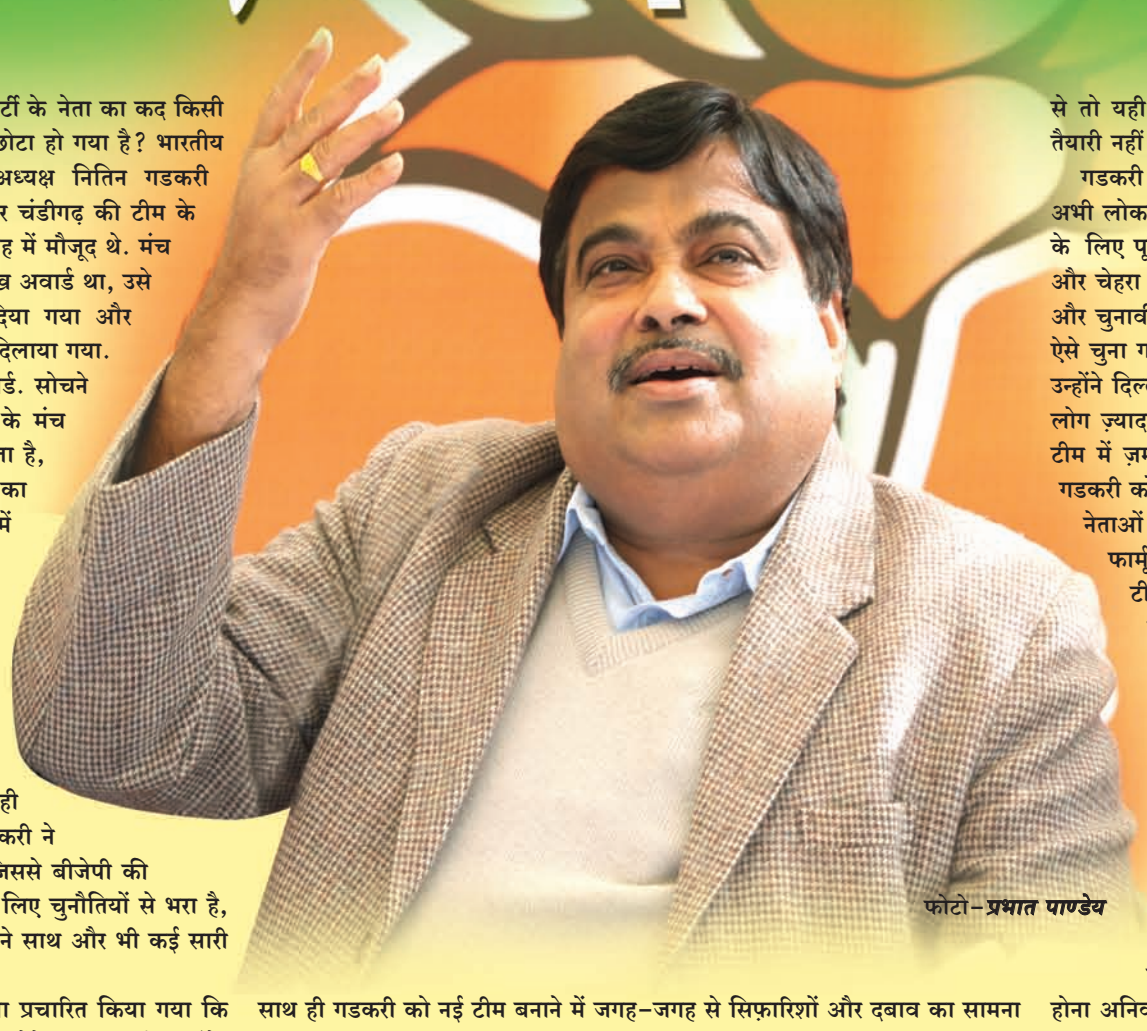

फोटो– *प्रभात पाण्डेय*

53 साल के युवा अध्यक्ष नितिन गडकरी के बारे में ऐसा प्रचारित किया गया कि वह भाजपा को सही रास्ते पर लेकर आएंगे. कांग्रेस को टक्कर देने वाली पार्टी बनाएंगे. यही वजह है कि भाजपा के समर्थकों और कार्यकर्ताओं को गडकरी में एक आशा की किरण नज़र आई. उनकी अपेक्षाएं बढ़ीं. जब फ़ैसले का वक़्त आया और नई टीम का चयन हुआ तो कार्यकर्ताओं और समर्थकों का पहले से टूटा हुआ मनोबल चकनाचूर हो गया. गडकरी ने एक ऐतिहासिक मौक़ा गंवा दिया. अब भाजपा के कार्यकर्ता यह सवाल कर रहे हैं कि नई टीम पार्टी संगठन को मज़बूत करने के लिए चुनी गई है या फिर नेताओं के मनोरंजन के लिए. सवाल जायज़ है, क्योंकि इसमें कामेडियन भी हैं, टीवी आर्टिस्ट भी हैं, डायलॉग मारने वाले बॉलीवुड के घिसे-पिटे कलाकार भी हैं. इस नई टीम में वह सब कुछ है, जो एक फ़िल्म को हिट बनाने के लिए ज़रूरी है, लेकिन ऐसी टीम से राजनीतिक दल को मज़बूत नहीं किया जा सकता है. कुछ लोगों ने तो यह भी कहा है कि गडकरी ने हर क्षेत्र और जाति के लिए जगह आरक्षित करने के चक्कर में मूर्ख नेताओं के लिए भी कुछ पदों को आरक्षित कर दिया है. असलियत यह है कि पिछले चुनाव में हार से निराश कार्यकर्ता गडकरी की नई टीम से नाउम्मीद हो चुके हैं. यह बात भी सच है कि भारतीय जनता पार्टी के पास संगठन चलाने के लिए सही लोगों की कमी है और साथ ही गडकरी को नई टीम बनाने में जगह-जगह से सिफ़ारिशों और दबाव का सामना करना पड़ रहा था.

बीजेपी की असल बीमारी यही है कि पार्टी के पास लोगों के बीच काम करने वाले नेताओं और कार्यकर्ताओं की कमी है. गडकरी को इसी बीमारी का इलाज करना था. एयरकंडीशन कमरे में बैठ कर राजनीति करने वालों को सर्जरी कर बाहर करना था. ज़मीनी स्तर पर काम करने वाले या काम करने के इच्छुक कार्यकर्ताओं को सामने लाना था. पार्टी की कार्यपद्धति बदलनी थी. पार्टी में फ़ैसले लेने की प्रक्रिया में पारदर्शिता लानी थी. युवाओं को आगे लाना था. बीजेपी के नए अध्यक्ष ने इनमें से किसी भी दायित्व को नहीं निभाया. कम से कम नई टीम को देखने से तो ऐसा ही लगता है. आम युवा नेताओं या उभरती हुई प्रतिभाओं की क्या बिसात, पार्टी में गुटबाज़ी ऐसी है कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष अमित ठक्कर को भी गडकरी कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं दे सके. वरुण गांधी को नई टीम में महत्वपूर्ण पद मिलने का मतलब साफ़ है कि यह लोकसभा चुनाव के दौरान दिए गए भाषण का ईनाम है. इसके अलावा पार्टी ने यह भी साफ़ कर दिया है कि पार्टी का मुस्लिम विरोधी एजेंडा जारी रहेगा. कांग्रेस से मुक़ाबला करने के लिए पार्टी को युवा कार्यकर्ताओं की ज़रूरत होगी, लेकिन गडकरी की नई टीम से तो यही संकेत मिलता है कि युवाओं को लुभाने के लिए पार्टी के पास कोई तैयारी नहीं है.

गडकरी पर ज़रूर दबाव रहा होगा, इसलिए उन्होंने नई टीम को चुनने में चूक कर दी. अभी लोकसभा चुनाव होने में काफी वक्त है. उनके पास पार्टी को नई राह पर ले जाने के लिए पूरा मौका था. अगर वह चाहते तो एक ही झटके में पार्टी की चाल, चरित्र और चेहरा बदल सकते थे, पार्टी में नई ऊर्जा भर सकते थे, लेकिन गडकरी सांगठनिक और चुनावी राजनीति की बारीकियों को समझ नहीं सके. संगठन के पदाधिकारियों को ऐसे चुना गया, जैसे चुनाव का टिकट बांटा जा रहा हो. गडकरी की ग़लती यह है कि उन्होंने दिल्ली में बैठकर ही नई टीम का चयन किया, इसलिए दिल्ली के दफ्तर में जो लोग ज़्यादा मंडराते नज़र आए, उन्हें टीम में शामिल कर लिया गया. गडकरी की नई टीम में ज़मीन पर संघर्ष करने वाले कार्यकर्ताओं और नेताओं को जगह नहीं मिली. गडकरी को अपनी टीम में ज़िले और राज्य स्तर पर सक्रिय कार्यकर्ताओं और उभरते हुए नेताओं को जगह देनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने नई टीम बनाने में कांग्रेस पार्टी का फार्मूला अपना लिया. गडकरी वरिष्ठ नेताओं को ख़ुश करना चाहते थे, ताकि नई टीम बनाने के बाद वह कठघरे में न खड़े दिखाई दें. यही वजह है कि पार्टी के सारे वरिष्ठ नेता अपने-अपने नुमाइंदों को संगठन में जगह दिलाने में कामयाब रहे. गडकरी की अपनी कोई राजनीतिक ज़मीन नहीं है, इसलिए विरोध के डर से वह सभी सीनियर लीडर्स को ख़ुश करने में लग गए. गडकरी की नई टीम में ज़्यादातर लोग वे हैं, जो पिछली कार्यकारिणी में जगह बनाने में विफल रहे या फिर वैसे लोग हैं, जिनका अलग-अलग राज्यों के चुनाव में पार्टी की हार में अहम योगदान है. इस लिस्ट में जनता और कार्यकर्ताओं द्वारा रिजेक्ट किए गए नेताओं की संख्या ज़्यादा है. बीजेपी कभी पार्टी विथ द डिफरेंस (अलग तरह की पार्टी) हुआ करती थी, जहां योग्यता ही सफलता की एकमात्र कुंजी होती थी. गडकरी को पार्टी को उसी राह पर लौटाना था, लेकिन नई टीम को देख कर लगता है कि अब इस पार्टी में सफल होने के लिए सेलिब्रेटी होना, दौलतमंद होना और पारिवारिक पृष्ठभूमि होना अनिवार्य हो गया है.

भारतीय जनता पार्टी के संगठन की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वह भीषण गुटबाज़ी की चपेट में है, जिसकी वजह से पार्टी कार्यकर्ता आम जनता से दूर होते जा रहे हैं और पार्टी के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं में दूरियां बढ़ रही हैं. कार्यकर्ताओं के लिए दिल्ली में बैठे नेताओं के पास वक्त नहीं है और कार्यकर्ता आम जनता के सामने जाते नहीं, क्योंकि उनमें अब वह हौसला ही नहीं रहा. इसका परिणाम यह है कि पार्टी ज़मीन से कट गई है. गडकरी से कार्यकर्ताओं को उम्मीद बंधी थी, लेकिन उन्होंने संघ और कुछ वरिष्ठ नेताओं की सिफारिशों के सामने घुटने टेक दिए. यही वजह है कि बीजेपी की नई टीम में कुछ भी नया नहीं है. सवाल यह है कि क्या बीजेपी की नई टीम कांग्रेस से टक्कर ले पाएगी? भाजपा के कार्यकर्ता दबी ज़ुबान में कहने लगे हैं कि पार्टी की हालत पहले से भी ज़्यादा ख़राब होने वाली है. नई टीम किसी भी नजरिए से राहुल और सोनिया गांधी की कांग्रेस से टक्कर लेने के लायक़ नज़र नहीं आती है. जिस धावक को मैराथन दौड़ना हो, अगर उसके पैर शुरुआत में ही डगमगा जाएं तो यह तय है कि वह धावक विजेता नहीं बन सकता.

manish@chauthiduniya.com

e देश का पहला इंटरनेट टीवी

तीन लाख से ज़्यादा दर्शक

- स्पेशल प्रोग्राम-भारत का राजनीतिक इतिहास
- समाचार-राजनीति, खेल, पर्यावरण, मनोरंजन
- संगीत और फ़िल्मों पर विशेष कार्यक्रम
- दुनिया की बेहतरीन डॉक्यूमेंट्री
- हैरतअंगेज़ वीडियो
- हर रोज़ मिलिए चौथी दुनिया के लेखकों से
- साई की महिमा

www.chauthiduniya.tv

एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा-201301

दुनिया में चिंतन का अभी तक का अनुभव बताता है कि चिंतन की एक मनोभूमि ऐसी होती है जहां अपने रास्ते और दृष्टि से पहुंचकर चिंतक विभक्त नहीं रह जाता है.

दलित चिंतन को मिटाने की मुहिम

डॉ. धर्मवीर

प्रेम सिंह

मध्यकाल के रचनाकारों में कबीर का अध्ययन और मूल्यांकन सबसे जटिल और चुनौती भरा रहा है. साहित्य के इतिहासकारों और आलोचकों के अलावा दूसरे विषयों के विद्वानों ने भी कबीर के अध्ययन में रुचि ली है. कबीर का एक विमर्श लोक में भी बराबर चलता रहा है. वहां भी लंबी परंपरा है. उस परंपरा में 1997 में डॉ. धर्मवीर की आलोचना पुस्तक कबीर के आलोचक प्रकाशित हुई. उस पुस्तक में कबीर के व्यक्तित्व और चिंतन के मूल्यांकन संबंधी पूर्व मान्यताओं को ध्वस्त कर डॉ. धर्मवीर ने अपनी नई स्थापनाएं प्रस्तुत की हैं. इस पुस्तक से कबीर के अध्ययन की परंपरा में पहली बार एक बड़ा तूफ़ान उठ खड़ा हुआ.

हिंदी आलोचना के परिदृश्य में सक्रिय सभी रंगतों के आलोचक डॉ. धर्मवीर की हिमाकत से क्षुब्ध हो उठते हैं, और साथ ही उन्हें ठिकाने लगाने के लिए सन्नद्ध. जमे हुए आलोचकों को तजुर्बा है, ख़ासकर प्रगतिवादी आलोचकों को, कि कैसे उनकी काट करने वालों को काटा जाता है. हिंदी के ज़्यादातर आलोचक और लेखक डॉ. धर्मवीर पर चौतरफ़ा हमला बोल देते हैं. इस विश्वास के साथ कि मैदान में नया और अकेला उतरा यह शख्स उनके हमलों के आगे थोड़ी देर भी नहीं टिक पाएगा. लेकिन धर्मवीर उनके हमलों से किंचित भी परेशान नहीं होते. स्वागत और ख़ुशी के साथ पूरी तसल्ली और तफ़सील से सबकी आपत्तियों और सवालों के नुक्ता दर नुक्ता जवाब देते हैं. बहस के साथ कबीर पर उनका शोध–कार्य जारी रहता है.

इस दौरान उनकी एक के बाद एक पांच पुस्तकें सामने आती हैं. तीन पुस्तकें–कबीर डॉ. हज़ारी प्रसाद द्विवेदी का प्रक्षिप्त चिंतन(2000), कबीर और रामानंद–किवदंतियां (2000), कबीर–बाज भी, कपोत भी, पपीहा भी (2000)–नई सदी में कबीर श्रृंखला के अन्तर्गत और दो पुस्तकें–कबीर के कुछ और आलोचक(2002) और सूत न कपास (2003) कबीर के आलोचक श्रृंखला के अंतर्गत. इन पुस्तकों से पता चलता है कि शुरुआती छोटी पुस्तक के पीछे लेखक की बड़ी तैयारी थी. चर्चा कबीर और उसकी आलोचना के दायरे से निकलकर ज्ञान की कई दिशाओं–दर्शन, धर्म, समाजशास्त्र, इतिहास, न्याय, क़ानून आदि–में व्याप्त हो जाती है. जो समझ रहे थे कि डॉ. धर्मवीर को हवा में उड़ा देंगे, जान गए कि मुठभेड़ किसी सामान्य आलोचक से नहीं एक गंभीर चिंतक से है. कबीर के आत्मविश्वास से लैस एक ऐसा चिंतक, जिसने प्रगतिशीलता एवं आधुनिकता के झंडाबरदार ब्राह्मणों –ठाकुरों–वैश्यों को एक झटके में दलित–चिंतन की धार पर धर दिया है. ब्राह्मणवादी दर्शन और संस्कृति में पगे दिमाग़ को मानववाद, मार्क्सवाद, अस्तित्ववाद, मनोविश्लेषणवाद, उत्तर–आधुनिकतावाद, आदि की पैकेजिंग से संवारकर आधुनिक बुद्धिजीवी बने विद्वानों के सामने यह कड़ी चुनौती थी. जो बड़े उत्साह और आत्मविश्वास के साथ डॉ. धर्मवीर से उलझे थे, वे सब पीछे हट गए.

दरपेश चुनौती के सामने प्रभुत्वशाली संस्थान अथवा महानुभाव कई बार चुप्पी की राजनीति (पॉलिटिक्स ऑफ साइलेंस) का सहारा लेते हैं. वह किसी गंभीर चुनौती को निष्क्रिय करने की बोलने–लिखने से ज़्यादा असरदार रणनीति होती है. डॉ. धर्मवीर की चुनौती के सामने हिंदी के कुछ विद्वानों ने चुप्पी का हथियार इस्तेमाल किया. डॉ. नामवर सिंह ने कहा कि वे डॉ. धर्मवीर के विरोध में नहीं बोलेंगे, हालांकि वे उनकी स्थापनाओं से सहमत नहीं हैं. उन्होंने पहेली बुझाई कि डॉ. धर्मवीर का विरोध करने से ब्राह्मणवाद मज़बूत होगा. शायद शुरू में डॉ. नामवर सिंह को लगा होगा कि उनके दो शिष्य डॉ. वीरभारत तलवार और डॉ पुरुषोत्तम अग्रवाल उनके साथी डॉ. मैनेजर पांडे के साथ मिलकर डैमेज कंट्रोल कर लेंगे. अर्थात तूफ़ान से मार्क्सवाद और डॉ. हज़ारीप्रसाद द्विवेदी को सुरक्षित बचाकर ले आएंगे. डैमेज कंट्रोल न हो पाने की स्थिति में वे ख़ुद कुछ देर के लिए मैदान में उतरकर डॉ. धर्मवीर को मर्यादा तोड़ने यानी शास्त्र एवं गुरु की निंदा का दंड देंगे. लेकिन लगता है कि वे जल्दी ही समझ गए कि इस बार चुनौती विकट है और अभी तक आजमाई साहित्यिक युक्तियों से मामला रफा–दफा होने वाला नहीं है. यह कबीर पर क़ब्ज़े की लड़ाई नहीं, डॉ. धर्मवीर ने ज्ञान पर ब्राह्मणी क़ब्ज़े को हटाने का कांड उपस्थित कर दिया है. यह पहचानने में वे सबसे ज़्यादा सयाने निकले कि पूरी तैयारी से मैदान में उतरे डॉ. धर्मवीर के सामने सीधी मुठभेड़ में जीतने का माद्दा इस समय हिंदी के किसी विद्वान में नहीं है. इसलिए चुप हो जाओ, झुक जाओ, नई रणनीति बनाओ.

कबीर के आलोचक समेत उपर्युक्त छह पुस्तकों और लंबी बहस के बाद कबीर पर कोई नया और गंभीर अध्ययन डॉ. धर्मवीर को नज़रअंदाज़ करके नहीं किया जा सकता है. भले ही उसमें डॉ. धर्मवीर की काट ही काट हो. अगर उस बहस में शामिल रहने वाला कोई विद्वान अपने कबीर संबंधी अध्ययन में डॉ. धर्मवीर को नज़रअंदाज़ करता है तो अकादमिक जगत के लिए यह चिंता का बायस होना चाहिए. अकादमिक ईमानदारी का विकल्प नहीं है और उसका समुचित निर्वाह सभी विद्वानों की सम्मिलित ज़िम्मेदारी है. जब डॉ. पुरुषोत्तम अग्रवाल की पुस्तक ,अकथ कहानी प्रेम की – कबीर की कविता और उनका समय का प्रकाशन–पूर्व प्रचार शुरू हुआ तो हमने स्वाभाविक तौर पर माना कि आलोचक ने डॉ. धर्मवीर की पुस्तकों और बहस को खाते में लेकर अपना अध्ययन पूरा किया होगा और इस रूप में वह कबीर पर एक महत्वपूर्ण आलोचना कृति होगी. पुस्तक प्रकाशित होने पर हमें अपने एक शोधार्थी से यह जानकर आश्चर्य हुआ कि डॉ. अग्रवाल की पुस्तक में डॉ. धर्मवीर की पुस्तकों का ज़िक्र ही नहीं है. पांच साल पहले जो महाभारत कबीर को लेकर मच चुका है उसके बाद यह संभव नहीं है कि कबीर पर तीस बत्तीस साल लगाकर काम करने वाले विद्वान के सामने डॉ. धर्मवीर के कबीर की तस्वीर न झूलती रहे.

यह स्वीकृत मान्यता है कि भक्तिकालीन भक्त एवं संत कवियों ने अपनी अपनी मनोभूमि से समवेत रूप में प्रेम को पांचवा पुरुषार्थ सिद्ध कर दिया था. यह भी माना जा सकता है कि कबीर और रैदास की प्रेमोपासना संभवत: सबसे निराली और सबसे उद्दात है. ऐसे में कबीर समेत समस्त भक्तिकालीन रचनाकारों के प्रेमोपासक होने से भला किसे ऐतराज़ हो सकता है. डॉ. धर्मवीर ने कबीर की खोज मुक्त–ज्ञान के करुणानिधान के रूप में की है. वहां उनसे मुठभेड़ की जा सकती है जो कुछ हद तक हुई भी और धर्मवीर ने जवाब भी दिए. उनके जवाबों को अपर्याप्त, यहां तक कि ग़लत ठहराया जा सकता है. डॉ. अग्रवाल की पुस्तक के शीर्षक से ही यह समझा जा सकता है कि लेखक ने प्रेम की अकथ कहानी की आड़ में ज्ञान पर वर्चस्व की राजनीति की है. कबीर को डॉ. धर्मवीर से छुड़ाकर प्रेम के पुराने अखाड़े में खींच कर ले जाना दरअसल प्रतिक्रियावाद कहा जाएगा.

दलित चिंतन की भूमि से इसे ब्राह्मणवादी साजिश भी कहा जा सकता है. हमने इस पुस्तक की राजनीति के बारे में बाहर से बताया है. बेहतर होगा कि डॉ. धर्मवीर तीन दशक लगाकर लिखी गई डॉ. अग्रवाल की बहुप्रशंसित पुस्तक को पढ़ें और उसकी अंदरूनी राजनीति की विस्तृत समीक्षा करें.

हमें विश्वास था कि डॉ. धर्मवीर के कबीर को ग़ायब करने का डॉ. अग्रवाल का जादू सभी विद्वानों पर नहीं चलेगा. कहीं न कहीं से आवाज़ आएगी. हमारे कान पुस्तक की भूरी भूरी प्रशंसा करने में लगे विद्वानों की तरफ़ लग गए कि वे डॉ. धर्मवीर का कोई ज़िक्र करते हैं या नहीं. भले ही यह कहकर कि डॉ. अग्रवाल ने कबीर के नाम पर फैलाया गया कूड़ा करकट साफ कर दिया गया है. डॉ. अग्रवाल की पुस्तक का प्रकाशन और विमोचन समारोहपूर्वक हुआ. उसपर गोष्ठियों और समीक्षाओं का सिलसिला अभी जारी है. जिसे सुनियोजित ढंग से पुस्तक को लांच किया गया है उससे लगता है कि गोष्ठियों और समीक्षाओं का सिलसिला लंबा चलेगा. अब तक प्राय: हर रंगत का विद्वान पुस्तक पर अपने को न्यौछावर कर चुका है. समस्या यह है कि विद्वान लेखक ने अपनी लिखित या मौखिक राय रखते वक़्त डॉ. धर्मवीर और उनके कबीर का हवाला नहीं दिया है. डॉ. नामवर सिंह ने भी नहीं, जो कहते थे कि कबीर पर आगे बात बिना धर्मवीर के नहीं हो सकती. ऐसा माहौल बना दिया गया है मानो कबीर पर धर्मवीर की पुस्तकें आई ही नहीं थीं, न कोई बहस थी, न धर्मवीर नाम का कोई विद्वान हिंदी में है. इसके बावजूद कि कबीर के बाद धर्मवीर की कई विषयों पर पुस्तकें आ चुकी हैं.

अब हम कह सकते हैं कि डॉ. धर्मवीर को ग़ायब करने का काम चूक से या अकेले डॉ. अग्रवाल के करने से नहीं हुआ है. यह जाना–बूझा और सम्मिलित उद्यम है. जिस तरह से आधुनिक और प्रगतिशील युग में डॉ. धर्मवीर को ग़ायब करने का तिलिस्म रचा गया है, उससे यह आशंका मज़बूत होती है कि पिछड़े सामंतकालों में दलित–चिंतन को दबाने और नष्ट करने की युक्तियां और रणनीतियां बड़े पैमाने पर ईजाद की गई होंगी और अमल में लाई गई होंगी. कम से कम शुरुआती दौर में तो ज़रूर ऐसा हुआ होगा – जब तक दलित और शूद्र जीवन को श्रम और सेवा का पर्याय बनाकर ज्ञान–विहीन क्षेत्र में तब्दील नहीं कर दिया गया. यह तो ख़ैर पीछे की बात है और उसे मध्यकाल के मत्थे मढ़कर तसल्ली पाई जा सकती है. लेकिन प्रस्तुत और इस तरह के अन्य वाकये बताते हैं कि हाशिए के समूहों और अस्मिताओं के सशक्तीकरण की आधुनिक बुद्धिजीवियों की चिंता वास्तविक नहीं है. आधुनिक बौद्धिक प्रतिष्ठान हज़ारों साल तक दबाकर रखी गई हाशिए की अस्मिताओं को स्वतंत्र चिंतन की छूट देने को तैयार नहीं है. ऐसे चिंतन को तो कतई नहीं जिसमें प्रभुत्वशाली चिंतन के बरक्स समुचित ढांचा और दृष्टि मिलती हो. डॉ. धर्मवीर के चिंतन की पद्धति में एक हद के बाद तेर–मेर का रवैया हमें ठीक नहीं लगता रहा है. दुनिया में चिंतन का अभी तक का अनुभव बताता है कि चिंतन की एक मनोभूमि ऐसी होती है जहां अपने रास्ते और दृष्टि से पहुंचकर चिंतक विभक्त नहीं रह जाता है. अब बात हमारी समझ में आती है कि एक दलित चिंतक अनेक ख़तरों के लिए खुला होता है. रास्ते के बटमार, दलित चिंतक को कभी पूर्णकाम नहीं होने दे सकते. दलित चिंतक प्रचलित अर्थ में समन्वयवादी नहीं हो सकता. अगर वह होता है तो ब्राह्मणी चिंतन कई तरह के हथकंडों से उसके चिंतन को रुला सकता है. डॉ. धर्मवीर ने दलित चिंतन को सबसे बड़ा ख़तरा मार्क्सवादी बटमारों से बताया है. शायद यही उनका सबसे बड़ा अपराध हो गया है.

डॉ. धर्मवीर के स्वतंत्र दलित चिंतन के विरोधियों ने पीछे हटते वक़्त मुंह बनाते हुए जताया था कि मूर्ख के मुंह कौन लगे. बात वहीं समाप्त हो जा सकती थी. लेकिन हुई नहीं. डॉ. धर्मवीर ने बारूद का जो ढेर इकट्ठा कर दिया था, उसे निष्क्रिय करना ज़रूरी था. पुश्त दर पुश्त चले आए सत्ता पर क़ब्ज़े को बरक़रार रखने के लिए ज्ञान पर क़ब्ज़ा बनाए रखना अनिवार्य है. उन्हें यह अहसास अच्छी तरह हो गया कि डॉ. धर्मवीर क़ब्ज़े में आने वाले नहीं हैं. लिहाजा, अंदर ही अंदर तय पाया गया कि उन्हें ध्वस्त करने की पुख्ता और दूरगामी रणनीति बनानी होगी. डॉ. अग्रवाल की पुस्तक और उसके जन्म पर जो सोहर गाए जा रहे हैं, उसी रणनीति का प्रतिफल है.

इस प्रतिफल तक आने के पहले काफी कुछ घटित हुआ है, जिसके विस्तृत ब्यौरे में नहीं जाया जा सकता. लेकिन एक दो मोटी बातें बताई जा सकती हैं. डॉ. अग्रवाल के शिष्य बजरंग बिहारी तिवारी और रमणिका गुप्ता के निर्देशन में दलित महिलाओं से नैतिकता के ठेकेदार धर्मवीर पर चप्पलें फिंकवाई गईं. डॉ. धर्मवीर द्वारा कफन की बुधिया के पेट में ठाकुर का बच्चा बताने पर, सामंतवाद को पानी पी–पी कर कोसने वाले राजेंद्र यादव सरीखे प्रगतिशील के पर्याय लेखक हाहाकार कर उठे. बड़े बड़े लेखकों ने गली के छोकरों के अंदाज़ में डॉ. धर्मवीर की बौद्धिकता पर फब्तियां कसीं और लानत भेजी. गोया किसी ठाकुर ने किसी दलित महिला का कभी शीलहरण किया ही न हो.

कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में कबीर सभी जगह पढ़ाए जाते हैं. लेकिन लगभग सभी जगह कबीर के अध्ययन के लिए प्रस्तावित संदर्भग्रंथों में डॉ. धर्मवीर की किताबें नहीं हैं. डॉ. धर्मवीर पर शोध करने के इच्छुक शोधार्थियों को हतोत्साहित किया गया. चार साल पहले एम.फिल. के हमारे एक शोधार्थी को डॉ. धर्मवीर की आलोचना दृष्टि पर शोध का विषय मिला तो डॉ. अग्रवाल ने उसपर विषय बदलने के लिए दबाव डाला. हमें यह सुनकर अपने पेशे पर गहरी ग्लानि हुई कि उन्होंने शोधार्थी के सामने डॉ. धर्मवीर के प्रति असंसदीय भाषा का प्रयोग किया. एक चर्चित दलित लेखक ने भी शोधार्थी को लताड़ा कि वह डॉ. धर्मवीर पर शोध करके क्यों उनका महत्व बढ़ाता है. हमारे नामचीन और ज़िम्मेदार पदों पर बैठे विद्वानों का यह क्या हाल हो गया है. डॉ. सुधीश पचौरी ने जताया है कि वे चौतरफा विरोध के बीच डॉ. धर्मवीर के समर्थक हैं. लेकिन वे पहली ही नज़र में पकड़े जाते हैं जब भारतीय समाज और वांग्मय की गहरी खुदाई करने वाली और अपने को आदि स्रोतों से जोड़ने वाली प्रतिभा को उत्तर–आधुनिकता की संजीवनी से जाग्रत हुआ बताते हैं. यानी एक आजीवक को आज के बाज़ार का जीव मानते हैं. समर्थन की आड़ में भ्रम फैलाने के और भी उदाहरण मिल सकते हैं.

कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि डॉ. धर्मवीर के चिंतन को निष्क्रिय करने के लिए जार–सत्ता, बाज़ार–सत्ता और सरकार–सत्ता के नुमाइंदे बुद्धिजीवी एकजुट हो गए हैं. यह अलग विषय है कि उनकी संलिप्तता में भारत में पिछले डेढ़ हज़ार सालों से चली आ रही रूढ़ि की बड़ी भूमिका है. क्योंकि वे इतने नादान नहीं हैं कि यह सच्चाई नहीं जानते हों कि मौलिक सृजन और चिंतन कुछ देर के लिए नज़रअंदाज़ किए जा सकते हैं, उन्हें हमेशा के लिए निष्क्रिय नहीं किया जा सकता.

राजेन्द्र यादव

डॉ. नामवर सिंह

लेखक दिल्ली विश्वविद्यालय में प्राध्यापक हैं

feedback@chauthiduniya.com

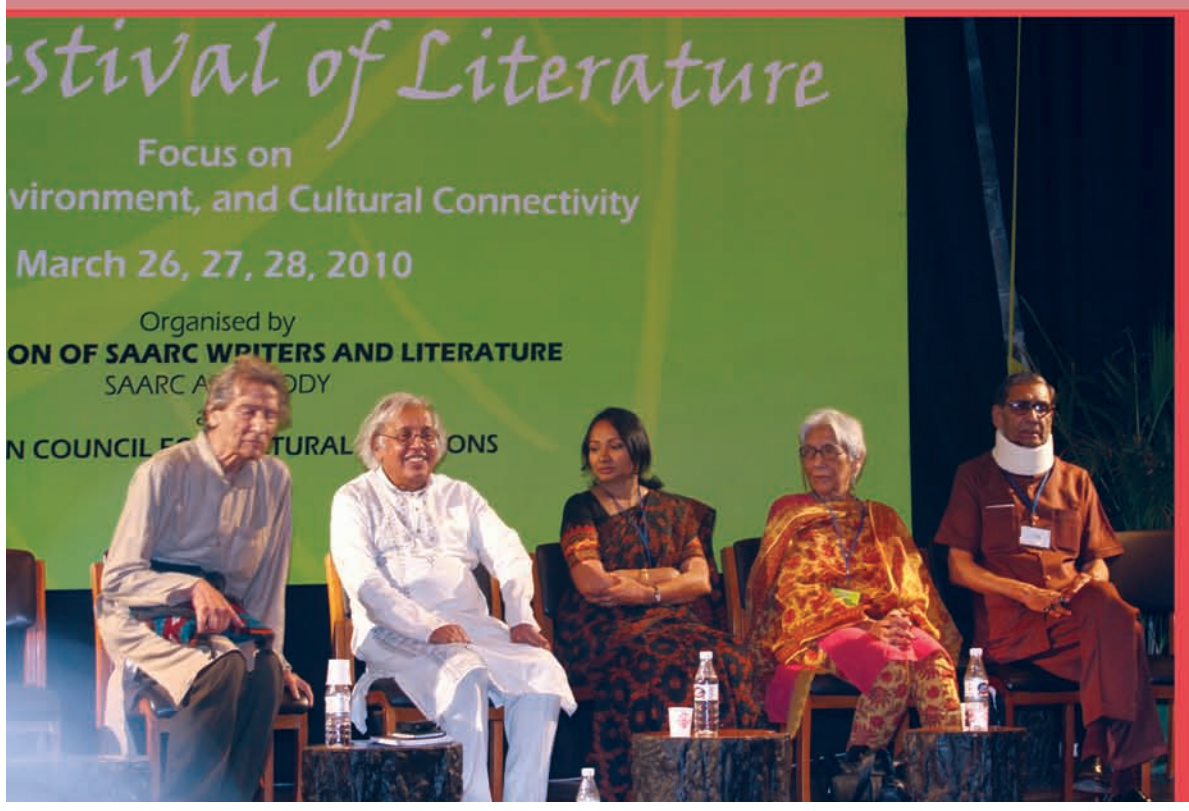

साहित्यकार फोसवाल में ऊबे दिखे

कला और साहित्य ज़मीन पर खींची गई किसी लकीर के दायरे में नहीं बांधे जा सकते. ऐसा ही कुछ देखने को मिला सार्क देशों से आए साहित्यकारों के सम्मेलन में. लगा जैसे इस कार्यक्रम के लंबे सत्र से अनेक साहित्यकार ऊब गए थे. जो सुबह आए,वे शाम तक रुक नहीं सके. फाउंडेशन ऑफ सार्क राइटर्स एंड लिटरेचर (फोसवाल) की ओर से इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित इस सालाना आयोजन में सार्क के आठ देशों से आए नए और पुराने साहित्यकारों ने तीन दिनों तक (26-28 मार्च) अपनी-अपनी कविताओं, कहानियों और नज्मों से लोगों को रूबरू कराया. यह आयोजन भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के सहयोग से आयोजित किया गया. लेकिन मज़ेदार बात यह कि आयोजन के दूसरे दिन जिन भारतीय कवियों और साहित्यकारों को मंच को सुशोभित करना था, वे उपस्थित ही नहीं थे. संचालक ने दूसरे सेशन में क़रीब 20 नाम पुकारे, जिनमें से महज 4 ही सभागार में उपस्थित थे. ज़ाहिर है, यह अनुपस्थिति भारतीय साहित्यकारों और कवियों की या तो लापरवाही या फिर ऐसे आयोजनों के प्रति उनकी उदासीनता को ही प्रदर्शित करती है. बहरहाल, इन कमियों के बाद भी पाकिस्तान, अफ़ग़ानिस्तान, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश और भूटान से आए साहित्यकारों ने आपसी रिश्तों को एक क़दम और आगे बढ़ाने का काम किया. पहले दिन समारोह की शुरुआत करते हुए डॉ. कर्ण सिंह ने कहा भी कि सार्क देशों के बीच राजनीतिक मतभिन्नता ने इन देशों के बीच संबंध को कटु ही बनाया है लेकिन साहित्यिक और सांस्कृतिक आदान-प्रदान की हमारी इस कोशिश में ही आशा की एक किरण भी छुपी हुई है. मशहूर भारतीय शायर गुलजार और पाकिस्तान के सरमद सहबाई ने श्रोताओं को अपनी शायरी से मंत्रमुग्ध कर दिया. भारत-पाक संबंध को ले कर गुलजार तो वैसे भी काफी भावुक रहे हैं और उनकी यह भावुकता उनकी शायरी में भी झलकती है. चौथी दुनिया से बात करते हुए गुलजार ने कहा कि यह अच्छी बात है कि इस तरह के आयोजन हो रहे हैं और आने वाले दिनों में इसके फ़ायदे भी देखने को मिलेंगे. इस मौके पर पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार और जीयो टीवी के कार्यकारी संपादक हामिद मीर को लाईफटाइम एचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया. हामीद मीर ने लेखन के ज़रिए ही भारत-पाक संबंधों में आई कटुता को ख़त्म करने का सुझाव दिया.

शशि शेखर
shashishekhar@chauthiduniya.com

नवंबर 2007 में जारी किया गया माले घोषणापत्र वैश्विक जलवायु परिवर्तन को मानवीय पक्षों से जोड़ने की दिशा में दूसरा बड़ा क़दम था.

ग्लोबल वार्मिंग बनाम मानवाधिकार

जस्टिस पी. सथाशिवम

जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए उठाए गए क़दमों की सुस्त चाल से, इससे प्रभावित हो रहे समुदायों में स्वाभाविक रूप से निराशा बढ़ी. परंपरागत राजनैतिक-वैज्ञानिक पद्धतियों पर आधारित उक्त उपाय ज़्यादा प्रभावी साबित नहीं हो रहे थे, पीड़ित लोगों की समस्याओं की अनदेखी हो रही थी और सबसे बड़ी बात यह थी कि मानवीय गतिविधियों के चलते वैश्विक तापमान में हो रही वृद्धि के लिए ज़िम्मेदारी तय करने की कोई व्यवस्था न होने से प्रभावित समुदायों को लगातार मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था. इन सब कारणों का सम्मिलित नतीजा यह रहा कि दिसंबर 2005 में कनाडा और अमेरिका में सक्रिय इन्युट ने इंटर अमेरिकन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स के समक्ष एक अपील दायर की. अपील में इन्युट ने आरोप लगाया था कि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को नियंत्रित करने में अमेरिका की विफलता से उसके मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है. हालांकि तत्काल इस अपील को ख़ारिज कर दिया गया, लेकिन फरवरी 2007 में कमीशन ने मानवाधिकारों और ग्लोबल वार्मिंग के बीच संबंध पर अपना पक्ष रखने के लिए इन्युट, सेंटर फॉर इंटरनेशनल एन्वॉयरमेंटल लॉ (सीआईईएल) और अर्थजस्टिस संस्था के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया. इस बैठक के काफी उत्साहजनक परिणाम निकले और पहली बार यह माना गया कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए मानवीय गतिविधियां ही ज़िम्मेदार हैं और इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित भी इंसान ही होता है. इस लिहाज़ से यह आवश्यक है कि मानवाधिकारों के अंतर्गत ज़िम्मेदारी, उत्तरदायित्व और न्याय के दायरे में रहकर ही इस पर विचार किया जाना चाहिए.

नवंबर 2007 में जारी किया गया माले घोषणापत्र वैश्विक जलवायु परिवर्तन को मानवीय पक्षों से जोड़ने की दिशा में दूसरा बड़ा क़दम था. इस घोषणापत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया कि मानवाधिकारों के पूरे उपभोग के नज़रिए से जलवायु परिवर्तन बेहद महत्वपूर्ण है. इस घोषणापत्र पर यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के बाली में हुए 13वें सम्मेलन में भी विचार किया गया. यह घोषणा की गई कि जलवायु परिवर्तन को केवल प्रकृति से ही जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि यह मानव जीवन के अस्तित्व और उसकी सुरक्षा से भी सीधे तौर पर जुड़ा है. यह सही है कि जलवायु परिवर्तन की सबसे बड़ी वजह प्रकृति में आने वाले बदलाव हैं, लेकिन प्रकृति में आ रहे इन बदलावों के लिए इंसान और उसकी गतिविधियां ही ज़िम्मेदार हैं. मानवाधिकारों के लिए संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त ने भी इसकी हामी भरी और जोर देकर कहा कि जलवायु परिवर्तन के ख़तरे को कम करने और उससे निबटने के लिए मानवाधिकारों के दायरे के अंदर ही प्रयास किया जाना आवश्यक है. इन्हीं सब प्रयासों का नतीजा था कि 28 मार्च 2008 को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने सर्वसम्मति से मानवाधिकार और जलवायु परिवर्तन पर प्रस्ताव संख्या 7/23 को मंजूरी दी. इस प्रस्ताव द्वारा पहली बार आधिकारिक तौर पर यह माना गया कि जलवायु में आ रहे बदलावों से विश्व भर में मानव जीवन पर तात्कालिक एवं दूरगामी प्रभाव पड़ते हैं और इससे मानवाधिकार भी प्रभावित होते हैं. इससे पैदा होने वाली परिस्थितियां मानवाधिकारों के उपभोग में बाधा का काम करती हैं. प्रस्ताव में उच्चायुक्त कार्यालय (ओएचसीएचआर) को यह निर्देश भी दिया गया कि वह जलवायु परिवर्तन और मानवाधिकारों के बीच संबंधों का विश्लेषण करके परिषद के दसवें सत्र में अपनी रिपोर्ट पेश करे. साथ ही परिषद की बैठक में हुए विचार-विमर्श को कोपेनहेगन में होने वाले यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के 15वें सम्मेलन (सीओपी-15) से पहले सदस्य राष्ट्रों के समक्ष पेश किया जाए, ताकि इस मुद्दे पर आगे विचार-विमर्श हो सके. प्रस्ताव के दिशानिर्देशों के मद्देनज़र 15 जनवरी 2009 को ओएचसीएचआर ने अपने अध्ययन की रिपोर्ट प्रकाशित की. इस रिपोर्ट में बताया गया कि वैसे तो ग्लोबल वार्मिंग सभी तरह के मानवाधिकारों को प्रभावित करती है, लेकिन कुछ ऐसे अधिकार हैं, जो जलवायु परिवर्तन के चलते विशेष रूप से प्रभावित होते हैं, जैसे जीने का अधिकार, भर पेट भोजन का अधिकार, पानी की उपलब्धता, स्वस्थ रहने का अधिकार और रहने के लिए आवास एवं स्वनिर्णय का अधिकार. इसमें यह भी कहा गया कि यूं तो ग्लोबल वार्मिंग पूरी दुनिया के लिए ख़तरा है, लेकिन कुछ ख़ास इलाक़ों जैसे छोटे द्वीपीय राष्ट्र, समुद्र किनारे गहराई में बसे देश, बाढ़ प्रभावित इलाक़े या ऐसे देश, जहां सूखा या मरुस्थलीकरण की समस्या है (मालदीव एवं माली आदि), के लिए यह ज़्यादा ख़तरनाक है. रिपोर्ट में बताया गया कि ख़तरे को कम करने या उससे निबटने के लिए अपनाए गए तरीक़ों जैसे लोगों को दूसरी जगह बसाए जाने में भी मानवाधिकारों का मुद्दा जुड़ा हुआ है.

ओएचसीएचआर की रिपोर्ट के जवाब में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने 25 मार्च 2009 को हुई अपनी दसवीं बैठक में मानवाधिकार और जलवायु परिवर्तन पर प्रस्ताव संख्या 10/4 का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया.

प्रस्ताव में कई महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं.

परिषद ने यह स्वीकार किया कि ग्लोबल वार्मिंग से मानवाधिकारों के उपभोग पर प्रत्यक्ष और परोक्ष, दोनों तरह का प्रभाव पड़ता है. प्रस्ताव में उन अधिकारों की भी चर्चा है, जो जलवायु परिवर्तन से विशेष रूप से प्रभावित होते हैं. इसमें यह भी माना गया कि भौगोलिक स्थिति, ग़रीबी, लिंग, उम्र या किसी समुदाय विशेष से संबद्ध लोगों के मानवाधिकार ज़्यादा गंभीर रूप से प्रभावित होते हैं.

पर्यावरणीय प्रदर्शन सूचकांक (एन्वॉयरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स) 2010

वर्ष 2010 का पर्यावरणीय प्रदर्शन सूचकांक 27 जनवरी 2010 को वाशिंगटन में हुई विश्व आर्थिक परिषद की सालाना बैठक में जारी किया गया. यह सूचकांक कोलंबिया और येल विश्वविद्यालय से जुड़े पर्यावरण विशेषज्ञों ने तैयार किया था. हर दो साल पर जारी होने वाला यह सूचकांक वर्ष 2006 में पहली बार तैयार किया गया था. प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए उठाए गए क़दमों के आधार पर भारत और चीन को इस सूचकांक में क्रमश: 123वां और 121वां स्थान दिया गया था, जो इस बात को रेखांकित करता है कि तीव्र आर्थिक विकास से पर्यावरण पर भी खासा जोर पड़ता है. हालांकि अन्य नए औद्योगीकृत देशों में ब्राजील 62वें और रूस 69वें स्थान पर थे, जो इस बात की ओर भी इशारा करता है कि प्रदूषण नियंत्रण के लिहाज़ से विकास का स्तर या उसकी गति ही एकमात्र कारक नहीं है. सूचकांक के मुताबिक़, प्रदूषण नियंत्रण और प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन की चुनौतियों से निबटने में आइसलैंड शीर्ष पर है. आइसलैंड की इस सफलता का आधार ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को नियंत्रित करना और जंगलों को दोबारा बसाने की कोशिश है. आइसलैंड के अलावा स्विट्जरलैंड, कोस्टारिका, स्वीडन और नॉर्वे जैसे देशों ने भी इस दिशा में प्रभावशाली प्रदर्शन किया है. यहां यह ध्यान रखना जरूरी है कि पर्यावरणीय प्रदर्शन सूचकांक में 163 देशों को दस अलग-अलग श्रेणियों में विभाजित कुल 25 मानकों के आधार पर जगह दी गई है. इसमें पर्यावरणीय स्वास्थ्य, हवा की गुणवत्ता, जल संसाधनों का प्रबंधन, जैव विविधता, वनीकरण, कृषि और जलवायु परिवर्तन जैसे मानक शामिल हैं.

2006-07 तक विकसित देशों द्वारा कार्बनडाई ऑक्साइड उत्सर्जन में 1.1 प्रतिशत की वृद्धि

1990 से 2007 के बीच 41 विकसित देशों द्वारा कार्बनडाई ऑक्साइड के कुल उत्सर्जन में 16 प्रतिशत की वृद्धि हुई. इसके लिए सबसे ज़्यादा दोषी ऑस्ट्रेलिया (42 प्रतिशत), कनाडा (29 प्रतिशत) और अमेरिका (20 प्रतिशत) जैसे देश हैं. ऊर्जा क्षेत्र में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के आंकड़ों पर नज़र डालें तो 1990 से 2007 के बीच उत्सर्जन में सबसे ज़्यादा वृद्धि ट्रांसपोर्ट यानी यातायात (17.9 प्रतिशत) के क्षेत्र में हुआ तो विनिर्माण एवं उत्पादन उद्योग में सबसे ज़्यादा कमी (17.3 प्रतिशत) आई. विकसित और विकासशील देशों के बीच उत्सर्जन के स्तर में इस भारी अंतर को देखते हुए कई विशेषज्ञों ने सलाह दी कि भारत जैसे विकासशील देशों को ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से संबंधित किसी भी ऐसे प्रस्ताव को मानने से इंकार कर देना चाहिए, जो 1997 के क्योटो प्रोटोकॉल की तर्ज पर कानूनी रूप से बाध्यकारी हो. विकासशील देश पहले ही ऐसे किसी बाध्यकारी क़ानून के प्रति अपना विरोध दर्ज़ कराते रहे हैं. उनका मानना है कि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की मात्रा के मद्देनज़र विकसित देशों को पहले और प्रभावशाली क़दम उठाने चाहिए.

वहीं क्योटो प्रोटोकॉल की समाप्ति से पहले 2008-12 के बीच विकसित राष्ट्रों को 1990 के मुक़ाबले अपने उत्सर्जन के स्तर में औसतन 5 प्रतिशत की कमी लानी है. उत्सर्जन के मामले में अग्रणी ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जैसे देश यूएनएफसीसीसी में शामिल होने के बावजूद क्योटो प्रोटोकॉल को मानने से इंकार कर रहे हैं. इतना ही नहीं, अब वे क्योटो प्रोटोकॉल को निरस्त करने के लिए समर्थन जुटाने की कोशिश भी कर रहे हैं और इसके लिए अलग-अलग देशों को तैयार करने की जद्दोज़हद जारी है. हालांकि भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील के नेतृत्व वाले जी-77 के सदस्यों सहित कुल 184 देशों में इसे अब तक अनुमोदित किया जा चुका है.

(लेखक सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश हैं)

feedback@chauthiduniya.com

प्रख्यात शिक्षाविद प्रो. अनिल सद्गोपाल का कहना है कि संसद में पेश बच्चों को अनिवार्य शिक्षा विधेयक-2009 दरअसल शिक्षा के अधिकार को छीनने वाला विधेयक है.

समान शिक्षा प्रणाली ही चाहिए

उमाशंकर मिश्र

केंद्र सरकार जनता को गुमराह करने के लिए धन की कमी का हवाला देकर कारपोरेट एवं ग़ैर सरकारी संगठनों की लॉबी से सांठगांठ करने में जुटी हुई है. इससे भविष्य में ग़रीब एवं अमीर के बीच की खाई गहराने के संकेत स्पष्ट नज़र आ रहे हैं. यदि इसी तरह चलता रहा तो आने वाले समय में यह सामाजिक विषमता विद्रोह का रूप धारण कर सकती है.

यह चिंता की बात है कि भारतीय गणतंत्र के 63वें साल में भी हमारे कर्णधारों ने देश के लिए समतामूलक शिक्षा का कोई ढांचा खड़ा नहीं किया है. अगर यही हालत रही तो आने वाले समय में इसके लिए एक लंबे संघर्ष की ज़रूरत पड़ सकती है. देश में पूर्व-प्राथमिक स्तर (नर्सरी, के.जी.) से लेकर उच्च तकनीकी शिक्षा तक सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली को स्थापित किए जाने की ज़रूरत है, पर इस दिशा में सरकार की ओर से कोई गंभीर पहल अब तक नहीं हुई है. फिलहाल ऐसा कुछ होता हुआ दिख भी नहीं रहा है.

लेकिन इसके ठीक विपरीत वर्तमान केंद्र सरकार शिक्षा के प्रति अपनी संवैधानिक जवाबदेही से पल्ला झाड़कर शिक्षा को वैश्विक बाज़ार में मुनाफ़ाखोरी के लिए बिकाऊ माल बनाने की नीति अपनाने में जुटी हुई है. यही नहीं, केंद्र सरकार जनता को गुमराह करने के लिए धन की कमी का हवाला देकर कारपोरेट एवं ग़ैर सरकारी संगठनों की लॉबी से सांठगांठ करने में जुटी हुई है. वास्तव में यह मसला धन की कमी का नहीं, बल्कि सरकार की जनविरोधी नीति का है, जिससे भविष्य में ग़रीब एवं अमीर के बीच की खाई गहराने के संकेत स्पष्ट नज़र आ रहे हैं.

शिक्षा को कारोबार से अधिक प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार के तौर पर देखा जाना चाहिए. मानव होने के कारण गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर ग़रीब छात्र का भी उतना ही अधिकार है, जितना कि किसी धनाढ्य परिवार के छात्र का है. शिक्षा व्यक्ति का मूल अधिकार ही नहीं, बल्कि उसका मानवाधिकार भी है. क्या सिर्फ़ धन के अभाव के चलते किसी ग़रीब विद्यार्थी को शिक्षा पाने के अधिकार से वंचित कर देना सही होगा? कतई नहीं. लेकिन, इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि आज़ादी से लेकर आज तक भारत की जनता इंतज़ार कर रही है कि पूर्ण रूप से सार्वजनिक धन पर टिकी हुई समान शिक्षा प्रणाली की स्थापना की जाए, ताकि प्राथमिक विद्यालय से लेकर महाविद्यालय स्तर तक समतामूलक गुणवत्ता की शिक्षा मुफ्त मिल सके.

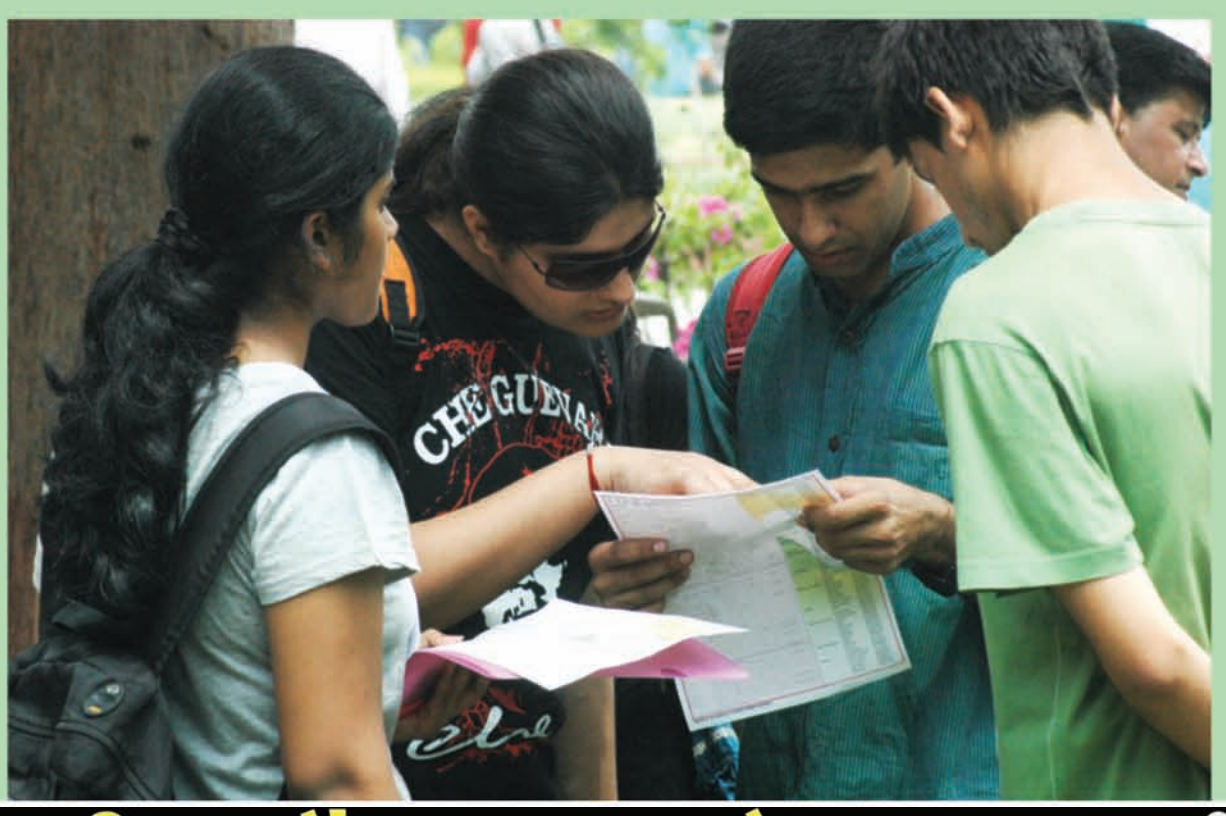

प्रख्यात शिक्षाविद प्रो. अनिल सद्गोपाल का कहना है कि संसद में पेश बच्चों को अनिवार्य शिक्षा विधेयक-2009 दरअसल शिक्षा के अधिकार को छीनने वाला विधेयक है. कुछ समय पूर्व यह बात उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल के जनसंचार विभाग द्वारा शिक्षा का अधिकार और भारत के भविष्य विषय पर आयोजित व्याख्यान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भी कही थी. प्रो. सद्गोपाल ने विधेयक की तमाम ख़ामियों की तरफ़ इशारा किया. उन्होंने कहा कि एक समान प्राथमिक शिक्षा की गारंटी से ही देश को बचाया जा सकता है. उन्होंने कहा कि इस ग़ैर संवैधानिक, बालविरोधी और निजीकरण-बाज़ारीकरण के समर्थक विधेयक से एक बार फिर प्राथमिक शिक्षा गर्त में चली जाएगी. उन्होंने आगे बताया कि यह सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करने और निजी स्कूलों को बढ़ावा देने की साजिश है. विवि के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विभाग के अध्यक्ष डा. श्रीकांत सिंह कहते हैं कि दोहरी शिक्षा प्रणाली के चलते देश में इंडिया और भारत के बीच का विभाजन बहुत साफ़ दिखने लगा है. इसके चलते समाज में अनेक समस्याएं पैदा हो रही हैं. शायद यही कारण है कि देश के अलग-अलग हिस्सों में समान शिक्षा प्रणाली को लेकर आवाज़ें उठने लगी हैं.

कई दूसरे शिक्षाविद् मानते हैं कि प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के स्तर में गिरावट है. वे शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 के निहितार्थों को लेकर भी चिंतित हैं. शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 के अंतर्गत सरकार की ओर से छह साल से 14 साल तक के बच्चों को नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की बात का हवाला दिया जा रहा है, जबकि तमाम बुद्धिजीवियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं शिक्षाविदों की राय सरकारी उद्घोषणा से बिल्कुल जुदा है. शिक्षा अधिकार मंच के संयुक्त सचिव शाहिद उल हुसैनी स्वयं शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 को तथाकथित अधिनियम बताते हैं. जानकारों का मानना है कि यह अधिनियम वास्तव में पहली कक्षा से आठवीं कक्षा तक पहले से ही दी जा रही नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को बाधित करने की साजिश है, जिससे इन सरकारी विद्यालयों की अवधारणा को समाप्त करके उच्च वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्यालयों जैसे-केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, 11वीं योजना के समय के 6000 मॉडल स्कूलों समेत राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के उच्च वर्गीय स्कूलों को प्रोत्साहित किया जा सके. और शिक्षा में निजीकरण का डंका ऐसे में जोर-शोर से बजने लगेगा, जिससे शिक्षा के व्यापारीकरण को फलने-फूलने का भरपूर अवसर भी मिलेगा.

असल में यह कारपोरेट जगत के हाथों एक बिकाऊ सरकार की शातिर चाल है, जिससे जनता को झुनझुना थमाकर उन्हें शिक्षा जैसे मौलिक अधिकार से दूर किए जाने की बिसात बिछाई जा रही है. इस क़ानून को 1990 के वर्ल्ड बैंक के डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम (डीपीईपी) और पिछले दशक से चल रहे सर्वशिक्षा अभियान जैसे बहुस्तरीय शिक्षा कार्यक्रमों को यथावत् बनाए रखने का प्रयास माना जा रहा है. वास्तव में देखा जाए तो इस अधिनियम को सरकार की उन्हीं नीतियों को लागू करने की कवायद के तौर पर देखा जा रहा है, जिसमें प्राइवेट-पब्लिक पार्टनरशिप, स्कूल वाउचर, कारपोरेट घरानों और धार्मिक एवं गैर सरकारी संगठनों द्वारा स्कूलों को गोद लेने जैसी बातें प्रमुख हैं. इस तरह के क़दमों से पिछले दरवाजे से कारपोरेट हाउसों को धन मुहैया कराने की सरकारी प्रतिबद्धता को समझने की ज़रूरत है.

इससे पहले यशपाल कमेटी की रिपोर्ट को भी विरोधाभासों भरी नज़रों से देखा जा रहा था, जिसमें उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के निजीकरण एवं व्यापारीकरण की तरफ झुकाव की बात सामने आई थी. लेकिन इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि सरकार एक ओर जहां विदेशी संस्थानों एवं कारपोरेट हाउसों के हाथों में शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय को सौंपने जा रही है, वहीं दूसरी ओर पहले से ही देश में मौजूद 18,000 कॉलेजों एवं क़रीब 400 विश्वविद्यालयों के स्तर में सुधार की कोई ठोस योजना सरकार की पोटली में नहीं है. ऐसे में सरकार की स्थिति एक व्यवसायी से अधिक कुछ नहीं जान पड़ती, जिसे सिर्फ़ अपना मुनाफा नज़र आता है. इसके अतिरिक्त उच्च शिक्षा की नियामक संस्थाओं जैसे-यूजीसी, एआईसीटीई, एनसीटीई, एमसीआई इत्यादि के स्थान पर एकमात्र नियामक संस्था राष्ट्रीय उच्च शिक्षा एवं शोध आयोग (एनसीएचईआर) के गठन की सिफारिश की गई है, जो सीधे तौर पर वित्त मंत्रालय के प्रति जवाबदेह होगी. यह क़दम एक तरह से मानव संसाधन विकास मंत्रालय को शक्तिहीन करने जैसा होगा. इसमें कोई दो राय नहीं कि इस तरह की कवायदें विदेशी संस्थानों एवं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश समेत शिक्षा के कारपोरेटीकरण का मार्ग तैयार करने की कड़ी का ही हिस्सा हैं.

हालांकि इन सबके बीच अगले साल 2011 से देश भर में विज्ञान और गणित में एक समान पाठ्यक्रम लागू करने पर सहमति बन गई है. यह एक अच्छी बात कही जा सकती है, क्योंकि ऐसा होने पर विभिन्न वर्ग एवं भौगोलिक समुदाय के विद्यार्थियों को समान प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा. इसी तरह, यह भी ध्यान रखना होगा कि समान शिक्षा प्रणाली भी समय की मांग है और सरकार को इस ओर पर्याप्त ध्यान देने की ज़रूरत है, न कि इससे मुंह मोड़ने की.

सभी प्रकार की सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पी.पी.पी.) पर पाबंदी लगाई जाए जिसमें आयकर माफ़ी, मुफ़्त या रियायती दरों पर दी गई ज़मीनें एवं अन्य सभी परोक्ष रियायतें, वाउचर स्कूल, सरकारी स्कूलों और उनके परिसरों की बिक्री, लीज़ या किराये पर चढ़ाना, सरकारी स्कूलों और स्कीमों की कारपोरेट घरानों व एन.जी.ओ. को आउटसोर्सिंग, फीस लेने वाले निजी स्कूलों तक मध्याह्न भोजन स्कीम का विस्तार करना आदि भी शामिल है.

सैम पित्रोदा के ज्ञान आयोग एवं उच्च शिक्षा पर यशपाल समिति की रिपोर्टों को ख़ारिज किया जाए, क्योंकि ये दोनों देश के मौजूदा कॉलेजों व विश्वविद्यालयों को बेहतर बनाने का एजेंडा पेश करने की जगह उच्च व तकनीकी शिक्षा को बिकाऊ माल बनाने, सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पी.पी.पी.) और विदेशी विश्वविद्यालयों को देश में स्थापित करने वाली नवउदारवादी नीति पर आधारित हैं.

विदेशी शिक्षा प्रदाता विधेयक और निजी विश्वविद्यालय विधेयक को संसद में पेश करने के सभी प्रस्तावों को तुरंत ख़ारिज किया जाए.

सन् 1986 से साल-दर-साल शिक्षा में किए जाने वाले पूंजी निवेश की कमी के चलते निवेश की जो चौड़ी खाई बन गई है, उसको पहले पर्याप्त धनराशि देकर पाटा जाए और उसके बाद शिक्षा व्यवस्था में निरंतर गुणवत्ता बढ़ाने के लिए यथोचित धनराशि मुहैया की जाए. लेकिन इस धनराशि को पी.पी.पी. के जरिए कारपोरेट घरानों व एनजीओ को पहुंचाकर सरकारी खजाना लुटवाने पर पाबंदी रहे.

विश्व व्यापार संगठन एवं गैट्स (जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड सर्विसेज़) के पटल पर उच्च एवं प्रोफेशनल शिक्षा की पेशकश को तुरंत वापस लिया जाए अन्यथा वह अपरिवर्तनीय प्रतिबद्धता बन जाएगी और फिर विदेशी संस्थानों को भारतीय संस्थानों के समकक्ष सभी सुविधाएं देना हमारी जबरन बाध्यता हो जाएगी.

(लेखक इंडिया फाउंडेशन फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड स्टडीज से संबंद्ध हैं)

feedback@chauthiduniya.com

मेरी दुनिया.... पहली अप्रैल का तोहफा ...धीर

कोई भी सच्चा और ईमानदार आदमी इसकी समीक्षा करेगा तो हताशा घेरेगी ही. और कानू सान्याल भी इससे बच नहीं पाए.

नक्सल क्रांति का एक जनक हताशा से हार गया

बिमल राय

हताशा ने न जाने कितनी जानें ली हैं, पर अभी हाल में इसने एक ऐसे नेता को अपना शिकार बनाया है, जिसने आज से 43 साल पहले हथियारों के बल पर उस व्यवस्था को बदलने का सपना देखा था, जो किसानों व मज़दूरों का शोषण करती है, उनका हक़ मारती है. इस हताशा के ताजा शिकार हैं, कानू सान्याल. हालांकि भूखों के लिए लड़ने वाले नक्सलियों के ख़ूनी खेल में अब तक क़रीब 65000 लोगों की जानें जा चुकी है. इनमें से बहुत ऐसे थे, जो सशस्त्र क्रांति का न तो मतलब समझते थे और न समझना चाहते थे. सत्ता और सशस्त्र संघर्ष के बीच की क्रॉस फायरिंग में हज़ारों मांगें सूनी हो गईं, हज़ारों बच्चों को स्लेट-पेंसिल के बदले बंदूक़ें थमा दी गईं, उनका बचपन छीन लिया गया. और इस तरह 43 साल बीत गए. पर हासिल क्या हुआ?

कोई भी सच्चा और ईमानदार आदमी इसकी समीक्षा करेगा तो हताशा घेरेगी ही. और कानू सान्याल भी इससे बच नहीं पाए. 1932 में दार्जिलिंग के कर्सियांग में जन्मे इस 78 वर्षीय नक्सली नेता ने गत 23 मार्च को जलपाईगुड़ी ज़िले के सेफतुल्लाजोट गांव में जब ख़ुदकुशी की, तो सहसा किसी को विश्वास नहीं हुआ. संदेह हुआ कि कहीं यह हत्या तो नहीं? शक़ की वजह भी थी. पिछले कुछ सालों से कानू दिल की बीमारी से जूझ रहे थे. एक साल पहले उन्हें सेरिब्रल अटैक भी हुआ. आर्थिक तंगी के बावजूद उन्होंने सरकारी मदद लेने से इनकार कर दिया. सीपीआई-एमएल के दार्जिलिंग ज़िला सचिव जोगेन विश्वकर्मा ने चौथी दुनिया को बताया कि दोपहर का खाना खाकर कॉमरेड सो गए, जबकि उनकी देखरेख करने वाली शांति मुंडा के मुताबिक़ खाना खाकर वह आराम से कुर्सी पर बैठकर अख़बार पढ़ने लगे और दरवाज़ा खुला रखने के लिए कहा. दो घंटे बाद जब शांति लौटी तो उसने दरवाज़े को खुला ही पाया और कानू का शव सीलिंग की हुक में लगी प्लास्टिक की रस्सी से लटका हुआ था. संदेह इसलिए भी बढ़ा कि पैर ज़मीन से सटे हुए थे. दो दिन बाद सिलीगुड़ी में पार्टी के राज्य सचिव सुव्रत बसु ने यह कहकर संदेह बढ़ा दिया कि पार्टी इसे आत्महत्या नहीं मानती और अपने स्तर पर इसकी जांच की जाएगी. पर एक ही साथ आत्महत्या की बात ज़्यादा साफ़ और सच लग रही है. मौत के तुरंत बाद कानू के छोटे भाई प्रवीर सान्याल ने स्वीकार किया कि वह पिछले कुछ समय से अवसाद से घिर गए थे. रही सही कसर पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पूरी कर दी. 30 मार्च को आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण आत्महत्या ही करार किया गया है. चौथी दुनिया से बात करते हुए उत्तर बंगाल के आईजी के.एल. टामटा ने भी इसकी पुष्टि की. फिर अपने घर में बंद रहने वाले कानू एक तरह से पार्टी में निष्क्रिय थे. स्थानीय स्तर पर उनका कोई दुश्मन होगा, इसकी भी कल्पना नहीं की जा सकती है. पूरे नक्सलबाड़ी इलाक़े में हर दल के लोग उनका सम्मान करते थे. नक्सल प्रभावित इलाक़ों में जब ऑपरेशन ग्रीन हंट चल रहा है और दर्ज़नों लोगों की जानें जा रही हैं, हो सकता है, यह देख-सुनकर उनका अवसाद और बढ़ गया हो. अवसाद इस वजह से भी बढ़ा हो सकता है कि पार्टी में अब उनकी बात नहीं सुनी जा रही थी और वे अब अतिवादी रवैया अपनाने के पक्ष में नहीं थे.

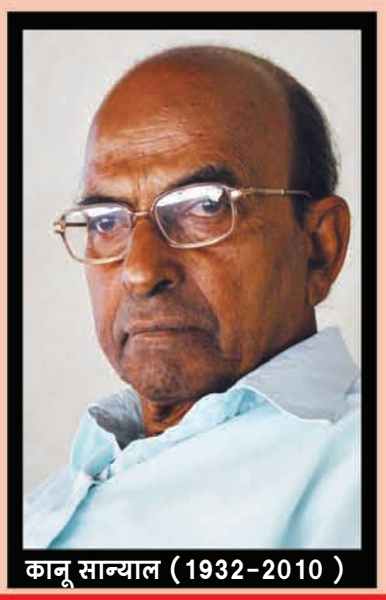
कानू सान्याल (1932-2010)

ग़ौर करने वाली एक बात और है कि जिन किसानों के लिए कानू ने नक्सल आंदोलन शुरू किया था, सत्ता में आने के बाद से ऑपरेशन बर्गा और पंचायती सुधारों के ज़रिए वाममोर्चा सरकार ने काफी हद तक शिक़ायतें दूर कर दीं. अगर सिंगुर, नंदीग्राम और लालगढ़ मामले में बुद्धदेव सरकार ने दूरदर्शिता दिखाई होती तो मामला इतना आगे नहीं बढ़ता. ज़ाहिर है न छत्रधर महतो पैदा होते और न किशन जी को बंगाल-झारखंड से यहां आकर मोर्चा संभालना पड़ता. ज़ाहिर है सरकार ने भी अपनी ताक़त का नग्न प्रदर्शन किया और हालात आपके सामने हैं.

वैसे कानू सान्याल माकपा और भाकपा दोनों के विरोधी रहे, पर उनकी मौत के बाद इन दलों ने माना है कि देश में कम्युनिस्ट आंदोलन को आगे बढ़ाने में उनका अहम योगदान रहा है. सीपीआई के उप महासचिव एस. सुधाकर रेड्डी ने कहा है, हालांकि पार्टी सशस्त्र संघर्ष की उनकी विचारधारा से सहमत नहीं थी, पर उन्होंने कम्युनिस्ट आंदोलन को काफी मज़बूती दी. माकपा के पोलितब्यूरो सदस्य सीताराम येचुरी ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा है, नंदीग्राम और लालगढ़ के बाद सान्याल यह मान रहे थे कि माओवादियों ने जो तरीक़ा अपनाया है, वह नक्सल आंदोलन शुरू करने के समय के अनुमोदित तरीक़े से अलग हो गया था. कानू के क़रीबी मित्र और दक्षिण बंगाल में पार्टी का मोर्चा संभालने वाले अजीजुल हक ने कहा, उन्हें ऐसा नहीं लगता कि कानू ने ख़ुदकुशी की. हम सबने उनकी हत्या की है, उनकी हत्या वर्तमान समाज ने की है. मरने के बाद भी कानू ने समाज को एक संदेश दिया है.

यह संदेश क्या हो सकता है? यह भी तो हो सकता है कि हिंसा किसी मसले का हल नहीं है. कुछ माह पहले चौथी दुनिया को दिए गए एक साक्षात्कार (जो किसी अख़बार को दिया गया उनका अंतिम साक्षात्कार था) में भी कानू ने इस बात को स्वीकार किया था. आज किसानों व मज़दूरों के सामने वैसी समस्याएं नहीं हैं, जो 40 साल पहले थीं. ज़ाहिर है हिंसा और ख़ून-ख़राबे से कुछ हासिल करने की कोशिश हताशा ही पैदा करेगी.

कभी हर समय घनघनाते रहने वाले कानू सान्याल का फोन (0353-2004020) भी पावर ऑफ हो गया है. हो भी क्यों नहीं, कभी लाखों दिलों में ऊर्जा का संचार करने वाला वह शख्स अब रिसीवर उठाने के लिए मौजूद जो नहीं है.

feedback@chauthiduniya.com

सशस्त्र क्रांति, जो विफल हो गई

25 मई, 1967 को नक्सलबाड़ी में भूमि विवाद के बाद एक जमींदार के भाड़े के लोगों ने एक किसान पर हमला किया. किसानों ने एकजुट होकर जमींदारों से लोहा लेने की ठानी. बंगाल पुलिस के जवानों ने 11 किसानों की हत्या कर दी. यहीं से पूरे बंगाल में चारु मजूमदार, जंगल संथाल और कानू सान्याल की अगुवाई में नक्सलवाद की चिंगारी भड़की, जो आज देश की सबसे ख़तरनाक समस्या बन गई है. माओ जे दांग से प्रभावित चारू मजूमदार ने किसानों का आह्वान किया कि वे सरकार और ऊंची जातियों के दबदबे वाली राजनीतिक व्यवस्था को पलट दें. कानू सिलीगुड़ी कोर्ट में रेवेन्यू क्लर्क का काम करते थे, पर केंद्र की ओर से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी पर पाबंदी लगाए जाने के विरोध में तत्कालीन कांग्रेसी मुख्यमंत्री विधानचंद्र राय को काले झंडे दिखाने के आरोप में उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया. जलपाईगुड़ी जेल में रहने के दौरान ही वे सीपीआई के ज़िला सचिवालय सदस्य चारु मजूमदार से प्रभावित हुए. रिहाई के बाद भारत-चीन युद्ध को लेकर हुए पार्टी के विभाजन के बाद वे सीपीआई -एम में शामिल हो गए. 1960 व 70 के दशक में बंगाल में उफने नक्सली आंदोलन को मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर राय ने कुछ ही महीनों में कुचल दिया. 1969 में कानू व चारु ने सीपीआई -एमएल का गठन किया और सशस्त्र क्रांति के ज़रिए बदलाव की मुहिम जारी रखी. सान्याल ने सशस्त्र संघर्ष के लिए खुलेआम चीन से मदद मांगी और वे बीजिंग भी गए, हालांकि यह साफ़ नहीं हो पाया कि चीन ने उनकी किसी तरह से मदद की या नहीं.

कानू सान्याल अगस्त 1970 में भूमिगत रहने के दौरान ही गिरफ़्तार कर लिए गए. पार्वतीपुरम मामले (आंध्रप्रदेश और उड़ीसा के जमींदारों के ख़िलाफ़ संगठित तरीक़े से बग़ावत को उकसाने के आरोप में), जिसे इतिहास का सबसे बड़ा षडयंत्र कहा जाता है, में कानू को विशाखापत्तनम की जेल में सात साल तक रखा गया. सन् 1977 में पश्चिम बंगाल में जब माकपा की अगुवाई में सरकार बनी तो ज्योति बसु के हस्तक्षेप से उनकी रिहाई मुमकिन हो सकी. रिहाई के बाद कानू ने सशस्त्र संघर्ष का कारवां आगे बढ़ाते हुए कम्युनिस्ट क्रांतिकारियों की आर्गेनाइज़िंग कमेटी(ओसीसीआर) बनाई, जिसका कम्युनिस्टों की मार्क्सवादी लेनिनवादी शाखा में विलय कर दिया गया.

सन 1972 में चारु मजूमदार को गिरफ़्तार कर लिया गया और एक पखवाड़े के बाद ही कोलकाता में पुलिस हिरासत में उनकी मौत हो गई. यह मौत भी अबतक रहस्य बनी हुई है. बताया जाता है कि पुलिस उत्पीड़न की वजह से उनकी मौत हो गई. तीसरे बड़े नेता जंगल संथाल एक दशक तक जेल में रहने बाद जब बाहर आए, हताशा का शिकार होकर शराब के नशे में चूर रहने लगे और किडनी का फेल होना उनकी मौत का कारण बना. 18 जनवरी 2006 को कानू सान्याल की अगुवाई में उनके कॉमरेडों क्षेत्र में बंद चाय बागानों के ख़िलाफ़ आंदोलन के तहत दिल्ली जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस को रोका तो उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया. 2003 से कानू सीपीआई-एमएल के महासचिव के रूप में काम कर रहे थे. अभी हाल में सिंगुर और नंदीग्राम में राज्य सरकार की भूमि अधिग्रहण नीति की उन्होंने कड़ी आलोचना की थी. हालांकि पिछले कुछ वर्षों से वे सीपीआई-एमएल की ग़लतियों को महसूस करने लगे थे और ऐलान किया कि आतंक से कोई बदलाव नहीं होता और इससे जनता से दूरी बढ़ती है. यही विचार अंततः अवसाद में बदल गया.

The Ormita Commerce Network has entered the Indian marketplace

Ormita provides a mechanism for business owners to turn their excess capacity into needed goods and services. It supplements existing cash income and provides a way to offset costs against new sales. If your business is not at 100% capacity all of the time then you have an opportunity to increase your revenue and reduce your current cash costs.

How It Works

Ormita acts as a clearinghouse for the trade of excess capacities, goods and services - much like an alternative commodity exchange.

Participants buy and sell their excess capacity and/or stock in return for already budgeted expenses, new investments, cash-flow enhancing products, professional services and donations.

Rather than promoting direct trade between participants the Company brokers transact through its centralized marketplace.

1. Transactions are detailed in a centralized "ledger" which records the value of the items purchased (debit) and sold (credit) - much like a clearinghouse does for stocks, or a commercial bank does for cheques.
2. This ledger system utilises a "credit" as a method of accounting with 1 Ormita Credit = 1 Cash Rupee.
3. Just like any brokerage firm, Ormita receives a cash commission on each transaction.
4. Buyers pay no transaction fees to Ormita but they may pay a small percentage of the entire purchase price in cash to the seller. This cash covers the sellers' fees, sales tax and their additional costs to create this new sale.

A Unique Offering

- 24 hour, 7 day a week live brokerage services.
- Buy, sell and transfer funds online.
- No monthly fees and no annual fees.
- Lowest overall price in the industry.
- No cash outlay until we have met both your buying and selling needs.

[1] Subject to customer meeting minimum trading volumes per month.

For more information about Ormita and franchises.

Website:
www.ormita.co.in
Offices:
(011) 433 55 555
Email:
info@ormita.co.in
Blog:
blog.ormita.co.in
Facebook:
www.facebook.com/pages/Ormita-India/370208677506
Twitter:
twitter.com/ormitaindia

Ormita®
Commerce Network

जैव प्रौद्योगिकी के विशेषज्ञों से जीन पारिस्थितिकी एवं अन्य संबद्ध विषयों की विस्तृत समझ की अपेक्षा नहीं की जा सकती.

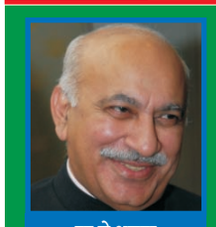

एम जे अकबर

हेडली से 26 नवंबर की पूरी सूची मांगें

डेविड कोलमैन हेडली उर्फ दाऊद गिलानी उर्फ जाने क्या-क्या. अलग-अलग पहचान और विश्वासों के साथ केवल एक चीज के प्रति ही हेडली प्रतिबद्ध रहा है, धोखा और अविश्वास के आधुनिकतम सिद्धांतों के प्रति. यह सही है कि आप उसे विश्व के सर्वश्रेष्ठ अपराधियों की श्रेणी में नहीं रख सकते. दाऊद इब्राहिम तो डेविड का केवल अरबी रूपांतरण ही है, लेकिन फिर भी वह बचा रहा, क्योंकि धंधे के सारे नियम-कायदे वह जानता था और हर हाल में उन पर टिका रहा.

धंधे के तमाम नियम-क़ायदे एजेंसी-नियंत्रक और प्यादा एवं कठपुतली के बीच रिश्ते की ओर इशारा करते हैं. एजेंट चाहे डबल हों या ट्रिपल या और भी ज़्यादा, ख़ुफ़िया अधिकारी जानकारी की सत्यता पर तभी भरोसा करते हैं, जब दुश्मन के साथ उसकी निकटता के पूरे सबूत हों. यह स्थिति शीत युद्ध वाले हालात से भी ज़्यादा जटिल है. उस समय का सिद्धांत था-चारा डालो, पटाओ, काम निकालो और फिर फेंक दो. इस नीति ने ख़ुफ़िया अधिकारियों को हलकान कर छोड़ा था. और, कई बार तो तत्कालीन महाशक्तियों का पूरा ख़ुफ़िया तंत्र इसमें उलझ कर रह जाता था.

राष्ट्रीयता की सीमा से बाहर निकल चुकी लड़ाई में डबल एजेंट की भूमिका अब बेमानी हो चुकी है. राष्ट्रीयता संकट के क्षणों में छोटी ही सही, लेकिन सुरक्षा के लिए उम्मीद की किरण जगाती है. यह और बात है कि राष्ट्रीयता के बंधनों से मुक्त दुश्मन ज़्यादा ख़तरनाक होता है, क्योंकि उसकी सेवाएं हर किसी के लिए उपलब्ध होती हैं. वह अपने आप में एक विरोधाभास होता है. द्वंद्व से भरा, अपने धंधे में नैतिकता की दुहाई देते हुए वह एक प्रशिक्षित सेल्समैन की तरह अपनी सेवाएं हर किसी को बेचने के लिए तैयार रहता है.

बड़े ओहदों पर काम करने वाले लोग जो उससे संपर्क साधते हैं, उन्हें भी यह पता होता है, लेकिन फिर भी वे इस रिश्ते को आगे बढ़ाते हैं. इस विश्वास के साथ कि जानकारी चाहे कितनी भी कम क्यों न हो, उसकी क़ीमत झूठ के पुलिंदों से कहीं ज़्यादा होती है. इन एजेंटों के तार कई लोगों से जुड़े होते हैं, क्योंकि सबसे मिलकर रहना और सबके पाप में भागीदार होना इनकी सुरक्षा की एकमात्र गारंटी होती है. यदि पकड़े जाने से पहले मौत नहीं हुई तो उनकी ज़ुबान कई लोगों के लिए ख़तरनाक हो सकती है, खासकर ऐसे लोगों के लिए, जो अपनी निजी ज़िंदगी के काले कारनामों को सार्वजनिक नहीं करना चाहते.

हेडली को शुक्रगुज़ार होना चाहिए, इस बात के लिए कि वह अभी भी ज़िंदा है और ऐसे लोगों की कैद में है जिन्हें उसकी पिछली ज़िंदगी से जुड़ी जानकारियों में खासी रुचि है. उसने अमेरिका को आतंकियों के हाथों बेचा और आतंकियों को अमेरिका के हाथों. और, दोनों इसी गफलत में रहे कि यह उनके लिए फ़ायदे का सौदा है. सच्ची सूचनाएं अभी भी गोपनीयता के अंधेरे में छुपी हैं और यह अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि हेडली किन लोगों के संपर्क में रहा था. हालांकि आप अक्ल दौड़ाएं तो इसका जवाब ढूंढ सकते हैं. यदि शीर्ष अमेरिकी अधिकारियों से उसके अच्छे संबंध नहीं होते तो भारत से दूर रहने की उसकी इच्छा फलित होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता.

हमारा सवाल यही है कि अमेरिका हेडली को अपने देश में रखने के लिए इतना जोर क्यों दे रहा है. हेडली पर डेनमार्क के एक कार्टूनिस्ट की हत्या की साजिश रचने का आरोप है और 26 नवंबर के मुंबई कांड में अपनी संलिप्तता की बात उसने ख़ुद स्वीकारी है. स्वाभाविक रूप से वह भारत और डेनमार्क का दुश्मन है. भारत का दावा इसलिए ज़्यादा मज़बूत है, क्योंकि कार्टूनिस्ट की हत्या नहीं हुई, लेकिन मुंबई कांड को अंजाम दिया गया.

अमेरिका की सरजमीं पर उसने कोई अपराध नहीं किया है, लेकिन अमेरिका उसे देश में रोके रखने पर आमादा है. पाकिस्तान पहले ही हेडली को अपने देश में रखने से इंकार कर चुका है. कोई भी ख़ुफ़िया एजेंसी अपनी गिरफ़्त में आए लोगों को किसी दूसरे के हवाले करने के लिए आसानी से तैयार नहीं होती. वार अगेंस्ट टेरर के इस दौर में भी अमेरिका और ब्रिटेन के बीच ख़ुफ़िया सूचनाओं के आदान-प्रदान में शत-प्रतिशत पारदर्शिता की उम्मीद नहीं की जा सकती. अमेरिका और भारत के बीच संबंध अब इतने परिपक्व हो चुके हैं कि भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय में सीआईए के एजेंट की मौजूदगी के खुलासे से भी कुछ खास असर नहीं पड़ा. अब उन्हें

हेडली के मामले में भी गंभीरता के साथ विचार करना चाहिए.

आम लोगों के गुस्से को शांत करने के लिए ही सही, लेकिन भारत को तय समय सीमा के अंदर अमेरिकी निगरानी में हेडली से पूछताछ करने का मौक़ा मिलेगा. लेकिन, हमारे अधिकारी उससे पूछेंगे क्या? इसके लिए सख्त मिजाज़ और अनुभवी अधिकारियों को भेजा जाना चाहिए. पहले से पता चीजों को फिर से पूछने का कोई मतलब नहीं है. हेडली जानकारियों का अथाह भंडार हो सकता है. लश्करे तैयबा, उसके कामकाज के तरीक़ों, रणनीति और पाकिस्तान के साथ संबंधों के बारे में वह कई सूचनाएं दे सकता है. लेकिन, सबसे बड़ा सवाल यह है कि योजना बनाते समय मुंबई हमलों की जानकारी किन लोगों के पास थी और उन्हें यह सूचना कब मिली? हेडली संदेशवाहक था, तो उसने यह संदेश किन लोगों तक पहुंचाया था? जेम्स बांड की मृत्यु हो चुकी है. बांड के दौर का एक ही उसूल था, तीर निशाने पर लगा तो अच्छा, वरना मौत निश्चित थी और कहानी का वहीं पटाक्षेप हो जाता था. 1960-70 के दशक में जॉन ला कैरी के दौर के आते-आते इसमें बदलाव आ चुका था. बांड को यह पता था कि उसके दुश्मन कौन हैं, लेकिन कैरी की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी. उसे अपने दुश्मनों के बारे में भी पता नहीं होता था. भारत के दुश्मनों की भी कोई कमी नहीं है. और, ख़ामोशी उनमें से एक है.

feedback@chauthiduniya.com

वंदना शिवा

बीटी बैगन पर रोक के वैज्ञानिक और लोकतांत्रिक पहलू

बीटी बैगन के इस्तेमाल पर पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने फ़िलहाल रोक की घोषणा की तो मीडिया में उसके ख़िलाफ़ आलोचनाओं का अंबार लग गया. कई लोगों ने तर्क दिए कि ऐसे फ़ैसले वैज्ञानिकों के लिए छोड़ दिए जाने चाहिए. लेकिन यह मामला विज्ञान और विज्ञान विरोध का नहीं है. दरअसल यह विज्ञान की ही दो अलग-अलग धाराओं से जुड़ा है. सच्चाई तो यह है कि बीटी बैगन पर लगाई गई रोक से संबंधित फ़ैसले में सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक सोच का सहारा लिया गया है.

कई वैज्ञानिकों ने मांग की कि इस मुद्दे पर निष्पक्ष और भलीभांति विचार करने के बाद ही कोई फ़ैसला लिया जाना चाहिए. भारत में जेनेटिक इंजीनियरिंग को स्थापित करने में अग्रणी भूमिका निभाने वाली वैज्ञानिक डॉ. पुष्पा भार्गव ने भी बीटी बैगन के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ बुलंद की. बीटी बैगन के पक्ष में बोलने वाले अधिकांश तथाकथित वैज्ञानिक वास्तव में तकनीकी विशेषज्ञ हैं, जो विज्ञान की एक पूर्ववर्ती शाखा की मदद से मोंसेंटो जैसी कंपनियों के लिए जीएम फ़सलों का विकास करने की कोशिश में लगे हैं. जैविक सुरक्षा जैसे गंभीर मसलों को ऐसे लोगों के भरोसे छोड़ देना अनैतिक तो है ही, समाज के लिए ख़तरनाक भी है. यह अनैतिक इसलिए है, क्योंकि किसी नई तकनीक के विकास के काम में लगे लोग यह फ़ैसला नहीं कर सकते कि वह तकनीक समाज के लिए अच्छी है या नहीं. यह हितों के टकराव से जुड़ा मामला है. फिर यह ख़तरनाक भी है, क्योंकि जैविक सुरक्षा का आकलन करने के लिए ज़रूरी वैज्ञानिक योग्यता की उनमें कमी है.

वे दरअसल रेफ्रिजरेटर निर्माताओं की तरह हैं, जिन्हें यह नहीं पता कि इसमें इस्तेमाल हुआ क्लोरो फ्लोरो कार्बन ओजोन परत को कमज़ोर करने में बड़ी भूमिका निभाता है. वे उन कार निर्माताओं की तरह हैं, जो बड़ी शान से अपने नए मॉडल्स लांच करते हैं, लेकिन यह नहीं जानते कि उनकी कार से निकलने वाला ख़तरनाक धुआं वातावरण को प्रदूषित करता है और पर्यावरण में अस्थिरता पैदा करता है. जेनेटिक इंजीनियरिंग जीव विज्ञान की एक शाखा रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी पर आधारित है, जो यह मानती है कि हर सजीव चीज एक मशीन की तरह है. साथ ही यह भी कि मशीन की तरह इसके हर कलपुर्जों को बदला जा सकता है और इससे उसके अस्तित्व पर कोई असर नहीं पड़ता. प्राकृतिक और सामाजिक विविधताओं पर आर्थिक एवं राजनीतिक नियंत्रण बनाए रखने के लिए विज्ञान की इस शाखा का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जीन को आधारभूत मानना विज्ञान से ज़्यादा विचारधारा की बात है. जीन का ख़ुद में कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, बल्कि वह एक पूर्ण संरचना का अभिन्न अंग मात्र है और इस संरचना से ही उसका अस्तित्व होता है. कोशिका के सभी अंग एक-दूसरे के संपर्क में होते हैं और किसी भी जैविक संरचना में जीनों का समूह एक जीन विशेष के मुक़ाबले ज़्यादा नहीं तो कम से कम उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है.

इसे ज़्यादा विस्तृत तरीक़े से इस तरह समझा जा सकता है कि किसी जीव को प्रोटीनों के एक समूह के रूप में नहीं देखा जा सकता. हर जीन का एक से ज़्यादा प्रभाव होता है और जीवों में पाए जाने वाले हर गुण के लिए एक से ज़्यादा जीन ज़िम्मेदार होते हैं. जेनेटिक इंजीनियरिंग में अलग-अलग प्रजातियों के जीनों को एक साथ इस्तेमाल किया जाता है. विभिन्न

स्रोतों से जमा किए गए उक्त जीन कई बार ऐसे जीवाणुओं से भी लिए जाते हैं, जिनमें कई ख़तरनाक मानवीय एवं पादपीय रोगों को पैदा करने वाले विषाणु पाए जाते हैं. पिछले कुछ सालों में जो जानकारियां हमारे सामने आई हैं, वे यही बताती हैं कि ऐसे जीन आनुवांशिकीय प्रदूषण फैलाते हैं और पर्यावरण एवं मानव स्वास्थ्य के लिए बेहद ख़तरनाक हो सकते हैं.

जोखिम का आकलन

जैव प्रौद्योगिकी के विशेषज्ञों से जीन पारिस्थितिकी एवं अन्य संबद्ध विषयों की विस्तृत समझ की अपेक्षा नहीं की जा सकती. यही वजह है कि जीएम फूड्स के इस्तेमाल से पर्यावरण एवं सामाजिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले असर और जोख़िमों का वास्तविक आकलन वे नहीं कर सकते. अधिकतर वैज्ञानिक भी यह मानते हैं कि जेनेटिक रिडक्शनिज़्म की अवधारणा में कई दोष हैं. इस क्षेत्र में ताज़ा शोधों ने एपिजेनेटिक्स की एक नई अवधारणा को जन्म दिया है, जो न केवल जीनों की सही व्याख्या करती है, बल्कि प्रत्येक जीन के लिए तीस हज़ार से भी ज़्यादा प्रोटीन रूपांतरणों को तैयार कर सकती है. एपिजेनेटिक यह भी बताती है कि जीनों की गतिविधियां और कोशिकीय व्यवहार पर्यावरणीय कारकों से नियंत्रित होते हैं, न कि डीएनए की आंतरिक संरचना से.

लेकिन समस्या यहीं तक सीमित नहीं है. बीटी बैगन को कीट प्रबंधन की समस्या के एक समाधान के रूप में भी पेश किया जा रहा है. टॉक्सीन पैदा करने वाले जीन को एंटीबायोटिक के साथ पौधों में डाला जा रहा है. यह वैसी ही हालत है, जैसे अपने घर की दीवार में एक छोटा सा छेद करने के लिए आप अर्थ मूवर जैसी भारी-भरकम मशीन का इस्तेमाल कर रहे हों. जिस तरह अर्थ मूवर पूरी दीवार को ही ख़त्म कर देता है, वैसे ही जीनों के ऐसे इस्तेमाल से उनके व्यवहार और गतिविधियों में आने वाला बदलाव पूरी जैविक प्रक्रिया के लिए ही ख़तरनाक हो सकता है. अर्थ मूवर की तरह ही जेनेटिक इंजीनियरिंग भी आधुनिकतम तकनीक है, लेकिन कृषि कार्यों में कीट नियंत्रण के सहारे पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन बनाए रखने जैसे संवेदनशील काम में इसका उपयोग ख़तरनाक हो सकता है. कीटों पर नियंत्रण के लिए जैव विविधता का इस्तेमाल होता है. ऐसी जैविक प्रक्रियाओं का सहारा लिया जाता है, जिससे बीमारियों और कीटों के ख़िलाफ़ प्रतिरोधी क्षमता विकसित हो सके. आंध्र प्रदेश में कीटनाशकों के प्रबंधन के लिए चलाई गई एक सरकारी परियोजना में 14 लाख एकड़ से ज़्यादा क्षेत्र को सम्मिलित किया गया है और इसके कई फ़ायदे भी देखने को मिले हैं.

एग्रो इकोलॉजी, टॉक्सिक जीनों को हमारे खाद्य पदार्थों में जबरदस्ती ठूंसे जाने की इस क्रूर तकनीक का एक वैज्ञानिक विकल्प हो सकती है. एग्रीकल्चरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट पर किए गए अंतरराष्ट्रीय सर्वेक्षण के जो नतीजे सामने आए हैं, वे यही बताते हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के मुक़ाबले एग्रो इकोलॉजी पर आधारित कृषि तंत्र ज़्यादा सफल होते हैं. सच तो यह है कि एपिजेनेटिक्स और एग्रो इकोलॉजी भविष्य के विज्ञान हैं, जबकि रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी गुज़रे जमाने के विज्ञान का पिछड़ा हुआ स्वरूप है. खाद्यान्न एवं कृषि से संबंधित हमारे फ़ैसले विज्ञान की नवीनतम और कारगर अवधारणाओं पर आधारित होने चाहिए. किसी क्रूर तकनीक को विज्ञान का दर्ज़ा देकर हम ऐसे फ़ैसले नहीं ले सकते.

हमारा शरीर हमारे भोजन से ही बनता है और हमारे पास यह निर्णय लेने की स्वतंत्रता होनी चाहिए कि हम क्या खाएं. विज्ञान और निर्णय प्रक्रिया का लोकतंत्रीकरण समय की ज़रूरत बन चुका है. अपना भला-बुरा सोचने की क्षमता हर इंसान में होती है और लोकतंत्र में हर नागरिक की इच्छा का सम्मान होना चाहिए. बीटी बैगन पर हुई सार्वजनिक बहस एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया का ही हिस्सा है. जो लोग यह मानते हैं कि हमारे भोजन से संबंधित फ़ैसले बायोटेक कंपनियों और तकनीकी विशेषज्ञों के जिम्मे छोड़ देने चाहिए, वे विज्ञान के साथ-साथ लोकतंत्र के भी ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं.

(लेखिका विख्यात पर्यावरणविद हैं)

feedback@chauthiduniya.com

एक अच्छा अख़बार

मेरे मित्र को नए-नए अख़बार पढ़ने का शौक है. एक दिन उसने कहा, मैं आपके लिए नया अख़बार लाया हूं. यह चौथी दुनिया हिंदी का साप्ताहिक अख़बार है. पढ़कर देखा तो लगा कि यह तो सचमुच चमत्कार है. वैसे तो हर अख़बार नेता, अभिनेता और क्रिकेट का गुणगान करता है, लेकिन चौथी दुनिया देखकर लगा कि यह कुछ अलग है. अगर छपाई, काग़ज़ की गुणवत्ता और कम क़ीमत स्थाई रही तो चौथी दुनिया सदा पाठकों के हाथों में दिखता रहेगा. पाठक चाहता है कि वह जो भी अपनी ज़ुबान से कहे, अखबार उसे छापे. इसका मतलब यह है कि अखबार को पाठकों की भाषा में छापा जाना चाहिए. उम्मीद है, चौथी दुनिया इसके लिए कुछ नया करेगा. अगर ऐसा हुआ तो भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष में अखबार जनता के साथ होगा. राजनीति का रूप बदलेगा तो देश का विकास होगा. धरती पर चैन से लोग जी सकेंगे. यही अच्छे अखबार की पहचान है.

नवीन कुमार शर्मा, हुगली, पश्चिम बंगाल.

मृत्युदंड का अंत होना चाहिए

भारत में अपराधियों को दी जाने वाली मृत्युदंड की व्यवस्था को बदलना चाहिए. चौथी दुनिया के एक मार्च के अंक में रवि किशोर जी का लेख पढ़ने के बाद लगा कि हमारे देश की विधायिका एवं न्यायपालिका दोनों असमंजस में है. कभी इसे समाप्त करने की चर्चा होती है तो फिर इसे बरक़रार रखने की बात सामने आती है. अभी तक अंग्रेज़ों के बनाए क़ानून का प्रचलन हमारे देश में है. देश की कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका को सामंजस्य बनाकर दूसरे विकल्पों पर विचार करना चाहिए. मृत्यु दंड को समाप्त कर देना चाहिए.

शंकर शर्मा, बेगूसराय, बिहार.

तोप मुकाबिल का कायल

मैं एक लेखक हूं. कई स्थानीय समाचारपत्र-पत्रिकाओं में लिखता हूं. चौथी दुनिया के कई अंक पढ़ने के बाद ख़ुशी का इज़हार करते हुए यही कहना चाहूंगा कि संतोष भारतीय जी चौथी दुनिया के माध्यम से वाकई निष्पक्ष पत्रकारिता कर रहे हैं. जब तोप मुक़ाबिल हो कॉलम में वह पूरी तरह से सच और सटीक बात लिखते हैं. इस बात पर गर्व महसूस करता हूं कि मैं लगातार चौथी दुनिया को पढ़ रहा हूं. उम्मीद है कि आगे भी इसे पढ़ता रहूंगा. आपसे एक गुज़ारिश करना चाहूंगा कि आप चौथी दुनिया में कोई बेहतरीन कहानी एवं ग़ज़ल भी प्रकाशित किया करें.

शिबली रामपुरी, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश.

राशिफल का औचित्य

चौथी दुनिया को हम लोग देश में छपने वाले अनेक अच्छे अखबारों में से एक मानते हैं. इसकी सामग्री और साजसज्जा तो शायद सबसे आधुनिक है. पिछले अनेक अंकों को देखने के बाद ऐसा लगा कि यह एक स्तरीय अखबार है और अपने पाठकों को किसी भी तरह से भ्रमित होने से बचाता है. ऐसे में पूरे अखबार में जो सबसे कमजोर कालम है, वह राशिफल वाला है. इस कालम में जो कुछ भी पंडित जी लिखते हैं, वह लगता है, सबसे ज्यादा भरमाने वाला है. लगभग एक ही बात उनके हर कालम में होती है. हम ज्योतिष को गलत नहीं मानते, लेकिन उसके लिए गणित में महारत हासिल होनी चाहिए. यह तो विज्ञान का हिस्सा है, मगर ऐसे नहीं, जैसा अखबारों में लिखा जाता है. चौथी दुनिया में तो ऐसी चीजें होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि इसके झांसे में जो आ सकते हैं, वे चौथी दुनिया के पाठक नहीं हो सकते. हमारा सुझाव है कि आप इस जगह का उपयोग कोई अच्छा साहित्य या रंगमंच की खबरें छाप कर करें.

संगीता कुमारी, विश्वास कुमार और रमेश रंजक, पटना, बिहार.

शिक्षा का कैसा अधिकार

चौथी दुनिया के 8 मार्च के अंक में शिक्षा का अधिकार विषय पर अंचल सिन्हा का आलेख पढ़ने को मिला. इसमें अधिकार के बारे में और उसके बाद की स्थिति के अलावा वर्तमान शिक्षा प्रणाली पर बड़ी अच्छी विवेचना की गई है. इनके लेख में एक दो और विषयों पर भी चर्चा आवश्यक थी, जो नहीं की गई है. वे विषय हैं योग्य शिक्षकों की बहाली और सरकारी एवं निजी विद्यालयों का अंतर. हालांकि दिल्ली के एक निजी विद्यालय की चर्चा की गई है, जिसमें अमीरों के लिए वातानुकूलित कमरे एवं ग़रीब या मध्य वर्ग के लिए सामान्य कमरे की बात की गई है. बताया गया है कि कैसे बाद में सरकार ने हस्तक्षेप करके स्कूल प्रबंधन पर दबाव डाला कि वह ऐसा प्रस्ताव वापस ले. इस पर और ध्यान दिया जाना चाहिए. बिहार में वर्तमान शिक्षा प्रणाली की चर्चा भी की गई है. इस आलेख के साथ-साथ दूसरे आलेख भी बढ़िया लगे.

राजेश कुमार वर्मा, पटना, बिहार.

सबके लिए ज़रूरी हो शिक्षा

सचमुच यह सरकार के लिए शर्म की बात है कि वह देश की आजादी के इतने सालों बाद भी हमारे लिए उचित और ज़रूरी शिक्षा लागू नहीं कर सकी है. होना यह चाहिए था कि आजादी के तुरंत बाद कांग्रेस की सरकारें शिक्षा को आम बच्चों के लायक बनाने और उसे रोजगार से जोड़ने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास करतीं. पर देश पर सबसे ज्यादा समय तक राज करने वाली कांग्रेसी सरकारों (और दूसरी सरकारों ने भी) ने शिक्षा जैसी सबसे महत्वपूर्ण चीज को पीछे छोड़ दिया. अब अगर देश के शिक्षा मंत्री कोई पहल करके इसे लागू कराना चाहते हैं तो उनका स्वागत किया जाना चाहिए. उन्हें यह भी ध्यान देना चाहिए कि अनिवार्य शिक्षा केवल 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए न हो. हमारी राय है कि देश के प्रत्येक बच्चे को पहली से लेकर कम से कम हाईस्कूल तक की शिक्षा तो दी ही जानी चाहिए.

प्रीति लखेड़ा, शालीमार गार्डेन, साहिबाबाद, उत्तर प्रदेश.

पाठक अपने विचार और सुझाव हमें इस पते पर भेज सकते हैं.
संपादक, चौथी दुनिया, एफ-2, सेक्टर - 11 नोएडा
(उत्तर प्रदेश) पिन-201301
ई-मेल पता : feedback@chauthiduniya.com

जब तोप मुक़ाबिल हो

संतोष भारतीय

अमिताभ को अपमानित मत करो

अमिताभ बच्चन को अभी और अपमान सहने पड़ सकते हैं. एक व्यक्ति के नाते उनकी व्यथा को कोई समझना नहीं चाहता. कोई से हमारा मतलब आम जनता से नहीं, बल्कि ख़ास लोगों से है. ये ख़ास लोग कांग्रेस से रिश्ता रखते हैं और किसी हद तक जा सकते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि इनकी हरकतों से सोनिया गांधी और राहुल गांधी ख़ुश होकर इन्हें शाबाशी देंगे. हम नहीं जानते कि सचमुच सोनिया गांधी और राहुल गांधी ख़ुश हो रहे हैं, पर अगर दोनों में राजनैतिक समझ या सामाजिक समझ है तो उन्हें ख़ुश नहीं होना चाहिए. अमिताभ बच्चन और राजीव गांधी की दोस्ती को उन्हें याद रखना चाहिए, तेजी बच्चन और इंदिरा जी की मित्रता उन्हें भूलनी नहीं चाहिए. सोनिया गांधी की शादी तो अमिताभ बच्चन के पिता के घर से ही हुई थी तथा वह वहां शादी से पहले महीने भर तक रही थीं.

राजनैतिक अलगाव तो पति–पत्नी के बीच भी होता है, भाई–बहनों के बीच भी. लेकिन अगर उनमें आपसी रिश्ते की वह डोर भी टूट जाए, जिसकी वजह से बातचीत होती है या सामाजिक अवसरों पर मिलना होता है तो इसे सिर्फ़ और सिर्फ़ बदक़िस्मती ही कहा जा सकता है. अमिताभ बच्चन और सोनिया गांधी आपस में क्यों इतने दूर हुए, किसी को नहीं पता. पर दूर हुए तो ठीक, दुश्मन क्यों हुए? अमिताभ बच्चन को राजीव गांधी ने हेमवती नंदन बहुगुणा के ख़िलाफ़ इलाहाबाद से चुनाव लड़वाया था. हेमवती नंदन बहुगुण का राजनीति में कद बहुत बड़ा था, लेकिन अमिताभ बच्चन को वोट इलाहाबाद के बच्चों ने दिलवा दिया. उन्होंने अपने मां–बाप की उंगली पकड़ कहा कि इस बार उनके कहने से वोट दे दो. ज़्यादातर ने अपने बच्चों की इच्छा पूरी की. बहुगुणा जी चुनाव हार गए. अमिताभ संसद में थे और उन्हें राजीव गांधी के सबसे विश्वस्त साथी के रूप में देखा जा रहा था. जब वी पी सिंह ने आर्थिक अपराध के ख़िलाफ़ वित्त मंत्री के नाते अभियान चलाया तो सारे शिकार पैसे वाले अमिताभ के पास गए. माना जाने लगा कि अमिताभ बच्चन उन्हें बचाने की सिफ़ारिश राजीव गांधी से कर रहे हैं. इसी बीच बोफोर्स खुला. वी पी सिंह ने पहला हमला अमिताभ पर किया तथा ऐसा माहौल बनने लगा कि बोफोर्स का पैसा अमिताभ के भाई अजिताभ ने रखा है या उसका इंतजाम कर रहे हैं. सबूत किसी बात का नहीं था, पर लोगों ने इसे सच मानना शुरू कर दिया.

अमिताभ बच्चन को समझना चाहिए कि ये राजनीतिज्ञ बेरहम होते हैं, जिन्हें अपने ही सम्मान की चिंता नहीं तो वे उनके सम्मान की चिंता क्या करेंगे. अमिताभ बच्चन की इज़्ज़त इन राजनेताओं से बहुत ज़्यादा है.

अमिताभ बच्चन बुनियादी तौर पर राजनैतिक चमड़ी के नहीं हैं. उन्होंने राजीव गांधी की इच्छा के विपरीत लोकसभा से इस्तीफ़ा दे दिया और अपने को इस विवाद से अलग रखने की कोशिश की. यहां अरुण नेहरू ने राजीव को समझाया कि कहीं दोस्त ऐसे होते हैं, जो परेशानी में साथ छोड़ दें. राजीव गांधी को भी बुरा लगा. सोनिया गांधी को शायद अरुण नेहरू की बात ज़्यादा सही लगी होगी, जिसे वह आज तक याद रखे हैं. राहुल गांधी और प्रियंका गांधी उन दिनों बहुत छोटे थे. उन्हें वही बात आज याद होगी, जो उन्हें उनकी मां ने बताई होगी, क्योंकि अरुण नेहरू का कोई रिश्ता अब गांधी परिवार से है नहीं.

इन सबसे अलग अमिताभ बच्चन ने अपना स्थान सिनेमा में बहुत ऊंचा बनाया. उनके अभिनय को हिंदुस्तान में बहुत पसंद किया गया. जहां भी भारत के लोग दुनिया में हैं, अमिताभ बच्चन उनके हीरो हैं. उन्हें दुनिया ने स्टार ऑफ मिलेनियम कहा है. अमिताभ व्यक्तिगत ज़िंदगी में कैसे बोलते हैं नहीं पता, पर जब वह सार्वजनिक जगहों पर होते हैं तो उनकी भाषा शालीन और गर्व रहित होती है. साठ से ज़्यादा की उम्र के बावजूद वह जहां होते हैं, सबसे ज़्यादा आकर्षित करते हैं. आज भी जहां जाते हैं, भीड़ उन्हें देखने के लिए इकट्ठी हो जाती है. मुंबई में जाने वाले यात्री आज भी उनके घर के बाहर शाम के समय इकट्ठा हो जाते हैं, ताकि अमिताभ बच्चन की एक झलक उन्हें मिल जाए. ऐसा अवसर किसी दूसरे कलाकार को नियति ने हिंदुस्तान में तो कम से कम नहीं दिया है.

अमिताभ बच्चन जब परेशानी में थे, उनका बाल–बाल क़र्ज़ में डूब गया था तथा उनका बंगला नीलाम होने वाला था. उस समय अमर सिंह ने उनकी मदद की तथा सुब्रत राय सहारा से उन्हें बीस करोड़ रुपये दिलवाए. यह अमिताभ बच्चन के जीवन का सबसे भावुक समय था, जब सबने उनका साथ छोड़ दिया था. उन्होंने उस मदद को हमेशा याद रखा और अमर सिंह का साथ देना प्रारंभ किया. अमर सिंह समाजवादी पार्टी के ज़रिए राजनीति में तेज़ी से कदम बढ़ा रहे थे, पर अमिताभ बच्चन ने उनसे साफ़ कह दिया कि वह राजनीति में नहीं जाएंगे, न किसी सभा में और न ही किसी राजनैतिक समारोह में. अमिताभ ने अपने इस रुख़ को आज तक कायम रखा, हालांकि उन पर बहुत दबाव पड़ा कि वह राजनैतिक सभाओं में जाएं.

अमिताभ से उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह सरकार ने कहा कि विज्ञापन में वह आएं. अमिताभ बच्चन सरकारी विज्ञापनों में आए, लेकिन पार्टी के विज्ञापनों में नहीं आए. अमिताभ ने कभी सोनिया गांधी के परिवार पर हमला नहीं किया. अमिताभ ने जया बच्चन को भी हमेशा हमलावर न होने की सलाह दी. जया बच्चन को राज्यसभा में जाने का अमिताभ बच्चन ने कभी खुशी से समर्थन नहीं किया, क्योंकि वह जानते थे कि राजनीति उनके परिवार के लिए नहीं है.

अमिताभ बच्चन ने गुजरात पर्यटन के ब्रांड एंबेसडर बनने की स्वीकृति क्या दी, तूफ़ान आ गया. वह अहमदाबाद गए थे नरेंद्र मोदी को अपनी फ़िल्म पा दिखाने, क्योंकि उन्हें वह फ़िल्म टैक्स फ्री करानी थी. उनसे प्रस्ताव किया गया, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया. अमिताभ बच्चन साफ़ थे कि उन्हें राजनैतिक समारोह में मोदी के साथ शामिल नहीं होना है. पर अमिताभ बच्चन के अमर सिंह से रिश्तों पर खार खाए बैठे कांग्रेस के छुटभइये नेताओं को हमले का मौक़ा मिल गया.

इसके बाद आया मुंबई में वरली सी लिंक के दूसरे पुल के उद्घाटन का मौक़ा. इसमें उन्हें शरद पवार की पार्टी के मंत्री और कॉरपोरेशन के अध्यक्ष ने निमंत्रित किया. अमिताभ आए. मुख्यमंत्री अशोक चह्वाण भी आए. दोनों अच्छी तरह मिले. मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष कृपा शंकर सिंह को बुरा लगा, क्योंकि उन्हें इस समारोह में नहीं बुलाया गया था. उन्होंने अमिताभ बच्चन को बुलाए जाने का सार्वजनिक विरोध कर दिया. राजनीति कांग्रेस के भीतर थी, निशाना ज़बरदस्ती अमिताभ बच्चन पर साधा गया.

दिल्ली में सेव अर्थ कैंपेन में अभिषेक बच्चन को बुलाया गया था, शीला दीक्षित हंसती–मुस्कराती नज़र आती थीं, पर मुंबई की घटना के बाद अभिषेक बच्चन की तस्वीरें ही हटा दी गईं. अचानक अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन देश में सबसे पापी इंसान क़रार दे दिए गए. इस सारी कवायद में अमिताभ बच्चन का दोष है कहां? अमिताभ बच्चन को समझना चाहिए कि ये राजनीतिज्ञ बेरहम होते हैं, जिन्हें अपने ही सम्मान की चिंता नहीं तो वे उनके सम्मान की चिंता क्या करेंगे. अमिताभ बच्चन की इज़्ज़त इन राजनेताओं से बहुत ज़्यादा है. अच्छा हो कि अमिताभ बच्चन राजनेताओं से जुड़े समारोह में न जाया करें. हम यह सलाह इसलिए दे रहे हैं, क्योंकि अमिताभ बच्चन ने विश्व सिनेमा में भारत का गौरवशाली प्रतिनिधित्व किया है. उन्हें दुनिया भर के हिंदुस्तानियों का प्यार मिला है.

ज़िंदगी के इस मोड़ पर उन्हें आगे बढ़ने की जरूरत है, न कि छिछोरे विवादों में उलझने की. भाजपा उनके पक्ष में बयान दे रही है. अमिताभ बच्चन को समझ में आ रहा होगा कि भाजपा उनका सम्मान नहीं, अपमान कराना चाह रही है. भाजपा और कांग्रेस से एक छोटा अनुरोध है कि आप अमिताभ बच्चन का सम्मान नहीं कर सकते तो कम से कम अपमान तो मत कीजिए. अमिताभ बच्चन का अपमान करने से अमिताभ बच्चन का कम बिगड़ेगा, उनका चेहरा ज़्यादा बिगड़ेगा, जो उनके अपमान में बढ़–चढ़कर हिस्सा लेगा. अमिताभ बच्चन को अमिताभ बच्चन बने रहने दीजिए.

संपादक
editor@chauthiduniya.com

क्या पाकिस्तान बदलाव के लिए तैयार है?

इसमें कोई संदेह नहीं कि पाकिस्तान को एक वैकल्पिक और दूरदर्शी नेतृत्व की ज़रूरत है. इससे पहले कि अपने बारे में हम दूसरों की सोच को प्रभावित करें या उनकी नई पेशकश पर विचार करें, पहली ज़रूरत यह है कि हम अपने नज़रिए में अपेक्षित बदलाव लाएं.

आयशा सिद्दीका

अमेरिकी विदेश मंत्रालय में तीन सौ से ज़्यादा विदेशी पाकिस्तानियों के साथ खड़े मेरे जेहन में कुछ ऐसे ही ख्याल आ रहे थे. अमेरिका–पाकिस्तान के बीच हुई रणनीतिक बैठक के दौरान एक समारोह में सारे लोग एकत्र हुए थे. पाकिस्तानी दूतावास के कर्मचारी बातचीत के माहौल से खासे उत्साहित थे. उन्हें लगा कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ बातचीत को काफी तवज्जो दे रहा है. सेकेट्री ऑफ स्टेट हिलेरी क्लिंटन ने इसे द्विपक्षीय संबंधों के लिहाज़ से एक नई शुरुआत माना, जिसमें सारा जोर सैन्य सुरक्षा पर ही नहीं होगा, बल्कि सामाजिक–आर्थिक विकास भी अहम होगा. वाशिंगटन जल, ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक विकास के अन्य क्षेत्रों में भी सहयोग का इच्छुक है. सूचना तंत्र को तंदुरुस्त कर हर स्तर पर, खासकर आतंकवाद के ख़िलाफ़ लड़ाई में विश्वास बनाए रखने के लिए भी दोनों पक्षों के बीच सहमति बनी.

इस बातचीत का एक अहम पहलू यह है कि इसमें निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के बीच साझीदारी की बात कही गई है और पाकिस्तान के विकास के लिए विदेशों में बसे उसके नागरिकों के अनुभव एवं धन का इस्तेमाल भी संभव हो सकता है. पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने भी इस रणनीतिक बातचीत को दोनों देशों के बीच संबंधों में एक नए अध्याय की संज्ञा दी. उन्होंने विदेशों में बसे पाकिस्तानी मूल के लोगों से भी राष्ट्र निर्माण में सहयोग की अपील की.

इसमें कोई शक नहीं कि बातचीत का माहौल काफी ख़ुशनुमा था और स्पष्ट लग रहा था कि अमेरिका दोनों देशों के बीच संबंधों को एक नया आयाम देने का इच्छुक है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान इसके लिए तैयार है? इसके लिए हमें दो स्तरों पर बदलाव लाने की ज़रूरत है, द्विपक्षीय और घरेलू. जहां तक अमेरिका और पाकिस्तान के द्विपक्षीय संबंधों की बात है, तो बड़ा सवाल यह है कि इस इलाक़े में अमेरिका की बढ़ी भूमिका के बाद क्या हमारे नज़रिए में बदलाव आएगा. अमेरिका पाकिस्तानी सेना को भी विश्वास में लेना चाहता है. बैठक के दौरान पाकिस्तानी सेना प्रमुख को मिली अहमियत से ही पता चलता है कि ओबामा प्रशासन राजनीतिक नेतृत्व के अलावा सैन्य नेतृत्व को भी साथ लेकर चलना चाहता है.

बैठक में मौजूद रहे सीनेट के सदस्य डेविड लुगर की राय में पाकिस्तान का राजनीतिक नेतृत्व कमज़ोर हो तो अमेरिका कुछ खास नहीं कर सकता. अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान हर तरह के आतंकी नेटवर्क को ख़त्म करने के लिए कमर कसे. दरअसल अमेरिका को लगता है कि अतिवादी शक्तियां देश पर अधिकार हासिल कर परमाणु हथियारों को अपने क़ब्ज़े में ले सकती हैं. अमेरिका की इस मांग के पीछे वास्तव में यही डर छुपा है. अफगानिस्तान में भारत की बढ़ी भूमिका से डरा पाकिस्तान ऐसे तत्वों को पूरी तरह खत्म करने से हिचक रहा है. यदि ऐसा हो कि अमेरिकी सहयोग से अफ़ग़ानिस्तान में पाकिस्तानी हितों की सुरक्षा की गारंटी हो सके, तो क्या हम जिहाद की इस फैक्ट्री को पूरी तरह नेस्तनाबूद करने के लिए तैयार होंगे? यह सवाल ऐसा है, जिसका जवाब आसानी से नहीं मिल सकता. कम से कम तब तक नहीं, जब तक हम देश के अंदर इस पर जमकर चर्चा न करें और इसके लिए माहौल न तैयार करें.

बैठक में मौजूद रहे सीनेट के सदस्य डेविड लुगर की राय में पाकिस्तान का राजनीतिक नेतृत्व कमजोर हो तो अमेरिका कुछ खास नहीं कर सकता. अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान हर तरह के आतंकी नेटवर्क को खत्म करने के लिए कमर कसे. दरअसल अमेरिका को लगता है कि अतिवादी शक्तियां देश पर अधिकार हासिल कर परमाणु हथियारों को अपने कब्जे में ले सकती हैं.

हर बात में साजिश की गंध सूंघने वाले लोग पाकिस्तान के प्रति अमेरिका के बदले रवैए पर सवाल उठा सकते हैं. राजनीति की वास्तविकताओं की समझ रखने वाले लोगों को यह भी समझना होगा कि तेज़ी से बदलते वैश्विक परिदृश्य में कोई भी देश संकीर्णतावादी सोच नहीं अपना सकता. अफ़ग़ानिस्तान में भारत की भूमिका को देखते हुए हो सकता है, अमेरिका ने महसूस किया हो कि उसे पाकिस्तान की सुरक्षा ज़रूरतों को समझना होगा. सच तो यह है कि अफ़ग़ान समस्या का तब तक कोई समाधान नहीं निकल सकता, जब तक भारत, पाकिस्तान और अमेरिका अपने संकीर्णतावादी विचारों को तिलांजलि देकर वास्तविकताओं को न समझें. उन्हें यह भी समझना होगा कि हर समस्या का समाधान बल प्रयोग से नहीं हो सकता.

इसका मतलब यह है कि परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ताक़त के साथ बातचीत को भी हथियार के रूप में इस्तेमाल करना होगा. साथ ही एक हथियार के रूप में बल प्रयोग की सीमाओं को भी समझने की ज़रूरत है. बल प्रयोग हमेशा फ़ायदेमंद नहीं होता और न ही अपनी शक्ति को बढ़ा कर आंकने का ही कोई लाभ है. पाकिस्तान को अफ़ग़ानिस्तान में अपने हितों की सुरक्षा के लिए ज़रूर क़दम उठाना चाहिए, लेकिन इसके लिए दूसरे पड़ोसी देशों को वहां से बाहर करने की रणनीति नुक़सान पहुंचा सकती है. अच्छा हो, यदि पाकिस्तान अफ़ग़ानिस्तान में अपनी स्वाभाविक भूमिका का निर्वाह करते हुए यह आश्वासन हासिल करने में कामयाब रहे कि भारत या कोई अन्य देश उसके हितों को चोट नहीं पहुंचाएगा.

इसके अलावा घरेलू स्तर पर बदलाव का माहौल तैयार करने के लिए सभी संबद्ध पक्षों को विश्वास में लेना होगा. विदेश मंत्री ने अन्य देशों में बसे पाकिस्तानियों से निवेश की अपील की, लेकिन उन्होंने शासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और सत्ता प्रतिष्ठान में उत्तरदायित्व के अहसास की कोई चर्चा नहीं की. शायद इन चर्चाओं के लिए यह मंच मुफ़ीद नहीं था, लेकिन कुरैशी ने जो कुछ भी कहा, उसमें सत्ता प्रतिष्ठानों के रवैए में बदलाव के लिए इच्छाशक्ति भी नहीं दिखी. वहां मौजूद भीड़ को देखने से यही लगा कि ये सभी सफल लोग हैं, लेकिन यह भी सच है कि ये वही लोग हैं, जिन्होंने आर्थिक सुधारों की गाड़ी को आगे बढ़ने से रोक दिया और देश की आर्थिक प्रगति का फल आम जनों के बजाय अमीर लोगों तक ही सिमट कर रह गया. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें अपनी मानसिकता में बदलाव लाना होगा और ऐसे तंत्र का विकास करना होगा, जिससे घरेलू, क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तरों पर हमारी उपलब्धियां बढ़ सकें. ज़मीनी हक़ीक़त का तात्पर्य केवल ताक़त से नहीं है, बल्कि अपने लिए अच्छा माहौल तैयार करना भी है. हम चाहें भी तो अपने प्रतिद्वंद्वियों को दक्षिण एशियाई राजनीति से बेदखल नहीं कर सकते. ऐसे में सबसे अच्छा विकल्प यही है कि हम मिल– जुल कर रहना सीखें और शांति प्रक्रिया में शामिल होकर अपनी भूमिका का निर्वाह करें. अब जबकि अमेरिका पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों को नया आयाम देने की कोशिश कर रहा है, हमें ख़ुद से यह पूछना होगा कि क्या हम बदलाव के लिए तैयार हैं.

लेखिका पाकिस्तान की राजनीतिक समीक्षक हैं

feedback@chauthiduniya.com

चीन विश्वविद्यालय में पढ़ रहे एक छात्र ने अपने रूममेट को इसलिए मौत के घाट उतार दिया क्योंकि वह खर्राटे लेता था.

सूचना का अधिकार — जानने का अधिकार जीने का अधिकार — चौथी दुनिया की पहल

विधायक कोष

आपके विधायक जी ने कितना काम किया?

कोई नेता जब आप से वोट मांगने आता है तो क्या कहता है? वह कहता है कि आप उसे वोट दें ताकि वह आने वाले पांच सालों तक आपकी सेवा करता रहे. मतलब, जनता मालिक और नेता सेवक. लेकिन चुनाव जीतने के बाद क्या होता है? क्या आपको यह पता चलता है कि विधायक जी को स्थानीय क्षेत्र के विकास के लिए जो करोड़ों रुपये सरकार की तरफ़ से मिलते हैं, वो कहां जाते हैं? आपके क्षेत्र के विकास में विधायक फंड का कितना इस्तेमाल हुआ? कहीं उस फंड का बंदरबांट विधायक जी के चमचों के बीच तो नहीं हो गया? या फिर ठेकेदार और नेताजी मिल कर इस फंड को हजम तो नहीं कर गए? ऐसे तमाम सवाल आपके मन में ज़रूर आते होंगे. लेकिन आप यही सारे सवाल अपने विधायक से नहीं पूछते. वजह चाहे जो भी हो. लेकिन, सवाल नहीं पूछ कर आप एक तरह से भ्रष्टाचार को ही बढ़ावा देते हैं. ऐसे में यह ज़रूरी है कि आप सवाल पूछें, ताकि व्यवस्था और आपके विधायक जी पर भी दबाव बन सके. इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह होगा कि बिना कोई काम किए या आधा–अधूरा काम कर के, अब तक जो पैसा भ्रष्ट लोगों की जेब में चला जाता था, वह पैसा अब आपके क्षेत्र के विकास में काम आएगा. ऐसा नहीं है कि एक आवेदन देने भर से ही परिवर्तन दिखना शुरू हो जाएगा. लेकिन आपका अकेला आवेदन भी उन भ्रष्ट लोगों तक इस संदेश को पहुंचाने के लिए काफ़ी होगा कि जनता यानी असली मालिक अपने सेवकों पर लगाम लगाना जानती है. यदि आप सचमुच परिवर्तन चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को ऐसे आवेदन डालने के लिए प्रेरित करें. ज़ाहिर, है जब ज़्यादा संख्या में लोग सवाल पूछेंगे तो इससे बनने वाले दबाव का असर भी उतना ही ज़्यादा होगा. चौथी दुनिया आपके इस आंदोलन में हर क़दम पर आपके साथ है. किसी भी समस्या या सुझाव के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं. इस अंक में भी हम विधायक विकास फंड से संबंधित एक आरटीआई आवेदन प्रकाशित कर रहे हैं. आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं साथ ही अन्य लोगों को भी इसके इस्तेमाल के लिए प्रेरित कर सकते हैं. और आपको जो सूचनाएं मिलें, वे आप हमसे शेयर कर सकते हैं.

यदि आपने सूचना क़ानून का इस्तेमाल किया है और अगर कोई सूचना आपके पास है जिसे आप हमारे साथ बांटना चाहते है तो हमें वह सूचना निम्न पते पर भेजें. हम उसे प्रकाशित करेंगे. इसके अलावा, सूचना का अधिकार कानून से संबंधित किसी भी सुझाव या परामर्श के लिए आप हमें ई–मेल कर सकते है या हमें पत्र भी लिख सकते है. हमारा पता है:–

चौथी दुनिया
एफ–2, सेक्टर–11, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर) उत्तर प्रदेश
पिन –201301
ई–मेल: rti@chauthiduniya.com

विधायक कोष से संबंधित आवेदन

सेवा में,
लोक सूचना अधिकारी
जिलाधिकारी कार्यालय
पता

दिनांक :

विषय:– सूचना का अधिकार कानून 2005 के तहत आवेदन

महोदय, मै....(नाम)...(गांव का नाम) का निवासी हूं. मेरा विधान सभा क्षेत्र...(क्षेत्र का नाम)है. कृपया इस विधान सभा क्षेत्र में साल...से साल ...के बीच विधायक फंड से कराए गए विकास कार्यों से संबंधित निम्नलिखित सूचना उपलब्ध कराएं.

1. प्रत्येक विकास कार्य का नाम.
2. प्रत्येक विकास कार्य का विस्तृत विवरण.
3. प्रत्येक विकास कार्य के लिए जारी रकम.
4. प्रत्येक विकास कार्य शुरु और खत्म होने की तिथि.
5. प्रत्येक विकास कार्य की प्रगति रिपोर्ट, वर्तमान स्थिति.
6. प्रत्येक विकास कार्य करने वाली एजेंसी का नाम.
7. किस दर पर विकास का कार्य ठेकेदार/एजेंसी को दिया गया.
8. अब तक कितने पैसे ठेकेदार/एजेंसी को दिए गए.
9. प्रत्येक विकास कार्य की रूप-रेखा(स्केच) की एक कॉपी.
10. प्रत्येक विकास कार्य को करने के लिए किस तरह से निर्णय लिए गए?
11. प्रत्येक विकास कार्य के लिए कितनी राशि अब तक स्वीकृत हो चुकी है और अभी कितनी राशि भुगतान के लिए बची है.
12. अगर विकास कार्यों के लिए अब तक राशि स्वीकृत नहीं है तो इसके कारण क्या है?

मै दस रूपए का आवेदन शुल्क जमा कर रहा हूं.

भवदीय

नाम–

हस्ताक्षर

पता–

ज़रा हट के

मानव ख़ून में पहुंचा प्लास्टिक

प्लास्टिक की ख़ोज पर वैज्ञानिक ज़रूर ख़ुश हुए होंगे. हो भी क्यूं न, क्योंकि इस छोटे से थैले में हम बहुत सारे सामान ले जा सकते हैं. लेकिन, आज यही ख़ोज मानव जीवन के लिए गले की हड्डी बन गया है. यह धीरे-धीरे भस्मासुर की तरह ईजाद करने वालों के लिए ही मुसीबत बन गया है. यह धरती की सबसे क़ीमती चीज़ पानी को ख़राब कर रहा है और झीलों-तालाबों ही नहीं, महासागरों के लिए भी ख़तरा बनता जा रहा है.

ग़ैर सरकारी संगठन ग्रीन पीस के थीलो माक कहते हैं, दुनिया के समुद्रों में बड़ी-बड़ी भंवरों वाली पांच जगहें हैं. वहीं समुद्री कूड़ा इकट्ठा होता है. ग़ौरतलब है कि 80 फ़ीसदी नदियों के रास्ते और 20 फ़ीसदी शिपिंग उद्योग के माध्यम से कचरा समुद्र में पहुंचता है.

थीलो माक सागर विज्ञान विशेषज्ञ हैं और ग्रीन पीस के एक जहाज द्वारा यह देखने निकल पड़े कि महासागरों में कितना कचरा जमा हुआ है. उन्होंने बताया कि हम सोच भी नहीं सकते कि महासागरों में प्लास्टिक वाला कचरा जमा हो रहा है. हमने पानी में गोता लगाया और समुद्री भूतल पर हमने नीले, लाल, सुनहरे, हरे रंग के प्लास्टिक के ऐसे टुकड़े देखे, जो ज़मीन से हज़ारों किलोमीटर दूर वहां पहुंच चुके थे.

उन्होंने कहा कि इसका सीधा असर समुद्री जीवों पर पड़ता है, क्योंकि वे अपने चारे के साथ इसे भी निगल जाते हैं और फिर उनकी जान पर बन आती है. कई समुद्री जीव और चिड़िया पानी में मिलने वाली चीज़ों को खाती हैं. इस क्रम में वे अक्सर पानी में पड़े प्लास्टिक के टुकड़ों, ब्रश के टुकड़ों या टूटी चेनों जैसी चीज़ें खा लेती हैं, जिससे उनकी मौत हो जाती है.

ऐसा नहीं है कि हम ये सोचकर शांत रहें कि चलो हमारे पेट में तो प्लास्टिक नहीं जा रहा. जी नहीं, इन कृत्रिम पदार्थों से निकले ख़तरनाक केमिकल हमारे शरीर में भी पहुंच रहे हैं. बात बिल्कुल साफ़ है. हम भी तो प्रकृति के खाद्य चक्र में आते हैं, तो फिर ख़तरे के कुचक्र से कैसे बच सकते हैं.

प्लास्टिक नाम की डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म बनाने वाले ऑस्ट्रिया के फ़िल्म निर्माता वेर्नर बूटे ने अपना ख़ून यह जानने के लिए टेस्ट करवाया कि उनके ख़ून में क्या कार्सिजेनिक यानी कैंसर पैदा करने वाले तत्व हैं? उन्होंने बताया कि इस ख़तरनाक रसायन की मात्रा उनके शरीर में इतनी ज़्यादा थी कि उन्हें शॉक लग गया. फिर उन्होंने पूरी फ़िल्म टीम का ख़ून चेक करवाया और सभी के ख़ून में वे सारे रसायन पाए गए, जो प्लास्टिक जैसे कृत्रिम पदार्थों से आते हैं.

खर्राटे ने ले ली जान

क्या खर्राटे की वजह से कोई किसी की जान ले सकता है. शायद आपका जवाब न हो, लेकिन यह वाकया चीन में हुआ है, जहां एक शख्स ने अपने रूममेट के खर्राटों से आजीज आकर उसे हमेशा–हमेशा के लिए चैन की नींद सुला दिया.

यह सुनने में भले अटपटा लगे, लेकिन चीन विश्वविद्यालय में पढ़ रहे एक छात्र ने अपने रूममेट को केवल इसलिए मौत के घाट उतार दिया क्योंकि वह खर्राटे लेता था. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस वजह से उसे मौत की सज़ा सुनाई गई थी, लेकिन चीन में इस तरह की व्यवस्था है कि अगर जेल में दोषी व्यक्ति का व्यवहार अच्छा रहता है तो मौत की सज़ा को निलंबित किया जा सकता है.

एजेंसी के मुताबिक़ जिलीन प्रोविंस के चेंगचुंग कोर्ट में 24 वर्षीय गुओ लिवी ने अपने रूममेट की हत्या का गुनाह कबूला है. सिंहुआ एजेंसी के अनुसार, चीनी न्याय व्यवस्था में यह प्रावधान है कि अगर दोषी व्यक्ति का व्यवहार ठीक रहा, तो जेल में दो वर्ष बिताने के बाद मौत की सजा को निलंबित किया जा सकता है. हालांकि उसकी हत्या से पहले गुओ ने जोहो के खर्राटे की शिक़ायत की थी और उसके खर्राटे की वीडियो उसने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर डाली थी, जिसकी वजह से दोनों में काफी तनाव हो गया. उसने कहा कि मैंने जोहो को इस बारे में बताया, लेकिन वह शांत होने के बजाए गुस्से में आ गया. गुओ को चेंगचेन इंटरमीडिएट पीपुल्स कोर्ट ने मृतक के परिवार को चालीस हज़ार डॉलर देने का आदेश दिया है. उसे राजनीतिक अधिकार से भी वंचित कर दिया गया है. गुओ ने कोर्ट में कहा कि वह इसके ख़िलाफ़ अपील नहीं करेगा.

राशिफल

12 अप्रैल–18 अप्रैल 2010

मेष (21 मार्च से 20 अप्रैल)
समाज के कार्यों में व्यस्त रहेंगे. जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी. व्यावसायिक नए अनुबंध प्राप्त होंगे. रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी. किसी कार्य के संपन्न होने से आपके प्रभाव तथा वर्चस्व में वृद्धि होगी.

वृष (21 अप्रैल से 20 मई)
उपहार या सम्मान का लाभ मिलेगा. जीवनसाथी का भरपूर सहयोग मिलेगा. संबंधों में निकटता आएगी. पारिवारिक जीवन सुखमय होगा. आर्थिक पक्ष मज़बूत होगा. यात्रा की स्थिति सुखद व लाभप्रद होगी.

मिथुन (21 मई से 20 जून)
दूसरों से सहयोग लेने में सफल होंगे. सृजन व निर्माण के क्षेत्र में चल रहे प्रयास फलीभूत होंगे. आर्थिक क्षेत्र में किया जा रहा प्रयास सफल होगा. यात्रा देशाटन का लाभ मिलेगा. स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें.

कर्क (21 जून से 20 जुलाई)
आर्थिक तनाव रहेगा. व्यर्थ की परेशानी और उलझनें रहेगी. जिसकी वजह से चिंतित रहेंगे. व्यर्थ की भागदौड़ रहेगी. जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी. पारिवारिक जीवन सुखमय होगा. वाहन प्रयोग में सावधानी अपेक्षित है.

सिंह (21 जुलाई से 20 अगस्त)
आर्थिक तनाव, भागदौड़, व्यर्थ के विवाद आदि की स्थिति से गुजरना पड़ सकता है. वाणी पर संयम रखें और व्यर्थ के विवाद से बचें. निजी संबंधों में भी ग़लतफहमी या विवाद की स्थिति आ सकती है.

कन्या (21 अगस्त से 20 सितंबर)
कोई अधूरा पड़ा हुआ कार्य पूरा हो जाएगा. दूसरे से सहयोग लेने में सफलता मिलेगी. रचनात्मक कार्यों में आशातीत सफलता मिलेगी. किसी मूल्यवान वस्तु के पाने की अभिलाषा पूरी होगी. स्वास्थ्य पर ध्यान दें.

तुला (21 सितंबर से 20 अक्टूबर)
नेत्र व उदर विकार की संभावना, भावुकता पर नियंत्रण रखें. व्यर्थ की परेशानी व उलझनें रहेगी. आर्थिक मामलों में जोख़िम न उठाएं. संतान के संबंध में कोई सुखद समाचार प्राप्त होगा जिससे आप बहुत प्रसन्न होंगे.

वृश्चिक (21 अक्टूबर से 20 नवंबर)
व्यावसायिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है. व्यर्थ की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. आर्थिक मामलों में सावधानी अपेक्षित है, खासतौर से रुपए पैसे में. किसी को कटु शब्द न कहें.

धनु (21 नवंबर से 20 दिसंबर)
संतान के दायित्व की पूर्ति होगी. उपहार या सम्मान का लाभ मिलेगा. आर्थिक मामलों में सावधानी अपेक्षित है. शिक्षा के कारण तनाव मिल सकता है. अचानक कहीं दूर की यात्रा पर जाना पड़ सकता है.

मकर (21 दिसंबर से 20 जनवरी)
व्यर्थ की भागदौड़ रहेगी. सामाजिक कार्यों में अधिक व्यस्त रहेंगे. व्यर्थ की समस्या में उलझ सकते हैं. दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप न करें, नहीं तो आपको हानि हो सकती है. जीवनसाथी के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहे.

कुंभ (21 जनवरी से 20 फरवरी)
भागदौड़ अधिक रहेगी. रचनात्मक दिशा में किया जा रहा प्रयास फलीभूत होगा. यात्रा देशाटन की स्थिति सुखद व लाभप्रद होगी. आय के नए रास्ते खुलेंगे. आर्थिक दिशा में किया जा रहा प्रयास सफल साबित होगा.

मीन (21 फरवरी से 20 मार्च)
संतान के व्यवहार से चिंतित होंगे. नई योजना को बल मिलेगा. पारिवारिक कार्यों में व्यस्तता रहेगी, लेकिन भाई के कारण तनाव मिल सकता है. मांगलिक दिशा में किया जा रहा प्रयास सफल होगा. वाणी पर नियंत्रण बनाएं रखे.

पंडित सुदर्शन
feedback@chauthiduniya.com

...ताकि आतंकवादी हमले न होने पाएं

पाक़िस्तान में आतंकवाद का एक और उत्पात. लाहौर छावनी में दो धमाके और रिहायशी इलाक़ों में छिटपुट विस्फोट. इन धमाकों ने चंद लम्हों में ही दर्ज़नों मासूमों को मौत के मुंह में धकेल दिया. इसके कुछ देर बाद ही मिन्गोरा में भी धमाका हुआ और फिर से कुछ मासूम ज़िंदगियां मौत के मुंह में समा गईं. वैसे पाक़िस्तान के लिए आतंकवादी धमाके कोई नई बात नहीं हैं. नई बात है तो यह कि इन धमाकों की तीव्रता अचानक बढ़ गई है, जबकि दो वारदातों के बीच का अंतराल लगातार कम होता जा रहा है. साथ ही इन्हें अंजाम देने का तरीक़ा भी बदल गया है. और तो और, इन धमाकों में जिन लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, वह भी पाकिस्तान में जारी आतंकवाद का एक नया चेहरा पेश करता है. आतंकवाद पाकिस्तान के लिए नया नहीं है. इसके छोटे से इतिहास में ही आतंकवाद, सांप्रदायिक हिंसा और समुदायों के बीच आपसी कलह की बहुतेरी घटनाएं दर्ज़ हैं.

वैसे तो पूरा देश ही मासूम ज़िंदगियों की मौत पर शोक मनाता है, लेकिन जो लोग अपनों को इन धमाकों में हमेशा के लिए खो देते हैं, दरअसल वे ही इसका असली दर्द समझते हैं. अपनी आंखों के सामने अपनों को दफनाने का दर्द उनसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता. यह दर्द ताउम्र उनके साथ रहता है. उन लोगों के लिए धमाकों में मरने वाले लोग सिर्फ़ आतंकवाद से जुड़े आंकड़ों की संख्या भर नहीं होते, बल्कि वे या तो परिवार की मां होते हैं या पिता या फिर बेटा अथवा बेटी. इसके अलावा धमाकों में मरने वाले किसी के दोस्त या हमदर्द होते हैं. धमाकों में मरने वाले लोग हमारी ही तरह इंसान होते हैं, जिनकी अपनी इच्छाएं और भावनाएं तो होती ही हैं, इन सबसे बढ़कर ज़िंदगी जीने की तमन्ना होती है. इन सबके बीच पाकिस्तान की जनता यह सोचती है कि कब उसके देश में सुरक्षा और संपन्नता की एक नई शुरुआत होगी. पाकिस्तानी जनता पूरे हक़ के साथ अपनी सरकार से यह जवाब मांगती है कि उसकी जान की सुरक्षा के लिए क्या योजनाएं बनाई जा रही हैं.

यह सच है कि हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं, जो अपने आप में असाधारण है, साथ ही चुनौतियों से भी भरा है. इसलिए सरकार को ऐसी रचनात्मक, चुस्त और प्रभावशाली योजनाओं को आकार देने की ज़रूरत है, जो आतंकवाद, सांप्रदायिक हिंसा और समुदाय विशेष की आपसी कलह से होने वाली तमाम हिंसक घटनाओं से लोहा लेने में सक्षम हों. पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसियों और दस्तों को आधुनिक हथियार, तकनीक और सुविधाओं से जल्द से जल्द लैस किया जाना चाहिए. लेकिन, पाक़िस्तान इस तरह के काम में अभी बहुत पीछे है. यहां डीएनए जांच के लिए लैब और स्थायी मुर्दाघरों की भारी कमी है, जिससे फोरेंसिक जांच के काम में दिक़्क़तें आती हैं. इससे पता चलता है कि देश का क़ानून और सुरक्षातंत्र तकनीक के लिहाज़ से कितना पिछड़ा है. सुरक्षा से जुड़ी तमाम संस्थाओं को चुस्त बनाने की इच्छा शक्ति की कमी अब ख़तरे की घंटी बजा रही है. साथ ही सीमित संसाधनों का दुरुपयोग भी सुरक्षा की समस्या को बढ़ा रहा है.

पाकिस्तान अभी दोहरी मार झेल रहा है. एक तो आतंकवाद की और दूसरी बग़ावत की. हालांकि आतंकवाद और बग़ावत के बीच कोई ख़ास अंतर नहीं है, लेकिन इनके उद्देश्य और ख़तरनाक गतिविधियां एक दूसरे से अलग हैं. लोकतांत्रिक तरीक़े से सत्ता में हिस्सेदारी करने के बजाय बग़ावत करने वाला धड़ा ताक़त और हिंसा का इस्तेमाल कर इलाक़ों पर नियंत्रण, सत्ता में हिस्सेदारी और राजनीतिक रियायत पाना चाहता है. दूसरी ओर आतंकवाद सरकार की वैधानिकता और उसकी क्षमताओं पर सवाल खड़े कर उसके चरित्र में बदलाव का प्रयास करता है. इसीलिए आतंकवादी सरकार की सत्ता को हमेशा सीधी चुनौती नहीं देते. आतंकवाद अपने आप में अंतिम उद्देश्य नहीं है, लेकिन यह किसी विद्रोह के उद्देश्य को हासिल करने का तरीक़ा हो सकता है.

आतंकवाद के नेटवर्क को तबाह और हमलों को निष्क्रिय करने के लिए एक चुस्त ख़ुफ़िया तंत्र का कामकाज ही सबसे प्रभावशाली हथियार हो सकता है, जो जानकारी इकट्ठा कर एवं दूसरे तरीक़ों से हिंसा से लड़ने और इसके मूल स्वभाव को जानने का काम करता है. हिंसा करने वाले अपनी रणनीति की अनिश्चितता और उसके प्रभाव को छुपाकर रखना चाहते हैं. हाल में हुए आतंकवादी हमलों को देखें तो पता चलता है कि सरकार अब बस प्रतिक्रिया देने की स्थिति में रहती है, न कि एक्शन लेने की स्थिति में. जब आतंकवादी जानलेवा हमले करते हैं तो सरकार प्रतिक्रिया भर ही देती है, न कि हमला होने से पहले एक्शन लेती है. इससे बड़ी चिंता की बात और क्या हो सकती है कि हम आतंकी हमलों को स्वीकार करने के आदी हो चुके हैं.

हिंसा को रोकने का सबसे सफल तरीक़ा यही है कि इसे घटने से पहले रोका जाए. हादसों को घटने से पहले रोकने में असफलता ही आतंकवादियों को उनका लक्ष्य पूरा करने का प्रोत्साहन देती है, जिससे बाद में कई मासूमों की ज़िंदगियां तबाह हो जाती हैं. ऐसे हालात में जब ख़ुफ़िया एजेंसियां और सुरक्षातंत्र हर हमले को रोक पाने में सफल नहीं हो पाते, तो भी उनकी निगरानी एवं चुस्ती आतंकवाद के नेटवर्क को तबाह और निष्क्रिय करने में मददगार साबित हो सकती है. हालांकि अब तक की पाकिस्तानी सरकारें दोनों ही हालात में नाकामयाब साबित हुई हैं. ऐसा इसलिए है, क्योंकि पाकिस्तानी सरकारों की प्राथमिकताओं में हिंसा को घटने से पहले रोकना शामिल नहीं रहा है. लगातार चुस्ती के साथ काम करने वाले प्रशासन और जनता के प्रति उसकी प्रतिबद्धता से ही हमलों को घटने से रोका जा सकता है.

प्रभावशाली सुरक्षा एजेंसियों का गठन और उन्हें आधुनिक तकनीक एवं हथियारों से लैस करने के अलावा हिंसा को रोकने के लिए न्याय व्यवस्था में भी सुधार की ज़रूरत है, क्योंकि आतंकवाद और हिंसा से जुड़े मामलों की ज़िम्मेदारी प्रशिक्षित और स्वतंत्र न्याय प्रणाली ही उठा सकती है. इतिहास बताता है कि सभी पिछली सरकारें आतंकवाद विरोधी क़ानून बनाने और उनके संचालन में असफल रही हैं, क्योंकि या तो उन्होंने अपने संसाधनों का सही इस्तेमाल नहीं किया या फिर उनके प्रयास में कमी रह गई.

अयूब ख़ान की सरकार से लेकर अब तक जितनी भी सरकारें पाकिस्तान में हुईं, सबने आतंकवाद पर राजनीति कर देश की सुरक्षा को और भी कमज़ोर बना दिया है. वह भी उन हालात के बीच, जब यहां शुरू से आतंकवाद की समस्या गंभीर बनी हुई है. जब किसी सरकार का मुख्य उद्देश्य कुछ चुनिंदा लोगों एवं उनके आसपास की सुरक्षा तक सीमित हो जाता है और शासन प्रणाली, आम जनता के हित एवं उसकी सुरक्षा को दूसरा दर्ज़ा दिया जाता है, तो वह देश अपने दुश्मनों के लिए आसान शिकार बन जाता है. इन परिस्थितियों में देश और उसकी जनता के ख़िलाफ़ होने वाली हिंसक घटनाओं को टालना मुश्किल हो जाता है.

आतंकवाद विरोधी क़ानून बनाने और प्रशिक्षित न्याय प्रणाली एवं सुरक्षातंत्र द्वारा उसके संचालन से ही एक उम्मीद जाग सकती है. आतंकवाद और बग़ावत की हिंसक घटनाओं को रोकने के लिए दो तरह के प्रयासों की ज़रूरत है. एक तो सैन्यबलों की तैनाती और दूसरा यह कि न्याय प्रणाली को मज़बूत बनाकर इससे लड़ा जाए. कहने की ज़रूरत नहीं है कि इस तरह के अपराध से निबटने वाली न्याय व्यवस्था को देश के संवैधानिक ढांचे के अंदर ही काम करना होगा. उसे हिंसा के पीछे छुपी ताक़तों से लड़ना होगा, न कि हिंसा से, क्योंकि हिंसा को शायद पूरी तरह उखाड़ कर नहीं फेंका जा सकता. हां, इसे सकारात्मक नीतियों और कार्यों से नियंत्रण में ज़रूर रखा जा सकता है. इसीलिए जब कोई सरकारी अधिकारी यह कहता है कि आतंकवाद अनप्रेडिक्टेबल है और आतंकवादी हमलों को रोका नहीं जा सकता, तो यह सरकार की अपनी कमज़ोरी के सिवा और कुछ नहीं है. आतंकवाद से लड़ने के लिए सरकार को अपने सभी संसाधनों का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि जनता सुरक्षित रह सके. अगर वह ऐसा कर पाने में नाकाम रहती है, तो वह शासन करने का अधिकार खो देती है.

सलीम रिज़वी
feedback@chauthiduniya.com

(लेखक न्यूयार्क के एक प्रतिष्ठित वकील हैं)

शिरडी साई बाबा फाउंडेशन पिछले कई वर्षों से समाज के अचेतन में साई की सच्ची भक्ति की चेतना जगाने का पुनीत कार्य कर रहा है.

साई बाबा सच्चे दिग्दर्शक हैं : राजीव अग्रवाल

विकास कपूर

पिछले दिनों प्रतिष्ठित फिल्म लेखक एवं गीतकार जावेद अख्तर को राज्यसभा के लिए मनोनीत किए जाने से लेखक बिरादरी खुद को सम्मानित महसूस कर रही है. वास्तव में फिल्म और टेलीविज़न की सभी विधाओं में लेखक का कार्य ही उसकी आत्मा माना जाता है. निर्देशन , अभिनय, संगीत एवं चित्रांकन आदि सभी कुछ लेखक की कल्पना पर आधारित होता है. अपनी कल्पना में कहानी गढ़ने वाले ऐसे ही एक मूर्धन्य लेखक हैं राजीव अग्रवाल. वर्ष 1980 में अलीगढ़ से कुछ कर दिखाने के सपने संजोए राजीव मुंबई आ गए. संई परांजपे और सिद्धार्थ काक के साथ राजीव ने अपना फिल्मी सफर शुरू किया और कुछ ही समय में अपनी लेखनी की धार से लोगों को प्रभावित करने लगे. फीचर फिल्म संजय, प्यार-प्यार, भूत अंकल एवं इकरार बाईचांस आदि के साथ ही राजीव ने कई प्रतिष्ठित धारावाहिकों का लेखन किया, जिनमें देख भाई देख, नींव (रापा पुरस्कार), कभी कभी मेरे घर में भूचाल आता है, इंद्रधनुष, ज़मीर, दुनिया, शुभारंभ, भारतरत्न, सर्कस, डैडी समझा करो, मां, पराया धन एवं शऽऽऽ कोई है आदि प्रमुख हैं. इनमें से कुछ का निर्देशन भी उन्होंने स्वयं ही किया. पिछले दिनों राजीव की साई भक्ति पर एक लंबी चर्चा हुई. प्रस्तुत हैं मुख्य अंश:

राजीव अग्रवाल

ॐ साई राम राजीव भाई.

ॐ साई राम.

अपनी भक्ति और आस्था को आप किस दृष्टि से देखते हैं?

सच कहूं तो मैं खुद को भगवान का नहीं, कर्म का पुजारी मानता हूं. समाज में जैसी भक्ति प्रचलित है, वह मुझे समझ में नहीं आती. मेरा मानना है कि भक्ति बहुत गहराई से समझी और कही जाने वाली अनुभूति है, लेकिन आज भगवान की भक्ति केवल दिखावा और ढकोसला बनकर रह गई है. यही वजह है कि मेरे बहुत सारे दोस्त मुझे नास्तिक समझते हैं.

भक्ति के प्रति आपका नज़रिया क्या है?

मैं और लोगों की तरह घंटी हिलाकर अथवा शंख फूंककर भगवान को नहीं रिझाता. अगर मेरी टेबिल पर कोई भी काम पेंडिंग है तो सबसे पहले उसे ख़त्म करना ही मैं अपनी पूजा समझता हूं. जहां तक पूजा-भक्ति का प्रश्न है तो मैं लगभग हर दिन कुछ पल मन ही मन भगवान को याद करके उन्हें जीवन देने के लिए धन्यवाद ज़रूर देता हूं.

आप प्राय: शिरडी जाते हैं, साई बाबा के विषय में आपकी क्या धारणा है?

साई बाबा के प्रति मेरे मन में गहरी श्रद्धा है. शिरडी जाकर मेरा मन तरोताज़ा हो जाता है. सारे शरीर में साई कृपा की ऊर्जा प्रवाहित हो जाती है. एक बात और है, वह यह कि साई बाबा के दर्शन और शिक्षा को मैं अन्य सभी गुरुओं और देवताओं से अधिक अपने समीप पाता हूं.

किस प्रकार?

अगर आप साई बाबा के जीवन चरित्र को देखें तो उन्होंने अपने अनुयाइयों को कभी लंबे-चौड़े उपदेश नहीं दिए. बाबा अपने भक्तों का कष्ट हरने के लिए जो उपाय करते थे, वे यज्ञ-अनुष्ठान न होकर प्राकृतिक और जीवों की सहायता से जुड़े रहते थे. अपने महानतम जीवनकाल में साई बाबा ने कभी अपने भक्तों को व्रत-उपवास आदि का आदेश भी नहीं दिया. यही कारण है कि मैं अन्य सभी से अधिक साई बाबा से प्रवाहित हुआ. मुझे अपने लिए और समाज के लिए भी साई बाबा सच्चे दिग्दर्शक प्रतीत होते हैं, जिनके बताए रास्ते पर चलकर सभी का कल्याण निश्चित है.

आप लेखक हैं, कई अच्छी कृतियां, फिल्में और धारावाहिक अब तक लिख चुके हैं. क्या साई बाबा के दर्शन पर कुछ लिखने की इच्छा है?

हां-हां, क्यों नहीं. यदि अवसर मिलेगा तो ज़रूर लिखूंगा.

आपके जीवन में साई कृपा की कभी कोई घटना घटी?

मैं कुछ नहीं था और बहुत कुछ हो गया, शायद यही सबसे बड़ी कृपा है. ॐ साई राम.

feedback@chauthiduniya.com

हमारी भक्ति

साई बाबा के जीवन एवं सच्चरित्र और आपकी अपनी भक्ति से संबंधित किसी एक विषय पर यहां परिचर्चा की जाएगी और श्रेष्ठ विचार भेजने वाले साई भक्त के विचार यहां प्रकाशित किए जाएंगे.

शिरडी यात्रा से जीवन में क्या सुख मिलता है?

आपके जवाब

1. हां, साई बाबा जीवित परमेश्वर हैं. अगर सच्ची श्रद्धा और सच्चे मन से उन्हें याद किया जाए तो शिरडी के साई बाबा अपने भक्तों के सामने साक्षात प्रकट हो जाते हैं. भक्तों को हर पल ऐसा महसूस होता है कि साई कृपा का हाथ उनका सिर सहला रहा है. साई बाबा, मां, बाप और गुरु बनकर सदा अपने भक्तों के साथ रहते हैं.

आत्माराम दुबे, *अमृतसर, पंजाब. (सर्वश्रेष्ठ विचार)*

2.शिरडी के साई बाबा का 1918 में अपनी महासमाधि के बाद भक्तों के सामने साक्षात प्रकट होना कोई यदा-कदा की घटना नहीं है.लगभग हर दिन साई भक्त उनके साक्षात दर्शनों की अनुभूति करते हैं.

कमलेश ऐलानी, *मुंबई, महाराष्ट्र.*

3. मैंने ख़ुद तीन बार जीवन में साई कृपा और साई दर्शन का अनुभव किया और यह अनुभव कोई सपना अथवा ख्याल नहीं, बल्कि मेरी पुकार पर साई बाबा अलग-अलग रूप लेकर मेरे जीवन के संकटों का अंत करने आए.

सरदार कर्मजीत सिंह, *कानपुर, उत्तर प्रदेश.*

आप अपने विचार sai4world@gmail.com पर मेल करें अथवा शिरडी साईबाबा फाउन्डेशन, पोस्ट बॉक्स नम्बर-17517, मोतीलाल नगर नम्बर-1, गोरेगाँव (पश्चिम), मुम्बई-58 पर डाक द्वारा भेजें या 09999989427 पर एसएमएस करें.

अगले सप्ताह का विषय

क्या आजकल तथाकथित आध्यात्मिक गुरु अपनी दुकान साई बाबा के नाम पर चला रहे हैं?

Giriraj
Sai Hills
Sai Vihar Township
Spiritual home... away from home
• Fully Furnished and Spacious studio Apartments.
• One Bedroom Apartments.
• Two bedroom Apartments.
• Fully Furnished Villas.
STARTING FROM RS. 9.65 LAKHS*
AUM Infrastructure & Developers
Aum Infrastructure & Developers
Tel: 011-46594226 / 46594227
www.ssbf.in
कृष्ण की नगरी में आपका अपना घर!

बाज़ारवाद का ताज़ा नमूना हैं ज्योतिषी और ज्योतिषशास्त्र

शिरडी की टूटी-फूटी मस्जिद में रहते हुए साई बाबा ने तंत्र-मंत्र, पाखंड और ढकोसलों का पुरज़ोर विरोध किया. श्री साई सच्चरित्र में नासिक के प्रसिद्ध ज्योतिषी मुले शास्त्री की एक कथा बताई गई है. वह बूटी सरकार के साथ शिरडी आए और बाबा की हस्तरेखा देखने की प्रार्थना करने लगे. उन्हें अपनी श्रेष्ठता, शुद्धता और ब्राह्मणत्व पर बहुत अभिमान था. मुले शास्त्री ने 6 शास्त्रों का अध्ययन किया था. ज्योतिष और सामुद्रिक ज्ञान में भी वह पारंगत थे, परंतु बाबा ने उन्हें अपना हाथ नहीं दिखाया. जब अभिमान के साथ उन्होंने द्वारकामाई में प्रवेश किया तो उन्हें बाबा के स्थान पर अपने कैलाशवासी गुरु घोलप स्वामी बैठे दिखाई दिए. उनका अभिमान जाता रहा और वह बाबा के चरणों पर सिर रखकर अपनी भूल के लिए क्षमायाचना करने लगे. यह तो उस समय की घटना थी, जब हमारे समाज में बाज़ारवाद का जन्म नहीं हुआ था.

आज हमारे समाज में ज्योतिषियों और ज्योतिषशास्त्र ने बाज़ारवाद और फलते-फूलते व्यापार का रूप धारण कर लिया है. सृष्टि की रचना के बाद हज़ारों-लाखों सूर्यग्रहण और चंद्रग्रहण पड़े होंगे, परंतु आज ज्योतिषी न जाने कौन सी गणना करके बता देते हैं कि ऐसा योग इतने सौ सालों के बाद आया है.

आज हमारे समाज में ज्योतिषियों एवं ज्योतिषशास्त्र ने बाज़ारवाद और एक फलते-फूलते व्यापार का रूप धारण कर लिया है. सृष्टि की रचना के बाद हज़ारों-लाखों सूर्यग्रहण और चंद्र ग्रहण पड़े होंगे, परंतु आज ज्योतिषी न जाने कौन सी गणना करके बता देते हैं कि ऐसा योग इतने सौ सालों के बाद आया है. सच कहा जाए तो इस व्यापार ने बाज़ारवाद के सबसे कारग़र अस्त्र अर्थात डराकर अपना उल्लू सीधा करने वाली शैली अपना रखी है. मसलन मेष राशि वाले ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा और सिंह राशि वाले ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा.

पिछले दिनों देश की एक जानी-मानी सर्वेक्षण कंपनी ने एक एनजीओ के लिए ज्योतिष विज्ञानियों की पिछले साल भर में की गई भविष्यवाणियों का मूल्यांकन करने के बाद पाया कि लगभग 70 प्रतिशत भविष्यवाणियां अनुमान के आधार पर की गई थीं. व्यापारवाद से दूर और परंपरागत ज्योतिष विज्ञान के आधार पर गणना करने वाले काशी के प्रसिद्ध ज्योतिषशास्त्री आर के मेहरोत्रा इस बात पर ताज्जुब करते हैं कि मीडिया और कैमरे के सामने बैठकर ज्योतिषी किस तरह और किस शास्त्र के आधार पर गणना करते हैं. मेहरोत्रा के अनुसार, कुंडली, हस्तरेखा और मस्तक रेखा विज्ञान का गहन अध्ययन करने पर भी विद्वान उस प्रकार की घोषणा नहीं कर सकते, जिस प्रकार आज के ज्योतिषी कैमरे के सामने बैठकर केवल नाम सुनकर कर देते हैं. मेहरोत्रा के अनुसार, ज्योतिष विज्ञान, विज्ञान के समान साधनों और रसायनों को जोड़ कर आविष्कार करने वाला प्रयोग नहीं है. यह सामुद्रिक ज्ञान अपने निश्चित पथ और ग्रहों के साथ ही काल की गणना के आधार पर घोषित किया जाता है. गणना के कारण ही पूर्व में ऋषियों ने इसे विज्ञान की संज्ञा दी, परंतु यह विज्ञान से बिल्कुल अलग काम करता है. मेहरोत्रा सावधान भी करते हैं कि जनता भयभीत करके अपना उल्लू सीधा करने वालों के चक्कर में न फंसे.

इतना ही नहीं, शिरडी साई फाउंडेशन के पोस्ट बॉक्स में हर दिन ऐसे कई पत्र आते हैं, जिनमें यह लिखा होता है कि मैं फलां ज्योतिषी अथवा तांत्रिक के चक्कर में फंस गया था, परंतु कोई फायदा नहीं हुआ. जबसे साई बाबा की शरण ली है, तबसे सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो रहा है. साईभक्तों! शिरडी साई बाबा फाउंडेशन का साई भक्त परिवार पिछले कई वर्षों से समाज के अचेतन में साई की सच्ची भक्ति की चेतना जगाने का पुनीत कार्य कर रहा है. हम इस पावन यज्ञ में आपका भी आह्वान करते हैं. आइए और अपनी भक्ति की समिधा श्री साई चरणों में अर्पित करने के अधिकारी बनिए. साईभक्त परिवार में शामिल होकर अपनी साई भक्ति को और अधिक दृढ़ करने तथा सदगुरु साई समर्थ की कृपा का अधिकारी बनने के लिए आप अपना नाम साईभक्त.....और फोन नंबर..... कृपया 09999989427 पर एसएमएस करें या info@ssbf.in पर मेल करें. ॐ साईराम.

ऑसिम खेत्रपाल
feedback@chauthiduniya.com

SSBF
Shirdi Sai Baba Foundation
presents
LIFE IS HOPE
Center
Complete
Mind, Body & Soul
Rejuvenation

OFFERS CLASSES/SESSIONS FOR:
☞ Antrang Yoga
☞ Innovative Meditative Dancing
☞ Innovative, Healthy, Nutritious Cooking
☞ Pottery Making
☞ Stain Glass Painting / Painting (Ladies & Children)
☞ Theatre - Children
☞ Spiritual Healing with Aushim Khetarpal
☞ Discover yourself with Kanu Priya
"Oneness with GOD"
Come and experience the serenity and Connect with the DIVINE
At PACIFIC SPORTS COMPLEX - a World Class Sporting & Swimming facility, opposite Petrol Pump, G.K. - I, Andrews Ganj in South Delhi.
REGISTRATION NOW OPEN
Contact : 01164640005/06 Mobile : 9999041571
E-mail : shirdisaibabafoundation@gmail.com
Register Online at www.ssbf.in

सभी साई भक्तों को विनम्रता से सूचित किया जाता है कि वे अपने साई अनुभव, साई उत्सवों आदि की विस्तृत सूचना (कार्यक्रम, प्रबंधक, तिथि, स्थान और समय सहित) विकास कपूर को sai4world@gmail.com पर मेल कर सकते हैं.

बैरागियों के तीन अखाड़े वैशाख पूर्णिमा पर गंगा स्नान करते आए हैं, पर उस स्नान को प्रशासन और परिषद दोनों ही वैयक्तिक मानते रहे हैं, शाही स्नान नहीं.

अनुवाद से जगती उम्मीदें

अनंत विजय

हिंदी में अनुवाद की हालत बेहद ख़राब है. जो अनुवाद हो भी रहे हैं, वे बहुधा स्तरीय नहीं होते हैं. अनुवाद इस तरह से किए जाते हैं कि मूल लेखन की आत्मा कराह उठती है. हिंदी के लेखकों में अनुवाद को लेकर बहुत उत्साह भी नहीं है. अमूनन अनुवाद में लेखक तभी जुटते हैं, जब उनके पास या तो काम कम होता है या नहीं होता है. जैसे ही काम मिलता है, अनुवाद को लेकर वे उदासीन हो जाते हैं. इसलिए हिंदी में अनुवाद एक विधा के रूप में विकसित नहीं हो पाया और अनुवादक को उचित सम्मान नहीं मिल पाया. नतीजा यह हुआ कि अन्य भारतीय भाषाओं से हिंदी में अनुवाद नहीं हो पाया और हिंदी के पाठक का परिचय विश्व की अन्यतम कृतियों से नहीं हो पाया.

लेकिन, अभी हाल के दिनों में हॉर्पर कालिंस पब्लिकेशंस और पेंग्विन बुक्स ने भारतीय अंग्रेजी लेखकों के अलावा विश्व के अन्य भाषाओं की कृतियों का अनुवाद हिंदी में प्रकाशित करना शुरू किया है. यह एक स्वागत योग्य क़दम है. हॉर्पर कालिंस से अभी अद्वैत काला के उपन्यास ऑलमोस्ट सिंगल का अनुवाद मनीषा तनेजा ने किया है. लगभग तीन सौ पन्नों का उपन्यास बेहतरीन अनुवाद का एक नमूना है. मनीषा तनेजा दिल्ली विश्वविद्यालय में स्पैनिश पढ़ाती हैं और इसके पहले भी उन्होंने गैबरील गारसिया मारक्कैज के उपन्यास एकाकीपन के सौ साल और पॉब्लो नेरुदा के संस्मरण का हिंदी में अनुवाद किया है. अभी-अभी मैंने उनके द्वारा अनूदित अद्वैत काला के उपन्यास का हिंदी अनुवाद लगभग सिंगल पढ़ा. मैंने अद्वैत काला का अंग्रेजी में लिखा मूल उपन्यास भी पढ़ा था. मनीषा के अनुवाद में मूल की आत्मा की रक्षा की गई है, जिससे उपन्यास के प्रवाह में बाधा नहीं आती. हिंदी अनुवाद में अंग्रेजी भाषा के शब्दों को लेकर कोई दुराग्रह दिखाई नहीं देता, बल्कि पात्रों के बीच बोलचाल में सहजता से जो अंग्रेजी के शब्द आते हैं, उन्हें हिंदी अनुवाद में बदला नहीं गया है. यही वजह है कि अनुवाद बेहतर हो पाया है. दारू पीते हुए उपन्यास की बिंदास नायिका और उसकी दोस्त अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग करती हैं, इसके बावजूद अनुवाद में उससे कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है.

कुछ दिनों पहले मैंने वाणी प्रकाशन से प्रकाशित 2004 की नोबेल पुरस्कार विजेता लेखिका फ्रेडरिक येलनिक के उपन्यास क्लावीयरश्पीलेरिन का हिंदी अनुवाद पियानो टीचर पढ़ा. उक्त उपन्यास का हिंदी अनुवाद विदेशी भाषा साहित्य की त्रैमासिक पत्रिका सार संसार के मुख्य संपादक एवं जर्मन भाषा के जानकार अमृत मेहता ने किया था. पहली नज़र में हिंदी अनुवाद ठीकठाक लगा था. मैंने अपने इस स्तंभ में ही उस उपन्यास पर लिखा भी था. लेकिन बाद में जमशेदपुर से लेखिका विजय शर्मा ने मेरा ध्यान कुछ त्रुटियों की ओर दिलाया तो फिर मैंने उसका अंग्रेजी अनुवाद पढ़ा. उसे पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि अमृत मेहता का अनुवाद बिल्कुल ही स्तरीय नहीं था.

ट्रांसलेशन के चक्कर में अमृत मेहता ने कुछ बेहद अश्लील शब्दों का इस्तेमाल किया, जो ग़ैर ज़रूरी था. साथ ही उपन्यास में वर्णित कुछ दृश्यों को भी उन्होंने बदल डाला. अमृत मेहता ने लिखा कि नायिका बाथटब में अपने हाथ की नस काट लेती है, जबकि मूल उपन्यास में येलनिक ने लिखा है कि नायिका बाथटब में अपना यौनांग काट लेती है. अनुवाद में शब्दों के चयन की स्वतंत्रता तो अनुवादक ले सकता है, लेकिन प्रसंग और घटनाओं को बदलने की छूट वह नहीं ले सकता है. इस तरह के लापरवाह अनुवाद का नतीजा यह होता है कि भविष्य के शोधार्थियों को ग़लत संदर्भ मिलते हैं और अर्थ का अनर्थ हो जाता है. इस मामले में मनीषा तनेजा ने सावधानी बरती है और उनके द्वारा अनूदित उपन्यास बेहद पठनीय बन गया है.

दूसरा अहम उपन्यास हॉर्पर कालिंस ने प्रकाशित किया, वह है बुकर पुरस्कार प्राप्त लेखक अरविंद अडिगा का द वाइट टाइगर. प्रकाशक का दावा है कि इस उपन्यास की सिर्फ़ भारत में दो लाख प्रतियां बिक चुकी हैं. किताब के बैक कवर पर इस सूचना के प्रकाशन से हिंदी प्रकाशन जगत सकते में पड़ सकता है. हिंदी में उपन्यासों का संस्करण पांच सौ या फिर अब तो तीन सौ का ही होता है और मेरे जानते हाल के दिनों में हिंदी का कोई उपन्यास दस हज़ार भी नहीं बिका है. दो लाख प्रतियां बिकने की बात तो हिंदी में सोची भी नहीं जा सकती है. जबकि भारत में हिंदी के पाठकों की संख्या अंग्रेजी के पाठकों से कई गुना ज़्यादा है. यह एक बेहद अहम सवाल है, जिस पर हिंदी समाज को विचार करने की ज़रूरत है.

अब अरविंद अडिगा के उपन्यास द वाइट टाइगर की बात. अरविंद के इस उपन्यास का अनुवाद मनोहर नोतानी ने किया है. मनोहर पेशे से इंजीनियर हैं, फिर भी वह एक लंबे अरसे से अनुवाद का काम कर रहे हैं, लेकिन किसी उपन्यास का अनुवाद करने का यह उनका पहला अनुभव है. वाइट टाइगर में मध्य भारत के गांव में जन्मे रिक्शा चालक के बेटे बलराम की कहानी है, लेकिन जब उसे स्कूल से निकाल दिया जाता है तो वह चाय की दुकान पर सफाई एवं बर्तन धोने का काम करता और अपने भविष्य के सपने बुनता है. उसकी तक़दीर तब बदलती है, जब उसके गांव का एक अमीर जमींदार उसे अपना ड्राइवर बनाकर दिल्ली ले आता है. महानगर की चकाचौंध में बलराम की एक नए तरीक़े से शिक्षा होती है. इस उपन्यास का अनुवाद थोड़ा शास्त्रीय किस्म का है, जो पाठ को बाधित करता है. इस उपन्यास के अनुवाद के क्रम में मनोहर नोतानी ने हिंदी के खांटी शब्दों के साथ-साथ स्थानीय शब्दों का भी इस्तेमाल किया है. एक बानगी देखिए, उस रात, एक बार फिर आंगन झाड़ने का बहाना करते हुए हम चमरघेंच और उसके बेटों के नजीक जा फटके, वे लोग एक बेंच पर बिराजे बतियाते रहे. हाथ में गिलास और गिलास में चमचम दारू. इस दो वाक्य में तीन शब्द ऐसे हैं, जो बिल्कुल स्थानीय भाषा के हैं-चमरघेंच, नजीक और चमचम दारू. इस तरह के कई शब्दों का इस्तेमाल अनुवादक ने किया है, जिससे उनकी मेहनत का पता चलता है.

एक तीसरी किताब जो हाल में प्रकाशित हुई है, वह है शिक्षाविद् एवं सांसद रह चुकीं भारती राय की आत्मकथा-ये दिन, वे दिन. मूल रूप से बांग्ला में लिखी गई इस आत्मकथा का हिंदी अनुवाद सुशील गुप्ता ने किया. सुशील गुप्ता का नाम हिंदी के पाठकों के लिए जाना-पहचाना है. उन्होंने बांग्ला की कई चर्चित लेखिकाओं और लेखकों की कृतियों का अनुवाद हिंदी में किया है. भारती राय ने अपनी इस आत्मकथा में पांच पीढ़ियों की कहानी लिखी है. यह कहानी शुरू होती है उनकी परनानी शैलबाला उर्फ सुंदर मां के साथ. कथा के दूसरे पड़ाव पर हैं लेखिका की नानी मां. तीसरे पड़ाव पर लेखिका की मां से पाठकों की मुलाक़ात होती है और चौथे पड़ाव पर वह खुद हैं. किताब के पांचवें भाग में कई अहम सवाल हैं. इस किताब की प्रस्तावना वरिष्ठ लेखिका एवं पत्रकार मृणाल पांडे ने लिखी है. इस किताब से एक लंबे कालखंड का इतिहास सामने आता है. लेखिका ने पारिवारिक स्थितियों के बहाने बंगाल और देश के राजनीतिक और साहित्यिक परिदृश्य का सुरुचिपूर्ण चित्र खींचा है. हिंदी में आत्मकथा के बहाने जो एक आत्म प्रचार का दौर चल पड़ा है, यह किताब उससे पूरी तरह से अलग है. इस वजह से ही मुझे उम्मीद है कि यह किताब हिंदी के पाठकों को पसंद आएगी. अन्य भाषाओं से हिंदी में अनूदित होकर आ रही उक्त कृतियां एक उम्मीद जगाती हैं.

(लेखक आईबीएन-7 से जुड़े हैं)

feedback@chauthiduniya.com

पुस्तक अंश मुन्नी मोबाइल

प्रदीप सौरभ

चुनाव परिणामों से सब स्तब्ध थे. बुद्धिजीवी और धर्म निरपेक्ष ताक़तें सकते में थीं. वे मतदाताओं का मूड भांप नहीं पाए. सांप्रदायिक ताक़तों को हराने की उनकी सारी अवधारणाएं हवाई साबित हुईं. उनकी मान्यता थी कि गांधी का गुजरात धर्म के आधार पर नहीं बंटेगा, पर ऐसा हुआ. मोदी ने अपने चुनावी एजेंडे में साफ़ कहा था कि यह चुनाव छद्म और ढोंगी धर्मनिरपेक्षतावादियों के ख़िलाफ़ है. जनता ने उस पर मोहर लगाई. जीत तो जीत होती है. लेकिन उस जीत में दो हज़ार बेगुनाहों की लाशें दफ़न हैं.

मोदी को जीत का नशा था. हिंदू ब्रिगेड भी नशे में चूर थी. चुन-चुन कर विरोधियों को निशाना बनाया जा रहा था. मीडिया पहले निशाने पर था. आनंद भारती पर भी हमला हुआ. उन्हें कार से उतार कर पानी से नहलाया गया. पानी के प्लास्टिक पाउचों से मारा गया. फिर छोड़ दिया गया. एक बार फिर इस हमले में उन्हें भारत माता की जय बोलने के लिए मजबूर किया गया.

आनंद भारती सदमे में थे. उनमें असुरक्षा घर कर गई थी. वह रात-रात भर सोते नहीं थे. अकेले रहने पर वह दहशत से घिरे रहते. उनके दफ़्तर का माहौल भी मोदी समर्थकों से भरा था. कोई भी आकर उनको चिढ़ा जाता, आपने मोदी को हराने के लिए टनों काग़ज़ ख़राब कर दिया, लेकिन मोदी का आप कुछ बिगाड़ नहीं पाए.

चपरासी भी आनंद भारती की अनदेखी करने लगा. चाय-पानी भी लगभग उसने उनकी बंद कर दी थी. पूरे दफ़्तर ने षडयंत्र कर उनकी शिक़ायत भी दिल्ली मुख्यालय में कर दी. आरोप था कि वह कुर्सी पर पैर रख कर बैठते हैं. गाली-गलौज करते हैं. उनके रहने से दफ़्तर का माहौल ख़राब हो रहा है. इस पूरे षडयंत्र में मैनेजर भी शामिल था.

आनंद भारती इतने मायूस हो गए थे कि उन्हें फोन की घंटी भी दहला देती थी. सड़क पर चलने से भी वह डरने लगे थे. एक शून्य में चले गए थे वह. उनके मित्र दो साल अहमदाबाद में रहने के बाद भी ज़्यादा नहीं थे. दो-चार अख़बारी मित्र थे. उनमें से ही एक पत्रकार मित्र की पत्नी ने उनको ढांढस बंधाया. उन्हें लेकर वह साइकेटिक के यहां गईं. साइकेटिक को उन्होंने बताया, डाक्टर साहब, आनंद जी काल्पनिक भय से परेशान हैं. हर चीज़ उन्हें डरा रही है. साइकेटिक ने आनंद से भी बात की. सुझाव दिया, आप

लोगों से मिलें-जुलें. कोई नहीं बोलता है तो भी पहल कर उसे स्माइल दें. बात की शुरुआत करें. अपने में बंद न रहें. तरह-तरह के नुस्खे उन्होंने बताए.

उन्हें अंदर-अंदर लग रहा था कि हिंदू ब्रिगेड उन पर फिर हमला करेगी. अब तक अपने साथ हुए सारे हमलों और परेशानी की जानकारी वह अपने संपादक को दे चुके थे. संपादक ने अंततः उन्हें दिल्ली वापस बुलाने का फरमान दे दिया. वैसे भी गुजरात अब समाचारों की दुनिया से बाहर होने वाला था.

ट्रांसफर की ख़बर सुनते ही भयग्रस्त और लंबी थकान महसूस कर रहे आनंद भारती की सारी बीमारी काफूर हो गई. उनमें ऐसी चमक दिखी कि मानो उनके साथ कुछ हुआ ही न हो. आनन-फानन में उन्होंने पैकर और मूवर को बुक किया और सामान लदवाकर ट्रक अहमदाबाद से रवाना करवा दिया. ख़ुद अपनी गाड़ी लेकर दिल्ली की ओर चल पड़े. अहमदाबाद जैसे-जैसे छूट रहा था, उन्हें एक ख़ास तरह की ख़ुशी मिल रही थी. दंगों में मारे गए और राहत शिविरों में रह रहे लोग उनकी स्मृतियों के बीच से गुजर रहे थे. शिविरों में आते-जाते कई पीड़ितों से उनके संबंध हो गए थे. शिविर चलाने वाले भी उनके दोस्त बन चुके थे. सबसे विदा लेकर वह वहां से चले थे. ख़ुशी के बावजूद इन सबको छोड़कर जाने का दुःख भी उन्हें अंदर-अंदर सता रहा था.

गतांक से आगे

feedback@chauthiduniya.com

संतों का प्रशासन पर दबाव, जनता ठगी गई

डॉ. कमलकांत बुधकर

हरिद्वार के महाकुंभ में 30 मार्च 2010 को इतिहास रचा गया. जो कभी नहीं हुआ था, वह हुआ. उत्तराखंड के इस पहले महाकुंभ में परंपराएं बदल दी गईं. गत तीन शाही स्नानों के क्रम में एक और अपरंपरागत शाही स्नान जोड़ दिया गया और शाही स्नानों की संख्या चार कर दी गई. चैत्र पूर्णिमा का दिन हरिद्वार के कुंभ में सामान्य स्नान-दान का दिन हुआ करता था. इस वर्ष साधुओं के तेरह अखाड़ों की प्रतिनिधि परिषद ने कुंभ प्रशासन पर दबाव बनाया कि वे चैत्र पूर्णिमा पर भी शाही जुलूस निकालेंगे और स्नान के लिए वैसे ही हरकी पौड़ी पहुंचेंगे, जैसे अन्य तीन शाही स्नानों पर जाते हैं. इस मांग और उसके पूरे होने का नतीजा यह निकला कि नौ-दस घंटों के लिए हरकी पौड़ी के मंदिरों-देवालयों को ऐन पूर्णिमा के दिन बंद कर दिया गया और सामान्य स्नानार्थी इस बीच हरकी पौड़ी पर गंगा स्नान नहीं कर पाए.

इस घटना के और भी कई निहितार्थ हैं. मूलतः यह मांग बैरागी, उदासीन और निर्मल संप्रदायों की रही, जिसे अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष बैरागी श्रीमहंत ज्ञानदास और महामंत्री संन्यासी श्रीमहंत हरि गिरि की परस्पर गहरी मित्रता के प्रतिफल के रूप में भी देखा जा रहा है. शैवों के अतिरिक्त उक्त संप्रदायों के छह अखाड़े परंपरा से ही हरिद्वार में केवल दो शाही स्नान कर पाते थे, जबकि संन्यासियों के सात अखाड़े तीन शाही स्नान करते आए हैं. महाशिवरात्रि, चैत्र अमावस्या और मेष संक्रांति ही वे तीन प्रमुख दिन हैं, जब हरिद्वार कुंभ में शाही स्नान की परंपरा रही है. महाशिवरात्रि पर बैरागी संप्रदाय वृंदावन में स्नान करता है, वे लोग हरिद्वार से वृंदावन चले जाते हैं. उदासीनों और निर्मलों का तब तक विधिवत नगर प्रवेश और पेशवाई होती ही नहीं है. अतएव हरिद्वार में महाशिवरात्रि का पहला स्नान केवल सात शैव संन्यासी अखाड़े ही करते हैं.

दूसरा चैत्र अमावस्या और तीसरा मुख्य कुंभ पर्व का स्नान तेरहों अखाड़े क्रमवार करते हैं. तीसरा यानी 14 अप्रैल को कुंभ का मुख्य स्नान संपन्न होने के बाद ही अखाड़ों की आकाश छूती धर्मध्वजाएं ढीली कर दी जाती हैं और कुंभ के लिए एकत्र साधु-संन्यासियों की विदाई का दौर शुरू हो जाता है. बैरागियों के तीन अखाड़े अलबत्ता वैशाख पूर्णिमा पर गंगा स्नान करते आए हैं, पर उस स्नान को प्रशासन और परिषद दोनों ही वैयक्तिक मानते आए हैं, शाही स्नान नहीं.

इस परिस्थिति में बदलाव के लिए ज्ञान-हरि मैत्री ने इस बार एक और शाही स्नान की व्यूह रचना की. एक अच्छा संयोग उनके लिए यह बन गया कि वैशाख पूर्णिमा पुरुषोत्तम अथवा मलमास के दिनों में पड़ रही है. बैरागियों की ओर से तर्क दिया गया कि मलमास में मांगलिक स्नान उपयुक्त नहीं होगा. अतः उन्हें एक महीना पहले स्नान करने दिया जाए. यह बात सामान्य होती तो किसी के सामान्य गंगा स्नान में किसी और को क्या आपत्ति होती? पर प्रशासन पर दबाव बनाकर तीन की जगह चार शाही स्नान करवाए गए और जनता के अधिकारों के साथ प्रशासन एवं संतों ने मिलकर खिलवाड़ किया. यही आपत्तिजनक है. इसका जवाब न तो संतों के पास है, न शासन-प्रशासन के पास. वक़्त आने पर जनता ही इस परिस्थिति के लिए जवाब मांगेगी या ख़ुद दे देगी. आज प्रदेश में भाजपा सरकार का होना साधु-संतों के पक्ष में गया, क्योंकि इसी शासन में अखाड़ा परिषद के आगे कुंभ प्रशासन और कुंभ पुलिस साष्टांग दंडवत की मुद्रा में बने हुए हैं. परिस्थितियां कुछ ऐसी पैदा हो गईं कि अखाड़ा परिषद की पांचों उंगलियां इन दिनों घी में हैं.

इन्हीं परिस्थितियों के चलते अखाड़ों, आश्रमों की

चर्चा कुंभनगर की

तो पौ बारह है, पर उन्हें ताक़त देने वाली जनता की उपेक्षा हर विभाग कर रहा है. परिषद भयादोहन कर रही है और शासन-प्रशासन एवं पुलिस दुहे जा रहे हैं. चैत्र पूर्णिमा का शाही स्नान इसका ज्वलंत उदाहरण है, क्योंकि इसके कारण वह हो गया, जो अबसे पहले कभी नहीं हुआ था. आने वाले कुंभों में अखाड़ा परिषद तीन की जगह हमेशा चार शाही स्नानों की मांग करेगी और आने वाली सत्ता को वैसा मानने पर बाध्य होना पड़ेगा.

बहरहाल, इस पूरे घटनाक्रम में एक बात अच्छी हुई. वह यह कि संन्यासियों के अखाड़ों ने इस बार शाही कही जाने वाली शोभायात्राओं का आडंबर नहीं किया. न इस शाही स्नान में उनके आचार्य शामिल हुए और न ही महामंडलेश्वरगण. न उन्होंने बैंडबाजे बजवाए, न हाथी-घोड़े साथ लाए और न बग्घी-पालकी. छत्र-चंवर भी नहीं! यहां तक कि अखाड़ों के देवता और ध्वज-पताकाएं भी वे हरकी पौड़ी पर नहीं लाए. हर अखाड़े के चार-चार प्रमुख संत-महंत यानी कुल 28 संन्यासी जूना अखाड़ा चौक पर एकत्र हुए और पुलिस सुरक्षा में पैदल ही हरकी पौड़ी पहुंच गए.

इस प्रदर्शन का अच्छा प्रभाव जनसामान्य पर पड़ा. लोगों ने सातों संन्यासी अखाड़ों के समन्वय और परस्पर एकता को सराहा. संन्यासी अखाड़े मूलतः इस अपारंपरिक स्नान के पक्ष में नहीं थे, पर उसे शाही घोषित किए जाने के शासकीय निर्णय से उन्हें भविष्य को देखते हुए जबरन इस स्नान में भाग लेना पड़ा. सरकारी रिकॉर्ड में यह दर्ज़ करवाना उन अखाड़ों ने ज़रूरी समझा कि चैत्र पूर्णिमा स्नान में संन्यासी अखाड़े भी शामिल हुए और उसी क्रम में शामिल हुए, जो हरिद्वार के कुंभों में शाही स्नानों का होता रहा है. यह तो हो गया, पर अगर संन्यासी अखाड़े तनिक उदारता और दिखाते तो परिवर्तन की इस सुखद बयार में चंदनगंध घुल जाती. जब सातों अखाड़ों के केवल 28 संतों को ही स्नान करना था तो वे 15 मिनट का समय लेकर शेष समय जनता-स्नान को दे सकते थे. वे अपने निश्चित समय के अंतिम पंद्रह मिनटों में हरकी पौड़ी पहुंचते, स्नान करते और लौट आते. उनके बाद बैरागियों का प्रवेश समय से होता. अगर ऐसा हो जाता तो निस्संदेह जनता-स्नान के लिए अधिक समय मिल सकता था. पर ऐसा नहीं हो सका और जनता से उसकी लक्ष्यस्थली हरकी पौड़ी पर स्नान करने का अवसर छीन लिया गया.

संन्यासी अखाड़ों का समय 11 बजे था, इसलिए साढ़े नौ बजे से ही न केवल हरकी पौड़ी, बल्कि मालवीय द्वीप और अस्थिप्रवाह घाट तक खाली करा लिए गए. 28 साधु आए और जनशून्य हरकी पौड़ी पर डेढ़ घंटे तक जल-किल्लोल करते रहे. कतिपय पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी, गंगासभा के कुछ अधिकारी-कर्मचारी और मीडिया वाले इस जल-किल्लोल का आनंद लेते रहे या कहिए संत-स्नान के दर्शन का पुण्य लूटते रहे. आम जनता हरकी पौड़ी से दूर दूसरे घाटों पर डुबकी लगाती रही.

ख़ैर...., यह इतिहास तो बन गया. कुछ को गदगद कर गया और कुछ को कचोट गया. पर इस परिवर्तन से कुछ आशा जगी है. भविष्य में अगर साधु समाज और अखाड़े जनसुविधा, जनभावना और जनकल्याण के बारे में गंभीरता से सोचें तो बहुत कुछ ऐसा कर सकते हैं, जो कुंभ को युगानुकूल संतजनोचित, अनुकरणीय एवं प्रशंसनीय रूप दे सकता है. मसलन, जैसे शैवों के सात अखाड़ों ने एक साथ पैदल आकर गंगा स्नान करने का उदाहरण पेश किया, उसी तरह बैरागियों की तीनों अणियां अपने प्रतिनिधियों के साथ एक साथ स्नान करें. उदासीन अखाड़ों के प्रतिनिधि एक साथ आएं और निर्मलों के एक साथ. प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ाई भी जा सकती है. अखाड़ों के देवताओं, आचार्यों और मंडलेश्वरों को शामिल किया जा सकता है. बड़ी और ख़र्चीली शोभा यात्राओं से बचकर चार संप्रदायों की चार शाहियों को पैदल ही हरकी पौड़ी लाकर नहलाया जा सकता है. परंपरा भी रह जाएगी और जनभावनाओं का आदर भी होगा.

पर यह एक बड़ी खुशफ़हमी है. जहां रणनीति के तहत सांकेतिक और प्रतीक स्नान होते हों, वहां परंपराओं में परिवर्तन भी सुविधा और अधिक प्राप्ति के लिए किए जाते हैं. परिवर्तन रूढ़ियों को बनाए रखने के लिए हों तो उनका लाभ जनसामान्य को नहीं मिल सकता, न ही उसका भला हो सकता है. अगर रूढ़ियों में सुधार के लिए परिवर्तन हों तो वे वरेण्य होंगे. पर दुर्भाग्य से जो परिवर्तन सामने आ रहे हैं, वे रूढ़ियों को सुधारेंगे नहीं, और रूढ़ कर देंगे.

kk@budhkar.in

माना जाता है कि सोशल और डिजिटल मीडिया ने उपभोक्ता के अनुभव को मोबाइल के मामले में बदल दिया है.

टीवी ने रूप बदला

भारत में तकनीक का प्रचार-प्रसार बढ़ता जा रहा है, चाहे वह मनोरंजन के क्षेत्र का हो या विज्ञान और संचार के क्षेत्र का. देश में तकनीक के बढ़ते डिमांड को देखते हुए सैमसंग ने भारत में ग्राहकों के लिए घरेलू मनोरंजन को नए सिरे से परिभाषित करते हुए एलईडी, एलसीडी तथा प्लाज़्मा प्लेटफार्मों पर नवीनतम 3डी टीवी रेंज मार्केट में उतारने की घोषणा की है. सैमसंग फुल एचडी 3डी टेलीविज़नों की संपूर्ण रेंज भारतीय बाज़ार में उपलब्ध है. इसमें एलईडी 7000/8000 सीरीज, एलसीडी 750 सीरीज और प्लाज़्मा+7000 सीरीज शामिल है. भारत में 3डी टेलीविज़नों के लॉन्च की घोषणा करते हुए कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जुंगसू शिन ने कहा कि हम भारत में अपने ग्राहकों के लिए फुल एचडी 3डी टीवी की तरह मनोरंजन की नई श्रेणियों में पेश कर रहे हैं. कंपनी भारतीय ग्राहकों को 3डी मनोरंजन का अहसास उनके घर पर दिलाना चाहती है. सैमसंग ने 3डी ब्लू रे प्लेयर बीडी-सी6900 , ब्लू रे इंटीग्रेटेड होम थिएटर सिस्टम एचटी-सी6950 और 3डी एक्टिव ग्लासेज लांच कर 3डी इको सिस्टम तैयार करने की योजना बनाई है. एलईडी टीवी के अलावा एलसीडी टीवी, प्लाज़्मा टीवी, ब्लू-रे प्लेयर और 3डी ग्लासेज आदि की 3डी पेशकश के ज़रिए सैमसंग ने घरेलू मनोरंजन के क्षेत्र में इस वर्ष पूर्ण 3डी समाधान उपलब्ध करा रही है. अबतक सैमसंग फुल एचडी 3डी टीवी की राह में सबसे बड़ा रोड़ा कंटेंट हुआ करता था पर इस कमी को दूर करते हुए कंपनी ने समाधान निकाल लिया है. इसमें एक बटन दबाने भर से ही 2डी कंटेंट को 3डी में बदला जा सकता है. लांच किए गए रेंज में इंटरनेट टीवी की ख़ूबी भी शामिल है और ऑलशेयर विशेषता के कारण यूजर अपने टीवी को कॉम्पेटिबल मोबाइल उपकरणों से वायरलेस ढंग से कनेक्ट कर सकते हैं. सैमसंग ने नए संग्रह में बेजेल को अधिक संकरे रूप में तथा सिल्वर को ब्लैक फ्रेम में पेश किया है. सैमसंग 3डी एलईडी टेलीविज़न सैट 40 से 65 सेमी स्क्रीन साइज में उपलब्ध है.और इसकी क़ीमत 130,000 रु से लेकर 435,000 रु के बीच है. जबकि 3डी एलसीडी सीरीज 46 और 55 स्क्रीन आकार में क्रमश 129,00रु से लेकर 86,900 रु में उपलब्ध है. सैमसंग का 63 3डी प्लाज़्मा टीवी 300,000 रूपए में उपलब्ध है.

खर्राटे से आज़ादी

देखने में आता है कि लगभग हर घर में एक सदस्य खर्राटा मारने वाला अवश्य मिल जाता है. माना जाता है कि खर्राटा मारना एक समस्या है जो बिना किसी समाधान के ठीक नहीं हो सकता है. ख़ास तौर से यह तब होता है जब आप गहरी नींद में सो रहे होते हैं. लेकिन अब इस समस्या का आसान समाधान बाज़ार में उपलब्ध है. मोदी वोमेगा फार्मा इंडिया प्राईवेट लिमिटेड ने अपना पहला फ्लैगशिप प्रोडक्ट साईलेंट टीएम के नाम से बाज़ार में उतारा है. यह एक एंटी स्नोरिंग स्प्रे है जिससे खर्राटे की समस्या से निजात पाई जा सकती है. मोदी वोमेगा के चेयरमैन एंड प्रेसीडेंट यु के मोदी का कहना है कि आज के संदर्भ में देखे तो स्वास्थ्य का कांसेप्ट बदल गया है. खर्राटा लेना एक समान्य समस्या है. साईलेंट टीएम एक रिवोल्युसनरी प्रोडक्ट है यह नैचुरल इनग्रेडिएंट से बना है.

यह पहला फॉर्मल प्रोडक्ट है जिसमें मोदी वोमेगा फार्मा इंडिया प्राईवेट लिमिटेड की आधी आधी संयुक्त भागीदारी मोदी मंडीफार्मा और ओमेगा फार्मा के बीच में है. शोध से पता चला है कि खर्राटा एक समान्य प्रक्रिया है जिसमें गले में स्पंदन होता है. सांस लेने के दौरान हवा के विक्षोभ के कारण गले में अवरोध उत्पन्न होता है जिससे खर्राटे की समस्या उत्पन्न होती है. खर्राटा बहुत तेज़ और परेशान करने वाला होता है ख़ास तौर पर जब आपके बगल में कोई सो रहा हो. अक्सर इसका कारण बढ़ती उम्र, ज़्यादा वजन, स्मोकिंग और एल्कोहल हो सकते हैं. आगे चलकर यह तनाव का कारण भी बन जाता है. इस समस्या के समाधान के लिए कंपनी ने मिंट फ्लेवर में वोरल स्प्रे बनाया हैं. इसके इस्तेमाल से आप खर्राटे की समस्या से निजात पा सकते है. साईलेंट टीएम 50 एमएल की क़ीमत मार्केट में 425 रू है. इसे बेपरवाह 30 रातों तक लगातार लिया जा सकता है.

मोबाइल का नया अवतार

सोनी एरिक्सन ने कम्युनिकेशन इंटरटेनमेंट के अंर्तगत रोमांचक फैमिली फोन भारत में उतारा है. कंपनी ने अपने मनोरंजन की परंपरा को जारी रखते हुए एक्सपेरिया 10 मॉडल के रूप में पेश किया है. जनता के बीच इसकी घोषणा करने के लिए सोनी एरिक्सन की ब्रांड एंबेसडर बॉलीवुड सुपरस्टार करीना कपूर फोन के लांच के मौक़े पर आईं. अपने नए फोन के लांच के दौरान कॉरपोरेट वाइस प्रेसीडेंट और एशिया पैसीफिक क्षेत्र के प्रमुख हिरोकाजु शिजुका ने कहा कि कंपनी इस बात पर ख़ास ध्यान रख रही है कि आज के उपभोक्ता क्या चाहते हैं. माना जा रहा है कि मोबाइल फोन के मामले में सोशल और डिजिटल मीडिया ने उपभोक्ता के अनुभव को मोबाइल के मामले में बदल दिया है. इसलिए मनोरंजन संचार के तहत कंपनी मोबाइल फोन का अगला लेवल पेश कर रही है. इस मोबाइल डिवाइस में कम्युनिकेशन और इंटरटेनमेंट के मिश्रण को प्रस्तुत किया गया है. सोनी एरिक्सन के एक्सपेरिया 10 मॉडल फीचर्स काफी आकर्षक है. इसके द्वारा आसानी से आप अपने परिवार और दोस्तों के संपर्क में रह सकते है. सोनी एरिक्सन ने अपने डिज़ाइन को इस तरह से निर्मित किया है कि कम्युनिकेशन में समय और जगह जैसी बातें बाधा नहीं बनें. इस उपकरण ने संवाद को आसान बना दिया है. इसके द्वारा आप फेसबुक, ट्वीटर का प्रयोग कर सकते हैं, और फोटो, ईमेल, टेक्स्ट आदि का आदान प्रदान एक साथ कर सकते हैं. इसका मीडियास्केप काफी एडवांस क्वालिटी का है, जिसके द्वारा आप अपना पसंदीदा म्यूज़िक, फोटो, वीडियो, अपने दोस्तों से या कलाकार से ले सकते हैं.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

मोबाइल फीवर को नया ट्रीटमेंट

मोबाइल कंपनियां लोगों में उच्च क्वालिटी के कैमरे वाले मोबाइल के प्रति जागते रुझान को देखते हुए अपने ग्राहकों को कुछ नया देने की कोशिश में लगी रहती है. फोटोग्राफी के शौक़ीन लोगों के लिए अब हर जगह कैमरा लेकर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि मोबाइल कंपनियां मोबाइल में ही अपने ग्राहकों को कई तरह की सुविधाएं दे रही है. इसी बात को ध्यान में रखते हुए स्पाइस मोबाईल ने एक नया फोन एस 1200 के नाम से मार्केट में उतारा है. स्पाइस की एस 1200 मोबाइल में उच्च क्वालिटी का कैमरा मोबाइल है. कंपनी के डायरेक्टर एंड सीईओ कुनाल कुमार आहुजा ने इस मौक़े पर कहा कि फोटोग्राफी एक कला है और यह एक क्रिएटिव काम है, जिसमें साथ देने के लिए कंपनी का नया फोन बिल्कुल फिट है. एस 1200 मोबाइल फोन इसका उदाहरण है. इस फोन द्वारा आप एक साथ दोहरी सुविधाओं का फ़ायदा उठा सकते है. इसे लांच करने के लिए कंपनी की नई ब्रांड एंबेसडर अभिनेत्री सोनम कपूर ने बताया कि स्पाइस तेज़ी से उभरता हुआ विश्वसनीय ब्रांड है. इस मोबाइल में ख़ूबियों का भंडार है. 12 मेगापिक्सल वाला कैमरा उच्चतम क्वालिटी की तस्वीरें निकालता है, इसमें 3 ऑप्टिकल ज़ूम है और 9 तक डिजिटल ज़ूम करने का विकल्प दिया गया है. अंधेरे में भी अच्छी फोटो खींचने के लिए इसमें जेनन फ्लैश दिया गया है. साथ ही मल्टीपल फेस डिटेक्सन, स्माइल शटर, ऑटो फोकस, एंटी शेक ऑप्शन और एडवांस्ड 24 प्रिसेट कैप्चर मोड व टेक्सट कैप्चर मोड दिया गया है. इसके अलावा स्टीरियो ब्लू टूथ, 32 जीबी एक्सपेंडेबल मेमोरी और टीवी आउटपुट भी दिए गए हैं. कंपनी ने ग्राहकों के लिए एस 1200 मोबाइल की क़ीमत 14500 रुपये तक की है.

यह माउस है ख़ास

यह युग कंप्यूटर का है. काम चाहे जैसा भी हो मनोरंजन, प्रबंधन या फिर दफ्तर का कोई काम. कंप्यूटर हर क्षेत्र में अपना व्यापक योगदान दे रहा है. ऐसे में शारीरिक रूप से अपंग या असामान्य शारीरिक सरंचना वाले लोगों के लिए कठिनाई हो सकती है. कुछ ऐसे ही लोगों का ख्याल करके विश्व की प्रमुख उत्पादक कंपनी रोजर ने पहला लेफ्ट हैंडर गेमिंग माउस डिज़ाइन किया है. ख़ासतौर से बायें हाथ का इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए कंपनी ने पहला गेमिंग ग्रेड माउस बनाया है. कंपनी ने इसे लेफ्ट हैंडर कम्युनिटी के डिमांड पर बनाया है.

लेफ्ट हैन्डर गेम लवर्स के लिए बेशक लंबे इंतज़ार के बाद पर एक बढ़िया विकल्प लाकर रोजर ने गेमिंग ग्रेड माउस का डिज़ाइन तैयार किया है. इसकी ख़ास बात यह है कि अन्य इस तरह के उपकरणों से अलग है. ज़्यादा देर तक खेलने के लिए यह लेफ्ट हैंड वालों के लिए लिए काफी आरामदेह है.

कंपनी के प्रेसीडेंट राज़ेग्यु का कहना है कि इस संदर्भ में हमारे बहुत से फैन का फीडबैक हमें मिला. पहले बहुत से गेमर इसे नहीं जानते थे, पर मीडिया के माध्यम से लोग इसे जानने लगे हैं. इस माउस के बारे में एक लेफ्टहैंडर गेमर साउथपाव का कहना है कि सच में मै बहुत ही उत्तेजित हूं इस बात को लेकर कि माउस पूरी तरह से मेरे हाथों में फिट बैठेगा. यूजर्स के नाते इस तरह के मेल, ज़ाहिर है कि कंपनी को ऐसी ही अन्य चीज़ें बनाने के लिए प्रेरित भी करेंगी. बहरहाल, इस लेफ्टहैंड एडिशन माउस की क़ीमत कंपनी ने 60 डॉलर तय की है. यह विश्व के सभी कोनों में उपलब्ध है.

विज्ञापन हेतु संपर्क करें : email : advt@chauthiduniya.com

भारतीय टीम में चार ऐसे खिलाड़ी हैं, जो फ़िलहाल चोटिल हैं या चोट से उबरने की कोशिश में हैं.

भारतीय खेलों पर डोपिंग का साया

पहले भारोत्तोलन और अब कबड्डी. यह डोपिंग है कि भारत में खेलों का पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा. व्यक्तिगत स्पर्द्धा वाले खेलों के किसी भी बड़े टूर्नामेंट से पहले जांच परीक्षणों में भारतीय खिलाड़ियों के पकड़े जाने की ख़बरें अब आम बनती जा रही हैं. संबद्ध बोर्ड या स्पोर्ट्स एसोसिएशन दोषी खिलाड़ियों को साल-दो साल या जीवन भर के लिए प्रतिबंधित कर अपने कर्तव्यों की खानापूर्ति कर लेते हैं. इसकी चिंता किसी को नहीं है कि ऐसी ख़बरों से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा को कितनी ठेस पहुंचती है.

पिछले 27 मार्च को भारतीय भारोत्तोलन महासंघ ने एक साथ तीन भारोत्तोलकों को आजीवन प्रतिबंधित करने की घोषणा की. विक्की बत्ता, जी दामोदरन और राजेश कुमार को इससे पहले भी नशीली दवाओं के इस्तेमाल का आरोपी पाया गया था. उन्हें पहले भी दंडित किया गया था, लेकिन वे अपनी आदतों से बाज नहीं आए और संघ ने उन पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया. इनमें विक्की बत्ता 2006 के राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक विजेता रहे हैं, जबकि दामोदरन और कुमार सेना से जुड़े हैं.

इसके दो दिन बाद ही मेडिकल एंड एंटी डोपिंग कमिटी फॉर वर्ल्ड कप कबड्डी ने एक साथ 13 खिलाड़ियों को अगले आदेश तक हर राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में भागीदारी से वंचित करने का निर्देश जारी किया. 3-12 अप्रैल के बीच पंजाब के विभिन्न हिस्सों में आयोजित हो रही विश्व कप कबड्डी प्रतियोगिता से पहले 29 खिलाड़ियों का परीक्षण किया गया था. इनमें से 13 खिलाड़ियों के नमूने संदेहास्पद पाए जाने के बाद कमिटी ने इनके ख़िलाफ़ आदेश जारी कर दिया.

अभी इसकी आग ठंडी भी नहीं हुई थी कि चार भारोत्तोलकों के नमूने पॉजिटिव पाए जाने की खबर आई. 21 से 24 फरवरी के बीच उदयपुर में आयोजित हुई राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप के दौरान इनका परीक्षण किया गया था. इन चारों यानी प्रदीप शर्मा, भगत सिंह, गुरप्रीत सिंह और परमजीत कौर पर दो साल तक का प्रतिबंध लगाया जा सकता है. इनमें से भगत सिंह को आगामी राष्ट्रमंडल खेलों के लिए भारतीय टीम में शामिल किए जाने की संभावना थी, लेकिन अब उन्हें इस प्रतियोगिता में भागीदारी से वंचित होना पड़ सकता है.

खिलाड़ियों द्वारा प्रतिबंधित दवाओं के सेवन के आरोप नए नहीं हैं. पहले भी ऐसी खबरें आती रही हैं. चिंता की बात तो यह है कि पिछले कुछ सालों से इनमें लगातार तेजी आई है, लेकिन अधिकारी हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं. उनकी तंद्रा तभी टूटती है, जब खिलाड़ी पकड़े जाते हैं और हल्ला-हंगामा होता है. इनमें से अधिकतर मामलों में देखा गया है कि खिलाड़ी अज्ञानतावश प्रतिबंधित दवाओं का इस्तेमाल कर लेते हैं. कई बार ऐसी खबरें भी आई हैं, जिनमें कहा गया कि प्रशिक्षक और खेल संघों के अधिकारी भी खिलाड़ियों को प्रतिबंधित दवाओं के सेवन के लिए प्रोत्साहित करते हैं. 2010 में जबकि भारत राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी के लिए तैयारियों में जुटा है, शायद वह समय आ चुका है कि डोपिंग के खतरे से बचाव के लिए देश में एक शीर्ष निकाय का गठन किया जाए, जो दोषी खिलाड़ियों पर नज़र रखने के अलावा युवा खिलाड़ियों का सही मार्गदर्शन कर सके.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले फुटबालर बने मेस्सी

अर्जेंटीना के फुटबाल खिलाड़ी लियोनेल मेस्सी को मिला एक और खिताब. मैदान पर अपनी तेज़ी और फुर्ती से विपक्षी टीमों की नाक में दम करने वाले मेस्सी अब दुनिया में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले फुटबालर बन गए हैं. फ्रांस की मशहूर पत्रिका फुटबाल फ्रांस ने वर्ष 2009 में खिलाड़ियों की कमाई की सूची जारी की है और 4.4 करोड़ डॉलर की कमाई के साथ मेस्सी को इसमें पहला स्थान मिला है. उन्होंने इंग्लैंड के स्टार फुटबाल खिलाड़ी डेविड बेकहम को पीछे छोड़ यह उपलब्धि हासिल की है. वेतन एवं प्रायोजन से 4.05 करोड़ डॉलर की कमाई कर बेकहम अभी भी इस सूची में दूसरे स्थान पर हैं, जबकि स्पेन के रियल मैड्रिड क्लब के लिए खेलने वाले क्रिस्टियानो रोनाल्डो तीसरे नंबर पर हैं.

केवल 22 साल के मेस्सी को फुटबाल जगत का नया सितारा माना जाता है. उन्हें अर्जेंटीना के महान फुटबालर डिएगो माराडोना के उत्तराधिकारी का दर्ज़ा हासिल है और ख़ुद माराडोना भी उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित कर चुके हैं. 2004-05 के सत्र में बार्सिलोना के साथ क्लब करियर की शुरुआत करने वाले मेस्सी अपने क्लब के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं. यही नहीं, सबसे कम उम्र में गोल करने का रिकॉर्ड भी उनके नाम दर्ज़ है. फुटबाल की दुनिया का शायद ही कोई ऐसा सम्मान हो, जो उनके खाते में दर्ज़ न हो. क्लब बार्सिलोना के लिए लीग स्तर पर शानदार प्रदर्शन और 2005 में फीफा वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप में सबसे ज़्यादा गोल करने की उपलब्धि हासिल करने के बाद उसी साल उन्हें अर्जेंटीना की सीनियर राष्ट्रीय टीम में शामिल किया गया. 2006 के फीफा वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना टीम का प्रतिनिधित्व कर ऐसा करने वाले वह सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए. 2008 ओलंपिक में अर्जेंटीना ने स्वर्ण पदक जीता तो इसमें भी उनकी अहम भूमिका रही.

केवल 22 साल के मेस्सी को फुटबाल जगत का नया सितारा माना जाता है. उन्हें अर्जेंटीना के महान फुटबालर डिएगो माराडोना के उत्तराधिकारी का दर्जा हासिल है और ख़ुद माराडोना उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित कर चुके हैं.

इतनी छोटी उम्र में ही मेस्सी को फुटबॉल इतिहास के महानतम खिलाड़ियों की श्रेणी में गिना जाने लगा है तो कार्लो तावेज जैसे लोग उन्हें मैदान पर अविश्वसनीय मानते हैं. उपलब्धियों और अवार्ड्स की बढ़ती संख्या के बीच उनकी कमाई भी आसमान छूने लगी है, लेकिन खुद मेस्सी का मानना है कि वह पैसे के लिए फुटबाल नहीं खेलते, खेल के प्रति उनका लगाव इसका सबसे बड़ा कारण है. एक पेशेवर खिलाड़ी के रूप में उन्हें सबसे ज्यादा ख़ुशी तब होती है, जब टीम जीतती है. मैदान पर अपने खेल से दर्शकों और प्रशंसकों का दिल जीतने के बाद मेस्सी अब कमाई के भी नए कीर्तिमान बना रहे हैं. यदि फिटनेस समस्याएं ज्यादा परेशान न करें, तो वर्ष 2009 में फीफा फुटबालर ऑफ द इयर घोषित किया गया यह खिलाड़ी फुटबाल के साथ बाज़ार की दुनिया में भी लंबे समय तक छाया रह सकता है.

अनफिट टीम और वर्ल्ड कप ड्रीम

क्रिकेट के मैदान पर चारो ओर फिलहाल आईपीएल का शोर है. टूर्नामेंट अपने दूसरे दौर में पहुंच चुका है, लेकिन क्रिकेट प्रशंसकों की निगाहें कहीं और भी टिकी हैं. उन्हें इंतजार है अप्रैल में शुरू हो रहे टी-20 वर्ल्ड कप का. 30 अप्रैल से वेस्टइंडीज में एक बार फिर यह टूर्नामेंट खेला जाना है और चयन समिति ने इसके लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी है. लेकिन हैरत की बात है कि इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता के लिए चुनी गई टीम में कई ऐसे खिलाड़ियों को शामिल किया गया है, जिनकी फिटनेस को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं.

टीम में कम से कम चार ऐसे खिलाड़ी हैं, जो फ़िलहाल या तो चोटिल हैं या चोट से उबरने की कोशिश में हैं. सलामी बल्लेबाज गौतम गंभीर, युसुफ पठान, तेज़ गेंदबाज आशीष नेहरा और कप्तान महेंद्र सिंह धोनी चोटों के शिकार हैं. आईपीएल में अलग-अलग टीमों के सदस्य इन खिलाड़ियों को इन्हीं चोटों की वजह से कई मुक़ाबलों से बाहर भी रहना पड़ा है. ऐसे में दावे के साथ यह कहना खासा मुश्किल है कि वे विश्व कप से पहले पूरी तह ठीक हो जाएंगे.

लेकिन चयन समिति के अध्यक्ष के श्रीकांत हर जगह यही दावे करते फिर रहे हैं. उनका मानना है कि चुनी गई टीम सर्वश्रेष्ठ है और सभी खिलाड़ियों को फिटनेस सर्टिफिकेट देखने के बाद ही चुना गया है. लेकिन क्या श्रीकांत को यह नहीं पता कि आशीष नेहरा चोट के चलते आईपीएल-3 में अब तक एक मुकाबला भी नहीं खेल पाए हैं? चेन्नई सुपरकिंग्स टीम के ब्रांड एंबेसडर बने श्रीकांत को इतना भी नहीं पता कि उनकी टीम के कप्तान धोनी इसी चोट की वजह से तीन मुकाबलों में टीम से बाहर रहने को मजबूर हुए. जबकि गौतम गंभीर को चोट से उबरने के लिए नेहरा के साथ श्रीलंका तक की यात्रा करनी पड़ी. युसुफ पठान की चोट ज़्यादा गंभीर नहीं है, लेकिन उन्हें आराम की सख्त ज़रूरत है. पर आईपीएल में उनकी टीम राजस्थान रॉयल्स की बल्लेबाज़ी उन्हीं पर आश्रित है और वह चोट के बावजूद खेलने को मजबूर हैं.

2009 में खेला गया दूसरा टी-20 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में भी ऐसा ही हुआ था. टीम इंडिया अपना खिताब बरक़रार रखने के इरादे से इंग्लैंड की सरजमीं पर पहुंची थी, लेकिन टूर्नामेंट जीतने की बात तो दूर, भारतीय टीम सेमीफाइनल में भी जगह नहीं बना पाई. इतना ही नहीं, उसका प्रदर्शन इतना ख़राब रहा कि आयरलैंड और बांग्लादेश जैसी कमज़ोर टीमों को छोड़ दें तो किसी भी अन्य टीम के ख़िलाफ़ जीत उससे दूर ही रही. टूर्नामेंट ख़त्म होने के बाद यही बताया गया कि फिटनेस समस्याओं से जूझ रहे खिलाड़ियों को चुने जाने से टीम की संभावनाओं को झटका लगा. यह काफी हद तक सही भी है, क्योंकि वीरेंद्र सहवाग और ज़हीर ख़ान आईपीएल के दौरान ही चोटिल थे, यह बात चयनकर्ता भी जानते थे, फिर भी उन्हें टीम में चुन लिया गया था. सहवाग बिना कोई मैच खेले ही वापस लौट आए, जबकि ज़हीर अपनी खोई लय हासिल करने में कामयाब नहीं रहे. टीम के इस प्रदर्शन को देखते हुए यह उम्मीद बंधी कि अगली बार से चोटिल खिलाड़ियों को टीम में नहीं चुना जाएगा. इसमें कोई संदेह नहीं कि उक्त चारों खिलाड़ी भारतीय टीम के लिए मैच विनर रहे हैं और आगे भी ऐसा करने की क्षमता रखते हैं, लेकिन उसके लिए फिट होना ज़रूरी है. चयनकर्ताओं को कठघरे में खड़ा करना इसलिए लाज़िमी है, क्योंकि उनके पास दूसरे विकल्प मौजूद थे. वे चाहते तो रॉबिन उथप्पा, मनीष पांडे, सौरभ तिवारी, इरफान पठान या सुदीप त्यागी जैसे युवाओं को मौक़ा मिल सकता था, लेकिन उन्होंने एक बार फिर अनफिट खिलाड़ियों के हाथों में टीम इंडिया की तकदीर सौंप कर अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर ली. डर इस बात का है कि चोटिल खिलाड़ियों की इस फौज से भारतीय टीम के विश्व कप जीतने का सपना कहीं मृग मरीचिका बनकर न रह जाए.

COACHING BY EXPERTS
PACIFIC SPORTS COMPLEX
MEMBERSHIP OPEN
Offers World Class Facilities in
Olympic Size Swimming Pool (50x21 m)
Taekwondo
Table Tennis
Ice Hokey
Yoga
Dance & Music
Lajpat Nagar, Near L.S.R., Opp. G.K .- I Petrol Pump New Delhi
Call : 64520554, 64520555, 26452747/48, 9911138192

Postal Regn. No. DL/ND-11/6139/2009-11, RNI No. 45843/86

चौथी दुनिया

दिल्ली, 12 अप्रैल–18 अप्रैल 2010

अनुराग बासु के निर्देशन में राकेश रोशन द्वारा निर्मित फ़िल्म में बारबरा रितिक के अपोजिट मुख्य भूमिका में हैं.

दिल की धनी है दिया मिर्ज़ा

बी स से अधिक फ़िल्मों में काम करने के बाद भी दिया मिर्ज़ा की स्थिति बॉलीवुड में उतनी मज़बूत नहीं हो पाई, जितनी उन्हें उम्मीद थी. उनकी हाल में रिलीज़ हुई ताज़ा फ़िल्म अरशद वारसी के साथ *हम तुम और घोस्ट* है. दिया सिर्फ़ पर्दे पर और चेहरे से ही नहीं, बल्कि दिल की भी अच्छी हैं. फ़िल्मों से वक़्त मिलते ही उनके क़दम चल पड़ते हैं समाजसेवा की ओर. वह कैंसर पेशेंट्स एड एसोसिएशन, स्पास्ट्रिक्स सोसायटी ऑफ इंडिया, क्राई, पेटा फीमेल फीटोसाइड की सुरक्षा, एचआईवी जागरूकता अभियान आदि में शामिल रही हैं. इसके अलावा एक रेडियो चैनल द्वारा बच्चों के लिए किताबें इकट्ठा करने का अभियान बुक देके देखो में भी वह सक्रिय दिखती हैं. दिया मिर्ज़ा सामाजिक मुद्दों पर लिखकर जागरूकता फैलाने में भी रुचि रखती हैं. किताबें पढ़ने, पेंटिंग करने, मिट्टी की मूरत गढ़ने, घोड़ों की रेस लगाने और थिएटर में भी उनकी बहुत दिलचस्पी है. उन्होंने कई भाषाओं में महारत हासिल की है, जैसे-तेलुगु, उर्दू, बांग्ला, हिंदी और अंग्रेजी. उनके पिता फ्रैंक हैंडरिक जर्मनी के इंटीरियर डिज़ाइनर थे और उनकी मां दीपा बंगाली हैं, इसलिए उनके स्वभाव में दोनों की सांस्कृतिक छाप दिखती है. हालांकि छह वर्ष की उम्र में उनके माता-पिता अलग हो गए थे और उनकी मां ने दूसरी शादी अहमद मिर्ज़ा से कर ली. यहीं से उनका नाम दिया हैंडरिक से दिया मिर्ज़ा हो गया. अपने जीवन की बाल्यावस्था में हुई इतनी अप्रिय घटनाओं की वजह से ही उनका आत्मविश्वास कमज़ोर पड़ गया, जो उनके काम में स्क्रीन पर भी नज़र आता है.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

बारबरा की शैतानी

का इट्स की बारबरा मोरी दक्षिण अमेरिका के ओरियंटल रिपब्लिक ऑफ उरुग्वे में जन्मी. वहां कुछ वर्ष बिताने के बाद यह जापान और फिर मेक्सिको में बस गईं. जानकर आश्चर्य होगा कि यह अंतरराष्ट्रीय अदाकारा चौदह वर्ष की आयु में वेट्रेस यानी नौकरानी का काम करती थीं. इसी दौरान फैशन डिज़ाइनर मार्कोस टोलेडो की नज़र इन पर पड़ी और उन्होंने बारबरा को मॉडलिंग करने का प्रस्ताव दिया. कुछ मॉडलिंग असाइनमेंट्स पूरे करके इन्होंने एक्टिंग में विधिवत शिक्षा ग्रहण की. इसके बाद लैटिन अमेरिका के कई टेलीविज़न सीरियलों के लिए काम करती रहीं. इन्होंने लगभग दस फ़िल्मों में काम किया. गुमनामी से ख्याति तक का इनका सफर बेहद कठिन रहा, पर अब यह अपने जीवन के हर पल को बेहद ख़ुशी के साथ जीती हैं. अनुराग बासु के निर्देशन में राकेश रोशन द्वारा निर्मित फ़िल्म में बारबरा रितिक के विपरीत मुख्य भूमिका में हैं.

फ़िल्म के सेट पर बारबरा ने ख़ूब मौजमस्ती की और सह कलाकारों से काफी घुलमिल गईं. फ़िल्म के एक दृश्य में बारबरा को रितिक को एक चांटा मारना था. पहले ही टेक में यह दृश्य ओके हो गया था, पर निर्देशक अनुराग बासु उस चांटे से पहले के संवाद के सीन को एक बार और शूट करना चाह रहे थे. जैसे ही बारबरा को इसका पता चला तो वह तुरंत ही अनुराग बासु के पास गईं और बोलीं कि चांटे वाले सीन को भी दोबारा शूट करो. वह रितिक के साथ शैतानी के मूड में थी. अनुराग ने रितिक को बताया कि पूरा सीन दोबारा शूट करना है. जब बारबरा ने चांटा मारा तो रितिक ने भी पलट कर उन्हें चपत लगा दी. फिर क्या था, दोनों एक-दूसरे के पीछे चूहे-बिल्ली की तरह भागने लगे और पूरे सेट पर जो मस्ती-धमाल हुआ, उसका लुत्फ सबने मिलकर उठाया.

फिल्म और किताबें समाज का आईना हैं : कंगना

कंगना रानाउत का नाम उन गिनी-चुनी अभिनेत्रियों में आता है, जिन्हें पहली ही फ़िल्म के लिए कई अवार्ड मिले. उनके लिए आठ प्रतिष्ठित अवार्ड मिलना इसलिए भी ख़ास है, क्योंकि इस इंडस्ट्री में उनका कोई गॉडफादर नहीं है. उड़ती हुई अफ़वाहों और ग़लतफहमियों को दरकिनार करते हुए उन्होंने निजी मसलों पर खुलकर बातचीत की.

यह दौर स्टार पुत्र-पुत्रियों के वर्चस्व का है, इंडस्ट्री में कोई बैकग्राउंड न होने के बावजूद आपने खुद को कैसे स्थापित किया?

मेरा बॉलीवुड में आना किसी ठोस निर्णय के तहत नहीं हुआ. मैं मुंबई में थिएटर एवं मॉडलिंग असाइनमेंट कर रही थी. इस दौरान किसी कॉफी शॉप में मुझे अनुराग बासु ने देखा और फ़िल्म गैंगस्टर के लिए चल रहे ऑडिशन में भाग लेने की सलाह दी. मैंने ऑडिशन दिया और मुझे फ़िल्म मिल गई. रिलीज़ के बाद फ़िल्म हिट भी हुई और अब मैं इस मुक़ाम पर पहुंच गई हूं.

आपने हिंदी माध्यम में अपनी पढ़ाई पूरी की. दूसरे यह कि आप छोटे शहर से हैं. ज़ाहिर है, इसका कुछ असर आपके करियर पर भी पड़ा होगा.

मुझे लगता है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री अभी भी हिंदी भाषा पर टिकी है. इसलिए मुझे कोई ख़ास कठिनाई नहीं हुई. हालांकि अंग्रेजी भाषा विश्वस्तरीय है और उस पैमाने पर अपनी पहचान बनाने के लिए इसका ज्ञान होना आवश्यक है, पर अपनी भाषा का सम्मान तो करना ही चाहिए और इसका मूल कभी नहीं भूलना चाहिए.

अपने काम के अलावा और क्या करना पसंद है?

मुझे किताबें पढ़ने का बेहद शौक़ है, ख़ासकर प्रतिष्ठित लोगों की आत्मकथाएं. इनमें ओबामा, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथाएं मेरी प्रिय किताबें हैं. इसके अलावा खाना पकाने में भी मेरी बहुत रुचि है. कभी-कभी खाना पकाने से मेरा तनाव दूर होता है. मैं चिकन करी बहुत स्वादिष्ट बना लेती हूं.

आमतौर पर लोग उसके बारे में जरूर जानना चाहते हैं, जो उनके क्षेत्र से जुड़े हों. आपने जितने नाम गिनाए, वे सभी राजनेता हैं. क्या राजनीति से कोई लगाव है?

बिल्कुल नहीं, मेरा राजनीति से कोई वास्ता नहीं है. मुझे अध्यात्म और स्वयं की खोज करने में दिलचस्पी है, क्योंकि कई गुण हमारे अंदर छिपे होते हैं, जिनके बारे में हमें पता नहीं होता है और आत्ममंथन द्वारा उसे पता लगाने से हमारे जीवन में नया सवेरा आता है. इन सभी ने स्वयं की खोज की और काफी कुछ पा लिया, जो उनके लालन-पालन और पैदायशी क़िस्मत से नहीं मिल सका था. गांधी जी न केवल राजनेता थे, बल्कि खासे आध्यात्मिक भी थे. उनके अलावा स्वामी विवेकानंद के जीवन से मैं बहुत प्रेरित हूं. उनकी लिखी किताबों में भी अध्यात्म का समावेश है.

पर आज के दौर के लिए गांधी और विवेकानंद के विचार पुरातन और आउटडेटेड हो चुके हैं.

मैं ऐसा नहीं मानती. दोनों का जीवन प्रेरणा से भरपूर है. किसी भी दौर में सफलता पाने के लिए युवाओं को उनके जीवन दर्शन का पाठ ज़रूर पढ़ना चाहिए. इससे भटकाव की स्थिति कम हो जाती है. उनकी सीख वक़्त की गुलाम नहीं है.

क्या आपको ऐसा लगता है कि फ़िल्म और किताबों के प्रति लोगों का नज़रिया नकारात्मक हो गया है?

किताबें और फ़िल्म दोनों ही समाज का आईना हैं. लोगों तक इनके पहुंचने का माध्यम बदल गया है. काग़ज़ की किताबों की जगह अब ई-बुक्स, ऑडियो बुक्स आदि ने ले ली है. इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री भी मंदी के दौर में घाटे में नहीं रही. साल भर में फ़िल्में बनने का अनुपात पहले से बढ़ गया है. हां, फ्लॉप और हिट फ़िल्मों का अनुपात ज़रूर गड़बड़ा गया है, पर इसकी वजह समाज में हो रहे बदलाव भी हो सकते हैं. भारतीय समाज एक ऐसे दौर से गुज़र रहा है, जिसमें संभावनाएं ज़्यादा हैं. दर्शक बंटे हुए हैं, इसलिए सभी फ़िल्मों का सभी वर्गों में हिट और फ्लॉप होना बहुत ज़्यादा संभव नहीं है.

आपकी फिटनेस का राज़ क्या है? क्या आप भी बिपाशा और शिल्पा शेट्टी की तरह आम लड़कियों को फिट बनाने के लिए डीवीडी लांच करने की सोच रही हैं?

नियमित योग के साथ बैलेंस डाइट लेकर मैं खुद को फिट रखती हूं, लेकिन वक़्त की कमी के कारण इस वक़्त ऐसे किसी प्लान पर काम नहीं कर रही हूं. फ़िलहाल मैं सिर्फ फ़िल्मों के लिए काम कर रही हूं.

रीतिका सोनाली
ritika@chauthiduniya.com

फिल्म रिव्यू

वेल डन अब्बा

अफ़सरशाही और घूस की परंपरा को दिखाते हुए ग्रामीण पृष्ठभूमि पर बनी फ़िल्म वेल डन अब्बा असल में देश की सरकारी संरचना पर व्यंग्य है. मुख्य किरदार का रोल निभाती हुई मिनीषा देश के हर ग़रीब पिता का सपना हक़ीक़त में खड़ा कर देती हैं, जो समाज की चार बातें सुनकर भी बेटी को पढ़ा-लिखा रहा है और उस पर भरोसा करता है. आंध्र प्रदेश के एक गांव चिकटपल्ली, जहां पानी की किल्लत है, वहां बोमन ईरानी अपनी इकलौती बेटी को अपने हमशक्ल भाई एवं उसकी पत्नी के पास छोड़ कर पैसे कमाने के लिए मुंबई में एक बड़े अधिकारी के यहां ड्राइवर का काम करता है, पर अपने भाई की चिट्ठी आने पर कि उसकी बेटी मुस्कान की शादी कर देनी चाहिए, वह एक महीने की छुट्टी लेकर गांव चला जाता है. वहां पहुंचकर वह बेटी की शादी के लिए लड़का खोजता है, मगर दहेज की वजह से उसका रिश्ता तय नहीं हो पाता है. पानी की समस्या ख़त्म करने और बेटी के लिए बढ़िया वर खोजने के लिए वह कई पचड़ों में पड़ता है और हारकर उसे बग़ावत पर उतरना पड़ता है. एक महिला के साक्षर होने और इसके ठीक विपरीत समाज के पुरुष वर्ग द्वारा उसे कोई भी पद भीख में दे देने की तुलनात्मक प्रस्तुति की गई है. सरकारी योजनाओं और उनके कार्यान्वित होने में शासन-प्रशासन की भूमिका पर रोशनी डाली गई है. भ्रष्टाचारी तंत्र को अंगूठा दिखाते हुए मुस्कान अली (मिनीषा लांबा), उसके ड्राइवर अब्बा अरमान अली (बोमन ईरानी) और दोस्त आरिफ अली (समीर दत्तानी) जनता की ताक़त को सिद्ध करते हैं. रामोजी फ़िल्म सिटी में शूट की गई पूरी फ़िल्म में ग्लैमर का कहीं कोई तड़का नहीं है. फ़िल्म का पहला भाग धीरे-धीरे खिसकता हुआ बोरियत की दिशा में ले जाता है. हालांकि दूसरे भाग में फ़िल्म को दिया गया ट्रीटमेंट मनोरंजक और अच्छा है. फ़िल्म की शुरुआत में दिए कास्ट की क्रेडिट टाइटल्स की प्रस्तुति बेहद सुंदरता से की गई है. ऐसा लगता है, मानों डायरी के पन्नों के फटे हुए अंश, जिन पर किसी व्यक्ति के संपूर्ण जीवन में मिले किरदारों का परिचय हो. इसके साथ बजता संगीत, पानी को तरसते चेहरे... बहुत उपयुक्त लगता है. फ़िल्म के बीच में भी इन्हीं बोलों पर संगीत चलता रहता है, जो सीन के साथ बिल्कुल फिट बैठता है. बहुत सारे ग्लैमरस रोल अदा करने के बाद मिनिषा एक ग्रामीण लड़की के किरदार में भी अच्छी लगी हैं. डबल रोल में बोमन ईरानी ने दगाबाज भाई का किरदार बख़ूबी से निभाया है. आरिफ अली का किरदार निभाते हुए समीर दत्तानी ने भी बढ़िया ऐक्टिंग की है.

एक बेहतरीन पटकथा पर बनी यह फ़िल्म समाज द्वारा बनाई गई परंपराओं पर चोट करती है. लेकिन इतने स्ट्रांग मैसेज वाली साधारण नॉन-ग्लैमरस फ़िल्म को आम दर्शक कितना पसंद करेंगे, यह कहना मुश्किल है.

निर्देशन : श्याम बेनेगल
संगीत निर्देशन : शांतनु मोइत्रा
पटकथा: श्याम बेनेगल
गीत : इला अरुण, स्वानंद किरकिरे, अशोक मिश्रा
कलाकार: बोमन ईरानी, इला अरुण, मिनीषा लांबा, रवि किशन, सोनाली कुलकर्णी, समीर दत्तानी, यशपाल शर्मा

चौथी दुनिया

बिहार झारखंड

दिल्ली, 12 अप्रैल-18 अप्रैल 2010

www.chauthiduniya.com

भाजपा में भूचाल

दरअसल संकट मिजाज के अंतर से पैदा हो रहा है. संघर्ष और सत्ता का मिजाज अलग-अलग होता है. भाजपा से अपेक्षा थी वह इसे ईमानदारी से समझते हुए सामंजस्य बिठाने में सफल रहेगी, लेकिन सत्ता के रोग के कारण गुटों में बंटी भाजपा इस काम में फेल हो गई और पूरी पार्टी बेहद लाचार व बेबस नज़र आती है.

सरोज सिंह

इस साल चुनावी अग्निपरीक्षा से गुजरने वाली भाजपा की तैयारियों पर ग्रहण लगने का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है. किशनगंज में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शाखा खोलने के मसले ने भाजपा में भूचाल ला दिया है. पटना की सड़कों पर जब इसका विरोध करने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र उतरे तो पुलिस के डंडों ने यह संकेत दिया कि नीतीश सरकार अपने क़दम पीछे नहीं खींचेगी. सत्ता में भागीदार भाजपा के लिए यह धर्मसंकट की स्थिति है, क्योंकि जिस राजनीतिक कुल से वह नजदीक है, उसी से विद्यार्थी परिषद का भी रिश्ता है. मौजूदा सरकार के कई मंत्री विद्यार्थी परिषद से आगे आए हैं. यही वजह है कि कुछ भाजपाई खुलकर तो कुछ दबी जुबान से सरकार के फ़ैसले का विरोध कर रहे हैं. विधानमंडल में भी भाजपा के अंदर चल रही दो धाराओं को देखा गया. गडकरी की नई टीम और अध्यक्ष पद को लेकर मचे घमासान के बीच इस संवेदनशील मुद्दे ने भाजपा को बैकफुट पर ला दिया है.

किशनगंज में एएमयू की शाखा खोलने की बात पिछले साल फरवरी से ही चल रही थी. विद्यार्थी परिषद कई स्तरों पर इसका विरोध कर रहा था, लेकिन पिछले सप्ताह जब सरकार ने सेंटर के लिए 243.76 एकड़ ज़मीन लगभग मुफ्त में दे दी तो बवाल और बढ़ गया. विद्यार्थी परिषद के छात्र पटना में पीटे गए और नीतीश कुमार ने साफ कहा कि किसी के तुष्टिकरण का सवाल ही नहीं है. यह सारा कुछ प्रदेश में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किया गया है. उन्होंने कहा कि प्रस्ताव आया तो वह बीएचयू को भी शाखा खोलने के लिए ज़मीन देने को तैयार हैं. नीतीश कुमार के इस रुख ने भाजपा की उलझन को बढ़ा दिया. विद्यार्थी परिषद के छात्र जिस तरह से पीटे गए, उसकी सफाई देते सरकार में शामिल भाजपाई मंत्रियों को नहीं बन रही है. पूर्व मंत्री चंद्रमोहन राय ने गुस्से में कहा कि सुशील मोदी और अश्विनी चौबे को बताना चाहिए कि आख़िर वे चाहते क्या हैं. कुछ मंत्री एवं विधायकों ने बताया कि जिससे पार्टी को ताक़त मिलती है हम सरकार में रहकर उसी का हाथ तोड़ रहे हैं. क्या इस तरह की लाचारी और बेबसी से भाजपा की चुनावी नैया पार लग जाएगी. ऐसा नाराज नेता कहते हैं कि लोकसभा चुनाव में किशनगंज की सीट छोड़कर पार्टी ने बड़ी गलती की. अब इसका खामियाजा भुगतने के लिए भी तैयार रहना चाहिए. घुसपैठ, आतंकवाद और मुस्लिम तुष्टिकरण जैसे मुद्दे पर है. पांच महीने बाद चुनाव मैदान में उतरने वाली भाजपा सेनापति की बाट जोह रही है. भाजपा के एक वरिष्ठ नेता कहते हैं कि आप अंदाज लगा लीजिए की भाजपा जदयू पर किस तरह आश्रित हो चुकी है. कहीं न कहीं मन में यह बात है कि अपनी तैयारी भले ही नहीं है, लेकिन नीतीश के भरोसे चुनावी नैया पार लग जाएगी. एक नेशनल पार्टी का यह एप्रोच दुख देने जैसा

एएमयू की शाखा खोलने के लिए एक्ट बदलना होगा : सैय्यद शहाबुद्दीन

सैय्यद शहाबुद्दीन का कहना है कि एएमयू की शाखा कहीं भी खोलने के लिए उसके एक्ट में संशोधन करना होगा. बिना संशोधन के ऐसा करना संभव नहीं है. उन्होंने कहा कि एएमयू कोर्ट के सदस्य रहने के नाते मैं जानता हूं कि बिना एक्ट को बदले कैंपस के बाहर कहीं भी इसकी शाखा नहीं खोली जा सकती है, क्योंकि मौजूदा एक्ट इसकी इज़ाज़त नहीं देता. केंद्र सरकार को इस मामले में मंजूरी देनी होगी. उन्होंने कहा कि अभी तो केवल ज़मीन दी गई है, लेकिन फाइनल एग्रीमेंट तो होना अभी बाकी है. एएमयू से ड्राफ्ट मांगा गया है. इसमें सारी बातों का जिक्र होगा. बिहार सरकार की जानकारी में भी सारी बातें आ जाएगीं. राज्य सरकार को भी इसके क़ानूनी पहलुओं को देखना होगा. इस प्रस्ताव को क़ानूनी शक्ल देने के लिए केंद्र की अनुमति जरूरी है. शहाबुद्दीन ने कहा कि क़ानूनी जामा पहना कर ही किशनगंज में एएमयू की शाखा खोलने का रास्ता साफ़ हो सकता है. उन्होंने बताया कि इस यूनिवर्सिटी से जुड़े कुछ मसले अभी न्यायालय में लंबित हैं और इस पर फ़ैसला आना अभी बाकी है.

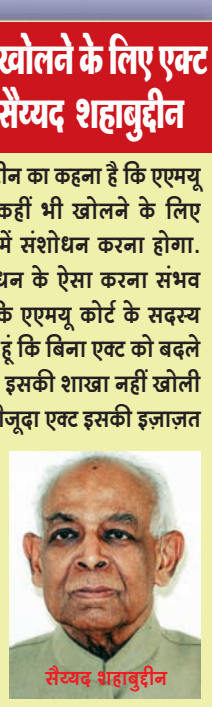

सैय्यद शहाबुद्दीन

सुशील कुमार मोदी

चंद्र मोहन

अश्विनी कुमार चौबे

सीपी ठाकुर

संघर्ष करने के लिए सीमा से सटे किशनगंज की ज़मीन भाजपा के लिए उपयुक्त है, लेकिन नीतीश सरकार में शामिल भाजपा चाहकर भी एएमयू के मसले पर कुछ नहीं बोल पा रही है. ऐसे में संघर्ष के लिए कार्यकर्ताओं को तैयार करने का मनोबल भी टूटता जा रहा है. फ़ैसले को लटका कर रखने की आदत सीख चुकी बिहार भाजपा का हौसला और कार्यकर्ताओं की हिम्मत तो पहले से ही टूट चुकी है. प्रदेश अध्यक्ष चुनने का काम जिस तरह से चल रहा है. उससे यह बात साफ़ हो गई कि सत्ता का रोग इस अलग दिखने वाली पार्टी को भी लग चुका है. रविशंकर प्रसाद कहना है कि अध्यक्ष के मसले पर विचार हो रहा है. विचार की आयु कितनी है, इसे बताने की स्थिति में भाजपा का कोई नेता नहीं है. अध्यक्ष मेरा अपना हो, मेरे गुट का हो, किसी जाति विशेष का हो आदि-आदि शर्तों ने अध्यक्ष का मसला लटका कर रख दिया गया है. इस वरिष्ठ नेता ने कहा कि लालू प्रसाद ने जो हाल कांग्रेस का किया वही हाल नीतीश कुमार भाजपा का कर रहे हैं. पार्टी नहीं संभली तो कांग्रेस से भी बुरा हाल होगा. हद तो तब हो जाती है, जब पार्टी कार्यकर्ता का सम्मेलन गांधी मैदान में न होकर एस के ममोरियल हॉल में होता है. गडकरी की नई टीम की घोषणा ने भी भाजपा का जख्म हरा कर दिया. सीपी ठाकुर, शत्रुघ्न सिन्हा सहित कई नेता सार्वजनिक तौर पर अपनी नाराजगी जता चुके हैं. दरअसल संकट मिजाज के अंतर से पैदा हो रहा है. संघर्ष और सत्ता का मिजाज अलग-अलग होता है और भाजपा से अपेक्षा थी वह इसे ईमानदारी से समझते हुए सामंजस्य बिठाने में सफल रहेगी, लेकिन सत्ता के रोग के कारण गुटों में बंटी भाजपा इस काम में फेल हो गई और पूरी पार्टी बेहद लाचार और बेबस नज़र आती है.

feedback@chauthiduniya.com

किशनगंज में आतंकवाद की फैक्टरी खोल रही सरकार : गोपाल शर्मा

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रदेश संगठन मंत्री गोपाल शर्मा का मानना है कि नीतीश सरकार किशनगंज में एएमयू की शाखा नहीं, बल्कि आतंकवाद की फैक्टरी खोलने जा रही है. अपने कार्यकर्ताओं पर पुलिस लाठीचार्ज से बेहद ख़फ़ा शर्मा का कहना है कि तुष्टिकरण की नीति से देश का भला नहीं होने वाला है. उन्होंने कहा कि सभी जानते हैं कि एएमयू में शिक्षा का स्तर अब क्या है और उसकी छवि कैसी है. उन्होंने कहा कि चार सौ यूनिवर्सिटी में एएमयू का स्थान नीचे से चौथा है. इसके बावजूद सरकार कहती है कि प्रदेश में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एएमयू की शाखा खोली जा रही है. सीमा से सटे किशनगंज में इस तरह के काम से केवल आतंकवाद को बढ़ावा मिलेगा. गोपाल शर्मा ने कहा कि हम पीछे हटने वाले नहीं हैं. सरकार ने तालीबानी रवैया अपना लिया है तो हमारे कार्यकर्ता इसका जवाब देना जानते हैं. शर्मा ने कहा कि कोई भी यूनिवर्सिटी की शाखा खोल ली जाए, लेकिन एएमयू की शाखा हम किसी भी क़ीमत पर नहीं खुलने देंगे. उन्होंने कहा कि जिस यूनिवर्सिटी में देश के विभाजन का दस्तावेज लिखा गया हो, उसे यहां कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है.

गोपल शर्मा

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्यों पर लाठी चार्ज करते पुलिसकर्मी.

चौथी दुनिया

नए परिसीमन में भाजपा का वोट बैंक माना जाने वाला मानपुर का पटवा टोली और लक्खीबाग इस बार कटकर वज़ीरगंज विधानसभा क्षेत्र में चला गया है.

दूध को अधिक देर तक सुरक्षित रखने के लिए कोई शीतगृह अथवा अन्य कोई साधन नहीं रहने के कारण पशुपालक अथवा दूध विक्रेता उसमें ख़तरनाक दवा मिलाने को मजबूर हो जाते हैं.

चौथी दुनिया

गर्मी के साथ राजनीतिक पारा चढ़ा

उग्रवाद प्रभावित होने के कारण गया ज़िले के दस विधानसभा क्षेत्रों को संवेदनशील माना जाता है. गया शहर विधानसभा क्षेत्र भी चुनाव के समय संवेदनशील हो जाता है, इससे हर कोई वाकिफ है. सांप्रदायिक सौहार्द और गंगा-जमुनी संस्कृति को अपने दामन में समेटे गया शहर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में सांप्रदायिक सौहार्द के लिए जाना जाता है. लेकिन चुनाव आते ही राजनीतिबाज इस विरासत को तार-तार करने की कोशिश से बाज नहीं आते, हालांकि वे अपने मक़सद में कभी कामयाब नहीं होते. चुनाव के दौरान जातीय संकीर्णता में जकड़े मतदाता दो खेमों में बंटे नज़र आते हैं. 1990 से पहले गया शहर कांग्रेस की परंपरागत सीट के रूप में जाना जाता था. 1962 में कालापानी की सज़ा पाने वाले निर्दलीय उम्मीदवार श्याम भरथुआर और 1977 में जनता पार्टी की सुशीला सहाय को छोड़कर 1990 तक इस सीट पर कांग्रेस का क़ब्ज़ा रहा. लेकिन, 1990 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के प्रेम कुमार ने जो जीत दर्ज़ की, उसके बाद वह लगातार पांच बार यहां से जीत कर वर्तमान में सूबे के पथ निर्माण मंत्री हैं. आने वाले विधानसभा चुनाव में उन्हें कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है.

नए परिसीमन में भाजपा का वोटबैंक माना जाने वाला मानपुर का पटवा टोली और लक्खीबाग इस बार कटकर वजीरगंज विधानसभा क्षेत्र में चला गया है. प्रेम कुमार से मतदाता नाराज़ तो होते हैं, लेकिन चुनाव के समय स्थिति बदल जाती है. भाजपा के परंपरागत वोटबैंक और गया शहर की स्थिति को देखते हुए प्रेम कुमार को शिकस्त देना आसान भी नहीं होगा.

क़रीब सवा दो लाख मतदाता वाले गया शहर विधानसभा क्षेत्र में सर्वाधिक मत वैश्य समाज के हैं, जबकि दूसरे स्थान पर कायस्थ और चंद्रवंशी समाज है. मुसलमानों का वोट भी चालीस से पचास हज़ार के बीच है. यहां से राजद-लोजपा गठबंधन के तहत लोजपा प्रत्याशी के आने की संभावना प्रबल है. वैश्य समाज से आने वाले वार्ड पार्षद एवं लोजपा नेता लालजी

गया शहर विधानसभा क्षेत्र

अमित गुप्ता

मोहन श्रीवास्तव

लाल जी प्रसाद

प्रेम कुमार

प्रसाद यहां से लोजपा के संभावित प्रत्याशी हैं. उनका दावा है कि गया नगर निगम में वैश्य समाज से दस वार्ड पार्षद हैं, जिसका फ़ायदा उन्हें मिल सकता है. लालजी प्रसाद यहां के जुझारू वैश्य नेता के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन सिर्फ़ वैश्य वोट के सहारे प्रेम कुमार को शिकस्त देना आसान नहीं होगा. अन्य समुदाय के मतों को गोलबंद करने के बाद ही प्रेम कुमार को चुनौती दी जा सकती है. कांग्रेस के साथ यहां एक अनार-सौ बीमार वाली कहावत चरितार्थ हो रही है. सबसे अधिक दावेदारी कांग्रेस में ही है. पूर्व विधायक जयकुमार पालित, पूर्व विधायक डॉ. युगल किशोर, गया नगर निगम के डिप्टी मेयर मोहन श्रीवास्तव, राजन सिन्हा, योगेंद्र सिंह एवं अमित गुप्ता आदि खुद को गया शहर विधानसभा क्षेत्र से प्रबल दावेदार बता रहे हैं, लेकिन इनमें जयकुमार पालित, मोहन श्रीवास्तव और डॉ. युगल किशोर की दावेदारी सबसे अहम मानी जा रही है. डॉ. युगल किशोर दो बार 1980 और 1985 में गया शहर के विधायक रह चुके हैं. वह कद्दावर नेता हैं और वैश्य समाज से आने के कारण मज़बूत दावेदारों की सूची में सबसे आगे हैं. डॉ. युगल किशोर 1972 में कांग्रेस के विधायक रह चुके हैं. वह अपने जातीय मत चंद्रवंशी के सहारे दावेदारी जता रहे हैं. गया नगर निगम के डिप्टी मेयर मोहन श्रीवास्तव अपने कार्यकाल में शहरवासियों को समस्याओं से निजात दिलाने और कायस्थ महासम्मेलन का उनका एकमात्र नेता होने का दावा करते हुए कांग्रेस से अपनी दावेदारी जता रहे हैं. इस सम्मेलन में शत्रुघ्न सिन्हा, अभिनेता शेखर सुमन, कांग्रेस सांसद संजय निरूपम, केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय और हास्य अभिनेता राजू श्रीवास्तव मंच पर मौजूद थे.

> नए परिसीमन में भाजपा का वोट बैंक माना जाने वाला मानपुर का पटवा टोली और लक्खीबाग इस बार कटकर वज़ीरगंज विधानसभा क्षेत्र में चला गया है. प्रेम कुमार से मतदाता नाराज़ तो होते हैं, लेकिन चुनाव के समय स्थिति बदल जाती है. भाजपा के परंपरागत वोट बैंक और गया शहर की स्थिति को देखते हुए प्रेम कुमार को शिकस्त देना आसान भी नहीं होगा.

राजन सिन्हा भी कायस्थ बिरादरी से आते हैं और शहर के जाने-माने अधिवक्ता हैं. वह इस साल अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस में शामिल होकर टिकट की दावेदारी कर रहे हैं. उन्हीं के साथ कांग्रेस में शामिल होने वाले अमित गुप्ता उर्फ बाइल भी अपनी दावेदारी वहां से कर रहे हैं. इससे पहले अमित लोजपा में थे. उनका दावा है कि अल्पसंख्यक मत उनके पक्ष में हैं. अन्य दर्जन भर कांग्रेसी नेता विभिन्न तर्क देकर टिकट पाने की कवायद में लगे हुए हैं. दो प्रत्याशी मुस्लिम मत पाकर चुनाव जीतने का सपना पाले हुए हैं. भाजपा सरकार में विधायक एवं पथ निर्माण मंत्री डॉ. प्रेम कुमार को चुनौती दे सकते हैं. गया में फिर एक बार योजनाओं के कार्यान्वयन के आधार पर प्रेम कुमार जनता से फिर एक मौका चाह रहे हैं. वैसे दलील और जातीय आधार पर वह मज़बूत स्थिति में हैं. प्रदेश युवा भाजपा मोर्चा के सचिव आरएस नामामणि का दावा है कि शहर के अधिकांश युवा प्रेम कुमार के साथ हैं. वामपंथी दल, बसपा एवं सपा आदि दलों के प्रत्याशी भी चुनाव मैदान में होंगे. नए परिसीमन और बदले समीकरण में भाजपा, कांग्रेस और लोजपा–राजद गठबंधन के बीच ही संघर्ष होने की संभावना है. इस हिसाब से तीनों दलों के संभावित प्रत्याशी प्रचार में लग गए हैं. चुनाव आने में अभी समय है, लेकिन गया शहर में गर्मी बढ़ने के साथ ही चुनावी पारा बढ़ने लगा है.

सुनील सौरभ

feedback@chauthiduniya.com

मुंगेर, जमालपुर एवं तारापुर विधानसभा क्षेत्र

ख़ेमेबाज़ी जारी, निशाना चूकने का अंदेशा

बिहार चुनावी वर्ष में प्रवेश कर चुका है, लिहाज़ा राजनीतिक दलों ने विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है. सत्तारूढ़ जदयू एवं भाजपा सहित विपक्षी दल राजद, लोजपा एवं कांग्रेस अपनी–अपनी रणनीति बनाने में जुट गए हैं. प्रमंडलीय मुख्यालय मुंगेर में भी राजनीतिक तापमान साफ़ दिखाई दे रहा है. नए परिसीमन के बाद राजनीतिक परिदृश्य काफी बदला–बदला नज़र आ रहा है. ज़िले की तीन विधानसभा सीटों में से दो पर राजद का क़ब्ज़ा है और एकमात्र जमालपुर विधानसभा क्षेत्र जदयू के खाते में है. बनते–बिगड़ते राजनीतिक समीकरणों को देखते हुए लगता है कि अगले विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ जदयू को मुंगेर में काफी पसीना बहाना पड़ेगा.

वी गुप्ता

शकुनी चौधरी

शैलेश कुमार

राजीव सिंह

अनंत सत्यार्थी

बीडीओ सिंह

मोहम्मद सलाम

मुंगेर विधानसभा क्षेत्र में पिछले वर्ष हुए उपचुनाव में यह सीट जदयू के हाथ से निकल कर राजद के खाते में आ गई और ज़िंदगी भर कमल खिलाने वाले विश्वनाथ गुप्ता लालटेन का दामन थाम विधानसभा पहुंच गए. गत लोकसभा चुनाव में मुंगेर के विधायक डॉ. मोनाज़िर हसन के बेगूसराय से सांसद बनने के बाद यह सीट रिक्त हुई थी और इस पर राजद ने हिंदू कार्ड खेलते हुए विश्वनाथ गुप्ता को अपना उम्मीदवार बनाया था. वहीं जदयू ने यहां से मो. सलाम को उम्मीदवार बनाया. चुनाव में जदयू को अंतर्कलह का सामना करना पड़ा और उसके हाथ से यह सीट निकल गई. वैसे उपचुनाव पुराने परिसीमन पर हुए थे, जबकि अगला विधानसभा चुनाव नए परिसीमन पर होना है. नए परिसीमन में जमालपुर विधानसभा क्षेत्र के बरियारपुर प्रखंड की 11 पंचायतें अब मुंगेर विधानसभा क्षेत्र में आ गई हैं, जिससे मुंगेर का जातीय और राजनीतिक समीकरण बदल गया है. नए जातीय समीकरण में कोयरी, कुर्मी और धानुक मतदाताओं के जुटने से जदयू का पलड़ा भारी लग रहा है, लेकिन पार्टी के अंदर मचे घमासान का असर यदि पुनः विधानसभा चुनाव पर पड़ा तो परिणाम चौंकाने वाले हो सकते हैं. मुंगेर के सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह के प्रदेश जदयू अध्यक्ष पद से हटने के बाद यहां पार्टी पूरी तरह दो ख़ेमों में बंट गई है.

जमालपुर विधानसभा क्षेत्र वर्तमान में जदयू के क़ब्ज़े में है. शैलेश कुमार यहां के विधायक हैं. पिछले 25 वर्षों से इस सीट पर काबिज़ राजद के उपेंद्र प्रसाद वर्मा को जमालपुर की जनता ने जिस उद्देश्य से गद्दी से उतार कर शैलेश कुमार को मुकुट पहनाया था, वह सत्ता के गलियारों में कहीं खो गया. नए परिसीमन में जहां जमालपुर विधानसभा क्षेत्र की 11 पंचायतें मुंगेर में चली गई हैं, वहीं खड़गपुर का राजपूत बहुल क्षेत्र जमालपुर में आ गया है. इसलिए इस बार राजपूत मतदाता यहां निर्णायक स्थिति में हैं. यही कारण है कि कई राजपूत नेता इस सीट पर अपना भाग्य आजमाने के लिए ताल ठोक रहे हैं. भाजपा नेता बीडीओ सिंह लोजपा का दामन थामकर विधानसभा पहुंचने के जुगाड़ में लगे हैं और वह पार्टी के प्रधान महासचिव सह जिला प्रभारी वीरेश्वर सिंह के मार्फत अपनी पैठ बना रहे हैं. इस सीट के राजद उम्मीदवार उपेंद्र प्रसाद वर्मा अब जदयू में हैं. इसलिए अधिक संभावना बन रही है कि यह सीट राजद–लोजपा गठबंधन में लोजपा को ही दी जाए. वैसे लोजपा नेत्री साधना सिंह यादव भी गठबंधन की उम्मीदवार बनने के लिए जी–जान से जुटी हुई हैं. कार्यकर्ताओं के भारी दबाव के कारण कांग्रेस के डॉ. समीर कुमार सिंह भी इस सीट से

> जमालपुर विधानसभा क्षेत्र वर्तमान में जदयू के क़ब्ज़े में है. शैलेश कुमार यहां के विधायक हैं. पिछले 25 वर्षों से इस सीट पर क़ाबिज़ राजद के उपेंद्र प्रसाद वर्मा को जमालपुर की जनता ने जिस उद्देश्य से गद्दी से उतार कर शैलेश कुमार को मुकुट पहनाया था, वह सत्ता के गलियारों में कहीं खो गया.

चुनाव लड़ने के मूड में हैं, क्योंकि क्षेत्र में राजपूत मतदाताओं की संख्या अधिक है. इसलिए वह अपने स्वजातीय लोगों को इकट्ठा कर क़िस्मत आज़मा सकते हैं. डॉ. सिंह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री डॉ. राजेंद्र प्रसाद सिंह के पुत्र हैं. यदि राजपूत मतदाता किसी एक उम्मीदवार के पक्ष में गोलबंद हुए तो जदयू को यह सीट काफी महंगी पड़ेगी.

ज़िले का तारापुर विधानसभा क्षेत्र वर्षों से राजद के क़ब्ज़े में है. यहां के विधायक शकुनी चौधरी राजद के वरिष्ठ नेता माने जाते हैं. वर्तमान में वह बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष हैं. चौधरी क्षेत्र के ऐसे नेता हैं, जो विपरीत परिस्थितियों में भी इस सीट पर क़ाबिज़ रहे हैं. उनकी पत्नी भी यहां से चुनाव जीत चुकी हैं. वैसे पिछले विधानसभा चुनाव में इस सीट पर जदयू के राजीव कुमार ने उन्हें कड़ी टक्कर दी, लेकिन शकुनी चौधरी बाज़ी मार गए. नए परिसीमन में खड़गपुर विधानसभा क्षेत्र का कुछ भाग तारापुर विधानसभा क्षेत्र में शामिल हो गया है और खड़गपुर विधानसभा क्षेत्र का अस्तित्व समाप्त हो गया है. अब यहां जदयू के दो दावेदार नज़र आ रहे हैं. एक राजीव कुमार सिंह, जो पिछले विधानसभा चुनाव में काफी कम मतों से पराजित हुए थे और दूसरे खड़गपुर के जदयू विधायक अनंत कुमार सत्यार्थी. चूंकि सत्यार्थी के लिए जदयू के पास कोई सीट नहीं है, इसलिए वह अपनी पूरी ताक़त तारापुर में ही लगाए हुए हैं. वैसे इस सीट पर शकुनी चौधरी को शिकस्त देना दांतों तले लोहे चबाने जैसा है. जदयू को इस सीट के लिए काफी पसीना बहाना पड़ेगा. वरना तीर का निशाना चूक सकता है.

कल्याणी सिंह

feedback@chauthiduniya.com

ज़हरीला हो गया दूध

राजेश सिन्हा

कल जहां अमृत समान दूध की नदियां बहती थी आज वहां का दूध ज़हरीला हो गया है. शायद यह सुनकर आप चौंक जाएं, लेकिन यह सौ फ़ीसदी सत्य है. जी हां, यहां हम बात कर रहे हैं बिहार के कोसी इलाक़े की. जहां आज भी मां कात्यायनी को दूध से स्नान कराने की परंपरा है, लेकिन इस इलाके में दूध को अधिक देर तक सुरक्षित रखने के लिए एक भी शीतगृह अथवा अन्य कोई ठोस साधन नहीं है. लिहाज़ा दूध को फटने से बचाने के लिए इसमें क्लोरीसीन नामक ख़तरनाक दवा मिलाई जा रही है.

जिसे आप दूध समझकर सेवन कर रहे हैं वह इस कदर ज़हरीला हो चुका है, जिसकी कल्पना आप कर भी नहीं सकते. इस दूध का अधिक दिनों तक सेवन करने से आप गंभीर बीमारियों की गिरफ्त में आ सकते हैं. इतना ही नहीं अगर आपने अपने बच्चों को इस दूध का सेवन कराया तो उसकी जान भी जा सकती है. दूध को अधिक समय तक फटने से बचाने के नाम पर चल रहे इस खेल के कारण ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि अब शायद आपके सामने दूध के बजाए धीमा ज़हर ही परोसा जाएगा. क्योंकि गर्मी के इस मौसम में दूध को फटने से बचाने के लिए इसमें क्लोरीसीन नामक ख़तरनाक दवा

> दूध का सेवन वयस्कों के लिए ख़तरनाक तो है ही बच्चों के लिए भी ज़हर के समान है. गर्मी के मौसम में बच्चे अन्य कारणों से तो बीमार पड़ते ही हैं, लेकिन ज़हरीला दूध पीने से वे अधिक बीमार पड़ रहे हैं.

का प्रयोग करना दूध विक्रेताओं की मजबूरी बन चुकी है. वैसे इस दवा का प्रयोग मुख्यतः मुर्देखाने में अधिक समय तक मुर्दे को सुरक्षित रखने या मरीजों को ऑपरेशन के समय बेहोश करने के लिए किया जाता रहा है, लेकिन अब इस दवा का प्रयोग दूध को अधिक समय तक फटने से बचाने के नाम पर किया जा रहा है. अब तक आपने दूध में पानी मिलाने की बात भी सुनी होगी और मिलावटी दूध का सेवन भी किया होगा, लेकिन जिस कोसी इलाक़े में दूध की नदियां बहने की बात सदियों से सामने आती रही है, वहां ज़हरीला दूध धड़ल्ले से बिक रहा है. बावजूद इसके इस तरह के व्यापार को ग़ैरक़ानूनी मानने से प्रशासनिक पदाधिकारी इंकार करते हैं.

प्रशासनिक पदाधिकारियों का मानना है कि जब तक यह प्रमाणित नहीं हो जाता कि दूध को अधिक समय तक फटने से बचाने के नाम पर जिस दवा का प्रयोग किया जा रहा है, वह सेहत के लिए बेहद ख़तरनाक है तब तक उनके ख़िलाफ़ कोई क़ानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती है. हालांकि चिकित्सकों का मानना है कि इस दूध का सेवन व्यस्कों के लिए ख़तरनाक तो है ही बच्चों के लिए भी ज़हर के समान है. गर्मी के मौसम में बच्चे अन्य कारणों से तो बीमार पड़ते ही हैं, लेकिन ज़हरीला दूध पीने से वे अधिक बीमार पड़ रहे हैं. जानकारों के मुताबिक़ कोसी इलाक़े में दूध को अधिक देर तक सुरक्षित रखने के लिए कोई शीतगृह अथवा अन्य कोई साधन नहीं रहने के कारण

पशुपालक अथवा दूध विक्रेता उसमें ख़तरनाक दवा मिलाने को मजबूर हो जाते हैं. फरकिया इलाक़े के दूध विक्रेता रामबदन यादव का कहना है कि दूध का अत्याधिक उत्पादन कोसी के फरकिया इलाक़े में इसलिए होता है, क्योंकि चारा संकट के कारण अधिकांश पशुपालक मवेशियों को फरकिया इलाक़े में रखते हैं.

जटिल रास्ते के कारण तुरंत दूध को शहरी इलाक़े में ला पाना आसान नहीं होता है. खगड़िया ज़िले के अलौली निवासी और दूध विक्रेता कार्तिक यादव ने एक सनसनीखेज ख़ुलासा करते हुए कहा कि फरकिया इलाक़े से बरौनी डेयरी को भी जो दूध उपलब्ध कराया जाता है. उसमें भी क्लोरीसीन नामक दवा मिलाई जाती है. जानकारों के मुताबिक़ अगर दूध का यह धंधा अनवरत चलता रहा तो शायद लोग दूध को अमृत के बजाए ज़हर मानने को मजबूर हो जाएंगे. इधर खगड़िया सदर अस्पताल में पदस्थपित चिकित्सक डॉक्टर योगेन्द्र सिंह प्रयासी इस दूध को नहीं पीने की सलाह दे रहे हैं. उन्होंने कहा कि इस दूध का सेवन करने से बच्चे टायफाईड, निमोनिया सहित अन्य ख़तरनाक बीमारी का शिकार हो सकते हैं. बच्चे जब इस दूध का सेवन करते हैं तो उनके मलद्वार में खुजलाहट भी होने लगती है. लगातार सेवन करने के बाद वह बचपन में ही बबासीर जैसी बीमारी का भी शिकार हो सकता है.

इतना ही नहीं उनकी जान भी जा सकती है. व्यस्क भी अगर अधिक दिनों तक इस दूध का सेवन करते हैं तो उनका फेफड़े खराब हो सकते हैं. खगड़िया के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर एच प्रसाद ने भी डॉक्टर प्रयासी की बातों के प्रति सहमति जताते हुए कहा कि बाज़ार में बिकने वाला डिब्बाबंद दूध की गुणवत्ता की गारंटी तो नहीं ही है, अब जबकि पशुपालक भी इस तरह के कारोबार में लग गए हैं तो लोगों को ज़हरीले हो चुके दूध के सेवन से हर हाल में बचना चाहिए.

feedback@chauthiduniya.com

ऑपरेशन ग्रीन हंट

सफलता पर सवालिया निशान

नवल किशोर सिंह

काफी जद्दोजहद के बाद झारखंड में ऑपरेशन ग्रीन हंट शुरू हुआ. केंद्र सरकार के दिशानिर्देश पर सूबे में उग्रवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाने और नक्सलियों पर नकेल कसने के उद्देश्य से यह अभियान जारी है. इससे राज्य की जनता को लगा कि अब उग्रवाद के नाम पर फैलाए जाने वाले आतंक और हिंसा का दौर थमेगा और वह अमन-चैन से रह सकेगी, लेकिन जिस प्रकार ऑपरेशन ग्रीन हंट की आड़ में पुलिसिया आतंक कायम किया जा रहा है, उससे अभियान की सफलता पर प्रश्नचिन्ह लग गया है. पुलिस नक्सली उत्पात को रोक नहीं पा रही है. उल्टे निर्दोष लोगों को नक्सली बताकर झूठे मुकदमों में फंसाने और बेरहमी से पिटाई करने में मशगूल है. हाल में रांची जिले के बुंडू प्रखंड केडीएसपी आनंद जोसेफ तिग्गा ने एक बैंक अधिकारी, उनकी पत्नी और ड्राइवर को नक्सली बताकर तीनों की पिटाई कर डाली. राज्य के विभिन्न इलाकों से ऐसी शिकायतें लगातार मिल रही हैं. हालांकि डीजीपी नेयाज़ अहमद ने पुलिसिया कहर की शिकायत के बाद जांच केआदेश दिए हैं.

हाल में माओवादियों की दो दिनों की बंदी के दौरान पुलिस की सारी तैयारियां धरी की धरी रह गईं. बंदी के दौरान नक्सलियों ने जमकर उत्पात मचाया. पहली बार राजधानी एक्सप्रेस जैसी वीआईपी ट्रेन को निशाना बनाया गया. गया ज़िले के परैया और कास्टा रेलवे स्टेशनों के बीच रेल पटरी ऐसे समय में उड़ाई गई, जब वहां से राजधानी एक्सप्रेस गुज़र रही थी. उसकेआठ डिब्बे पटरी से उतर गए. अगर विस्फोट में कुछ सेकेंड का अंतर होता तो पूरी ट्रेन उसकी चपेट में आ जाती. इसके बाद दिल्ली–हावड़ा ग्रैंड कॉड लाइन पर रेल सेवा रोक देनी पड़ी. यह जानते हुए भी कि माओवादी बंदी में रेल यातायात उनका सॉफ्ट टारगेट होता है. बावजूद इसके पुलिस-प्रशासन की ओर से कोई इंतजाम नहीं किया गया. ऑपरेशन ग्रीन हंट जिन इलाकों में चल रहा है, वहां अर्द्धसैनिक बलों के भीषण दबाव के बावजूद नक्सलियों ने जिस तरह उत्पात मचाया, उससे उनके बैकफुट पर आने के सरकारी दावे खोखले साबित हो रहे हैं. नक्सली संगठन से जुड़े शीर्ष नेता और उनके थिंकटैंक एक ठोस रणनीति के तहत ख़ामोशी अख्तियार करके जवाबी हमले करते हैं. वैसे भी नक्सली आमने-सामने की लड़ाई से परहेज करते हैं. वह गुरिल्ला तरीक़े से हमले करते हैं. लंबी चुप्पी के बाद अचानक तेज़ हमला करना उनकी युद्धशैली में शुमार रहा है.

ऐसी सूचनाएं मिल रही हैं कि अभी माओवादी आंदोलन के नीतिकारों में हैदराबाद लॉबी का प्रभाव कम हुआ है और नेपाली लॉबी का असर बढ़ा है. वे नेपाल की तरह भारत में सत्ता पर क़ब्ज़ा करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं. नेपाल में माओवादी अब भूमिगत नहीं हैं. वे खुले में हैं. उन्हें पहचानना या उन पर नज़र रखना कोई मुश्किल काम नहीं है. भारत में उनका बेख़ौफ़ आना-जाना है. इस बात का ख़ुलासा कई बार नेपाली माओवादियों की गिरफ्तारी से भी हो चुका है. भारतीय सीमा पर उनकी गतिविधियों पर चौकसी न के बराबर है. भारत-नेपाल सीमा से सटे इलाके ऑपरेशन ग्रीन हंट के दायरे में नहीं आते. फिर भी रॉ और आईबी जैसी हमारी ख़ुफ़िया संस्थाएं उनकी गतिविधियों पर पैनी नज़र नहीं

पुलिस ने नक्सली बता कर इस युवक की पिटाई कर दी

रख पातीं. सिर्फ नेपाल के लिंक को काट दिया जाए तो उन पर नियंत्रण पाने में आसानी हो जाएगी. दूसरी अहम बात यह है कि भारत का माओवादी आंदोलन विदेशी पूंजी से पोषित नहीं है. लेवी के रूप में प्रतिवर्ष अरबों की वसूली से उनका वित्तीय पोषण होता है. इसमें एक बड़ा हिस्सा विकास योजनाओं से आता है. कोई बीडीओ उन्हें लेवी दिए बिना किसी योजना का काम नहीं करा सकता. बड़े ठेकेदार, राजनेता एवं नौकरशाह उन्हें नियमित रूप से लेवी देते हैं. वनोत्पादों के वैध-अवैध व्यवसाय में उनकी हिस्सेदारी होती है. कोयले के लोड या रैक लोडिंग में उनका हिस्सा निकलता है. अफ़ीम की खेती और ड्रग्स स्मगलिंग उनके संरक्षण में होती है. उनके आंदोलन का मुख्य लक्ष्य आतंक पैदा कर लेवी वसूलना है. सुदूर ग्रामीण इलाकों और घने जंगलों में नक्सली संगठनों के हथियार ढोते साधारण कार्यकर्ता भले ही अभावों के बीच जीते हों, लेकिन उनके बड़े नेता ऐशोआराम की ज़िंदगी जीते हैं. पुलिस-प्रशासन का मानना है कि नक्सलियों पर नियंत्रण पाने के लिए उनके आर्थिक स्रोतों की नाकेबंदी ज़रूरी है. जंगलों और पहाड़ों में वे अर्द्धसैनिक बलों के इंतजार में बैठे नहीं रहेंगे. वहां उनके द्वारा छोड़ा गया सामान भले मिल जाए, लेकिन वे नहीं मिलने वाले. आर्थिक नाकेबंदी के जरिए ही उन पर नकेल कसी जा सकती है.

दूसरी तरफ पुलिस-प्रशासन अभियान को सफल बनाने की दिशा में कोई ठोस और कारगर कदम नहीं उठा रहा है. अभियान की सफलता पर सवालिया निशान लगने का एक कारण केंद्रीय अर्द्धसैनिक बलों और राज्य पुलिस के बीच तालमेल का अभाव भी है. उग्रवाद प्रभावित कई इलाकों में नक्सलियों के पुलिसिया संरक्षण के मामले भी अक्सर उजागर होते रहे हैं. गौरतलब है कि ऑपरेशन ग्रीन हंट के रणनीतिकार उग्रवादियों की खोज़ में जंगलों की ख़ाक छान रहे हैं. वहीं दूसरी तरफ राज्य पुलिस के अधिकारी और जवान ग्रीन हंट के नाम पर ग्रामीणों के बीच आतंक का माहौल कायम कर रहे हैं. पुलिस की इन जनविरोधी कार्रवाइयों से नक्सलियों को लाभ पहुंच रहा है. ऐसे में ऑपरेशन ग्रीन हंट किस हद तक कामयाब होगा, यह एक यक्ष प्रश्न है.

feedback@chauthiduniya.com

नगर परिषद मोतिहारी : क्यों न सिर शर्म से झुका लें

मनोज कुमार राव

तेईस मार्च को मोतिहारी नगर परिषद की बैठक में जो शर्मनाक घटना हुई वह शहर के इतिहास का काला अध्याय बन गई. नगर सभापति, उपसभापति और कार्यपालक पदाधिकारी के पी सिंह की मौजूदगी में नगर पार्षदों ने एक दूसरे पर कुर्सियां फेंकीं एवं मारपीट की, जिसमें कई पार्षद घायल हो गए. अंत में मामला नगर थाने तक पहुंच गया. कार्यपालक पदाधिकारी ने प्राथमिकी दर्ज़ कराई, जिसके तहत कांड संख्या 83/10 के अधीन 323,41,353,307 एवं 34 का मामला दर्ज़ हुआ.

हालांकि इस पूरे प्रकरण से इतना तो ज़रूर हुआ कि शहरवासियों ने अपने-अपने प्रतिनिधियों का असली चेहरा पढ़ा. माहौल ऐसा बना कि घटना के बाद कई चर्चित पार्षद मीडिया को बयान देने से कतराने लगे हैं. इतना ही नहीं कई ने अपना मोबाईल स्विच ऑफ कर लिया है. मामला अंदर ही अंदर गर्म है और समय रहते न चेता गया तो अंजाम ख़तरनाक़ भी हो सकता है.

इस बीच चौथी दुनिया ने मामले की गंभीरता को समझते हुए शहर के अलग अलग वार्डों के गणमान्य और आम लोगों से बातें कीं, जिन्होंने अपना क़ीमती वोट देकर इन पार्षदों को जिताया था. साथ ही नगर सभापति प्रकाश अस्थाना, उपसभापति राजकुमारी गुप्ता, कार्यपालक पदाधिकारी के पी सिंह एवं पूर्व उपसभापति ई विभूति नारायण सिंह से भी पूछा कि क्या इस तरह की शर्मनाक घटनाओं से बचा नहीं जा सकता है. जिस चंपारण से गांधी जी ने अहिंसा का संदेश पूरी दुनिया को दिया उसी चंपारण में पार्षदों की बैठक में कुर्सियां चले तो क्या सिर शर्म से झुक नहीं जाएगा. मीना बाज़ार चौक से गुज़रने वाले सुबोध, अफ़रोज़, काली प्रसाद, दिवाकर नाथ, समरेश महतो, दिग्विजय झा, सुभाष मिश्रा, अंजनी पांडे, अभ्यूदय जायसवाल, रिंकी देवी, सुषमा कुमारी, अभिनंदन कुमार जैसे कई लोगों ने इस प्रकरण पर चौथी दुनिया से बात की. रिंकी देवी और सुषमा कुमारी ने बताया कि बैठक में कुर्सी फेंकने वाले पार्षदों को टेंडर के रूप में पास होने वाले अवसर, राशि और चुनाव में ख़र्च होने वाले फंड की चिंता हमेशा रहती है, लेकिन कुर्सी की भाषा समझने वाले इन पार्षदों को हमारी दुर्दशा नहीं दिखती. उन्हें यह क्यों नहीं दिखता कि मोतीझील के लिए निर्धारित सौ करोड़ की राशि कब ज़िले तक पहुंचेगी और कब हमारा मोतीझील सुंदर बनेगा. उन्हें अतिक्रमण के शिकार मीना बाज़ार क्यों नहीं दिखता?

अफ़रोज़, काली प्रसाद, दिवाकर नाथ, समरेश महतो और अन्य ने बताया कि हमारा किरासन तेल आज दलालों के चुंगल में फंसा हुआ है. एपील, बीपीएल तथा अंत्योदय अनाज की सरेआम कालाबाज़ारी हो रही है. इसकी चिंता किसी भी पार्षद को नहीं है, लेकिन कुर्सी के लिए कुर्सियों को फेंकने में हमारे पार्षद अपनी शान समझते हैं. उन्होंने धमकी देते हुए कहा कि अगर ऐसे ही हालात रहें तो जनता अपने-अपने वार्ड में सड़कों पर उतर जाएगी और अपना हक स्वयं लेगी. सुनील कुमार, अभय रंजन, मनीष कुमार, रंभा देवी और सुनीता श्रीवास्तव ने बताया कि ऐसे पार्षदों को फौरन सज़ा देनी चाहिए. वे विकास का काम तो कम करते हैं, लेकिन निजी फायदों के लिए दबंगई अधिक दिखाते हैं. इन्होंने बताया कि टाउन हॉल के पास लोगों को जाम की समस्या से रोज़ दो-चार होना पड़ता है, लेकिन इस समस्या की

ई विभूति नारायण

म[illegible] भूषण

मोहिबुल हक

प्रकाश अस्थाना

राज कुमारी

तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता. उन्हें फंड के बंटवारे को लेकर आपस में कुर्सी फेंकने से फुर्सत नहीं मिलती है.

इस बीच जब पूर्व उपसभापति व नगर पार्षद ई विभूति नारायण सिंह से बातचीत की गई तो उन्होंने अपनी नाराज़गी जताते हुए कई बातें बताईं. मसलन उन्होंने कहा कि अधिकांश भवनों का निर्माण पूर्ववर्ती ज़िलाधिकारी एस शिवकुमार के समय में हुआ है. जैसे शौर्य स्तंभ का निर्माण, नए टाउन हॉल का निर्माण, अधिकांश पार्कों का निर्माण आदि, लेकिन आज ये सभी भवन या तो उपेक्षित हैं या इनका गलत इस्तेमाल हो रहा है. इन समस्याओं पर किसी भी नगर पार्षद का ध्यान नहीं जा रहा है. सभी राजनीतिक स्वार्थ के कारण एक दूसरे पर कुर्सियां फेंकने में व्यस्त हैं. उन्होंने बताया कि नए टाउन हॉल की क्षमता लगभग 1500 लोगों के बैठने की है. मगर, इन दिनों इसका इस्तेमाल ईवीएम रखने और होमगार्ड के जवानों के रहने के लिए हो रहा है. वहीं किसी और आयोजन के लिए पुराने टाउन हॉल से ही काम चलाया जा रहा है. इसकी क्षमता 300 लोगों की है. जिसकी वजह से लोगों को जाम की समस्या से दो-चार होना पड़ रहा है. उन्होंने यह भी बताया कि बतौर नगर पार्षद कई बार शहर में सफाई से संबंधित मांगों को सबके सामने रखा गया, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ. पूरी व्यवस्था की खिंचाई करते हुए उन्होंने कहा कि शहर में बिना रखरखाव के जगह-जगह मूर्तियां लगवाई गई हैं, क्योंकि अनावरण के लिए पार्षदों के राजनीतिक गुरु जो पधारते हैं. मगर, विडंबना यह है कि पूरे शहर की गंदगी को एक जगह रखने के लिए आज तक एक कूड़ादान नहीं बनवाया जा सका. शायद इस कार्य के लिए किसी के पास वक्त नहीं है. क्योंकि उन्हें कुर्सी फेंकने से फुर्सत नहीं मिलती. उन्होंने बताया कि यह शर्म की बात है कि हमारे ज़िले के समाहरणालय भवन के पास बापू की वह प्रतिमा लगाई गई है, जो संसद भवन में लगी बापू की प्रतिमा से भी चार इंच ऊंची है, लेकिन उसके आसपास गंदगी का भंडार है. इस ओर न तो किसी अधिकारी का और न ही किसी पार्षद का ध्यान जाता है. जानपूल चौक के रघुवीर, उमा, आनंद, समरेश, रामखेलावन ने बताया कि ठेले पर जो किरासन तेल का वितरण होता है, उसे एकल महिला, विधवा महिला, लॉज के छात्र, झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले ग़रीब व अस्पतालों में इलाज के लिए आए लोगों के बीच बांटना है. पर इस पर भी दलालों का क़ब्ज़ा है. इसमें अधिकारी बड़े आराम से कमीशन की राशि खाते हैं और अपनी जेब गर्म करते हैं. देखरेख के अभाव में नालियां बजबजा रही हैं, सड़कें साल भर के अंदर ही उखड़ने लगी हैं. इस ओर भी किसी का ध्यान नहीं जा रहा है. इधर पूरे प्रकरण पर जब उपसभापति राजकुमारी गुप्ता से बातचीत की गई तो उन्होंने अफ़सोस ज़ाहिर करते हुए कहा कि हंगामे के दौरान एक लोहे की कुर्सी उनके सिर पर गिरने ही वाली थी, लेकिन उन्होंने उसे हाथ से रोक लिया. इससे उनकी पांचों उंगलियों में चोटें आईं. उन्होंने बताया कि कारण चाहे जो भी हो, आज हम सभी पार्षद शर्मिंदा हैं. हमलोगों ने जनता के सामने अपना जो रूप परोसा है वह निश्चय ही निंदनीय है. उन्होंने सभापति प्रकाश अस्थाना की खिंचाई करते हुए कहा कि अनुशासन नाम की कोई चीज़ बैठक में नहीं दिखती. कई बार बैठक सभापति अपने ही चैंबर में कर लेते हैं. बतौर उपसभापति मुझे इसकी कोई सूचना नहीं दी जाती. उन्होंने यह भी बताया कि कई बार, टेंडर निकालते समय एकमुश्त राशि के भुगतान की बात की जाती है, जिससे योग्य लोग धन के अभाव में टेंडर में शामिल नहीं होते, जबकि बाद में इसी टेंडर की भुगतान राशि का मामला छह माह के किश्तों में कर दिया जाता है. ऐसा सिर्फ़ अपने चहेते को ख़ुश करने के लिए किया जाता है. उन्होंने कहा कि जो भी हुआ इसके लिए बतौर उपसभापति मैं अत्यंत दुखी महसूस कर रही हूं. नगर पार्षद मोहिबुल ने बताया कि पूरे प्रकरण के लिए सदन के सभी लोग ज़िम्मेवार हैं. उन्होंने विशेषकर कार्यपालक पदाधिकारी के पी सिंह को घेरते हुए कहा कि सदन की प्रशासनिक ज़िम्मेवारी उनकी है, लेकिन अनुशासन तोड़ने में वह सबसे आगे रहते हैं. मोहिबुल ने बताया कि बिना रसायन के ही मच्छर् गाने वाली फॉगिंग मशीन का इस्तेमाल हो रहा है. इस समस्या को लेकर जब के पी सिंह से सदन में सवाल किया गया तो वह आपे से बाहर हो गए और अपनी डायरी को टेबल पर ज़ोर से पटकते हुए हंगामे की शुरुआत कर दी. मोहिबुल ने आरोप लगाते हुए कहा कि नगर परिषद के कर्मचारी किसी भी कार्य के लिए जब जनता से सीधे रिश्वत की मांग करते हैं, तो उनके अधिकारी को यह क्यों नहीं दिखता. उन्होंने कहा कि नगर परिषद के लिए जो स्कॉरपियो ख़रीदी गई है. उसका इस्तेमाल अधिकारी पटना जाने के लिए करते हैं. मोहिबुल ने यह भी कहा कि जनता के प्रति उनका व्यवहार अत्यंत खराब है. अगर जनता उन्हें सही कह दे तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं. इधर जब पूरे प्रकरण के बारे में के पी सिंह से बातचीत की गई तो उन्होंने सभी आरोपों को ख़ारिज करते हुए कहा कि मेरी जान को ख़तरा है. जब मैं ऑफिस में सुरक्षित नहीं हूं तो भला और कहां सुरक्षित रह सकता हूं. उन्होंने सभापति प्रकाश अस्थाना पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह असमाजिक तत्वों का सहारा लेकर मेरे खिलाफ़ कुछ भी कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि कई नगर पार्षद आपराधिक पृष्ठभूमि के हैं. जब मेरे पास कोई विकल्प नहीं बचा तब मैंने नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज़ करवाई.

जब नगर पार्षद मणि भूषण श्रीवास्तव से बातचीत की गई तो उन्होंने भी प्रशासनिक लापरवाही का राग अलापा. के पी सिंह की खिंचाई करते हुए कहा कि उनके इशारे पर ही यह पूरा हंगामा हुआ है. उन्होंने कहा कि हंगामे के बाद के पी सिंह उनके घर गए और परिजनों से बदतमीजी भी की. इस बाबत जब नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज़ करने मेरे परिजन गए तो प्राथमिकी दर्ज़ नहीं की गई. अंत में कोर्ट में मामला दर्ज़ कराया गया. उन्होंने यह भी बताया कि बतौर टैक्स लगभग सवा दो करोड़ की राशि जमा हुई है, जिसका इस्तेमाल कार्यपालक पदाधिकारी अपने निजी कार्यों के लिए करते हैं. इस संबंध में ज़िलाधिकारी सहित सीएम को भी ज्ञापन भेज दिया गया है. इधर नगर पार्षद मोहिबुल और अन्य पार्षदों ने बताया कि हम पर 307 का मामला दर्ज़ किया गया है. क्या हम लोग हत्यारे हैं. हम सिर्फ विकास कार्य करना चाहते हैं, लेकिन प्रशासनिक लोग इसमें अपनी दबंगता दिखाते हैं और जनता के कार्य में बाधा उत्पन्न करते हैं. नगर पार्षद रेयाज़ अहमद ने कहा कि पूरे प्रकरण के लिए कोई एक पक्ष ज़िम्मेवार नहीं है, बल्कि यह हम सभी पार्षदों के लिए शर्म की बात है. नगर पार्षद विनोद श्रीवास्तव ने बताया कि सभापति महोदय इस पूरे प्रकरण के लिए अधिक ज़िम्मेवार हैं. उन्होंने कहा कि प्रतिमाह होने वाली बैठक समय पर नहीं होती और अनुपस्थित पार्षदों के घर रजिस्टर भेजकर हस्ताक्षर करवा लिया जाता है. मामले की जांच करने के लिए उन्होंने निगरानी विभाग को भी लिखा है. इधर नगर सभापति प्रकाश अस्थाना ने बताया कि जो भी हुआ वह अपने आप में शर्मनाक है. मुझ पर जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वे बेबुनियाद हैं. यह उनकी छवि को खराब करने की कोशिश है. फिर भी पूरे प्रकरण की जांच कराने के लिए एक कमिटी बनाई जा रही है. मामला शीघ्र ही सबके सामने सही रूप में आएगा. जो भी दोषी होंगे उनके ख़िलाफ कार्यवाही होगी. उन्होंने कार्यपालक पदाधिकारी के पी सिंह को घेरते हुए कहा कि वह जिन पार्षदों को असामाजिक कह रहे हैं, उन्हें जनता ने चुना है. सभापति ने बताया कि पूरे प्रकरण को लेकर ज़िलाधिकारी, नगर विकास विभाग और नगर विकास मंत्रालय को भी लिखा जा चुका है.

feedback@chauthiduniya.com

Postal Regn. No. DL/ND-11/6139/2009-11, RNI No. 45843/86

चौथी दुनिया

दिल्ली, 12 अप्रैल–18 अप्रैल 2010

90 के दशक से अभिनय के मैदान में उतरी नगमा आज भोजपुरी फ़िल्मों की लोकप्रिय अभिनेत्री हैं.

टाल में दाल पर आफत

दिव्या कुमारी

देश भर में दाल की आसमान छूती क़ीमतों ने हर तबके को परेशानी में डाल रखा है. एक तो महंगाई की मार, ऊपर से दलहन के उत्पादन में कमी ने लोगों को परेशान कर दिया है. वे अगले साल की फ़सल के लिए अभी से चिंतित हैं. दरअसल देश के दूसरे बड़े दलहन उत्पादक क्षेत्र यानी टाल में इस बार दलहनी फ़सल पूरी तरह कीड़ों की चपेट में आ गई है. सैकड़ों हेक्टेयर की फ़सल चौपट हो चुकी है, जिससे उत्पादन में भारी गिरावट आने की आशंका है. राज्य का कृषि महकमा भी इस संकट से पशोपेश में आ गया है. खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार करीब साढ़े छह हज़ार करोड़ रुपये के नए कृषि रोड मैप की घोषणा कर चुकी है. बावजूद इसके दाल के उत्पादन में बढ़ोतरी होने के बजाय लगातार गिरावट आ रही है. कीड़ों का प्रभाव और सिंचाई के साधनों का अभाव दलहन की पैदावार में गिरावट का सबसे बड़ा कारण है. हाल के वर्षों में कीड़ों के प्रभाव के कारण अधिकांश किसानों ने चने की खेती करना ही छोड़ दिया. वहीं सिंचाई के लिए किसानों को केवल बारिश पर निर्भर रहना पड़ता है, जिससे दलहन के उत्पादन में कमी हो रही है. कृषि विभाग का आकलन है कि इस वर्ष दलहन के उत्पादन में कम से कम 20 फ़ीसदी की कमी आ सकती है. राज्य में लगभग छह लाख हेक्टेयर ज़मीन में दलहन की खेती की जाती है, जिसका 30 फ़ीसदी हिस्सा टाल क्षेत्र में आता है.

पटना ज़िले के फतुहा, बख्तियारपुर, बाढ़ पंडारक और मोकामा प्रखंडों की करीब 48517 हेक्टेयर ज़मीन में किसान चना, मटर, मसूर और राजमा जैसे दलहनों की खेती करते हैं, लेकिन पिछले कई वर्षों से टाल की ज़मीन दगा दे रही है. पिछले दो दशकों में हालत ऐसी हो गई कि इलाक़े से चने

की खेती अब दूर होती जा रही है. किसानों ने लगातार बढ़ते घाटे के कारण चने की खेती करना ही छोड़ दिया. चने के पौधों में कजरा कीट और फली छेदक कीटों का प्रकोप इतना ज़्यादा बढ़ गया कि अब इलाक़े में बमुश्किल दस से पंद्रह फ़ीसदी किसान ही चने की खेती कर रहे हैं. ज़िले के 459 गांवों के ज़्यादातर किसानों ने अपना रुख़ मसूर की खेती की ओर कर लिया है. ज़िले के अधिकांश क्षेत्रों में इस साल मसूर की खेती कीड़ों के कारण बुरी तरह प्रभावित हुई है. मसूर की फ़सल बर्बाद हो रही है. साल दर साल कीड़ों का प्रकोप लगातार बढ़ता ही जा रहा है. इस वर्ष कृषि विभाग द्वारा तय उत्पादकता दर में भी व्यापक कमी आ रही है. बाढ़ अनुमंडल कृषि विभाग ने वर्ष 2009–10 के लिए चना उत्पादन का लक्ष्य 13.50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर निर्धारित किया है. वहीं मसूर उत्पादन के लिए 11.50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर का लक्ष्य तय किया गया है. कृषि विभाग महज़ बीस फ़ीसदी नुक़सान का ही अनुमान करता है. हालांकि अधिकारियों का मानना है कि पानी की कमी के कारण फ़सल प्रभावित हो रही है. दलहन की फ़सल पर आई इस विपदा ने कृषि विभाग में भी हलचल मचा दी है. राज्य कृषि विभाग की टीम ने पटना, नालंदा और शेखपुरा ज़िले के कई क्षेत्रों का दौरा कर फ़सलों की तबाही का जायजा लिया. हालांकि विभाग महज़ 25 से 30 फ़ीसदी तक फ़सल बर्बाद होने की बात कह रहा है. राज्य के कृषि निदेशक डॉ. बी राजेंद्र भी मोकामा–टाल क्षेत्र का दौरा करने के बाद कुछ ऐसा ही कह रहे हैं. हालांकि टाल क्षेत्र में दलहन उत्पादन में लगातार हो रही गिरावट के लिए कृषि वैज्ञानिक अलग ही कारण बताते हैं. कृषि विज्ञान केंद्र अगवानपुर के वैज्ञानिक डॉ. उमेश सिंह मानते हैं कि टाल में लगातार एक ही फ़सल की बुआई करने से मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है. पहले जहां स्थानीय प्रभेद की खेती की जाती थी, वहीं अब उन्नत और हाईब्रिड बीजों का दौर आ गया है. बावजूद इसके किसान पारंपरिक तरीक़े से ही खेती कर रहे हैं, जिसका ख़ामियाजा दलहन उत्पादन में गिरावट के रूप में भुगतना पड़ रहा है. कृषि के जानकार टाल में सिंचाई व्यवस्था का न होना इसका सबसे बड़ा कारण मानते हैं. मध्य प्रदेश में सिंचाई व्यवस्था कारगर है, जबकि टाल में आज भी दाल की पैदावार भगवान भरोसे ही निर्भर है.

सबल किसान डीजल पंपों की सहायता से कहीं–कहीं सिंचाई कर पाते हैं, जबकि ज़्यादातर किसान बुआई के बाद केवल फ़सल काटने ही खेत जाते हैं. सिंचाई के साधनों के अभाव में टाल के किसान किसी दूसरी फ़सल की खेती नहीं कर पाते हैं.

टाल क्षेत्र से जुड़े कुल गांवों की संख्या क़रीब 2500 है, जो लगभग 1–7 किलोमीटर की चौड़ाई में फतुहा से पीरपैंती (भागलपुर) तक फैले हुए हैं. छिछला इलाक़ा होने की वजह से बरसात के दिनों में जून से सितंबर तक टाल का अधिकांश हिस्सा जलमग्न रहता है, जिससे यहां खरीफ़ की खेती नहीं हो पाती है.

feedback@chauthiduniya.com

टाल का कुल क्षेत्रफल (136794 हेक्टेयर)

पटना	48,517 हेक्टेयर
नालंदा	12,929 हेक्टेयर
शेखपुरा	7,162 हेक्टेयर
लखीसराय	27,939 हेक्टेयर
मुंगेर	9,786 हेक्टेयर
भागलपुर	30,461 हेक्टेयर

बाढ़ अनुमंडल में दलहन उत्पादन का लक्ष्य (वर्ष 2009-10)

चना	13.50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर
मसूर	11.50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर

नुक़सान का ग़ैर सरकारी अनुमान 40 से 50 फ़ीसदी

नुक़सान का सरकारी अनुमान 20 से 30 फ़ीसदी

बेंत तस्करी से अधिकारी अंजान

बेंत का सोफा हो या कुर्सी, डायनिंग टेबल हो या टोकरी, अगर आपको ये सारी चीज़ें ख़रीदनी हैं तो इसके लिए महज़ छह से सात हज़ार रुपये ख़र्च करने होंगे और संपर्क करना होगा नेपाल के किसी कारीगर से. वजह, नेपाल के रानीगंज, रत्नगंज एवं त्रिवेणी आदि इलाक़ों में बेंत तो नहीं उपजता है, लेकिन बड़े पैमाने पर इसका कारखाना ज़रूर चलता है. यहां थोक के भाव में बेंत से बने सामानों का कारोबार भारत एवं अन्य देशों के लिए होता है. ख़रीदारी या धंधा करने वाले लोग काफी परेशानी उठाकर यहां तक आते हैं, मगर वे हैरत में पड़ जाते हैं कि जब यहां बेंत होता ही नहीं है तो फिर कारखाना कैसे चल रहा है. मामले की तह तक जाने पर पता चला कि उक्त बेंत भारत स्थित वाल्मीकि व्याघ्र परियोजना के जंगलों से तस्करी करके यहां लाए जाते हैं. कारखाना चलाने वाला मालिक भी विशुद्ध भारतीय है. इतना ही नहीं, माल को गंतव्य तक सुरक्षित पहुंचाने का भी दावा किया जाता है. अब आप जानना चाहेंगे कि आख़िर यह हस्ती है कौन? इस शख़्स को नेपाल में मुन्ना खां और लैला बेगम के नाम से जाना जाता है. यह वही मुन्ना खां है, जो भारत का शातिर अपराधी और भगोड़ा है. इस पर एक पुलिस इंस्पेक्टर की हत्या का भी आरोप है. भारतीय पुलिस को आज भी इसकी तलाश है. इसका कारोबारी नेटवर्क भारत के अलावा अन्य देशों में भी है. बताया जाता है कि यह आईएसआई का एजेंट है. इसकी पहुंच का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ख़रीदार को केवल भुगतान करना पड़ता है और सामान मंजिल तक पहुंचा दिया जाता है. वाल्मीकि नगर स्टेशन रोड, उत्तर प्रदेश के निचलौल और गोरखपुर आदि के रास्ते इसके द्वारा तैयार माल गाज़ियाबाद और दिल्ली आदि शहरों तक आसानी से पहुंच जाता है. कमाई का एक बड़ा हिस्सा वाल्मीकि व्याघ्र परियोजना के कुछ बाबुओं तक भी पहुंचता है. तस्कर कटाई करने वाले मज़दूरों को एक सौ पचास रुपये तक मजदूरी देते हैं. एक महिला मज़दूर ने बताया कि मालिक नेपाल में रहता है. उसके कहने पर हम बेंत की कटाई करते हैं. जब उसे बताया गया कि यह देश के साथ गद्दारी है तो उसका जवाब था कि गद्दारी क्या होती है, यह हम लोग नहीं जानते. मालिक खां साहब जो कहते हैं, हम लोग वही करते हैं. मुन्ना खां गंडक नदी के रास्ते अपने ठिकानों तक कब पहुंचता है और कब गायब हो जाता है, इसका पता भी नहीं चलता. परियोजना के कांटी, नौरंगीया, सीरीसीया, भेडीहारी आदि के जंगलों में बेंत की कटाई धड़ल्ले से हो रही है. ग्रामीणों के मुताबिक़, बेंत की कटाई और तस्करी की व्यवस्था लैला बेगम संभालती है. मुन्ना खां बाहर के तस्करों से लेनदेन और कब कहां सामान भेजना है, की योजना बनाता है. ग्रामीणों ने बताया कि पहले जब ईमानदार पदाधिकारी थे तो कई ट्रक पकड़े जाते थे. अब तो पदाधिकारियों की तस्करों से साठगांठ है. कार्रवाई के नाम पर छोटे–मोटे बंडल पकड़ कर अधिकारी अपने कर्तव्य की इतिश्री कर लेते हैं. रामपुर वन चेकपोस्ट पर 1996 में बेंत से लदे हुए दो ट्रक पकड़े गए थे, जिनके नंबर यूएचएन 2117 और ओएन 2089 थे. इन्हें बरेली भेजा जा रहा था. उसके बाद कोई भी वाहन नहीं पकड़ा गया. तस्करों ने ट्रक की जगह पर नावों का इस्तेमाल शुरू कर दिया. लोजपा के जिला अध्यक्ष बृजेश्वर राव कहते हैं कि तस्करी से परियोजना और सरकार को प्रत्येक वर्ष करोड़ों रुपये का नुक़सान हो रहा है. इस बाबत सीएफओ जे पी गुप्ता का कहना है कि अगर तस्करी हो रही है और ग्रामीण जानते हैं तो उन्हें विभाग को बताना चाहिए. उनके नाम गोपनीय रखे जाएंगे. सवाल तो इस बात का है कि जब आला अफसर ही मामले से अनभिज्ञ हैं तो फिर तस्करी पर रोकथाम कैसे हो सकती है?

अरविंद नाथ तिवारी
feedback@chauthiduniya.com

नो कंट्रोवर्सी प्लीज!

फिल्मों का बाज़ार यानी शोबिज अफवाहों और गरमागरम मसालेदार ख़बरों से ही चलता है. हर सितारा कभी कंट्रोवर्सी तो कभी प्रेम संबधों की वजह से सुर्खियों में रहता है. कुछ सितारों को इससे फ़ायदा मिलता है तो कुछ का करियर ही दांव पर लग जाता है, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं, जो लगातार अफवाहों के बीच भी अपनी छवि बचाए रखने के लिए जद्दोजहद करते रहते हैं. ऐसे ही सितारों में एक नाम नगमा का भी है. 90 के दशक से अभिनय के मैदान में उतरी नगमा आज भोजपुरी फ़िल्मों की लोकप्रिय अभिनेत्री हैं. गंगा, दूल्हा मिलल दिलदार, दिल दीवाना तोहार हो गईल, राजा ठाकुर, माई बाप, अब तो बन जा सजनवा हमार और तू हमार होउ में नगमा बतौर अभिनेत्री काम कर चुकी हैं. 2005 में पंडित जी बताई न बियाह कब होई से भोजपुरी फ़िल्मों में अपनी पारी शुरू करने वाली नगमा शुरुआत से ही कंट्रोवर्सी में फंसती रही हैं. कभी उन पर भोजपुरी सुपर स्टार रवि किशन के साथ अफेयर के चलते उनकी शादी तोड़ने का आरोप लगा तो कभी भोजपुरी में संवाद अदायगी को लेकर सवाल उठते रहे. इतना ही नहीं, साउथ स्टार शरथ विवाद और इंटरनेट में आपत्तिजनक वेबसाइट में भी उनका नाम उछला. कुल मिलाकर विवाद ही विवाद. लेकिन, अब नगमा सिर्फ अपने करियर पर ही ध्यान देना चाहती हैं. हाल में एक भोजपुरी पुरस्कार समारोह के दौरान उन्होंने कहा कि वह इन अफवाहों से तंग आ चुकी हैं. चाहे जितनी सफाई दो, कोई न कोई नया विवाद फिर से पैदा हो जाता है. इसलिए अब उन्होंने इस तरह के मसलों पर बात करना ही बंद कर दिया है. ग़ौरतलब है कि नगमा राजनीति में भी हैं. इसके अलावा नगमा ने लगभग सभी क्षेत्रीय भाषा की फ़िल्मों में काम किया है. चाहे वह हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ एवं मलयालम हो या फिर बंगाली, मराठी एवं पंजाबी. अपने आगामी भोजपुरी प्रोजेक्ट पर पूरा समय दे रही नगमा को अब कोई कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया

मध्य प्रदेश
छत्तीसगढ़

दिल्ली, 12 अप्रैल–18 अप्रैल 2010

www.chauthiduniya.com

उच्च शिक्षा विभाग बदहाली का शिकार

विनय दीक्षित

मध्य प्रदेश के किसी विश्वविद्यालय में उप कुलपति बनने से बेहतर है किसी होटल का मैनेजर बनना. यह कथन है लेफ्टिनेंट जनरल (अवकाशप्राप्त) के टी सतारावाला का. इस कथन की पृष्ठभूमि यह है कि 1978 में सतारावाला को जबलपुर विश्वविद्यालय का उप कुलपति नियुक्त किया गया था. इसी समय उन्हें भारत सरकार के पर्यटन विकास निगम के प्रबंध संचालक का पदभार ग्रहण करने का प्रस्ताव भी मिला था. सतारावाला ने प्रबंध संचालक का पद स्वीकार कर लिया और उप कुलपति का पद स्वीकार नहीं किया.

वर्ष 1978 में जनता पार्टी की सरकार में मध्य प्रदेश निवासी एवं रायपुर के सांसद पुरुषोत्तम कौशिक पर्यटन एवं नागरिक विमानन मंत्री थे. सतारावाला ने पदभार ग्रहण करने के बाद अपने विभाग के मंत्री से शिष्टाचार भेंट की. कौशिक ने जब उनसे उप कुलपति पद स्वीकार न करने का कारण पूछा तो सतारावाला ने बड़ी विनम्रता से व्यंगात्मक शैली में कहा, क्षमा कीजिए आप मध्य प्रदेश के हैं, लेकिन आपके राज्य में किसी विश्वविद्यालय का उप कुलपति बनने से बेहतर है होटल का मैनेजर बन जाना. पर्यटन विकास निगम की मुख्य गतिविधियों में निगम के होटलों का प्रबंधन और संचालन कार्य भी है. कौशिक को यह सुनकर शर्म आई और दु:ख भी हुआ, लेकिन तबसे आज तक मध्य प्रदेश की उच्च शिक्षा में कोई उल्लेखनीय सुधार नहीं आया है और न ही सुधार लाने के कोई सार्थक प्रयास दिखाई देते हैं.

जनता पार्टी शासन में तत्कालीन मुख्यमंत्री वीरेंद्र कुमार सखलेचा से लेकर कांग्रेसी मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह तक सभी ने शिक्षा में सुधार लाने की जी तोड़ ईमानदार कोशिशें भले ही की हों, लेकिन राज्य की नौकरशाही और शिक्षा क्षेत्र के महंतों–मठाधीशों ने सभी कोशिशों को नाकाम कर दिया. दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश को भारत का ज्ञान केंद्र बनाने का सपना संजोया था. उनके प्रयासों से राज्य में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग शिक्षा के क्षेत्र में कई निजी संस्थान खोले गए और ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को यह शिक्षा सुलभ कराई गई. निजी और सरकारी क्षेत्र में भारी–भरकम धनराशि ख़र्च करने के बाद शिक्षा में मात्रात्मक वृद्धि तो हुई, लेकिन गुणात्मक वृद्धि नहीं हो पाई.

भारतीय जनता पार्टी ने प्राचीन भारतीय संस्कृति का सिर्फ़ गुणगान किया है, अतीत से कोई सबक नहीं सीखा. प्राचीन काल में मध्य प्रदेश शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था. अयोध्या में जन्मे भगवान श्रीराम ने महर्षि विश्वामित्र के पास दंडकारण्य में शिक्षा पाई थी. द्वापर में श्रीकृष्ण मथुरा राज्य से उज्जैयनी ऋषि संदीपन के गुरुकुल में शिक्षा पाने आए थे. बौद्धकाल में भी सांची ज्ञान–विज्ञान का केंद्र था. ब्रिटिश शासनकाल में जबलपुर का नाम उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विख्यात था.

मध्य प्रदेश के विद्वानों–शिक्षाशास्त्रियों की भी प्रतिष्ठा थी. दिल्ली विश्वविद्यालय के पहले उप कुलपति डॉ. सर हरिसिंह गौर थे, जिन्होंने बाद में अपनी संपूर्ण संपत्ति सागर विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु दान देकर एक प्रतिष्ठित शिक्षा केंद्र की स्थापना की. सागर विश्वविद्यालय का नाम एक अच्छे शिक्षा संस्थान के रूप में जाना जाता रहा है. इसमें देश भर के ख्यातिनाम विषय विशेषज्ञों को सम्मानजनक पदों पर नियुक्त किया गया था. एक समय था, जब जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र पढ़ाई ख़त्म होने से पहले ही देश और विदेशों में अच्छी नौकरी पा जाते थे, लेकिन आज मध्य प्रदेश की बदहाल और बर्बाद शिक्षा व्यवस्था अपने अतीत को याद कर केवल आंसू बहा रही है.

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 2009 में यूनिवर्सिटी विद पोटेंशियल फॉर एक्सीलेंस स्कीम के तहत महाकौशल क्षेत्र के एक भी कॉलेज को उत्कृष्ट नहीं माना है. पूरे राज्य में केवल चार सरकारी कॉलेजों को चुना गया है. इसके तहत आयोग

लक्ष्मीकांत शर्मा | अर्जुन सिंह | डॉ सर हरि सिंह गौर

UGC University Grants Commission

प्रत्येक कॉलेज को अकादमिक उत्कृष्टता बढ़ाने के लिए डेढ़ करोड़ रुपये का अनुदान देता है, लेकिन मध्य प्रदेश के लगभग 700 महाविद्यालयों में से केवल चार को ही आयोग ने इसके योग्य माना है.

शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में इतना ही कहना पर्याप्त है कि पिछले पांच वर्षों में मध्य प्रदेश के किसी भी प्रोफेसर या उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सेवारत शिक्षक और शोधकर्ता का एक भी शोध–अनुसंधान अथवा उत्कृष्ट अध्ययन विषयक लेख किसी प्रतिष्ठित राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय शोध पत्रिका और शोध ग्रंथ में प्रकाशित नहीं हुआ. देश–विदेश में ज्ञान–विज्ञान के विभिन्न विषयों पर आयोजित उच्चस्तरीय कार्यशाला, संगोष्ठी या सम्मेलन में मध्य प्रदेश के किसी विद्वान को भाषण देने या शोधपत्र पढ़ने के लिए आमंत्रित नहीं किया गया है. राज्य में ऐसे कई उप कुलपति हो चुके हैं, जिन्हें आर्थिक अनियमितताओं, घोटालों, अनैतिकता, पक्षपात, और भाई–भतीजावाद के चलते पद से हटा दिया गया.

राज्य सरकार ने उप कुलपति पद को अपने चहेते अफसरों को उपकृत करने के लिए भी बदनाम किया. कई अवकाशप्राप्त आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारी विभिन्न विश्वविद्यालयों में उप कुलपति बने और बिना कुछ किए सुख–सुविधाएं भोगते रहे. इंदौर विश्वविद्यालय के उप कुलपति अवकाशप्राप्त आईएएस डॉ. भागीरथ प्रसाद ने कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए कार्यकाल पूरा होने से पहले ही पद छोड़ दिया था, लेकिन जनता ने उन्हें नकार दिया और वह चुनाव हार गए.

यदि भूले–भटके कभी किसी विश्वविद्यालय में कोई योग्य उप कुलपति आ भी जाता है तो वहां पहले से जमे प्रोफेसरों एवं प्रशासनिक अधिकारियों की तगड़ी गुटबंदी के कारण उसे असमय ही पद छोड़ना पड़ता है. राज्य में कुल दस विश्वविद्यालय, 309 सरकारी महाविद्यालय, नौ संस्कृत महाविद्यालय एवं उच्च शिक्षा विभाग से अनुदानप्राप्त 77 अशासकीय महाविद्यालय हैं. लगभग 300 निजी महाविद्यालयों को कोई सरकारी अनुदान नहीं मिलता है. भोज मुक्त विश्वविद्यालय, नटनागर शोध संस्थान, सामाजिक शोध संस्थान उज्जैन और गांधी सृजनपीठ जबलपुर में शोध कार्य किए जाते हैं. सागर विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्ज़ा हासिल है. राज्य में स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर लगभग तीन लाख 28 हज़ार छात्र–छात्राओं को उच्च शिक्षा उपलब्ध कराई जा रही है. इनमें 54 हज़ार अनुसूचित जाति, 34 हज़ार अनुसूचित जनजाति के छात्र–छात्राएं शामिल हैं.

उच्च शिक्षा विभाग का वार्षिक बजट (2010–11) लगभग 530 करोड़ रुपये का है, जिसमें से 490 करोड़ रुपये वेतन–भत्तों, पेंशन एवं निर्माण कार्यों पर ख़र्च हो जाते हैं. शेष 40 करोड़ छात्रवृत्ति वितरण, ग़ैर सरकारी कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों को सहायता, खेलकूद–स्टेडियम निर्माण आदि पर ख़र्च किए जाते हैं, लेकिन हालत वही ढाक के तीन पात वाली है. ऐसा नहीं है कि राज्य में विद्वानों एवं प्रतिभाओं की कमी है, पर राजनेता और अफसर इन स्थानीय प्रतिभाओं को उचित अवसर देने की ज़हमत नहीं उठाते. रीवा में एक बुज़ुर्ग कांग्रेस नेता विश्वविद्यालय और सरकारी महाविद्यालयों के अध्यापकों पर आतंक बने रहे, क्योंकि वह स्वयं निजी कॉलेज के संचालक थे और शिक्षा क्षेत्र में अपना वर्चस्व कायम किए हुए थे. अध्यापकों की पदस्थापना और ट्रांसफर–प्रमोशन आदि सभी मामलों में उनका और उनके चहेतों का सरकार पर दबाव बना रहता था. कई वर्ष पूर्व संस्कृत में पीएचडी के बाद उच्चस्तरीय शोध कर रहे एक व्याख्याता को शासन ने विश्वविद्यालय स्तर के शहर से हटाकर एक छोटे कस्बे में स्थानांतरित कर दिया. जब इस व्याख्याता ने अपनी स्थिति के बारे में आला अधिकारियों को बताया तो उन्होंने भी अनसुना कर दिया. अंत में तंग आकर इस व्याख्याता ने नौकरी छोड़ दी और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में नौकरी कर ली. यह व्याख्याता विश्वविद्यालय में डीन पद के अलावा संचालन समिति के सदस्य एवं विषय विशेषज्ञ के रूप में कार्य करते हुए सेवानिवृत्त हुआ और आज भी विश्वविद्यालय में अतिथि विद्वान के रूप में सेवा दे रहा है. इसके साथ ही यह विद्वान अमेरिका, जर्मनी एवं इंग्लैंड आदि देशों में प्रति वर्ष व्याख्यान के लिए बुलाया जाता है. अनेक नामचीन देशी–विदेशी संस्थानों से उन्हें कई सम्मान और पुरस्कार भी मिले हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में जब एक बार वह किसी काम से शिक्षा सचिव से मिलने आए और एक घंटे तक उन्हें सचिव के कक्ष के बाहर चपरासी के साथ बेंच पर बैठना पड़ा, तबसे उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार का नाम

(शेष पृष्ठ 18 पर)

नकलची कुलपति

मध्य प्रदेश की शिक्षा पर राजनेताओं का शिकंजा इतना मज़बूत है कि वे कुलपति जैसे सम्मानजनक पद पर अपने चहेतों को बैठाने के लिए सभी नियम–क़ायदों और नैतिकता के मानदंडों को त्याग देते हैं. भोपाल विश्वविद्यालय में डॉ. कमलाकर सिंह कुलसचिव थे, तभी उन पर पीएचडी के शोधकार्य में किसी अन्य विद्धान के शोधग्रंथ की नकल करने का आरोप लगा था और जांच भी शुरू हो गई थी, लेकिन इसके बाद भी वह कुलपति बनाए गए. बाद में वहां से जब हटे तो भोज मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति बना दिए गए. लेकिन जब उनके ख़िलाफ़ शोधपत्र में नकल करने का आरोप सिद्ध हो गया और मामला उच्च न्यायालय तक चला गया, तब कहीं जाकर उन्हें हटाया गया.

पीएचडी भी बिकती हैं

केवल राजनेता, नौकरशाह या उप कुलपति ही नहीं, बल्कि विभिन्न विश्वविद्यालयों और विभिन्न विषयों के प्रोफेसरों एवं शिक्षकों के निहित स्वार्थ भी शिक्षा की गुणवत्ता बिगाड़ने के लिए उत्तरदायी हैं. पीएचडी के लिए चयन से लेकर उपाधि दिलाने तक की प्रक्रिया में शोध छात्रों का ज़बरदस्त शोषण–उत्पीड़न होता है. कुछ विषयों और कुछ प्रोफेसरों के बारे में तो प्रसिद्ध है कि इनके ज़रिए 50 हज़ार से लेकर एक लाख रुपये तक में पीएचडी दिला दी जाती है. योग्य शोध छात्रों को कड़ी मेहनत और उच्च स्तर के शोधकार्य के बाद भी सफलता नहीं मिलती. कई बार तो ऐसे छात्रों के आधे–अधूरे शोध कार्य प्रोफेसर किसी अन्य को बेच भी देते हैं. यही कारण है कि मध्य प्रदेश से कई हताश–निराश और प्रताड़ित प्रतिभाएं पलायन कर गईं हैं. भोपाल के एक निजी कॉलेज में वनस्पति विज्ञान की एक प्राध्यापक वर्षों तक प्रयास करने के बाद भी पीएचडी के लिए पंजीकरण नहीं करा पाईं, क्योंकि उनके मौलिक शोध कार्य को समझने वाला कोई था ही नहीं. औषधीय वनस्पतियों पर शोध कर रही एक बड़ी बहुराष्ट्रीय अमेरिकी कंपनी ने जब महिला प्राध्यापक की परामर्श सेवा लेनी चाही तो सेवा नियमों के अनुशासन और स्वदेशी हितों के कारण उन्होंने असमर्थता जता दी. लेकिन जब उन्होंने स्वेच्छा से राज्य के जैव विविधता बोर्ड को अपनी सेवाएं देने की पेशकश की तो बोर्ड के अफसरों ने इतनी उपेक्षा से देखा कि महिला प्रोफेसर ने ज्ञान दान का पुण्य विचार ही त्याग दिया. ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं.

किसी मामले में ख़रीदे गए और बेचे गए माल का सत्यापन किए बिना ही कर भुगतान को सही मानकर विभाग ने कर राशि जमा कर ली.

चौथी दुनिया

बिरला अस्पताल सतना द्वारा आठ वर्षों में अवैध कार्य करने के कारण सैकड़ों मरीज़ों की जान गई है, इसलिए उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की गई है.

सार -संक्षेप

मछलियों की पचास प्रजातियां विलुप्त

मध्य प्रदेश की जीवनरेखा कही जाने वाली पवित्र नदी नर्मदा में प्रदूषण का स्तर घातक स्थिति में पहुंच चुका है. पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि नर्मदा नदी में बढ़ते प्रदूषण और छोटे-बड़े बांधों से पानी में ठहराव के कारण कई स्थानों पर मछलियों के जीवन पर संकट मंडरा रहा है. यह जानकारी नर्मदा समग्र बांद्राभान (होशंगाबाद) में आयोजित अंतरराष्ट्रीय नदी महोत्सव में आए विशेषज्ञों ने दी. जलजन्य जीवों पर अध्ययन करने वालों का कहना है कि नर्मदा नदी के निचले इलाक़ों में होशंगाबाद के आसपास

मछलियों की 95 प्रजातियां पाई जाती थीं, लेकिन अब उनकी संख्या घटकर 46 रह गई है. छोटी और अल्पजीवी मछलियों की प्रजातियां जल प्रदूषण के कारण नष्ट हुई हैं. यह स्थिति मात्र 15 वर्षों में बनी है. इंदौर की शोध छात्रा बबीता मालाकार के अनुसार, महाशिर प्रजाति की मछलियां एक ज़माने में बहुतायत में पाई जाती थीं, लेकिन अब वे कहीं-कहीं कम मात्रा में पाई जाती हैं. महाशिर प्रजाति की मछलियां उथले साफ़ बहते पानी में ही रहने की अभ्यस्त होती हैं और पानी में ही प्रजनन करती हैं. अब इन मछलियों के लिए नदी में उथला बहता साफ़ पानी कहीं-कहीं मुश्किल से बचा है. डॉ. विपिन व्यास ने नर्मदा की अनेक मछली प्रजातियों के विलुप्त होने पर चिंता जताते हुए कहा कि विकास के लिए हमने नदी के प्राकृतिक बहाव को बुरी तरह बदला और प्रदूषित किया है, इसलिए अनेक जलजन्य जीवों और वनस्पतियों की प्रजातियां सदा के लिए विलुप्त हो रही हैं. जैव विविधता भंडार में होने वाली यह क्षति कालांतर में मानव के लिए मुसीबत खड़ी कर सकती है.

आदिवासी क्षेत्रों में बदहाल शिक्षा व्यवस्था

मध्य प्रदेश सरकार आदिवासियों के कल्याण और विकास के भले ही बड़े-बड़े दावे करती हो, लेकिन ज़मीनी हक़ीक़त कुछ और है. तमाम सरकारी प्रयासों के बावजूद आदिवासियों में साक्षरता का प्रतिशत 40 है, जबकि राज्य में साक्षरता का औसत प्रतिशत 63 है. कहने को तो आदिवासी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में स्कूल खोले और बच्चों को शिक्षित करने के लिए प्रोत्साहनकारी कार्यक्रम शुरू किए गए हैं, लेकिन आदिवासी बच्चे इनका लाभ नहीं उठा पाते, क्योंकि सरकारी अमला लापरवाह है. प्राथमिक स्तर पर 60 प्रतिशत और माध्यमिक स्तर पर 55 प्रतिशत बच्चे बीच में ही स्कूल छोड़ देते हैं. सरकारी तर्क है कि ग़रीबी के चलते खेती एवं पशुपालन का काम करने के लिए बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं. आदिवासी स्कूलों में पांच हज़ार से ज़्यादा शिक्षक हैं, इनमें से 638 तो प्राचार्य हैं. इसका अर्थ यह हुआ कि 638 स्कूल बिना प्राचार्य के चल रहे हैं. हायर सेकेंडरी स्तर के स्कूलों की हालत ऐसी है कि विज्ञान विषय पढ़ाने का काम हिंदी या संस्कृत के शिक्षक को करना पड़ता है. कहीं-कहीं तो पढ़ाई केवल परीक्षा के समय में कुछ दिनों पहले होती है. जहां स्कूल हैं, वहां शिक्षक नहीं हैं. जहां शिक्षक हैं, वहां छात्र नहीं हैं. कहीं ज़रूरत से ज़्यादा शिक्षक हैं तो कहीं बहुत कम. शिक्षा सामग्री, छात्रवृत्ति, गणवेश, बालिकाओं को साइकिल एवं मध्याह्न भोजन आदि प्रोत्साहनकारी सरकारी कार्यक्रमों में भ्रष्टाचार का बोलबाला है.

दलित परिवार क़र्ज़ नहीं लौटाते

मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के अधिकारियों की शिक़ायत है कि ग़रीबी रेखा के नीचे के स्तर के अनुसूचित जाति वर्ग के लगभग 16000 व्यक्तियों को बांटे गए 300 करोड़ रुपये के क़र्ज़ में से ज़्यादातर धनराशि वापस नहीं आई है. इस कारण लगभग 150 करोड़ रुपये का क़र्ज़ डूबने की स्थिति में आ गया है. निगम के अधिकारियों का यह भी कहना है कि क़िस्तों में वसूली के लिए क़र्ज़दारों से लगातार संपर्क भी किए जाते हैं, लेकिन फिर भी वे क़र्ज़ नहीं लौटाते. कई क़र्ज़दार अपने दिए गए पते से कहीं और चले गए हैं. निगम ने अब क़र्ज़ देने में बहुत सावधानी बरतनी शुरू कर दी है. कई मामलों में वह क़र्ज़ देने से मना भी करने लगा है. लगता है कि राज्य में रहने वाले लाखों ग़रीब दलित परिवारों से प्रदेश सरकार का भरोसा ख़त्म हो गया है, क्योंकि उनके पुनर्वास एवं स्वरोज़गार के लिए राष्ट्रीय निगमों से मिलने वाले क़र्ज़ पर वित्त विभाग ने गारंटी देने से इंकार कर दिया है. राज्य सरकार के ताज़े रुख़ के बाद राष्ट्रीय निगमों ने भी चालू वित्तीय वर्ष में चल रही योजनाओं के तहत कोई राशि जारी नहीं की है. केंद्र द्वारा दलितों के पुनर्वास एवं स्वरोज़गार के लिए प्रदेश में क़रीब आधा दर्जन से ज़्यादा योजनाएं संचालित की जा रही हैं. इनमें सफ़ाई कामगार पुनर्वास और विकलांगों के स्वरोज़गार की कई बड़ी परियोजनाएं शामिल हैं. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम इन योजनाओं के लिए प्रति वर्ष 50 करोड़ रुपये से ज़्यादा की राशि क़र्ज़ के रूप में उपलब्ध कराता रहा है, लेकिन यह राशि राज्य सरकार की गारंटी पर दी जाती थी. एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इसे लेकर वित्त विभाग के साथ बैठक भी की गई थी, लेकिन वह गारंटी के लिए राजी नहीं हुआ.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

नौकरशाहों की लोकतंत्र में आस्था नहीं

संध्या पाण्डे

प्रदेश के आला अफसरों की लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई आस्था नहीं है. नौकरशाह मनमाने ढंग से प्रशासन चलाना चाहते हैं और चला भी रहे हैं. संवैधानिक बाध्यता के कारण विधानसभा एवं मंत्री परिषद आदि संस्थाओं की कार्यवाही में वे औपचारिकता ही पूरी करते हैं. राज्य में भाजपा के शासन में तो विधानसभा के सत्र भी केवल संवैधानिक औपचारिकता पूरी करने के लिए बुलाए जाते हैं. यही कारण है कि विधानसभा में विधायकों के प्रश्नों के उत्तर देने में अधिकारी लापरवाही दिखाते हैं. ज़्यादातर प्रश्नों के उत्तर के लिए जानकारी एकत्रित की जा रही है, जैसी सूचना देकर टाल दिए जाते हैं. विधायकों द्वारा अधिकारियों-कर्मचारियों या सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार, नियम विरुद्ध काम होने और वित्तीय अनियमितताओं आदि विषयों पर प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन इन असुविधा-जनक प्रश्नों का उत्तर समय पर नहीं मिलता. ग्रीष्मकालीन सत्र में विपक्ष के साथ-साथ सत्तापक्ष के विधायकों ने भी इस पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की. अध्यक्ष ईश्वर दास रोहाणी ने विधायकों के प्रश्नों के उत्तर न दिए जाने पर शासन से स्पष्टीकरण मांगा है. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सदन में आश्वासन दिया कि भविष्य में विधायकों द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर उन्हें उपलब्ध कराए जाएंगे, लेकिन दूसरे ही दिन सदन में जब प्रश्नोत्तरी बांटी गई तो विधायक यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि 20 से ज़्यादा प्रश्नों के उत्तर में शासन की ओर से यही सूचना दी गई कि जानकारी एकत्रित की जा रही है.

प्रशासन में ऊपर से नीचे तक ज़बरदस्त एकता है. इसीलिए भ्रष्टाचार का मामला चाहे आईएएस अफसर का हो या फिर मामूली पंचायत सचिव का, संबंधित प्रश्नों के उत्तर विधानसभा में टाल दिए जाते हैं. इसी तरह तमाम घपलों, घोटालों, वित्तीय एवं प्रशासनिक अनियमितताओं, घटिया निर्माण कार्यों आदि से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने से सत्तापक्ष बचता है. नौकरशाह अपने बचाव के लिए सत्तापक्ष पर दबाव बनाए रखते हैं. संसदीय प्रणाली में प्रशासन पर जनता की पकड़ बनाए रखने और प्रशासन को विधायिका के प्रति जवाबदेह बनाने के लिए विभागीय परामर्शदात्री समितियां वर्षों से काम करती आई हैं. इन समितियों की बैठक में विधायक, चाहे वे किसी भी दल के क्यों न हो, प्रशासनिक अधिकारियों एवं मंत्रियों से किसी भी विभागीय विषय पर चर्चा करते हैं, सुझाव देते हैं और शिकायतें रखते हैं. इन बैठकों में मंत्रियों एवं अधिकारियों को जवाब देना होता है. मध्य प्रदेश में भी सभी सरकारी विभागों के लिए परामर्शदात्री समितियां बनाई गई हैं और उनके गठन-संचालन के नियम भी तैयार किए गए हैं, लेकिन पिछले पांच वर्षों में उक्त परामर्शदात्री समितियां प्रभावी भूमिका अदा नहीं कर पाई हैं. अनेक विभागों में मंत्री और अफसरों की मिलीभगत से परामर्शदात्री समिति की बैठक ही नहीं बुलाई जाती या औपचारिकता के लिए कभीकभार बैठक बुला ली जाती है.

जमुना देवी

ईश्वर दास रोहाणी

सरकारी विभाग विधायकों के नियंत्रण से मुक्त रहना चाहते हैं. उन्हें न तो विधायकों की सलाह की ज़रूरत है और न ही उनकी शिकायतों की परवाह. इस कारण विभिन्न विभागों में बनी 38 परामर्शदात्री समितियां कागजों में कैद होकर रह गई हैं. 27 समितियों की अब तक एक भी बैठक नहीं हुई. सिर्फ ग्यारह समितियों की एक-एक बैठक हुई. जबकि हर दो महीने में बैठक होना तय है. हाल यह है कि न तो इनकी अध्यक्षता करने वाले विभागीय मंत्री इच्छुक हैं और न ही आला अफसर. इस कारण अधिकांश समितियों की कई सालों से बैठकें नहीं हुईं. संसदीय कार्य विभाग ने 6 अगस्त 2009 को 38 परामर्शदात्री समितियां गठित की थीं. इनमें कुछ विभागों की संयुक्त समितियां बनाई गई हैं. इनमें पक्ष और विपक्ष दोनों के विधायक सदस्य और अध्यक्ष विभागीय मंत्री हैं. सभी दलों के सदस्य बैठक के माध्यम से संबंधित विभाग को बेहतर काम करने के सुझाव देते हैं. इसलिए समितियों की हर दो महीने में बैठक करने का नियम है, ताकि सभी सदस्य विभाग की योजनाओं पर विचार-विमर्श कर सकें. जिन 11 समितियों की सिर्फ एक-एक बैठक हुई है, उनमें सामान्य प्रशासन, वन, ऊर्जा, पशुपालन, विधि-विधायी एवं संसदीय कार्य, सहकारिता, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, आवास एवं पर्यावरण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी और जल संसाधन विभाग शामिल हैं.

सामान्य प्रशासन विभाग की 4 नवंबर को हुई पहली बैठक में भी नियमित बैठकें न होने का मुद्दा उठा था. तब सभी विभागों को बैठक करने के निर्देश दिए गए थे. बावजूद इसके आज तक खुद सामान्य प्रशासनिक विभाग की दूसरी बैठक नहीं हुई. नियमानुसार विभाग को बैठक की व्यवस्था करनी होती है. कई विभागों की समितियों की बैठकें पिछले 10-11 साल से नहीं हुई हैं. यह समितियां कागजों में बनती-मिटती रहीं, लेकिन बैठकें नहीं हुईं. इनमें जनसंपर्क, जनशिकायत निवारण, संस्कृति, पर्यटन, गृह, विमानन, वित्त योजना एवं सांख्यिकी, बीस सूत्रीय कार्यक्रम, स्कूल शिक्षा, राजस्व, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार, सार्वजनिक उपक्रम, किसान कल्याण, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा, लोक निर्माण, वाणिज्यिक कर, नगरीय प्रशासन, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व तथा पुनर्वास आदिम जाति, अनुसूचित जाति कल्याण, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग कल्याण, श्रम, महिला एवं बाल विकास, खनिज साधन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, जेल, तकनीक़ी शिक्षा, परिवहन, खेल एवं युवक कल्याण, ग्रामोद्योग जैव विविधता और भोपाल गैस त्रासदी आदि विभाग शामिल हैं.

नियम क्या कहता है

- समितियों का कार्यकाल दो साल रहेगा.
- हर दो महीने में बैठक अनिवार्य.
- संबंधित विभाग द्वारा समिति अध्यक्ष से चर्चा कर बैठक की तिथि निर्धारित करना और एक महीने पहले संसदीय कार्य विभाग को अवगत कराना, जहां से बैठक से बीस दिन पहले सदस्यों को सूचित किया जाना.
- बैठक की कार्यसूची दो दिन पहले सदस्यों तक पहुंचाना.
- बैठक में विभाग से सिर्फ विभागाध्यक्ष और सचिव ही उपस्थित रहेंगे.
- अध्यक्षता मंत्री या राज्यमंत्री कर सकेंगे.

feedback@chauthiduniya.com

एमपी बिरला अस्पताल

अवैध ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जांच शुरू

पुष्पेंद्र मौर्य

मध्य प्रदेश विधानसभा में पूछे गए एक प्रश्न ने सतना के एमपी बिरला अस्पताल में हड़कंप मचा दिया है. इस अस्पताल के पास ब्लड बैंक की अनुमति नहीं है, जबकि यह अब तक हज़ारों मरीज़ों को स्वयं ख़ून चढ़ाने का काम कर चुका है. पिछले आठ वर्षों से चल रहे इस गोरखधंधे से कई मरीज़ों की जान संकट में पड़ चुकी है. राज्य विधानसभा में चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी ने एक प्रश्न के तहत इस अस्पताल द्वारा अपने मरीज़ों को ख़ून चढ़ाए जाने की प्रक्रिया पर संदेह व्यक्त किया था. एमपी बिरला अस्पताल को सतना में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त एवं नवीनतम टेक्नोलॉजी का एक प्रमुख केंद्र माना जाता है. ज़िले के सभी गंभीर मामले इस अस्पताल को विश्वास के साथ भेजे जाते हैं.

फोटो : संजय मौर्य

विधायक ने जानकारी चाही थी कि बिरला अस्पताल द्वारा तीन वर्षों में किस-किस मरीज़ को कितनी मात्रा में किस ग्रुप का ख़ून चढ़ाया गया? उक्त ख़ून ज़िला अस्पताल स्थित ब्लड बैंक से कब लिया गया? उन्होंने निजी अस्पतालों, जिनके पास स्वयं का ब्लड बैंक लाइसेंस नहीं है और जो न तो ब्लड निकाल सकते हैं और न ही उसे भर्ती किए गए मरीज़ों को चढ़ा सकते हैं, के बारे में भी प्रश्न किए थे. विधायक ने अस्पताल के चेरिटेबल ट्रस्ट की प्रकृति पर भी संदेह करते हुए पूछा कि किसी मरीज़ का इलाज यह अस्पताल चेरिटी में क्यों नहीं कर रहा है? विधायक ने स्वास्थ्य मंत्री से मांग की कि बिरला अस्पताल सतना द्वारा आठ वर्षों में अवैध कार्य करने के कारण सैकड़ों मरीज़ों की जान गई है, इसलिए उस पर आपराधिक मामला दर्ज़ कर उच्चस्तरीय जांच कराई जाए.

उल्लेखनीय है कि एमपी बिरला अस्पताल के सिविल सर्जन प्रमोद पाठक के अवकाश पर जाने के बाद डॉ. एसबी सिंह ने कुछ समय के लिए कार्यभार संभाला. उन्होंने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए एक पत्र ज़िले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजा, जिसमें एमपी बिरला अस्पताल द्वारा अवैध रूप से ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने की बात कही गई और यह भी लिखा गया कि इससे रोगी कल्याण समिति को भारी आर्थिक क्षति होती है. मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने एक कमेटी का गठन किया और मामला ठंडे बस्ते में चला गया.

> उल्लेखनीय है कि एमपी बिरला अस्पताल के सिविल सर्जन प्रमोद पाठक के अवकाश पर जाने के बाद डॉ. एसबी सिंह ने कुछ समय के लिए कार्यभार संभाला.

विधानसभा में मामला गूंजने के बाद मार्च माह में उपरोक्त टीम ने अपना मौन तोड़ते हुए बिरला अस्पताल के समस्त दस्तावेज़ों को अपने क़ब्ज़े में ले लिया और मामले की विधिवत जांच शुरू कर दी. सवाल तो यह है कि छह माह पूर्व नवंबर में ज़िला स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा गठित जांच दल ने अपने काम में इतनी देर क्यों की? इससे सतना के मरीज़ों को कितना नुकसान झेलना पड़ा और बिरला समूह द्वारा चलाए जा रहे अस्पताल की इस ग़ैरक़ानूनी हरकत को नियंत्रित करने में ज़िला प्रशासन क्यों अक्षम रहा?

feedback@chauthiduniya.com

सार -संक्षेप

बाज़ार में आने वाला है बीटी आलू

बॉयो टेक्नोलॉजी द्वारा जेनेटिकली मोडिफाइड बैंगन (बीटी बैंगन) का विरोध थमा नहीं कि अब बाज़ार में बीटी आलू उतारने की तैयारी चल रही है. जानकारी के अनुसार, बीटी आलू तैयार हो गया है, लेकिन अभी उसे बाज़ार में उतारने के लिए सही समय और अनुकूल वातावरण की प्रतीक्षा है. पता चला है कि भारत सरकार की आनुवांशिक अभियंत्रण मंजूरी समिति (जीईएसी) के पास इसकी मंजूरी के लिए कोई आवेदन नहीं किया गया है. वैसे भी ताक़तवर बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भारत सरकार की किसी भी संस्था की कोई परवाह नहीं है. यह उन कंपनियों और उनके समर्थक वैज्ञानिकों एवं कृषि विशेषज्ञों का कमाल है. उन्होंने 2002 में भारत सरकार से बीटी कॉटन, बीटी बैंगन आदि के बीजों का कारोबार करने की अनुमति ली थी. बाद में इसका विरोध भी हुआ, लेकिन अभी तक भारत सरकार ने इस मामले में कोई कड़ी कार्यवाही नहीं की है, जबकि मध्य प्रदेश समेत कुछ राज्य सरकारों ने बीटी बैंगन पर प्रतिबंध लगाया है. बीटी आलू के पक्षधरों का कहना है कि इसके बाज़ार में आ जाने से बच्चों में कुपोषण की समस्या से निपटने में मदद मिलेगी. प्रचार किया जा रहा है कि यह आलू पौष्टिक और शरीर के लिए लाभदायक ज़रूरी तत्वों से भरपूर है. यह विटामिन ए की कमी को भी दूर करेगा और इससे भारत में रतौंधी के शिकार लाखों ग़रीबों की आंखों को नया जीवन मिलेगा. जेनेटिकली मोडिफाइड आलू पर अभी तक सभी प्रयोग उसके उत्तकीय प्रजनन पर किए गए हैं. आशय यह कि आलू के टुकड़े काटकर उसे ज़मीन में बोया जाता है. उत्तर भारत में इसे आलू की आंखें लगाना कहते हैं. लैंगिक बीज (फूल-फल लगने) के उपरांत इस प्रजाति के गुण-दोषों के बारे में कोई जानकारी नहीं है. अभी अंतर आनुवांशिक आलू की स्थिरता के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसके लिए लैंगिक प्रजनन के प्रयोगों की ज़रूरत होती है, जो अभी तक नहीं किए गए.

वनभूमि पर अधिकार के दो तिहाई दावे निरस्त

भारत सरकार द्वारा लागू वनाधिकार मान्यता क़ानून के तहत मध्य प्रदेश में वनभूमि पर क़ाबिज़ आदिवासियों-वनवासियों को भू-अधिकार के पट्टे देने की कार्यवाही के तहत बड़ी संख्या में दावों को निरस्त किया जा रहा है. जानकारी के अनुसार, अब तक शासन को लगभग साढ़े तीन लाख दावे प्राप्त हुए हैं, लेकिन उसने केवल एक लाख सात हज़ार दावों को ही मान्य किया है और उनके आधार पर भू-अधिकार देने की कार्यवाही की जा रही है. जबकि दो लाख 41 हज़ार दावे शासन द्वारा निरस्त किए जा चुके हैं. वनमंत्री सरताज सिंह का कहना है कि वनाधिकार कानून में उन्हीं लोगों को भू-अधिकार के पट्टे देने का प्रावधान है, जो 75 वर्षों से वनभूमि पर क़ाबिज़ रहे हैं. 75 वर्षों से भूमि पर अपना क़ब्ज़ा सिद्ध करने में असफल रहने वाले दावेदारों के पट्टे और दावे निरस्त किए जाएंगे. कांग्रेस प्रवक्ता अरविंद मालवीय का कहना है कि शासन वनभूमि को उद्योगों एवं अन्य उपयोग के लिए अपने क़ब्ज़े में रखना चाहता है, इसलिए वर्षों से वनभूमि पर क़ाबिज़ लोगों के दावे निरस्त किए जा रहे हैं. भू-माफ़िया और खदान माफ़िया के दबाव में आकर पट्टे देने में जानबूझ कर गड़बड़ी की जा रही है. भोपाल संभाग में 8959 दावे मान्य किए गए, जबकि 44,122 दावे निरस्त कर दिए गए. संभाग के रायसेन, सीहोर एवं विदिशा आदि ज़िलों में बड़ी संख्या में आदिवासी सदियों से वनभूमि पर क़ाबिज़ हैं. नवाबी दौर में भी इन वनवासियों को उनके क़ब्ज़े की भूमि से बेदख़ल नहीं किया गया. जबकि आज भारत सरकार द्वारा क़ानून बना दिए जाने के बाद अधिकारी अनपढ़ आदिवासियों और वनवासियों को 75 वर्ष का प्रमाण न मिलने के बहाने भूमि से बेदख़ल कर रहे हैं. मालवीय ने कहा कि वन और राजस्व विभाग के छोटे अधिकारी दावेदारों के मामले ग्रामसभा में ले जाने की औपचारिकता शरारती तरीक़े से पूरी कर रहे हैं. दावेदारों को इसकी ख़बर नहीं लग पाती और न ही उन्हें ग्रामसभा की बैठकों का पता चलता है. इसलिए निरस्त दावों की दोबारा जांच और समीक्षा की जानी चाहिए.

प्लास्टिक कचरे का ईंधन के रूप में इस्तेमाल

प्लास्टिक कचरे की समस्या से निजात दिलाने के लिए एक आसान हल निकाला गया है. इस कचरे को सीमेंट कारखानों में ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा है और इसके अच्छे नतीजे भी मिल रहे हैं. मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट 2008-09 के अनुसार, इस वर्ष राज्य के सतना, नीमच, कटनी, दमोह और रीवा के कारख़ानों में 300 टन प्लास्टिक कचरा बतौर ईंधन उपयोग किया गया है. इससे कोयले की बचत भी हुई और अनुपयोगी प्लास्टिक कचरा सुरक्षित रूप से नष्ट भी कर दिया गया. मध्य प्रदेश के शहरों में प्रतिदिन औसतन 44 मैट्रिक टन से अधिक ठोस कचरा निकलता है, जिसमें 2 से 8 प्रतिशत तक प्लास्टिक कचरा होता है. कम तापमान पर प्लास्टिक जलाने से ज़हरीली और हानिकारक गैसें निकलती हैं, जो प्राणी और वनस्पति जगत के लिए हानिकारक होती हैं. सीमेंट कारख़ानों में 1400 से 1450 डिग्री तक तापमान में यह कचरा जलाने से हानिकारक गैसें आग के साथ ही नष्ट हो जाती हैं. इसलिए प्रदूषण का ख़तरा भी नहीं रहता.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

उच्च शिक्षा विभाग बदहाली का शिकार

पृष्ठ एक का शेष

लेना ही छोड़ दिया. यही कहानी भूगर्भ विज्ञान के एक विद्वान प्रोफेसर की है. रीवा के सरकारी कॉलेज के इस प्रोफेसर का शोधपत्र लगभग 15 वर्ष पूर्व लंदन में अंतरराष्ट्रीय भू-विज्ञान कांग्रेस के वार्षिक सम्मेलन के लिए चुना गया था और उन्हें सम्मेलन में बुलाया गया था. जब आने-जाने के ख़र्च के लिए पीएफ एकाउंट से पैसा निकालने और लंदन जाने की अनुमति के लिए उन्होंने शासन से पत्र व्यवहार किया तो सम्मेलन संपन्न हो जाने के एक माह बाद शासन की अनुमति प्राप्त हुई. सेवानिवृत्ति के बाद यह प्रोफेसर भूगर्भ विज्ञान के कई देशी-विदेशी शोध छात्रों को मार्गदर्शन देने का काम कर रहे हैं और उन्हें मुंबई, चेन्नई एवं पुणे विश्वविद्यालयों में शोध कर रहे छात्रों के बीच व्याख्यान देने के लिए बुलाया जाता है. मध्य प्रदेश निवासी एक युवक एवं एक युवती अमेरिका के नासा में उच्च पद पर हैं, लेकिन अपने राज्य में उन्हें कॉलेज में व्याख्याता की नौकरी के क़ाबिल भी नहीं समझा गया. एक अन्य युवक अमेरिका की एक बड़ी आईटी कंपनी में वरिष्ठ पद एवं ऊंचे वेतन पर अपनी सेवाएं दे रहा है, जिसे सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में दैनिक वेतन पर भी व्याख्याता पद के लिए योग्य नहीं माना गया था, क्योंकि नौकरी देने वालों को अपने चहेतों को उपकृत करना था.

मध्य प्रदेश की नौकरशाही तो फाइलों पर संत तुलसीदास को टी. दास और महाकवि कालीदास को के. दास लिखने के लिए मशहूर है. विज्ञान के एक शोध विद्वान का कहना है कि यदि मध्य प्रदेश का कोई प्रोफेसर अमृत की खोज भी कर लेगा तो यहां के विश्वविद्यालयों के मठाधीश उसे पागल क़रार देंगे, लेकिन उसी अमृत को पीकर वो अमर होना ज़रूर चाहेंगे. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने मध्य प्रदेश में ही स्कूल से लेकर कॉलेज तक शिक्षा पाई. वह दर्शनशास्त्र विषय के प्रतिभाशाली छात्र रहे हैं और कॉलेजों-विश्वविद्यालयों की ख़ूबियों एवं ख़ामियों को भली प्रकार से समझते हैं, लेकिन आओ बनाएं अपना मध्य प्रदेश नामक अभियान चलाते समय उनका ध्यान राज्य की उच्च शिक्षा की बदहाली की तरफ़ नहीं है, यह राज्य का दुर्भाग्य है.

feedback@chauthiduniya.com

जवाब देने का काम बाबू के ज़िम्मे

उच्च शिक्षा विभाग में आईएएस आराम फरमाते हैं और उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों को वर्षों तक टालते रहते हैं. जब न्यायालय द्वारा फटकार मिलती है और एडवोकेट जनरल या दिल्ली के सरकारी वकील बार-बार जवाब देने के लिए कहते हैं, तब विभाग के प्रमुख सचिव किसी बाबू को इस काम पर लगा देते हैं. अशासकीय महाविद्यालयों के शिक्षकों और कर्मचारियों को शासकीय कोषालय से पूरा वेतन देने का क़ानून 1978 में बना था, लेकिन दिग्विजय सिंह के शासन में कुछ आईएएस अफसरों ने सरकारी ख़र्च में बचत के लिए इन निजी कॉलेजों को अनुदान देने पर रोक लगाने की सलाह दी और एक क़ानून भी बना दिया. इस क़ानून को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई और वहां राज्य सरकार मामला हार गई, लेकिन राज्य सरकार ने अपनी हार न मानते हुए उच्च न्यायालय के फ़ैसले के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर दी. लगभग दस सालों से मामला चल रहा है. सरकार बदल गई. कई मुख्यमंत्री, मंत्री और शिक्षा सचिव बदल चुके हैं. फिर भी मामले में सरकार की ओर से समाधान योग्य उत्तर सर्वोच्च न्यायालय में नहीं दिया गया. विभाग के एक बाबू को जवाब तैयार करने का ज़िम्मा सौंपा गया है और उसकी सहायता के लिए प्रतिनियुक्ति पर आए एक सरकारी कॉलेज के प्राध्यापक को लगाया गया है. महत्वपूर्ण सरकारी निर्णय बाबू कैसे ले सकता है?

राज्य में प्राचार्यों के 150 से अधिक पद, विभिन्न विषयों के प्राध्यापकों एवं सहायक प्राध्यापकों के 300 पद और व्याख्याताओं के 1000 पद खाली हैं. छोटे कस्बों और आदिवासी क्षेत्रों में कॉलेजों की स्थिति हास्यापद है. इन कॉलेजों में कई विषयों के व्याख्याता नहीं हैं. इसलिए पढ़ाई नहीं होती है, केवल परीक्षा होती है.

अफसरों ने सरकार को 2342 करोड़ रुपयों का चूना लगाया

जिन अफसरों और कर्मचारियों पर सरकारी करों और सेवाओं के शुल्क की वसूली का दायित्व है, वे किस लापरवाही और ग़ैर ज़िम्मेदारी से काम करते हैं, इसका खुलासा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट में किया गया है.

इस रिपोर्ट के मुताबिक 31 मार्च 2009 को समाप्त वित्त वर्ष में विभिन्न करों और सरकारी सेवाओं के शुल्क के रूप में वसूल करने योग्य 2342 करोड़ रुपयों की धनराशि वसूल नहीं की जा सकी, क्योंकि कर निर्धारण में अधिकारियों ने गंभीरता से ध्यान नहीं दिया. कहीं, निर्धारित मात्रा से कम मात्रा में करारोपण किया, तो कहीं बिना दस्तावेजों के देखे ही व्यापारियों पर भरोसा करके कर राशि का निर्धारण कर दिया गया. किसी मामले में खरीदे गए और बेचे गए माल का सत्यापन किए बिना ही कर भुगतान को सही मानकर विभाग ने कर राशि जमा कर ली. कुछ मामलों में तो उद्योगों में लगने वाले कच्चे माल और अन्य वस्तुओं पर करारोपण किया ही नहीं गया और कई मामलों में तो अधिकारियों ने स्वविवेक से मनमाने तरीके से कर निर्धारण में और छूट दे दी. आबकारी विभाग, परिवहन विभाग, वाणिज्यकर विभाग, सिंचाई विभाग, मुद्रांक एवं पंजीयक विभागों में बड़ी मात्रा में कर निर्धारण में भूलचूक और गड़बड़ी होने से सरकार को एक वर्ष में ही करोड़ों रुपयों की आय से वंचित होना पड़ा है.

बकाया कर वसूली

मध्य प्रदेश सरकार की, वित्त वर्ष 2008-09 में कुल कर राजस्व आय 13613 करोड़ रुपए थी, लेकिन महालेखापरीक्षक की मानें तो 2342 करोड़ रुपयों का चूना तो अफसरों ने ही लगा दिया और वसूल होने लायक कर का निर्धारण ही नहीं किया. इसके अलावा लगभग 765 करोड़ रुपयों की कर राशि वसूल नहीं की और इसे बकाया राजस्व के मद में डाल दिया गया. कर वसूली में सिर्फ़ एक विभाग नहीं, सभी विभाग लापरवाह हैं, इसे इस तालिका से समझा जा सकता है.

महालेखापरीक्षक ने विभिन्न दो लाख 96 हज़ार मामलों की जांच के बाद यह नतीज़ा निकाला है कि राज्य सरकार को 2342 करोड़ रुपयों का चूना लगा है. वाणिज्यकर में व्यापारियों द्वारा प्रतिभूति जमा करने के लिए वैधानिक प्रावधान की कमी के कारण 2 करोड़ 18 लाख रुपए प्राप्त नहीं हुए, जबकि इन्वेंटरी रिबेट तथा इनपुट टैक्स क्रेडिट का गलत लाभ दिये जाने से 16 लाख रुपए की चपत लगी. कर की गलत दर लागू किये जाने से 2 करोड़ 57 लाख, राज्य उत्पाद शुल्क के तहत निर्धारित अवधि में विदेशी मदिरा, बीयर तथा स्पिरिट के निर्यात, परिवहन में सत्यापन नहीं करने से 14 करोड़ 47 लाख, 4 हजार 851 रुपये वाहनों पर 7 करोड़ 46 लाख का दण्ड सहित करों का भुगतान नहीं लेने से 18 करोड़ 59 लाख रुपए का नुकसान सरकार को उठाना पड़ा.

सिंचाई और पेयजल हेतु पानी उपलब्ध कराने वाले जल संसाधन विभाग में कर वसूली में 589 करोड़ रुपयों की हानि हुई. सिंचाई क्षमता का उपयोग न होने से 160 करोड़ रुपयों की आय की क्षति हुई. इसके अलावा आबकारी विभाग को 13.47 करोड़ रुपयों के आबकारी शुल्क का नुकसान हुआ है.

रिपोर्ट में बताया गया है कि 4851 वाहनों से वाहन कर के मद में 18.59 करोड़ रुपए न तो वाहन स्वामियों ने जमा कराया और न ही विभाग ने उनसे इस कर के भुगतान के बारे में कोई मांग की. भू राजस्व मद में एक करोड़ 53 लाख रुपए की हानि हुई. सरकारी वन विभाग में वाणिज्य कर और वैट कर प्राप्तियों के गलत निर्धारण से 200 करोड़ रुपए बढ़ाकर बताये गए, जबकि बांस का दोहन न होने से 11 करोड़ रुपयों की कर हानि हुई. सड़क विकास कर का निर्धारण न होने से 93.56 करोड़ रुपए और मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस में 5.95 करोड़ रुपए कम मिले. ज़िला कलेक्टरों को भेजे गए प्रकरणों के निराकरण में देरी के कारण 4.85 करोड़ रुपयों का नुकसान हुआ.

कर वसूली में लागत ज़्यादा आमद कम

मध्य प्रदेश सरकार में कर वसूली के काम में लागत ज़्यादा आती है, लेकिन लागत की तुलना में कर वसूली करने वाले अधिकारी, कर्मचारी काम करते हैं. विक्रयकर वसूली की कुल आय की तुलना में कुल ख़र्च का राष्ट्रीय औसत जहां 0.83 प्रतिशत है, वहीं मध्य प्रदेश में यह 1 से 1.41 फीसदी तक आता है. राज्य उत्पाद शुल्क वसूली में यह राष्ट्रीय औसत 3.27 फीसदी की तुलना में 19 से 21.96 फीसदी तक और मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क के मामले में राष्ट्रीय औसत 2.09 की तुलना में 2.92 फीसदी तक है. इसका अर्थ है कि राष्ट्रीय औसत की तुलना में मध्य प्रदेश अपने कर वसूली अमले पर ज़्यादा ख़र्च करता है, पर यह अमला लागत की तुलना में आमदनी कम ही करता है. इसका अर्थ स्पष्ट है कि कर वसूली के मामले में कहीं न कहीं कर वसूली करने वाले भ्रष्टाचार और निजी हित में काली कमाई करने में ज्यादा रुचि लेते हैं. अपने लाभ के लिए वे सरकारी कोष को चूना लगाने में ज़रा भी शर्म महसूस नहीं करते हैं.

विद्युत मंडल पर 745 करोड़ रुपया बकाया

इस रिपोर्ट में एक चौंका देने वाला तथ्य उजागर हुआ है. मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल ताप और जल विद्युत उत्पादन के लिए राज्य के जल संसाधन विभाग के स्त्रोतों से, जो पानी लेता है, उसके मद में 745 करोड़ रुपयों का बकाया चढ़ा हुआ है, लेकिन विद्युत मंडल इसका भुगतान नहीं कर रहा है. वर्ष 2004-05 में जल शुल्क का बकाया 185 करोड़ रुपए था जो विद्युत मंडल ने नहीं चुकाया और इसके बाद के वर्षों में भी मंडल अपने बिजली घरों के लिए मुफ्त पानी लेता रहा. मार्च 2008 तक उस पर 745 करोड़ रुपए की राशि बकाया हो गई, लेकिन जल संसाधन विभाग, विद्युत मंडल से यह धनराशि वसूल नहीं कर पाया.

क्र.	कर राजस्व मद	31 मार्च 2009 को बकाया राशि (करोड़ रुपयों में)	पांच वर्षों से अधिक समय से बकाया राशि (करोड़ रुपयों में)
1.	वाहनों पर कर	31.17	जानकारी उपलब्धनहींकराई गई
2.	राज्य उत्पाद शुल्क	59.60	55.49
3.	विद्युत पर कर एवं शुल्क	19.72	13.86
4.	विक्रय कर	546.04	424.29
5.	अलौह धातु खनन एवं धातुकर्म उद्योग	12.19	12.19
6.	सहकारिता	9.23	5.51
7.	मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस	87.50	21.69
	योग	765.45	533.03

विद्युत मंडल ने बाण सागर बांध से पानी लेने के लिए सरकार के जल संसाधन विभाग से कोई अनुबंध नहीं किया और बिना जल शुल्क चुकाए पानी लेना शुरू कर दिया. परिणामस्वरूप दिसंबर 2008 तक मंडल पर अकेले बाण सागर बांध के पानी का 586 करोड़ रुपया बकाया हो गया, लेकिन मंडल ने उसका कोई भुगतान नहीं किया.

सिंचाई क्षमता के उपयोग में कमी

जल संसाधन विभाग द्वारा अरबों-खरबों रुपए खर्च करके पिछले 62 वर्षों में राज्य में तैयार की गई सिंचाई क्षमता का कभी भी 50 प्रतिशत तक भी उपयोग नहीं किया गया है. वर्ष 2004-05 में कुल सिंचाई क्षमता का 46 प्रतिशत उपयोग हुआ तो वर्ष 2006-07 से वर्ष 2008-09 तक केवल 35 प्रतिशत उपयोग ही होता आया है. क्षमता का पूरा उपयोग न होने से हर साल जल शुल्क के मद में सरकार को 25 से 40 करोड़ रुपयों तक की क्षति हुई है. वर्तमान में राज्य में कुल 125.35 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई क्षमता विकसित की जा चुकी है, लेकिन राज्य का जल संसाधन विभाग उपलब्ध क्षमता का केवल 39 प्रतिशत ही उपयोग कर पाता है और इस कारण लगभग 161 करोड़ रुपयों के राजस्व की क्षति हुई है.

वित्त प्रबंधन में लापरवाही

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट देखने से साफ पता चलता है कि राज्य सरकार के वित्त प्रबंधन में भारी लापरवाही बरती जा रही है. एक ओर तो राज्य सरकार विकास और जनकल्याण के लिए हमेशा धन की कमी का रोना रोती है और केंद्र सरकार से मिलने वाली मदद को कम बताती है, तो दूसरी ओर सरकार अपने आय के संसाधनों और स्रोतों का पूरा-पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाती.

मध्य प्रदेश के कर राजस्व प्राप्तियों में वर्ष 2004-05 से 2008-09 तक वृद्धिदर 15.01 प्रतिशत रही और वर्ष 2009-10 में वृद्धिदर 18.08 प्रतिशत रही, जबकि इस अवधि में केंद्र से केंद्रीय करों में राज्य के हिस्से के रूप में मिलने वाला अंशदान 21.87 प्रतिशत की दर से बढ़ा तथा केंद्रीय अनुदान 27.46 प्रतिशत से 52.07 प्रतिशत तक बढ़ा है.

वर्ष 2009-10 में राज्य की कुल कर राजस्व आय 16075 करोड़ रुपए थी जबकि केन्द्र से अनुदान और कर हस्तांतरण के रूप में कुल 19949 करोड़ रुपए मिले.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

Postal Regn. No. DL/ND-11/6139/2009-11, RNI No. 45843/86

चौथी दुनिया

दिल्ली, 12 अप्रैल–18 अप्रैल 2010

अमेरिका एवं यूरोपीय देशों के साथ-साथ अरब और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में भी बासमती चावल की मांग बढ़ रही है.

बासमती चावल उत्पादक किसान ठगी के शिकार

भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश के किसानों को भरोसा दिलाया है कि उसकी सरकार खेती को लाभप्रद व्यवसाय बनाने के लिए उपाय करेगी. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान किसानों की हमदर्दी पाने के लिए स्वयं को किसान पुत्र तो कहते हैं, लेकिन उन्हें राज्य के किसानों के हितों की ज़रा भी परवाह नहीं है. इसीलिए भरपूर मेहनत के बाद भी राज्य के किसानों को उनकी उपज का उचित दाम नहीं मिल पाता. मध्य प्रदेश में लगभग दो लाख एकड़ भूमि में बासमती चावल की खेती होती है. बासमती चावल की मांग दुनिया भर में हर साल बढ़ रही है. केवल शाकाहारी ही नहीं, बल्कि मांसाहारी भोजन प्रेमी भी इस स्वादिष्ट चावल को पसंद करते हैं. अमेरिका एवं यूरोपीय देशों के साथ-साथ अरब और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में भी बासमती चावल की मांग बढ़ रही है. भारत सरकार बासमती चावल के निर्यात को भरपूर प्रोत्साहन दे रही है. देशी बाज़ार में बासमती चावल की क़ीमत 50 से 60 रुपये प्रति किलोग्राम है, लेकिन किसानों से व्यापारी और दलाल इसे 30 से 35 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से ख़रीदते हैं. मुंबई, दिल्ली एवं बंगलुरु आदि बड़े शहरों के शानदार मॉल्स में बासमती चावल 100 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से बिकता है. विदेशों में तो इसकी क़ीमत और भी ज़्यादा है.

बताया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा केंद्र से पहल न करने के कारण बासमती चावल एपिडा की सूची में शामिल नहीं हो पाया है. इसके चलते इसे निर्यात के लिए कोई सुविधा नहीं मिलती. मध्य प्रदेश के ज़्यादातर बासमती उत्पादक दलालों और बड़े व्यापारियों के माध्यम से ही यह चावल विदेश भेजने की जुगत में रहते हैं, लेकिन उन्हें अन्य राज्यों की तुलना में अपने चावल का मूल्य नहीं मिल पाता. कांग्रेस प्रवक्ता अरविंद मालवीय का कहना है कि नर्मदांचल क्षेत्र में ज़्यादा क़ीमत मिलने के लालच में हज़ारों किसानों ने उन्नत क़िस्म के बासमती धान बोए और फ़सल भी अच्छी हुई, लेकिन उन्हें सीधे निर्यात करने की सुविधा नहीं मिली. इस कारण उन्हें तीस से चालीस रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से चावल बेचना पड़ा. हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान के बासमती उत्पादकों का चावल विदेशों में बिक रहा है, लेकिन हमारा चावल राज्य सरकार की उदासीनता के चलते सस्ते दामों पर बेचा जाता है. यह किसानों के हितों की उपेक्षा है. इधर मध्य क्षेत्र बासमती उत्पादक संघ ने मुख्यमंत्री से एपिडा सूची में शामिल कराने के लिए पहल करने की मांग की है. एपिडा की सूची में अभी तक रायसेन, सीहोर, विदिशा, होशंगाबाद, बैतूल, नरसिंहपुर, जबलपुर, कटनी, गुना, ग्वालियर, शिवपुरी एवं श्योपुर ज़िलों को शामिल नहीं किया गया है. इन ज़िलों में लगभग दो लाख एकड़ भूमि में बासमती चावल की खेती होती है. राज्य में पीवी-1, पी-1121 एवं सीएसआर-30 क़िस्म के बासमती चावल का उत्पादन होता है. प्रदेश में स्थापित संयंत्रों में धान से 50 प्रतिशत चावल निकलता है. ज़्यादा भाव न मिलने की वज़ह से राज्य के किसान बड़े व्यापारियों एवं निर्यातकों के दलालों के हाथों उनकी मनचाही क़ीमत पर चावल बेचने के लिए मजबूर हैं.

आश्चर्य की बात यह है कि राज्य के कृषि विभाग, वाणिज्य विभाग और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के ज़िम्मेदार अधिकारियों ने बासमती चावल निर्यात के लिए एपिडा सूची में राज्य के उत्पादक ज़िलों को शामिल नहीं कराया है. कृषि मंत्री, वाणिज्य मंत्री और मुख्यमंत्री को तो शायद मालूम ही नहीं है कि एपिडा सूची क्या होती है और इसका क्या महत्व है? बासमती चावल पैदा करने वाले किसान बुरी तरह ठगे जा रहे हैं. फिर भी राज्य सरकार को अपनी ग़लती का एहसास नहीं है. उसे शायद यह नहीं मालूम कि बासमती उत्पादक क्षेत्रों में किसानों के बीच निर्यातकों के दलालों और बड़े व्यापारियों का जाल कितनी मज़बूती से फैला हुआ है. खेत से धान निकलते ही व्यापारी और दलाल उस पर अपनी नज़रें गड़ा लेते हैं और कई बार तो धान का सौदा ही कर लेते हैं. हालत यह है कि जिन ज़िलों में बासमती चावल पैदा होता है, वहां के अनाज बाज़ार में यह चावल न तो बेचा जाता है और न ही बेचने के लिए रखा जाता है. यह जानकर अचरज होता है कि बुधनी के आसपास पैदा होने वाला बासमती चावल बुधनी के बाज़ार में भी नहीं बेचा जाता, क्योंकि दलालों और व्यापारियों के साथ सौदा करने के बाद खुले बाज़ार में बेचने के लिए किसानों के पास चावल का एक दाना भी नहीं बच पाता. स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश के बासमती चावल की ज़बरदस्त मांग है. यदि सरकार इसके निर्यात का मार्ग खोल दे तो इससे किसानों को ख़ासा लाभ होगा और यह भी दिखाई देने लगेगा कि सरकार कृषि को लाभदायक व्यवसाय बनाना चाहती है.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

वन विभाग में जंगलराज

मध्य प्रदेश के शासन-प्रशासन में अराजकता और भ्रष्टाचार का बोलबाला है. ऐसे में यदि वन विभाग में जंगलराज चल रहा है तो यह आश्चर्य का विषय नहीं है, क्योंकि जंगलराज हमारी प्रशासनिक संस्कृति की विशेषता बन चुका है. मध्य प्रदेश कभी हरे-भरे वनों से आच्छादित सुरम्य प्राकृतिक दृश्यों से शोभायमान हुआ करता था, लेकिन अब तो हरियाली केवल सरकारी विज्ञापनों में ही दिखाई देती है. राजमार्गों पर जगह-जगह सरकार रंग-बिरंगे होर्डिंग्स लगा रही है, जिन पर लिखा है हरा-भरा मध्य प्रदेश. लेकिन, जब हम इस होर्डिंग्स के आसपास नज़रें दौड़ाते हैं तो सूखा, बंजर और भयभीत करने वाले दृश्य ही दिखाई देते हैं.

वनों की रक्षा करने और वन क्षेत्र बढ़ाने के लिए सरकारी वन विभाग है, लेकिन यह विभाग कैसे काम करता है, सभी को मालूम है. विभाग के छोटे-बड़े अफसर सरकारी पैसा ख़र्च करना जानते हैं, लेकिन काम करना नहीं. क़ाग़ज़ों पर हिसाब बराबर दिखाया जाता है, लेकिन बाद में पोल खुल जाती है. करोड़ों रुपये ख़र्च करके बनाया गया पन्ना टाइगर रिजर्व में आज एक भी टाइगर नहीं बचा है. इसे वन विभाग ने स्वीकार भी किया है. इसी तरह और भी वन्यप्राणी अभ्यारण्य हैं, जहां जानवर बेमौत मारे जाते हैं. संरक्षित वनों में पेड़ और क़ीमती पौधे काटे जाते हैं. जगह-जगह वनों में माफियाओं का क़ब्ज़ा है. वनकर्मी उनसे डरे रहते हैं या फिर लाभ लेकर चुप बैठे रहते हैं.

प्रदेश में वनों के सुदृढ़ीकरण और संरक्षण के लिए एक ओर करोड़ों रुपये ख़र्च किए जा रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ़ जंगलराज की वज़ह से माफ़िया और अफ़सर चार अरब से ज़्यादा की राशि डकार गए. पोल खुलने पर अफ़सर एक-दूसरे पर दोष मढ़ने पर उतारू हैं. सरकार ने भी किसी दोषी के ख़िलाफ़ अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है. राज्य सरकार पांच करोड़ बांस और अन्य पौधे लगाकर वनों को आच्छादित करने की क़वायद कर रही है, लेकिन वनों को बचाने के लिए उसकी हर कसरत औंधे मुंह गिर रही है. वानिकी दिवस मनाने वाली सरकार ने यह देखने की ज़रूरत नहीं समझी कि दो दशक पूर्व अरबों रुपये ख़र्च कर तैयार की गई सामाजिक वानिकियों का क्या हश्र हुआ है. किस तरह बंदरबांट हुई और करोड़ों डकारने वाले अफसरों का अब तक कुछ भी नहीं बिगड़ा. इनमें से ज़्यादातर तो रिटायर हो चुके हैं.

इस सरकार में हिम्मत कोठारी से लेकर कुंवर विजय शाह और राजेंद्र शुक्ल तक वन मंत्री रहे और अब ज़िम्मा सरताज सिंह पर है. इसी तरह अफ़सरों में प्रशांत मेहता के अलावा सर्वाधिक चर्चित अधिकारी पीवी गंगोपाध्याय रहे. यही नहीं, हाल में सरकार ने ख़ुद स्वीकार किया कि 67 अफ़सरों के ख़िलाफ़ विभागीय जांच लंबित है. इनमें एक दर्ज़न से ज़्यादा आईएएफ भी शामिल हैं. इन मामलों में न पहले कभी कोई कार्रवाई हुई और न अब कोई रुचि ली जा रही है. चौंकाने वाली बात तो यह है कि वन मंडलाधिकारी बालाघाट एवं रीवा क्षेत्र में नक्सलियों और डकैतों के ख़ौफ़ की बात कर रहे हैं. दूसरी तरफ़ कई वन अधिकारियों ने सालों से बांस एवं इमारती-जलाऊ लकड़ी के उत्पादन, विक्रय और पैसों का कोई हिसाब-किताब ही नहीं रखा. वन माफिया और अफसरों की मिलीभगत के चलते 222.67 करोड़ रुपये की धनराशि सरकारी ख़ज़ाने तक नहीं पहुंच सकी . इसके अलावा बांस और इमारती लकड़ी के कूपों का विदोहन न किए जाने से 10 करोड़ 29 लाख, कम उत्पादन दर्शाने से 4 करोड़ 48 लाख, वन उपज की गुणवत्ता में लापरवाही बरतने से 1 करोड़ 37 लाख, लेखाजोखा न रखने से 62 लाख, इमारती लकड़ी का पुनर्मापन किए जाने से 60 लाख, कम क़ीमत पर बिक्री किए जाने से 48 लाख और अन्य कई गंभीर अनियमितताओं से 185 करोड़ 58 लाख रुपये की हेराफेरी की गई. राज्य के छिंदवाड़ा पश्चिम, देवास, डिंडौरी, जबलपुर, खंडवा, मंडला पश्चिम, शहडोल उत्तर एवं विदिशा सामान्य वन मंडलों में कूप नियंत्रण पुस्तिकाएं उचित ढंग से नहीं तैयार की गईं. ऐसा जानबूझ कर किया गया, ताकि पोल न खुल सके. बालाघाट और रीवा के वन मंडलाधिकारियों ने यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि वे डकैतों और नक्सलियों के कारण कूपों का विदोहन नहीं कर सके. यही नहीं, बालाघाट में कोई भी निजी ट्रांसपोर्ट कूपों से डिपो तक वन उपज का परिवहन करने के लिए तैयार नहीं हुआ. हक़ीक़त यह है कि प्रदेश में धड़ल्ले से बड़े पैमाने पर हो रही अवैध कटाई में कहीं ऐसी दिक्क़त नहीं हो रही है.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

मनरेगा मुर्दों ने की मज़दूरी

प्रदेश में भ्रष्टाचार के नित नए कीर्तिमान कायम किए जा रहे हैं. महात्मा गांधी के नाम वाली राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना तो सरकारी अमले के लिए अवैध कमाई की गंगा बन चुकी है. आए दिन कोई न कोई ऐसा उदाहरण सुनने या देखनों को मिल ही जाता है जब इस योजना का दुरूपयोग होता रहता है. हाल में शहडोल की जनपद पंचायत जयसिंह नगर के ग्राम चरहेट में दर्ज़नों मुर्दों द्वारा मनरेगा के तहत काम करने और काम के बदले भुगतान लेने का आश्चर्यजनक मामला प्रकाश में आया है. ग्रामीण विकास और रोज़गार गारंटी योजना की जानकारी लेने के उद्देश्य से इंटरनेट का मुआयना करने वालों ने गांव वालों की सहायता से यह पता लगाया है. छानबीन से मालूम हुआ कि ग्राम चरहेट के 64 जॉब कार्डधारकों में से आधा दर्ज़न से ज़्यादा लोग बहुत पहले ही भगवान को प्यारे हो चुके हैं. इनमें कुछ नाम सरकारी कर्मचारियों एवं उनके परिवारजनों के हैं और कुछ स्थानीय जनप्रतिनिधियों के. यही हाल आसपास के गांवों के जॉब कार्ड चार्ट में देखने को मिला. इन गांवों में वर्षों पहले मर चुके लोगों के नाम पर जॉब कार्ड बना दिए गए और उन्हें बाक़ायदा काम दिया जा रहा है. यही नहीं, उन्हें मज़दूरी का भुगतान भी कर दिया जाता है. ग्राम चरहेट के पंचायत सचिव ने मृत लोगों के नाम से फ़र्ज़ीवाड़ा करके 20 लाख रुपये मज़दूरी के रूप में भुगतान करने का हिसाब ऊपर भेज दिया. बाद में गांव के कुछ दबंग लोगों ने शहडोल के संभागायुक्त को एक लिखित शिकायत सौंपी कि फ़र्ज़ी मास्टररोल तैयार करके सचिव ने इंदिरा आवास योजना, समग्र स्वच्छता अभियान, सड़क एवं शौचालय निर्माण जैसे कार्यों में मज़दूरी भुगतान करना बताया है.

मज़दूरी के रूप में भुगतान पाने वालों में कई मृत लोगों के अलावा सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवार वालों के नाम भी हैं. जिन सरकारी कर्मचारियों के नाम से मज़दूरी का भुगतान हुआ है, उनमें पटवारी कवर सिंह, शिक्षक अनिल कुमार उर्मलिया, उनकी पत्नी निर्मला और वन विभाग के कर्मचारी ध्यान सिंह आदि शामिल हैं. जयसिंह नगर की जनपद पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओपी द्विवेदी ने मामले की जांच और शिकायत सही पाए जाने पर दोषी लोगों के ख़िलाफ़ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है. अब यह बात सर्वविदित है कि जब भी कोई अधिकारी दोषियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई का आश्वासन देता है, तो उसके बयान में कितनी विश्वसनीयता होती है.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com